



1-5

जून 2026

PIB

साप्ताहिक संक्षेप

UPSC अभ्यर्थियों के लिए
रणनीतिक एवं नीति संकेत



RUDRAM-II मिसाइल
Table of Contents
स्वदेशी सटीक प्रहार
INDIA-MYANMAR JOINT STATEMENT
दमता



भारत-म्यांमार वक्तव्य
एक्ट ईस्ट और
सामा सुरक्षा



कंबोडिया में UPI
भारत की डिजिटल पब्लिक
इन्फ्रास्ट्रक्चर की पारिवर्तिक पहल



PM सूर्य घर
75 लाख सौर परिवार
लक्ष्य... दिसंबर 2026 तक..5



MINISTRY:	5
EASY EXPLANATION:	5
KEY TERMS:	5
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	6
INDIA–OMAN CEPA — INDIA’S TRADE GATEWAY TO WEST ASIA	7
MINISTRY:	7
EASY EXPLANATION:	7
KEY TERMS:	7
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	8
INDIA’S SEAFOOD EXPORTS — RECORD HIGH IN FY 2025–26.....	9
MINISTRY:	9
EASY EXPLANATION:	9
KEY TERMS:	9
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	10
INDIA–AUSTRALIA DEFENCE MINISTERS’ DIALOGUE — INDO-PACIFIC SECURITY	10
MINISTRY:	10
EASY EXPLANATION:	10
KEY TERMS:	11
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	11
DIGITAL INDIA BHASHINI–DPIIT MoU — MULTILINGUAL INVESTMENT ACCESS	12
MINISTRY:	12
EASY EXPLANATION:	12
KEY TERMS:	13
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	13
SWACHH GAON, SURAKSHIT JALVAYU CAMPAIGN — CLEAN VILLAGES & CLIMATE RESILIENCE	14
MINISTRY:	14
EASY EXPLANATION:	14
KEY TERMS:	14
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	15
ANRF–MAHA WATER MISSION — STARTUPS FOR WATER SECURITY.....	16
MINISTRY:	16
EASY EXPLANATION:	16
KEY TERMS:	16
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	17
RUDRAM-II AIR-TO-SURFACE MISSILE — INDIGENOUS PRECISION STRIKE CAPABILITY	18
MINISTRY:	18
EASY EXPLANATION:	18





KEY TERMS:	18
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	19
VYOMA INNOVATION CHALLENGE — MULTILINGUAL EDGE AI FOR INDIAN LANGUAGES.....	20
MINISTRY:.....	20
EASY EXPLANATION:	20
KEY TERMS:	20
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	21
JAL JEEVAN MISSION 2.0 — REFORM-LINKED MoUs FOR RURAL WATER SUPPLY	22
MINISTRY:.....	22
EASY EXPLANATION:	22
KEY TERMS:	22
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	23
CCPA ACTS AGAINST DARK PATTERNS — DIGITAL CONSUMER PROTECTION	23
MINISTRY:.....	23
EASY EXPLANATION:	24
KEY TERMS:	24
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	25
CROSS-BORDER UPI PAYMENTS IN CAMBODIA — INDIA'S DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE GOES GLOBAL.....	25
MINISTRY:.....	25
EASY EXPLANATION:	26
KEY TERMS:	26
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	27
DISTRICT DOMESTIC PRODUCT GUIDELINES — DISTRICT-LEVEL ECONOMIC DATA	27
MINISTRY:.....	27
EASY EXPLANATION:	27
KEY TERMS:	28
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	28
INDIA-UK CRITICAL MINERALS GLOBAL SUPPLY CHAIN OBSERVATORY.....	29
MINISTRY:.....	29
EASY EXPLANATION:	29
KEY TERMS:	30
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	30
PM SURYA GHAR — 75 LAKH ROOFTOP SOLAR HOUSEHOLDS TARGETED BY DECEMBER 2026 .	31
MINISTRY:.....	31
EASY EXPLANATION:	31
KEY TERMS:	31
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	32





FLEX-FUEL PASSENGER VEHICLE — ETHANOL, FARMERS & ENERGY SECURITY	33
MINISTRY:.....	33
EASY EXPLANATION:	33
KEY TERMS:	33
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	34
JAI PRAKASH NARAYAN BIRD SANCTUARY — INDIA'S 100TH RAMSAR SITE.....	35
MINISTRY:.....	35
EASY EXPLANATION:	35
KEY TERMS:	35
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	36
G-SEC MARKET & FPI REFORMS — DEEPENING INDIA'S FINANCIAL MARKETS	36
MINISTRY:.....	36
EASY EXPLANATION:	37
KEY TERMS:	37
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	37
INDIGENOUS SECOND-GENERATION DIESEL-EQUIVALENT BIOFUEL TECHNOLOGY	38
MINISTRY:.....	38
EASY EXPLANATION:	38
KEY TERMS:	39
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	39
AMAZON FUTURE ENGINEER PROGRAM IN EMRSs — DIGITAL SKILLING FOR TRIBAL STUDENTS	40
MINISTRY:.....	40
EASY EXPLANATION:	40
KEY TERMS:	40
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	41
INDIA'S BIODIVERSITY — COMMITMENTS AND ACHIEVEMENTS	42
MINISTRY:.....	42
EASY EXPLANATION:	42
KEY TERMS:	42
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	43
10 PRELIMS QUESTIONS	44
ANSWER KEY	48
EXPLANATIONS	48
2 MAINS QUESTIONS	49
EXPECTED POINTS:.....	49
EXPECTED POINTS:.....	50



INDIA-MYANMAR JOINT STATEMENT — NEIGHBOURHOOD FIRST & ACT EAST

Ministry:

प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) / विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)

Easy Explanation:

म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग ने 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, भारत और म्यांमार ने सुरक्षा, कनेक्टिविटी (संपर्क), सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा की। भारत के लिए म्यांमार केवल एक पड़ोसी नहीं है। यह भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया (Southeast Asia) के बीच एक थल सेतु (land bridge) है। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy), उत्तर-पूर्व के विकास, सीमा सुरक्षा और उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए बहुत मायने रखता है। संयुक्त बयान की सबसे महत्वपूर्ण बात म्यांमार का यह आश्वासन है कि उसकी भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।

Key Terms:

- **Act East Policy (एक्ट ईस्ट नीति):** व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और कूटनीति के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को गहरा करने की भारत की नीति।
- **Neighbourhood First (पड़ोसी पहले):** भारत का विदेश नीति दृष्टिकोण जो तात्कालिक पड़ोसियों को प्राथमिकता देता है।





- **Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (कालादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना):** कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से और फिर मिजोरम से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी परियोजना।
- **India–Myanmar–Thailand Trilateral Highway (भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग):** भारत के उत्तर-पूर्व को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने वाली सड़क कनेक्टिविटी परियोजना।
- **Border Management (सीमा प्रबंधन):** उग्रवाद, तस्करी, अवैध आंदोलन और सीमावर्ती क्षेत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समन्वय।
- **Sovereignty and Territorial Integrity (संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता):** किसी देश की स्वतंत्रता, सीमाओं और आंतरिक राजनीतिक अधिकार का सम्मान।
- **Development Partnership (विकास साझेदारी):** बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण, अनुदान, ऋण व्यवस्था (lines of credit) और सामुदायिक परियोजनाओं के माध्यम से भारत का समर्थन।

Important Points for UPSC:

- म्यांमार भारत का एकमात्र ऐसा आसियान (ASEAN) पड़ोसी है जिसके साथ भारत की थल सीमा साझा होती है। यह इसे भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु बनाता है।
- भारत म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर एक लंबी थल सीमा साझा करता है।
- म्यांमार भारत के उत्तर-पूर्व की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ उग्रवादी समूहों ने ऐतिहासिक रूप से शरण और आवाजाही के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग किया है।
- संयुक्त बयान की सुरक्षा से जुड़ी लाइन महत्वपूर्ण है: म्यांमार ने आश्वासन दिया कि उसकी भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा।
- म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी भारत के उत्तर-पूर्व के भौगोलिक अलगाव को कम करने में मदद करती है।
- कालादान परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग म्यांमार से जुड़ी प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों तक भारत की पहुंच के लिए भी म्यांमार मायने रखता है।





- भारत को मानवीय चिंताओं के साथ सुरक्षा सहयोग को संतुलित करना होगा क्योंकि म्यांमार ने आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और जातीय संघर्ष का सामना किया है।
- म्यांमार में चीन का प्रभाव इस देश को भारत के लिए भू-राजनीतिक (geopolitically) रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

INDIA-OMAN CEPA — INDIA'S TRADE GATEWAY TO WEST ASIA

Ministry:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry)

Easy Explanation:

भारत और ओमान ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) में प्रवेश किया है। एक CEPA सामान्य व्यापार समझौते की तुलना में अधिक व्यापक होता है क्योंकि इसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, पेशेवरों की गतिशीलता और नियामक सहयोग शामिल होते हैं। ओमान भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास स्थित है और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इस समझौते के तहत, भारत को ओमान में अपने निर्यात के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच (duty-free access) मिलती है। इससे कपड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, खाद्य उत्पाद और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को मदद मिल सकती है।

Key Terms:

- **CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement - व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता):** एक साधारण मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक समझौता।
- **Tariff Line (टैरिफ लाइन / शुल्क रेखा):** एक उत्पाद श्रेणी जिस पर सीमा शुल्क (customs duty) लगाया जाता है।





- **Duty-Free Market Access (शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच):** सीमा शुल्क के बिना किसी अन्य देश में वस्तुओं का प्रवेश।
- **Trade in Services (सेवाओं में व्यापार):** आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्त और व्यावसायिक सेवाओं जैसी सेवाओं का निर्यात।
- **Professional Mobility (पेशेवर गतिशीलता):** देशों के बीच कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की आसान आवाजाही।
- **Rules of Origin (उत्पत्ति के नियम):** यह तय करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम कि क्या कोई उत्पाद वास्तव में किसी देश का है और टैरिफ लाभों के लिए पात्र है या नहीं।
- **Gulf Cooperation Council (खाड़ी सहयोग परिषद):** ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन सहित खाड़ी देशों का क्षेत्रीय समूह।

Important Points for UPSC:

- भारत-ओमान CEPA महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमान पश्चिम एशिया में एक रणनीतिक भागीदार है।
- ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- यह समझौता भारत को ओमान की अधिकांश टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करता है।
- इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, पेशेवरों की गतिशीलता और नियामक सहयोग में व्यापार शामिल है।
- ओमान की स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को खाड़ी, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और वैश्विक शिपिंग मार्गों से जोड़ता है।
- ओमान बड़े जीसीसी (GCC) बाजार में भारतीय निर्यात के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है।
- यह समझौता भारतीय क्षेत्रों जैसे कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, रसायन, खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं को मदद कर सकता है।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी CEPA महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमान व्यापक खाड़ी ऊर्जा भूगोल का हिस्सा है।
- भारत हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का विस्तार कर रहा है, जिसमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए (EFTA), यूके और ओमान के साथ समझौते शामिल हैं।





INDIA'S SEAFOOD EXPORTS — RECORD HIGH IN FY 2025–26

Ministry:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry)

Easy Explanation:

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य (seafood) निर्यात रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंच गया। भारत ने ₹73,890.46 करोड़ या लगभग 8.46 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का 19,72,018 मीट्रिक टन समुद्री भोजन निर्यात किया। फ्रोजन झींगा (Frozen shrimp) प्रमुख निर्यात वस्तु बनी रही। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन शीर्ष बाजार बने रहे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्री खाद्य निर्यात भारत की नीली अर्थव्यवस्था (blue economy), तटीय आजीविका, जलीय कृषि (aquaculture), समुद्री उत्पाद गुणवत्ता मानकों और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ा हुआ है।

Key Terms:

- **Seafood Exports (समुद्री खाद्य निर्यात):** मछली, झींगा, स्क्विड, कटलफिश और अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात।
- **Frozen Shrimp (जमे हुए झींगे):** मूल्य के मामले में भारत की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खाद्य निर्यात वस्तु।
- **MPEDA (Marine Products Export Development Authority - समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण):** भारत से समुद्री उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था।
- **Blue Economy (नीली अर्थव्यवस्था):** आर्थिक विकास और आजीविका के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग।
- **Aquaculture (जलीय कृषि):** मछली और झींगे जैसे जलीय जीवों का पालन।
- **SPS Standards (Sanitary and Phytosanitary Standards - स्वच्छता और पादप-स्वच्छता मानक):** खाद्य सुरक्षा और पशु/पौधों के स्वास्थ्य से संबंधित मानक।



| Click to Connect Now.



- **Value Addition (मूल्य संवर्धन):** कच्चे उत्पादों को उच्च मूल्य वाले निर्यात उत्पादों में संसाधित (process) करना।

Important Points for UPSC:

- भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 19,72,018 मीट्रिक टन समुद्री भोजन का निर्यात किया।
- समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य ₹73,890.46 करोड़ या 8.46 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।
- यह मात्रा (volume) और मूल्य (value) दोनों में सर्वकालिक उच्च स्तर था।
- फ़ोजन झींगा भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का मुख्य चालक बना रहा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय समुद्री भोजन के शीर्ष बाजार बने रहे।
- समुद्री खाद्य निर्यात तटीय राज्यों, मछुआरों, जलीय कृषि किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यात कमाई के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत का समुद्री खाद्य क्षेत्र नीली अर्थव्यवस्था से बारीकी से जुड़ा हुआ है।
- गुणवत्ता नियंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्री खाद्य निर्यात को विदेशी बाजारों में सख्त खाद्य सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ता है।
- एसपीएस (SPS) मानक, ट्रेसिबिलिटी (पता लगाने की क्षमता), रोग नियंत्रण, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- भारत को कच्चे या कम मूल्य वाले समुद्री खाद्य निर्यात से अधिक मूल्य वर्धित (value-added) उत्पादों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

INDIA-AUSTRALIA DEFENCE MINISTERS' DIALOGUE — INDO-PACIFIC SECURITY

Ministry:

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

Easy Explanation:



| Click to Connect Now.

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में दूसरी रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की। बैठक रक्षा सहयोग, सैन्य अंतःक्रियाशीलता (military interoperability), रक्षा उद्योग सहयोग, सह-विकास (co-development), सह-उत्पादन (co-production) और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड (Quad) के सदस्य हैं और एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) के बारे में समान चिंताएं साझा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा सहयोग भारत को विशेष रूप से हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है।

Key Terms:

- **Defence Ministers' Dialogue (रक्षा मंत्रियों की वार्ता):** सैन्य और रणनीतिक सहयोग की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक।
- **Indo-Pacific (हिंद-प्रशांत):** हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रणनीतिक क्षेत्र।
- **Quad (क्वाड):** भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का समूह।
- **Military Interoperability (सैन्य अंतर-संचालनीयता):** दो देशों के सशस्त्र बलों की एक साथ सुचारु रूप से काम करने की क्षमता।
- **Co-development (सह-विकास):** रक्षा तकनीक या प्लेटफॉर्म का संयुक्त विकास।
- **Co-production (सह-उत्पादन):** रक्षा उपकरणों का संयुक्त निर्माण।
- **Maritime Security (समुद्री सुरक्षा):** समुद्री लेन, बंदरगाहों, जहाजों, व्यापार मार्गों और महासागरीय हितों की सुरक्षा।
- **Defence Industry Cooperation (रक्षा उद्योग सहयोग):** रक्षा कंपनियों, अनुसंधान निकायों और सरकारों के बीच सहयोग।

Important Points for UPSC:

- भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक समुद्री भागीदार हैं क्योंकि दोनों के हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत हित हैं।
- ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड भागीदार है, इसलिए रक्षा सहयोग व्यापक हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढांचे में भी फिट बैठता है।
- इस संवाद में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा की गई और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की गई।

- चर्चा किए गए प्रमुख क्षेत्रों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग, सैन्य अंतःक्रियाशीलता और रक्षा उद्योग सहयोग शामिल थे।
- सह-विकास और सह-उत्पादन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत रक्षा आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है।
- समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख साझा चिंता है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा आवाजाही सुरक्षित समुद्री लेन पर निर्भर करती है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही रक्षा अभ्यास और नौसैनिक सहयोग करते हैं, जिससे विश्वास और परिचालन समन्वय में सुधार होता है।
- चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक उपस्थिति के कारण हिंद-प्रशांत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।
- भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) बनाए रखते हुए क्वाड भागीदारों के साथ सहयोग को संतुलित करना होगा।
- यह संवाद केवल राजनयिक बयानों के बजाय व्यावहारिक रक्षा साझेदारी के लिए भारत की बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है।

DIGITAL INDIA BHASHINI–DPIIT MoU — MULTILINGUAL INVESTMENT ACCESS

Ministry:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology)

Easy Explanation:

डिजिटल इंडिया भाषिणी (BHASHINI) डिवीजन और DPIIT ने भारत के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। कई निवेशकों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि सरकारी प्लेटफॉर्म और निवेश से संबंधित जानकारी तक स्थानीय भाषाओं में पहुंचना अक्सर कठिन होता है। इस सहयोग के माध्यम से, निवेश-संबंधित सेवाओं के लिए अनुवाद, आवाज-आधारित पहुंच, बहुभाषी शब्दावली और भाषा मॉडल प्रदान करने के लिए भाषिणी उपकरणों को DPIIT प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत (integrate) किया जाएगा।



| Click to Connect Now.

Key Terms:

- **BHASHINI (भाषिणी):** डिजिटल इंडिया के तहत भारत का एआई-आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म।
- **DPIIT:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)।
- **Multilingual Access (बहुभाषी पहुंच):** कई भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना।
- **Translation API (अनुवाद एपीआई):** सॉफ्टवेयर टूल जो एक प्लेटफॉर्म को दूसरे सिस्टम का उपयोग करके टेक्स्ट का अनुवाद करने की अनुमति देता है।
- **Voice-enabled Technology (आवाज-सक्षम तकनीक):** तकनीक जो उपयोगकर्ताओं को बोलने और डिजिटल प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देती है।
- **Language Model (भाषा मॉडल):** भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित एआई (AI) मॉडल।
- **Investment Ecosystem (निवेश पारिस्थितिकी तंत्र):** निवेशकों, स्टार्टअप, उद्यमियों, नियामकों, नीतियों और प्लेटफॉर्म का तंत्र।
- **Digital Public Infrastructure (डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा):** आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, ओएनडीसी और भाषिणी जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक डिजिटल सिस्टम।

Important Points for UPSC:

- भाषिणी का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस में भारत की भाषा बाधा को कम करना है।
- यह समझौता ज्ञापन DPIIT प्लेटफॉर्म को भारतीय भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगा।
- यह छोटे उद्यमियों, स्थानीय निवेशकों और पहली पीढ़ी के व्यापार मालिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
- सहयोग में अनुवाद एपीआई एकीकरण, बहुभाषी शब्दावली निर्माण, आवाज-सक्षम उपकरण और डोमेन-विशिष्ट भाषा मॉडल शामिल हैं।

- डोमेन-विशिष्ट (Domain-specific) भाषा मॉडल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि व्यवसाय, निवेश और नीतिगत शर्तों के लिए सटीक अनुवाद की आवश्यकता होती है।
- व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) के लिए भाषा समावेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजी बाधाओं के कारण लोगों को आर्थिक अवसरों से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
- यह पहल गैर-अंग्रेजी उपयोगकर्ताओं के लिए निवेश से संबंधित सरकारी जानकारी तक पहुंच में सुधार कर सकती है।
- यह भारत के व्यापक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- यह शहरी अंग्रेजी बोलने वाले उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रीय-भाषा उपयोगकर्ताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है।
- यह पहल दिखाती है कि कैसे एआई का उपयोग केवल निजी क्षेत्र के स्वचालन (automation) के बजाय समावेशी शासन के लिए किया जा सकता है।

SWACHH GAON, SURAKSHIT JALVAYU CAMPAIGN — CLEAN VILLAGES & CLIMATE RESILIENCE

Ministry:

जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

Easy Explanation:

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए "स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु" अभियान शुरू किया। यह अभियान ग्रामीण स्वच्छता को जलवायु लचीलेपन (climate resilience) से जोड़ता है। विचार सरल है: एक स्वच्छ गाँव केवल शौचालयों या कचरा संग्रह के बारे में नहीं है। यह ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने, जल स्रोतों की रक्षा करने और गांवों को जलवायु जोखिमों के लिए अधिक तैयार करने के बारे में भी है।

Key Terms:



| Click to Connect Now.



- **Swachh Gaon, Surakshit Jalvayu (स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु):** स्वच्छ गांवों को जलवायु-सुरक्षित जीवन से जोड़ने वाला अभियान।
- **DDWS:** जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (Department of Drinking Water and Sanitation)।
- **Mission LiFE (मिशन लाइफ):** पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली; पर्यावरण अनुकूल व्यवहार के लिए भारत का अभियान।
- **SWM Rules (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम):** कचरा संभालने, पृथक्करण, उपचार और निपटान का मार्गदर्शन करने वाले नियम।
- **IEC Campaign (आईईसी अभियान):** जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication) अभियान।
- **ODF Plus (ओडीएफ प्लस):** खुले में शौच मुक्त स्थिति के बाद का चरण, जो ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर केंद्रित है।
- **Climate Resilience (जलवायु लचीलापन):** जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए तैयार होने और उनसे उबरने की समुदायों की क्षमता।
- **Greywater Management (ग्रेवॉटर प्रबंधन):** रसोई, स्नानघर और धोने से निकलने वाले अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुनर्चक्रण या निपटान।

Important Points for UPSC:

- यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के आसपास शुरू किया गया था।
- यह ग्रामीण स्वच्छता को जलवायु कार्रवाई से जोड़ता है।
- स्वच्छता को कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और जलवायु-सुरक्षित व्यवहार से जोड़ा जा रही है।
- यह अभियान पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किया गया था।
- इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर एक राष्ट्रीय आईईसी (IEC) अभियान भी शामिल है।
- ग्रामीण कचरा प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रबंधित कचरा मिट्टी, भूजल, तालाबों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित कर सकता है।





- शौचालय निर्माण के बाद ओडीएफ प्लस अगला चरण है; यह ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।
- जलवायु परिवर्तन गांवों में पानी की कमी, बाढ़, बीमारी के प्रकोप और स्वच्छता की समस्याओं को बदतर बना सकता है।
- मिशन लाइफ (Mission LiFE) प्रासंगिक है क्योंकि कचरे को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवहार में बदलाव केंद्रीय है।
- यह अभियान केवल शौचालय निर्माण से हटकर व्यापक ग्राम-स्तरीय पर्यावरण प्रबंधन की ओर बदलाव को दर्शाता है।

ANRF-MAHA WATER MISSION — STARTUPS FOR WATER SECURITY

Ministry:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology)

Easy Explanation:

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) और जल शक्ति मंत्रालय ने ₹200 करोड़ का महा (MAHA) वॉटर मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य पानी के क्षेत्र में समाधान पर काम कर रहे स्टार्टअप, एमएसएमई, विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स का समर्थन करना है। भारत को भूजल की कमी, प्रदूषण, असमान वर्षा, बाढ़, सूखा और खराब जल-उपयोग दक्षता जैसी गंभीर जल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह मिशन व्यावहारिक जल समाधान बनाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, उद्योग और सरकार को एक साथ लाने की कोशिश करता है जिन्हें लैब अनुसंधान से क्षेत्र के उपयोग तक ले जाया जा सके।

Key Terms:

- **ANRF (Anusandhan National Research Foundation - अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन):**
भारत में अनुसंधान के वित्तपोषण को मजबूत करने और व्यापक बनाने के लिए बनाई गई संस्था।





- **MAHA:** उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए मिशन (Missions for Advancement in High-Impact Areas)।
- **MAHA Water Mission (महा जल मिशन):** भारत के जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी समाधानों का समर्थन करने वाला मिशन।
- **Ministry of Jal Shakti (जल शक्ति मंत्रालय):** जल संसाधन, नदी विकास, पेयजल और स्वच्छता संभालने वाला मंत्रालय।
- **Startup-led Innovation (स्टार्टअप-नेतृत्व नवाचार):** नई तकनीकों के माध्यम से सार्वजनिक समस्याओं को हल करने के लिए स्टार्टअप और उद्यमियों का उपयोग करना।
- **Technology Validation (प्रौद्योगिकी सत्यापन):** यह परीक्षण करना कि क्या कोई तकनीक वास्तविक क्षेत्र की स्थितियों में काम करती है।
- **Water Security (जल सुरक्षा):** लोगों, कृषि, उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी की विश्वसनीय उपलब्धता।
- **Whole-of-Government Approach (समग्र-सरकार दृष्टिकोण):** मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों और हितधारकों के बीच समन्वय।

Important Points for UPSC:

- इस मिशन का वित्तीय परिव्यय (financial outlay) ₹200 करोड़ है।
- यह एनआरएफ (ANRF) और जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा है।
- महा (MAHA) का अर्थ है 'उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए मिशन'।
- महा मिशन रणनीतिक क्षेत्रों में मिशन-संचालित नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- जल को उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि जल सुरक्षा भारत के लिए एक प्रमुख विकासात्मक चुनौती है।
- यह मिशन स्टार्टअप, एमएसएमई, विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं, उद्योग और इनोवेटर्स का समर्थन करेगा।
- इसका उद्देश्य बुनियादी अनुसंधान से आगे बढ़ना और प्रौद्योगिकी विकास, सत्यापन और तैनाती का समर्थन करना है।





- भारत की जल चुनौतियों में भूजल का अत्यधिक उपयोग, नदी प्रदूषण, शहरी जल संकट, बाढ़, सूखा और जलवायु से जुड़ी जल असुरक्षा शामिल हैं।
- यह मिशन केवल सरकार द्वारा निर्मित समाधानों से हटकर पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित नवाचार की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एएनआरएफ कुछ विशिष्ट विशिष्ट संस्थानों से परे अनुसंधान वित्तपोषण का लोकतंत्रीकरण करने की कोशिश कर रहा है।

RUDRAM-II AIR-TO-SURFACE MISSILE — INDIGENOUS PRECISION STRIKE CAPABILITY

Ministry:

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

Easy Explanation:

डीआरडीओ (DRDO) और भारतीय वायु सेना ने एक हवाई प्लेटफॉर्म से रुद्रम-II (RudraM-II) हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण अत्यधिक कठिन रिलीज स्थितियों में किया गया था और इसे सटीक सटीकता के साथ एक पूर्व-निर्धारित लक्ष्य पर निर्देशित किया गया था। रुद्रम-II एक स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विमान से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की भारत की क्षमता में सुधार करती है और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है।

Key Terms:

- **RudraM-II (रुद्रम-II):** डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।
- **Air-to-Surface Missile (हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल):** जमीन या सतह पर किसी लक्ष्य को भेदने के लिए विमान से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल।





- **DRDO:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation); भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था।
- **IAF:** भारतीय वायु सेना (Indian Air Force)।
- **Airborne Platform (हवाई प्लेटफॉर्म):** विमान या उड़ने वाला प्लेटफॉर्म जिससे हथियार लॉन्च किया जाता है।
- **Extreme Release Conditions (अत्यधिक रिलीज स्थितियां):** मिसाइल विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली कठिन लॉन्च स्थितियां।
- **Integrated Test Range (एकीकृत परीक्षण रेंज):** मिसाइल परीक्षणों के लिए उपयोग की जाने वाली चांदीपुर में डीआरडीओ की परीक्षण रेंज।
- **Precision Strike (सटीक हमला):** चयनित लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता।

Important Points for UPSC:

- रुद्रम-II स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
- इसका उड़ान परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया था।
- मिसाइल को एक हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था।
- परीक्षण अत्यधिक रिलीज स्थितियों के तहत आयोजित किए गए थे।
- मिसाइल को बिल्कुल सटीक सटीकता के साथ एक पूर्व-निर्धारित लक्ष्य पर निर्देशित किया गया था।
- परीक्षणों ने इसके सबसिस्टम और महत्वपूर्ण प्रक्षेपवक्र (trajectory) के प्रदर्शन की पुष्टि की।
- उड़ान के डेटा को एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर में तैनात रेंज उपकरणों द्वारा कैचर किया गया था।
- रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद रुद्रम-II के लिए नोडल डीआरडीओ प्रयोगशाला है।
- इसमें शामिल अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL), उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (HEMRL), आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) और एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) शामिल हैं।
- रुद्रम-II उन्नत हथियार प्रणालियों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।





VYOMA INNOVATION CHALLENGE — MULTILINGUAL EDGE AI FOR INDIAN LANGUAGES

Ministry:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology)

Easy Explanation:

डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन, करंट एआई (Current AI) और कल्प इम्पैक्ट ने व्योम (VYOMA) इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। यह चैलेंज ओपन-सोर्स, बहुभाषी, वॉयस-फर्स्ट एआई समाधानों को बढ़ावा देता है जो ऑफ़लाइन या कम-कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। यह 'सुनो सूत्र' (Sunno Sutra) पर आधारित है, जो इंडियाएआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अनावरण किया गया एक हैंडहेल्ड एआई संदर्भ उपकरण है। विचार एआई को उन लोगों के लिए उपयोगी बनाना है जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, कम-इंटरनेट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, या जिन्हें भारतीय भाषाओं में आवाज-आधारित सेवाओं की आवश्यकता है।

Key Terms:

- **VYOMA Innovation Challenge (व्योम इनोवेशन चैलेंज):** बहुभाषी, वॉयस-फर्स्ट, ओपन-सोर्स एआई समाधान बनाने की चुनौती।
- **BHASHINI (भाषिणी):** भारत की राष्ट्रीय एआई-संचालित भाषा अनुवाद और भाषा प्रौद्योगिकी पहल।
- **Edge AI (एज एआई):** एआई जो पूरी तरह से क्लाउड सर्वर पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय रूप से एक डिवाइस पर चलता है।
- **Voice-first AI (वॉयस-फर्स्ट एआई):** मुख्य रूप से बोले जाने वाले संवाद के लिए डिज़ाइन किया गया एआई सिस्टम।
- **Open-source AI (ओपन-सोर्स एआई):** एआई उपकरण या मॉडल जिनके कोड या डिज़ाइन का खुले तौर पर उपयोग और सुधार किया जा सकता है।
- **Sunno Sutra (सुनो सूत्र):** बहुभाषी, वॉयस-फर्स्ट, हैंडहेल्ड एआई संदर्भ उपकरण।



| Click to Connect Now.



- **Low-connectivity Environment (कम-कनेक्टिविटी परिवेश):** वह क्षेत्र जहां इंटरनेट पहुंच कमजोर, अस्थिर या अनुपस्थित है।
- **National Hub for Language Technology (भाषा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र):** भाषिणी का भाषा प्रौद्योगिकी मंच जो भाषण और पाठ-आधारित सेवाओं का समर्थन करता है।

Important Points for UPSC:

- व्योम इनोवेशन चैलेंज डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन द्वारा करंट एआई और कल्प इम्पैक्ट के सहयोग से शुरू किया गया था।
- यह ओपन-सोर्स, बहुभाषी, वॉयस-फर्स्ट एआई समाधानों को बढ़ावा देता है।
- यह चुनौती उन एआई उपकरणों पर केंद्रित है जो ऑफ़लाइन और कम-कनेक्टिविटी वाले वातावरण में काम कर सकते हैं।
- यह भाषिणी और करंट एआई द्वारा विकसित एक हैंडहेल्ड एआई संदर्भ उपकरण 'सुनो सूत्र' पर आधारित है।
- सुनो सूत्र ऑन-डिवाइस एआई क्षमता के साथ बहुभाषी भाषा प्रौद्योगिकियों को जोड़ता है।
- यह चुनौती स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, एमएसएमई, उद्योग भागीदारों और स्वतंत्र इनोवेटर्स को आमंत्रित करती है।
- प्रतिभागी नए उपयोग के मामले बना सकते हैं, हार्डवेयर में सुधार कर सकते हैं, मॉडल को अनुकूलित कर सकते हैं और तैनात करने योग्य एप्लिकेशन बना सकते हैं।
- संभावित क्षेत्रों में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण शामिल हैं।
- बीस शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को डेवलपर किट और सुनो सूत्र प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त होगी।
- विजेता टीमें ₹80 लाख तक के पुरस्कार और केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों के साथ संभावित तैनाती के अवसरों के लिए पात्र हैं।
- भाषिणी 36 भारतीय लिखित भाषाओं, 23 भारतीय बोलचाल (वॉयस) भाषाओं और 35 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन करती है।
- भाषिणी 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को शक्ति प्रदान करती है और दैनिक 15 मिलियन से अधिक अनुमानों (inferences) को संसाधित करती है।





JAL JEEVAN MISSION 2.0 — REFORM-LINKED MoUs FOR RURAL WATER SUPPLY

Ministry:

जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

Easy Explanation:

अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और नागालैंड ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधारों से जुड़े समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते सिर्फ पाइपलाइनों के लिए धन देने के बारे में नहीं हैं। ये ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के प्रबंधन के तरीके में सुधार करने के बारे में हैं। ध्यान सेवा वितरण मानकों, स्थिरता, समुदाय के नेतृत्व वाले प्रबंधन, डिजिटल निगरानी और जल आपूर्ति प्रणालियों के दीर्घकालिक रखरखाव पर है। विचार केवल "नल कनेक्शन बनाने" से हटकर यह सुनिश्चित करने पर है कि पानी वास्तव में नियमित रूप से और सुरक्षित रूप से घरों तक पहुंचे।

Key Terms:

- **Jal Jeevan Mission 2.0 (जल जीवन मिशन 2.0):** जल जीवन मिशन का विस्तारित चरण जो टिकाऊ और जवाबदेह ग्रामीण पेयजल वितरण पर केंद्रित है।
- **Reform-linked MoU (सुधार-संबद्ध समझौता ज्ञापन):** समझौता जहां राज्य मिशन को लागू करते समय शासन और सेवा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
- **Har Ghar Jal (हर घर जल):** ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य।
- **Service Delivery Standards (सेवा वितरण मानक):** जल आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता, नियमितता और विश्वसनीयता के लिए बेंचमार्क।
- **Community-led Management (समुदाय-नेतृत्व प्रबंधन):** जल आपूर्ति के संचालन, रखरखाव और निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।
- **Sujalam Bharat (सुजलाम भारत):** ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की मैपिंग और ट्रेकिंग के लिए डिजिटल ढांचा।



| Click to Connect Now.



- **Sujal Gaon ID (सुजल गांव आईडी):** जल आपूर्ति ट्रेकिंग ढांचे के तहत गांवों/सेवा क्षेत्रों को सौंपी गई अनूठी डिजिटल आईडी।
- **Sustainability Measures (स्थिरता उपाय):** पेयजल प्रणालियों की दीर्घकालिक उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करने के कदम।

Important Points for UPSC:

- अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और नागालैंड ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार-संबद्ध जापनों पर हस्ताक्षर किए।
- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ इन जापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- ध्यान टिकाऊ, पारदर्शी और समुदाय के नेतृत्व वाली ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण पर है।
- जल जीवन मिशन 2.0 कार्यक्रम को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा वितरण की ओर ले जाता है।
- सुधार ढांचे में सेवा मानक, स्थिरता उपाय, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही शामिल हैं।
- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल नल कनेक्शन ही नियमित और सुरक्षित पानी की आपूर्ति की गारंटी नहीं देता है।
- ग्रामीण पेयजल प्रणालियाँ अक्सर खराब रखरखाव, कमजोर स्थानीय स्वामित्व, स्रोत की कमी और निगरानी के अभाव के कारण विफल हो जाती हैं।
- सुजलाम भारत पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की मैपिंग और वास्तविक समय की ट्रेकिंग के लिए एक डिजिटल ढांचा प्रदान करता है।
- समुदाय के नेतृत्व वाला प्रबंधन स्थानीय जवाबदेही में सुधार कर सकता है और ऊपर से नीचे के प्रशासन पर निर्भरता को कम कर सकता है।
- सुधार-संबद्ध दृष्टिकोण खर्च-आधारित योजनाओं से प्रदर्शन-आधारित शासन की ओर बदलाव को दर्शाता है।

CCPA ACTS AGAINST DARK PATTERNS — DIGITAL CONSUMER PROTECTION

Ministry:



| Click to Connect Now.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

Easy Explanation:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'डार्क पैटर्न' (dark patterns) के खिलाफ कार्रवाई की। डार्क पैटर्न वेबसाइटों या ऐप द्वारा उपभोक्ताओं को ऐसे विकल्प चुनने के लिए हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तरकीबें हैं जिन्हें वे शायद स्वतंत्र रूप से नहीं चुनते। उदाहरणों में कार्ट में चुपके से सामान जोड़ना, रद्दीकरण (cancellation) विकल्पों को छिपाना, नकली तात्कालिकता पैदा करना, भ्रमित करने वाले बटन का उपयोग करना, या उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना शामिल है। सीसीपीए ने ऐसी प्रथाओं के लिए फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) पर ₹5 लाख और मैकेफी (McAfee) पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण को अब डिजिटल हेरफेर से निपटना होगा, न कि केवल दोषपूर्ण वस्तुओं या भ्रामक विज्ञापनों से।

Key Terms:

- **CCPA (Central Consumer Protection Authority - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण):** उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है।
- **Dark Patterns (डार्क पैटर्न):** उपभोक्ता विकल्पों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग की जाने वाली हेरफेर वाली डिज़ाइन प्रथाएँ।
- **Basket Sneaking (बास्केट स्नीकिंग):** स्पष्ट सहमति के बिना कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद, सेवाएं या शुल्क जोड़ना।
- **Confirm Shaming (कंफर्म शेमिंग):** किसी विकल्प को मना करने के लिए उपयोगकर्ताओं को दोषी महसूस कराना।
- **Forced Action (मजबूरन कार्रवाई):** उपयोगकर्ताओं को वह पूरा करने से पहले एक अतिरिक्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना जो वे करना चाहते थे।
- **Interface Interference (इंटरफ़ेस हस्तक्षेप):** स्क्रीन को इस तरह से डिज़ाइन करना जो उपयोगकर्ता को गुमराह या भ्रमित करे।



- **Trick Questions (चालाकी भरे प्रश्न):** उपयोगकर्ताओं से अनजाने में कुछ चुनने के लिए भ्रमित करने वाले तरीके से तैयार किए गए प्रश्न।
- **Informed Consent (सुविज्ञ सहमति):** स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से और परिणामों को समझने के बाद दी गई सहमति।

Important Points for UPSC:

- सीसीपीए ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न के खिलाफ कार्रवाई की।
- फिजिक्सवाला पर ₹5 लाख और मैकेफी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- डार्क पैटर्न को अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में माना जाता है क्योंकि वे उपभोक्ता की पसंद में हेरफेर करते हैं।
- 'डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023' 13 डार्क पैटर्न की पहचान करते हैं।
- महत्वपूर्ण डार्क पैटर्न में बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, इंटरफेस इंटरफेरेंस और ट्रिक क्वेश्चन शामिल हैं।
- सीसीपीए ने इससे पहले ई-कॉमर्स कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्व-ऑडिट करने और डार्क पैटर्न को हटाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी।
- उपभोक्ता की सहमति स्पष्ट, सूचित और हेरफेर वाली डिज़ाइन से मुक्त होनी चाहिए।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, भाषा, बटन प्लेसमेंट और छिपे हुए शुल्कों के माध्यम से उपयोगकर्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।
- यह पारंपरिक उपभोक्ता संरक्षण से डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण की ओर बदलाव का प्रतीक है।
- यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और अधिक उपभोक्ता ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स, फिनटेक, यात्रा और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।

CROSS-BORDER UPI PAYMENTS IN CAMBODIA — INDIA'S DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE GOES GLOBAL

Ministry:



| Click to Connect Now.

Easy Explanation:

एनपीसीआई इंटरनेशनल (NPCI International) और एक्लेडा बैंक (ACLEDA Bank) ने कंबोडिया के राष्ट्रीय क्यूआर कोड सिस्टम 'KHQR' के माध्यम से कंबोडिया में क्रॉस-बॉर्डर (सीमा पार) यूपीआई भुगतान शुरू किया। पहले चरण में, कंबोडिया में भारतीय यात्री KHQR कोड को स्कैन करके UPI-सक्षम ऐप का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि UPI अब केवल एक घरेलू भुगतान प्रणाली नहीं है। यह भारत की डिजिटल कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक उपस्थिति का हिस्सा बन रहा है। यह लॉन्च भारत और कंबोडिया के बीच भविष्य के दो-तरफा भुगतान कॉरिडोर के लिए आधार भी तैयार करता है।

Key Terms:

- **UPI (Unified Payments Interface - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस):** भारत की त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली।
- **NPCI (National Payments Corporation of India - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम):** भारत में खुदरा भुगतानों के लिए छाता संगठन।
- **NPCI International (एनपीसीआई इंटरनेशनल):** एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो विदेशों में भारतीय भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देती है।
- **ACLEDA Bank (एक्लेडा बैंक):** KHQR के माध्यम से UPI भुगतान के लिए भागीदारी करने वाला कंबोडियाई बैंक।
- **KHQR:** कंबोडिया की राष्ट्रीय क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली।
- **Cross-border Payments (सीमा पार भुगतान):** जुड़े हुए भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके देशों के बीच किए गए भुगतान।
- **Two-way Payment Corridor (दो-तरफा भुगतान कॉरिडोर):** दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को एक-दूसरे के बाजारों में डिजिटल भुगतान करने की अनुमति देने वाली व्यवस्था।
- **Digital Public Infrastructure (डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा):** सार्वजनिक पैमाने पर उपयोग के लिए निर्मित डिजिटल सिस्टम, जैसे यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर और भाषिणी।





Important Points for UPSC:

- एनपीसीआई इंटरनेशनल और एक्लेडा बैंक ने KHQR के माध्यम से कंबोडिया में सीमा पार यूपीआई भुगतान शुरू किया।
- KHQR कंबोडिया की राष्ट्रीय क्यूआर कोड प्रणाली है।
- पहला चरण कंबोडिया में भारतीय यात्रियों को KHQR कोड स्कैन करके UPI भुगतान करने की अनुमति देता है।
- यह लॉन्च भारत और कंबोडिया के बीच भविष्य के दो-तरफा भुगतान कॉरिडोर का रास्ता साफ करता है।
- यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय पर्यटकों, छात्रों, व्यावसायिक यात्रियों और छोटे व्यापारियों की मदद करता है।
- क्रॉस-बॉर्डर यूपीआई नकदी, विदेशी मुद्रा (forex) कार्ड और महंगे भुगतान मध्यस्थों पर निर्भरता कम करता है।
- यह वैश्विक स्तर पर भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के मॉडल को मजबूत करता है।
- विदेश में यूपीआई का विस्तार भी फिनटेक डिप्लोमेसी (कूटनीति) का एक रूप है।
- कंबोडिया भारत के एकट ईस्ट जुड़ाव और आसियान पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह कदम भारत और कंबोडिया के बीच पर्यटन, व्यापार, लोगों की आवाजाही और आसान कम मूल्य वाले भुगतानों का समर्थन कर सकता है।

DISTRICT DOMESTIC PRODUCT GUIDELINES — DISTRICT-LEVEL ECONOMIC DATA

Ministry:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics & Programme Implementation)

Easy Explanation:



| Click to Connect Now.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ जिला घरेलू उत्पाद (District Domestic Product) अनुमानों को संकलित करने के लिए समान दिशानिर्देश जारी किए। जिला घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तरह है, लेकिन जिला स्तर पर। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रत्येक जिले में कितनी आर्थिक गतिविधि हो रही है। अब तक, अलग-अलग राज्य अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए तुलना करना मुश्किल था। एक समान दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक सुसंगत और तुलनीय तरीके से जिला-स्तरीय आर्थिक डेटा तैयार करने में मदद करेगा।

Key Terms:

- **District Domestic Product (जिला घरेलू उत्पाद):** किसी जिले के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- **GDDP (Gross District Domestic Product - सकल जिला घरेलू उत्पाद):** किसी जिले का कुल आर्थिक उत्पादन।
- **NDDP (Net District Domestic Product - शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद):** मूल्यहास (depreciation) घटाने के बाद जीडीडीपी।
- **Per Capita Income (प्रति व्यक्ति आय):** किसी जिले में प्रति व्यक्ति औसत आय।
- **Base Year (आधार वर्ष):** समय के साथ आर्थिक डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला संदर्भ वर्ष।
- **Bottom-up Approach (नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण):** जहां भी उपलब्ध हो जिला-स्तरीय डेटा का उपयोग करके जिला आय का अनुमान लगाना।
- **Top-down Approach (ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण):** उपयुक्त संकेतकों का उपयोग करके जिलों को राज्य-स्तरीय अनुमान आवंटित करना।
- **NSO:** MoSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office)।

Important Points for UPSC:

- दिशानिर्देश संशोधित आधार वर्ष 2022-23 का उपयोग करते हैं।



- इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला घरेलू उत्पाद के अनुमानों के लिए एक समान ढांचा तैयार करना है।
- दिशानिर्देश जिला स्तर पर जीडीडीपी, एनडीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को कवर करता है।
- जहां भी जिला-स्तरीय डेटा उपलब्ध हो, नीचे से ऊपर (bottom-up) के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है।
- जहां जिला-वार डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां उपयुक्त आवंटन संकेतकों के साथ ऊपर से नीचे (top-down) के दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है।
- वर्तमान में, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान संकलित करते हैं।
- तुलनीय जिला-स्तरीय डेटा विकेन्द्रीकृत योजना (decentralized planning) में मदद कर सकता है।
- यह किसी राज्य के भीतर क्षेत्रीय असमानता की पहचान करने में मदद कर सकता है।
- विश्वसनीय जिला-स्तरीय डेटा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (evidence-based policymaking) में सुधार कर सकता है।
- बेहतर डीडीपी (DDP) अनुमान राज्यों को अपनी सांख्यिकी प्रणालियों और योजना क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।

INDIA-UK CRITICAL MINERALS GLOBAL SUPPLY CHAIN OBSERVATORY

Ministry:

खान मंत्रालय (Ministry of Mines)

Easy Explanation:

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में 'भारत-यूके क्रिटिकल मिनेरल्स ग्लोबल सप्लाइ चैन ऑब्जर्वेटरी' लॉन्च की। क्रिटिकल मिनेरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) वे खनिज हैं जो आधुनिक तकनीकों के लिए आवश्यक हैं लेकिन उनके साथ आपूर्ति के जोखिम जुड़े हैं। वे इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, सौर पैनलों, पवन ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, रक्षा प्रणालियों और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं। यह ऑब्जर्वेटरी वैश्विक क्रिटिकल मिनेरल आपूर्ति श्रृंखलाओं



| Click to Connect Now.

की निगरानी करेगी, जोखिमों की पहचान करेगी, बाजार की जानकारी (market intelligence) उत्पन्न करेगी और नीति निर्माताओं तथा उद्योग को सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी।

Key Terms:

- **Critical Minerals (क्रिटिकल मिनेरल्स / महत्वपूर्ण खनिज):** रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिज लेकिन आपूर्ति व्यवधान के प्रति संवेदनशील।
- **Supply Chain Resilience (आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन):** झटके या व्यवधान के दौरान भी आपूर्ति जारी रखने की क्षमता।
- **National Critical Mineral Mission (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन):** महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत का मिशन।
- **Global Supply Chain Observatory (वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला):** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निगरानी रखने, उनका विश्लेषण करने और खुफिया जानकारी उत्पन्न करने का मंच।
- **TEXMiN:** आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन।
- **IIT (ISM) Dhanbad:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद।
- **University of Cambridge (केंब्रिज विश्वविद्यालय):** ऑब्जर्वेटरी में भागीदारी करने वाला यूके का विश्वविद्यालय।
- **Market Intelligence (बाजार आसूचना / जानकारी):** कीमतों, जोखिमों, स्रोतों और आपूर्ति प्रवृत्तियों को समझने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा और विश्लेषण।

Important Points for UPSC:

- इस ऑब्जर्वेटरी को भारत के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री और यूके के विदेश सचिव द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह TEXMiN, IIT (ISM) धनबाद और केंब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ी एक संयुक्त पहल है।
- इस पहल की घोषणा अक्टूबर 2025 में भारत-यूके प्रधान मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक के दौरान की गई थी।
- इसे मार्च 2026 में एक अनुसंधान सहयोग समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था।



- यह ऑब्जर्वेटरी वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी करेगी।
- यह आपूर्ति जोखिमों और व्यवधानों की पहचान करने में मदद करेगी।
- यह नीति निर्माताओं, उद्योग और शोधकर्ताओं के लिए बाजार आसूचना उत्पन्न करेगी।
- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक गतिशीलता, उन्नत विनिर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिज महत्वपूर्ण हैं।
- यह पहल भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का समर्थन करती है।
- यह लचीली और विविध खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए विश्वसनीय भागीदारों के साथ काम करने के भारत के प्रयास को भी दर्शाती है।

PM SURYA GHAR — 75 LAKH ROOFTOP SOLAR HOUSEHOLDS TARGETED BY DECEMBER 2026

Ministry:

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)

Easy Explanation:

सरकार ने कहा है कि 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' ने दो साल के भीतर 40 लाख लाभार्थी परिवारों का आंकड़ा पार कर लिया है। लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 75 लाख परिवारों तक पहुंचना और अंततः 1 करोड़ रूफटॉप सोलर परिवारों तक बढ़ाना है। यह योजना घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का समर्थन करती है ताकि परिवार अपनी खुद की बिजली पैदा कर सकें, बिजली के बिल कम कर सकें और स्वच्छ ऊर्जा में योगदान दे सकें। विशेष रूप से कम सेवा वाले परिवारों के बीच इसे तेजी से अपनाने के लिए एक नया 'यूटिलिटी-लिंक्ड एग्रीगेशन मॉडल' भी पेश किया गया है।

Key Terms:

- **PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना):** परिवारों के बीच रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की सरकारी योजना।
- **Rooftop Solar (रूफटॉप सोलर):** बिजली पैदा करने के लिए छतों पर लगाए जाने वाले सौर पैनल।



- **Utility-Linked Aggregation Model (यूटिलिटी-लिंकड एग्रीगेशन मॉडल):** मॉडल जहां बिजली उपयोगिता कंपनियां (utilities) रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को इकट्ठा करने और लागू करने में मदद करती हैं।
- **DISCOM (डिस्कॉम):** उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार वितरण कंपनी (Distribution company)।
- **Residential Solar (आवासीय सौर ऊर्जा):** घरेलू उपयोग के लिए स्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियाँ।
- **Battery Energy Storage System (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली):** सिस्टम जो बाद में उपयोग के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहीत करता है।
- **Model Solar Village (मॉडल सोलर विलेज):** व्यापक रूप से सौर ऊर्जा अपनाने को प्रदर्शित करने के लिए ग्राम-स्तरीय मॉडल।
- **Non-fossil Capacity (गैर-जीवाश्म क्षमता):** सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु जैसे गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता।

Important Points for UPSC:

- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी।
- इस योजना का परिव्यय ₹75,021 करोड़ है।
- इसने दो साल के भीतर 40 लाख लाभार्थी परिवारों का आंकड़ा पार कर लिया है।
- लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 75 लाख परिवारों तक पहुंचना है।
- 65 लाख से अधिक आवेदन पहले से ही प्रक्रिया में हैं।
- मई 2026 तक 33 लाख से अधिक रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा चुके थे, जिससे 12 गीगावाट से अधिक क्षमता जुड़ी।
- इस योजना का उद्देश्य अंततः 1 करोड़ रूफटॉप सोलर परिवारों तक विस्तार करना है।
- कम सेवा वाले परिवारों के बीच इसे तेजी से अपनाने के लिए यूटिलिटी-लिंकड एग्रीगेशन मॉडल पेश किया गया है।
- राज्यों में इस मॉडल के तहत लगभग 30 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की योजना बनाई गई है।



- ₹22,750 करोड़ से अधिक की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
- 17 लाख से अधिक परिवारों ने शून्य बिजली बिल हासिल किया है।
- रूफटॉप सोलर घरेलू बिजली बिलों को कम कर सकता है, डिस्कॉम पर दबाव कम कर सकता है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन कर सकता है।

FLEX-FUEL PASSENGER VEHICLE — ETHANOL, FARMERS & ENERGY SECURITY

Ministry:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum & Natural Gas)

Easy Explanation:

पेट्रोलियम मंत्री ने पहला फ्लेक्स-फ्यूल (flex-fuel) यात्री वाहन लॉन्च किया। एक फ्लेक्स-फ्यूल वाहन इथेनॉल के उच्च स्तर के साथ मिश्रित पेट्रोल पर चल सकता है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इथेनॉल सम्मिश्रण (ethanol blending) कच्चे तेल के आयात को कम कर सकता है, विदेशी मुद्रा बचा सकता है, उत्सर्जन को कम कर सकता है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय पैदा कर सकता है। पीआईबी ने यह भी उल्लेख किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के 48 खुदरा आउटलेट पर E85 की शुरुआत हो चुकी है। E85 का अर्थ है ऐसा ईंधन जिसमें 85% तक इथेनॉल और 15% पेट्रोल हो।

Key Terms:

- **Flex-Fuel Vehicle (फ्लेक्स-फ्यूल वाहन):** वह वाहन जो उच्च स्तर के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चल सकता है।
- **E85:** ईंधन मिश्रण जिसमें 85% तक इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है।
- **Ethanol Blending (इथेनॉल सम्मिश्रण):** जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाना।

- **Oil Marketing Companies (तेल विपणन कंपनियां):** पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री करने वाली कंपनियां, जैसे IndianOil, BPCL और HPCL।
- **Biofuel (जैव ईंधन):** गन्ना, मक्का, कृषि अपशिष्ट या बायोमास जैसे जैविक स्रोतों से उत्पादित ईंधन।
- **Energy Security (ऊर्जा सुरक्षा):** आयात पर अत्यधिक निर्भरता के बिना ऊर्जा तक विश्वसनीय और सस्ती पहुंच।
- **Foreign Exchange Savings (विदेशी मुद्रा बचत):** आयात कम करके विदेशी मुद्रा की बचत करना।
- **Farm-to-Fuel Economy (फार्म-टू-फ्यूल अर्थव्यवस्था):** कृषि उपज या अवशेषों का उपयोग ईंधन उत्पादन के लिए करना, जिससे किसानों के लिए आय हो।

Important Points for UPSC:

- भारत ने अपना पहला फ्लेक्स-फ्यूल यात्री वाहन लॉन्च किया।
- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के 48 खुदरा आउटलेट पर E85 रोलआउट शुरू हो गया है।
- E85 सामान्य पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रणों की तुलना में बहुत अधिक इथेनॉल हिस्से की अनुमति देता है।
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- इथेनॉल सम्मिश्रण विदेशी मुद्रा बचा सकता है क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है।
- यह नीति ऊर्जा सुरक्षा को किसान की आय से भी जोड़ती है।
- यदि इथेनॉल के लिए कृषि उपज और अवशेषों का उपयोग किया जाता है, तो किसानों को एक अतिरिक्त बाजार मिल सकता है।
- शुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तुलना में इथेनॉल सम्मिश्रण वाहनों के उत्सर्जन को कम कर सकता है।
- भारत पहले से ही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के माध्यम से इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा दे रहा है।
- एक बड़ी चुनौती खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुँचाए बिना या फसलों के पानी के तनाव को बढ़ाए बिना पर्याप्त इथेनॉल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- फीडस्टॉक (कच्चा माल) का चयन मायने रखता है: गन्ना आधारित इथेनॉल पानी के उपयोग की चिंताओं को बढ़ा सकता है, जबकि कृषि अवशेषों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल अधिक टिकाऊ है।

- फ्लेक्स-फ्यूअप अपनाने के लिए वाहन अनुकूलता, ईंधन की उपलब्धता, उपभोक्ता स्वीकृति और मूल्य समर्थन की भी आवश्यकता होगी।

JAI PRAKASH NARAYAN BIRD SANCTUARY — INDIA'S 100TH RAMSAR SITE

Ministry:

प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

Easy Explanation:

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल (Surha Tal) के नाम से भी जाना जाता है, को भारत के 100वें रामसर स्थल (Ramsar site) के रूप में नामित किया गया है। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि (wetland) है। आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पक्षियों का समर्थन करती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं, बाढ़ को नियंत्रित करती हैं, कार्बन संग्रहीत करती हैं और जैव विविधता की रक्षा करती हैं। यह स्थल विशेष रूप से पक्षी जैव विविधता (avifaunal biodiversity) के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रवासी और निवासी पक्षी शामिल हैं।

Key Terms:

- **Ramsar Site (रामसर स्थल):** रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण के रूप में मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि।
- **Ramsar Convention (रामसर कन्वेंशन):** आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- **Wetland (आर्द्रभूमि / दलदली भूमि):** वह क्षेत्र जहां पानी स्थायी या मौसमी रूप से मिट्टी को ढकता है।
- **Surha Tal (सुरहा ताल):** जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य से जुड़ा स्थानीय नाम।
- **Avifaunal Biodiversity (पक्षी जैव विविधता):** किसी क्षेत्र में पक्षी प्रजातियों की विविधता।

- **Migratory Birds (प्रवासी पक्षी):** वे पक्षी जो प्रजनन, भोजन या जलवायु कारणों से क्षेत्रों के बीच मौसमी रूप से प्रवास करते हैं।
- **Wise Use (विवेकपूर्ण उपयोग):** आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखते हुए उनका सतत उपयोग।
- **Ecosystem Services (पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ):** पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल शोधन और कार्बन भंडारण।

Important Points for UPSC:

- जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है।
- इसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है।
- इसे भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
- यह स्थल पक्षी जैव विविधता से समृद्ध है।
- यह प्रवासी और निवासी दोनों तरह के पक्षियों को आकर्षित करता है।
- रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं।
- रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।
- आर्द्रभूमियाँ अतिरिक्त पानी को सोखकर प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करती हैं और बाढ़ नियंत्रण में मदद करती हैं।
- आर्द्रभूमियाँ भूजल को रिचार्ज करने और स्थानीय जल चक्र को बनाए रखने में मदद करती हैं।
- वे मत्स्य पालन, कृषि, पर्यटन और स्थानीय आजीविका का भी समर्थन करती हैं।
- आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण कार्बन सिंक (carbon sinks) हैं और जलवायु नियमन में मदद करती हैं।
- आर्द्रभूमियों के लिए प्रमुख खतरों में अतिक्रमण, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियाँ, अत्यधिक पर्यटन और पानी के प्रवाह में बदलाव शामिल हैं।

G-SEC MARKET & FPI REFORMS — DEEPENING INDIA'S FINANCIAL MARKETS

Ministry:



| Click to Connect Now.

Easy Explanation:

सरकार ने सरकारी प्रतिभूति (Government Securities) बाजार को गहरा करने और इक्विटी (equity) खंड में अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को सुगम बनाने के उपायों की घोषणा की। सरकारी प्रतिभूतियां, या जी-सेक (G-Secs), सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए जाने वाले ऋण साधन (debt instruments) हैं। एक गहरा जी-सेक बाजार सरकार को अधिक कुशलता से उधार लेने में मदद करता है, तरलता (liquidity) में सुधार करता है, और बेहतर मूल्य खोज (price discovery) का समर्थन करता है। इक्विटी में एफपीआई को सुगम बनाने से भारतीय कंपनियों और बाजारों में विदेशी पूंजी आ सकती है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक विनियमन की भी आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसा प्रवाह अस्थिर हो सकता है।

Key Terms:

- **G-Sec (Government Security - सरकारी प्रतिभूति):** सरकार द्वारा जारी ऋण साधन।
- **Bond Market (बॉन्ड बाजार):** वह बाजार जहां ऋण साधन जारी और कारोबार किए जाते हैं।
- **Yield (यील्ड / प्रतिफल):** किसी बॉन्ड पर निवेशक द्वारा अर्जित रिटर्न।
- **Liquidity (तरलता):** वह सुगमता जिसके साथ किसी संपत्ति को बिना किसी बड़े मूल्य परिवर्तन के खरीदा या बेचा जा सकता है।
- **Price Discovery (मूल्य खोज):** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मांग और आपूर्ति के माध्यम से बाजार की कीमतें निर्धारित होती हैं।
- **FPI (Foreign Portfolio Investment - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश):** शेयरों, बॉन्ड और वित्तीय संपत्तियों में विदेशी निवेश।
- **Equity Segment (इक्विटी खंड):** कंपनियों के स्वामित्व शेयरों से निपटने वाला शेयर बाजार खंड।
- **Capital Market Reform (पूंजी बाजार सुधार):** वित्तीय बाजारों में दक्षता, गहराई, पारदर्शिता और भागीदारी में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतिगत बदलाव।

Important Points for UPSC:





- बाजार से पैसा उधार लेने के लिए सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग किया जाता है।
- एक गहरा जी-सेक बाजार कुशल सार्वजनिक उधार लेने में मदद करता है।
- जी-सेक में बेहतर तरलता उधार लेने की लागत को कम कर सकती है और बाजार के विश्वास में सुधार कर सकती है।
- जी-सेक यील्ड अर्थव्यवस्था में अन्य ऋणों और बॉन्डों के मूल्य निर्धारण के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- एक मजबूत बॉन्ड बाजार बैंक ऋण पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर सकता है।
- इक्विटी बाजारों में अधिक एफपीआई भागीदारी भारतीय कंपनियों में अधिक पूंजी ला सकती है।
- एफपीआई अंतर्वाह बाजार की गहराई में सुधार कर सकता है, लेकिन वे वैश्विक अनिश्चितता के दौरान जल्दी से उलट भी सकते हैं।
- पूंजी बाजार सुधारों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संतुलन की आवश्यकता है।
- बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, कॉर्पोरेट उधार और दीर्घकालिक निवेश के लिए भारत का वित्तीय बाजार विकास महत्वपूर्ण है।
- यह सुधार भारतीय वित्तीय बाजारों को अधिक गहरा, अधिक तरल और वैश्विक रूप से आकर्षक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

INDIGENOUS SECOND-GENERATION DIESEL-EQUIVALENT BIOFUEL TECHNOLOGY

Ministry:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology)

Easy Explanation:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने स्वदेशी दूसरी पीढ़ी के डीजल-समतुल्य जैव ईंधन (diesel-equivalent biofuel) तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए ग्रीनजूल प्राइवेट लिमिटेड, पुणे का समर्थन



| Click to Connect Now.

किया है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि अपशिष्ट और कृषि-प्रसंस्करण अवशेषों से उन्नत जैव ईंधन का उत्पादन करना है। मुख्य विचार कचरे को ईंधन में बदलना है। यह आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकता है, भारत के नेट-जीरो (net-zero) लक्ष्यों का समर्थन कर सकता है, और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था (circular economy) बना सकता है जहां कृषि अपशिष्ट एक ऊर्जा संसाधन बन जाता है।

Key Terms:

- **Second-Generation Biofuel (दूसरी पीढ़ी का जैव ईंधन):** गैर-खाद्य बायोमास जैसे कृषि अवशेष, अपशिष्ट या लिग्नोसेल्युलॉसिक सामग्री से बना जैव ईंधन।
- **Diesel-equivalent Biofuel (डीजल-समतुल्य जैव ईंधन):** जैव ईंधन जो डीजल जैसे अनुप्रयोगों के लिए विकल्प या मिश्रण के रूप में कार्य कर सकता है।
- **Technology Development Board (प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड):** डीएसटी (DST) के तहत वैधानिक निकाय जो स्वदेशी तकनीकों के व्यावसायीकरण का समर्थन करता है।
- **Greenjoules Private Limited (ग्रीनजूल प्राइवेट लिमिटेड):** इस जैव ईंधन परियोजना के लिए समर्थित पुणे स्थित कंपनी।
- **Agricultural Waste (कृषि अपशिष्ट):** फसल अवशेष और अन्य कृषि कचरा जिसे उपयोगी उत्पादों में बदला जा सकता है।
- **Agro-processing Residue (कृषि-प्रसंस्करण अवशेष):** कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा।
- **Circular Economy (परिपत्र अर्थव्यवस्था):** आर्थिक मॉडल जहां कचरे को एक संसाधन के रूप में पुनः उपयोग किया जाता है।
- **Waste-to-Wealth (कचरे से कंचन / धन):** अपशिष्ट पदार्थों को आर्थिक रूप से उपयोगी उत्पादों में बदलना।

Important Points for UPSC:

- इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा समर्थित किया गया है।



- समर्थित कंपनी ग्रीनजूल प्राइवेट लिमिटेड, पुणे है।
- परियोजना का शीर्षक "दूसरी पीढ़ी के डीजल समतुल्य जैव ईंधन का विनिर्माण" है।
- इसका उद्देश्य उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक वाणिज्यिक स्तर की सुविधा स्थापित करना है।
- फीडस्टॉक कृषि अपशिष्ट और कृषि-प्रसंस्करण अवशेषों से आएगा।
- दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन पहली पीढ़ी के जैव ईंधन से बेहतर हैं क्योंकि वे सीधे खाद्य फसलों पर निर्भर नहीं होते हैं।
- यह पराली जलाने और कृषि अपशिष्ट निपटान की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है।
- डीजल-समतुल्य जैव ईंधन परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं।
- यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नेट-जीरो आकांक्षाओं का समर्थन करती है।
- यह वेस्ट-टू-वेल्थ मिशन और सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण में भी फिट बैठता है।

AMAZON FUTURE ENGINEER PROGRAM IN EMRSs — DIGITAL SKILLING FOR TRIBAL STUDENTS

Ministry:

जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

Easy Explanation:

आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (NESTS) ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समस्या-समाधान से परिचित कराना है। यह मायने रखता है क्योंकि कई आदिवासी छात्रों को डिजिटल पहुंच के अंतराल का सामना करना पड़ता है। यह कार्यक्रम EMRS के छात्रों के लिए भविष्य के लिए तैयार कौशल लाने की कोशिश करता है ताकि वे प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था में पीछे न छूटें।

Key Terms:



| Click to Connect Now.



- **NESTS:** जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (National Education Society for Tribal Students); एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है।
- **EMRS:** आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School)।
- **Amazon Future Engineer Program (अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम):** कंप्यूटर विज्ञान और डिजिटल कौशल पर केंद्रित कार्यक्रम।
- **Learning Links Foundation (लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन):** कार्यान्वयन के लिए NESTS के साथ भागीदारी करने वाला संगठन।
- **Digital Divide (डिजिटल विभाजन):** उन लोगों के बीच की खाई जिनके पास डिजिटल उपकरणों तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है।
- **Computational Thinking (कम्प्यूटेशनल सोच):** तर्क, पैटर्न और चरण-दर-चरण तर्क का उपयोग करके समस्या-समाधान विधि।
- **Coding (कोडिंग):** प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके कंप्यूटर के लिए निर्देश लिखना।
- **AI Literacy (एआई साक्षरता):** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके उपयोगों की बुनियादी समझ।

Important Points for UPSC:

- NESTS ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन EMRSs में अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए है।
- EMRSs का उद्देश्य आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।
- यह कार्यक्रम आदिवासी छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान और डिजिटल कौशल सीखने में मदद करेगा।
- यह छात्रों को कोडिंग, कम्प्यूटेशनल सोच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी-आधारित समस्या-समाधान से अवगत करा सकता है।
- यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी छात्रों को अक्सर डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुंच का सामना करना पड़ता है।



- डिजिटल कौशल अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक और कैरियर के अवसरों में सुधार कर सकता है।
- यह सरकारी संस्थानों और गैर-सरकारी/निजी पारिस्थितिकी तंत्र अभिनेताओं के बीच साझेदारी का एक उदाहरण है।
- यह कम सेवा वाले समुदायों तक उन्नत कौशल ले जाकर समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है।
- यह कार्यक्रम आदिवासी शिक्षा में डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद कर सकता है।

INDIA'S BIODIVERSITY — COMMITMENTS AND ACHIEVEMENTS

Ministry:

पीआईबी बैकग्राउंडर (PIB Backgrounder) / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

Easy Explanation:

पीआईबी बैकग्राउंडर ने भारत की जैव विविधता प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। भारत दुनिया के मेगा-जैव विविधता (mega-biodiverse) वाले देशों में से एक है और यहाँ वनों, आर्द्रभूमियों, वन्यजीवों, तटीय पारिस्थितिक तंत्रों, घास के मैदानों और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान की एक विस्तृत विविधता है। जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, आजीविका और आपदा सुरक्षा का समर्थन करती है। भारत की जैव विविधता नीति कानूनी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, संरक्षित क्षेत्रों, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय कार्रवाई पर आधारित है।

Key Terms:

- **Biodiversity (जैव विविधता):** पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और पारिस्थितिक तंत्र सहित जीवन रूपों की विविधता।
- **Mega-biodiverse Country (मेगा-जैव विविधता वाला देश):** असाधारण रूप से उच्च जैविक विविधता वाला देश।

- **Biological Diversity Act (जैविक विविधता अधिनियम):** जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ-साझाकरण के लिए भारतीय कानून।
- **National Biodiversity Authority (राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण):** जैविक विविधता अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय।
- **Biodiversity Management Committee (जैव विविधता प्रबंधन समिति):** स्थानीय निकाय जो स्थानीय जैव विविधता को दस्तावेज और संरक्षित करने में मदद करता है।
- **People's Biodiversity Register (पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर):** जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने वाला स्थानीय रजिस्टर।
- **Protected Area (संरक्षित क्षेत्र):** वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र।
- **Ramsar Site (रामसर स्थल):** रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि।

Important Points for UPSC:

- भारत दुनिया के मेगा-जैव विविधता वाले देशों में से एक है।
- जैव विविधता संरक्षण खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और आजीविका सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
- भारत का जैव विविधता शासन जैविक विविधता अधिनियम पर आधारित है।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता विनियमन और लाभ-साझाकरण (benefit-sharing) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय समुदायों को जैव विविधता शासन में लाने में मदद करती हैं।
- पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर स्थानीय जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करते हैं।
- भारत संरक्षण के एक समुदाय-संबद्ध मॉडल का अनुसरण करता है, विशेष रूप से स्थानीय संस्थानों और पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से।
- संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और रामसर स्थल संरक्षण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

- आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और बाढ़ नियंत्रण, भूजल रिचार्ज और कार्बन भंडारण भी प्रदान करती हैं।
- जैव विविधता का नुकसान आवास विनाश, प्रदूषण, आक्रामक विदेशी प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण हो सकता है।
- जैव विविधता संरक्षण को केवल वन्यजीव संरक्षण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; यह कृषि, चिकित्सा, स्थानीय आजीविका, जलवायु लचीलेपन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से भी जुड़ा हुआ है।
- यह बैकग्राउंडर इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह कानूनी ढांचे, स्थानीय कार्रवाई और भारत की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता प्रतिबद्धताओं को एक ही स्थान पर समेकित करता है।

10 PRELIMS QUESTIONS

Q1. भारत-म्यांमार संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. म्यांमार भारत का एकमात्र ऐसा आसियान (ASEAN) देश है जिसके साथ भारत थल सीमा साझा करता है।
2. कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत के पूर्वी तट को म्यांमार और भारत के उत्तर-पूर्व से जोड़ता है।
3. भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग मुख्य रूप से एक समुद्री कनेक्टिविटी परियोजना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q2. व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPAs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक CEPA आम तौर पर केवल वस्तुओं के व्यापार को कवर करता है और इसमें सेवाओं या निवेश को शामिल नहीं किया जाता है।
2. भारत-ओमान CEPA खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार संबंध को मजबूत कर सकता है।
3. उत्पत्ति के नियमों (Rules of Origin) का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई उत्पाद व्यापार समझौते के तहत अधिमान्य टैरिफ उपचार के लिए योग्य है या नहीं।



ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

इहल/ शब्द — संबद्ध मंत्रालय/ संस्थान

1. BHASHINI — इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2. MAHA Water Mission — विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय
3. National Sports Tribunal — गृह मंत्रालय
4. National e-Vidhan Application — संसदीय कार्य मंत्रालय

ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चारों

Q4. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डार्क पैटर्न ऐसे डिज़ाइन अभ्यास हैं जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे विकल्प चुनने के लिए हेरफेर या गुमराह करते हैं जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से नहीं चुनते।
2. बास्केट स्नीकिंग का तात्पर्य स्पष्ट सहमति के बिना उपयोगकर्ता के कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद, सेवाएं या शुल्क जोड़ना है।
3. डार्क पैटर्न केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विनियमित होते हैं न कि उपभोक्ता संरक्षण तंत्र के तहत।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 and 3 (d) 1, 2 और 3

Q5. रुद्रम-II (RudraM-II) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
2. इसका उड़ान परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया था।
3. यह मुख्य रूप से एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।





ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 and 3 (c) केवल 1 and 3 (d) 1, 2 और 3

Q6. कंबोडिया में सीमा पार यूपीआई भुगतान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एनपीसीआई इंटरनेशनल ने KHQR के माध्यम से यूपीआई भुगतान सक्षम करने के लिए एक्लेडा बैंक के साथ भागीदारी की है।
2. KHQR कंबोडिया की राष्ट्रीय क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली है।
3. पहले चरण में, भारत में कंबोडिया के नागरिक भारतीय यूपीआई व्यापारियों पर KHQR का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q7. भारत-यूके क्रिटिकल मिनेरल्स ग्लोबल सप्लाय चेन ऑब्जर्वेटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी और विश्लेषण से जुड़ा है।
2. इसमें TEXMiN, IIT (ISM) धनबाद और केंब्रिज विश्वविद्यालय शामिल हैं।
3. महत्वपूर्ण खनिज केवल कोयला और इस्पात क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हैं और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उनकी कोई प्रमुख भूमिका नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q8. जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य हाल ही में चर्चा में था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।



2. इसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है।
3. इसे भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
4. रामसर स्थलों की घोषणा जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तहत की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q9. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देता है।
2. यह योजना 2024 में शुरू की गई थी।
3. इसे केवल वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू किया गया है।
4. रूफटॉप सोलर घरेलू बिजली बिलों को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने में मदद कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q10. दूसरी पीढ़ी (second-generation) के जैव ईंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इनका उत्पादन कृषि अपशिष्ट और कृषि-प्रसंस्करण अवशेषों से किया जा सकता है।
2. इन्हें आम तौर पर पहली पीढ़ी के जैव ईंधन से बेहतर माना जाता है क्योंकि ये सीधे खाद्य फसलों पर निर्भर नहीं होते हैं।
3. ये वेस्ट-टू-वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण में योगदान दे सकते हैं।
4. इनका उत्पादन केवल आयातित कच्चे तेल से किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? (a) केवल 1 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4



ANSWER KEY

1. (a)
2. (b)
3. (c)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
8. (a)
9. (a)
10. (b)

EXPLANATIONS

- **Q1.** म्यांमार थल सीमा वाला भारत का एकमात्र आसियान पड़ोसी है। कालादान कोलकाता/सितवे/मिजोरम को जोड़ता है। त्रिपक्षीय राजमार्ग एक सड़क परियोजना है, समुद्री परियोजना नहीं।
- **Q2.** CEPA केवल वस्तुओं के बुनियादी समझौते से अधिक व्यापक है और इसमें सेवाएं, निवेश और गतिशीलता शामिल हो सकती है। उत्पत्ति के नियम टैरिफ लाभों के दुरुपयोग को रोकते हैं।
- **Q3.** भाषिणी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत है। महा जल मिशन ANRF/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जल शक्ति से जुड़ा है। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण युवा मामले और खेल मंत्रालय से जुड़ा है, गृह मंत्रालय से नहीं। NeVA संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा है।
- **Q4.** डार्क पैटर्न उपभोक्ता की पसंद में हेरफेर करते हैं। बास्केट स्नीकिंग का मतलब बिना स्पष्ट सहमति के आइटम या शुल्क जोड़ना है। इन्हें सीसीपीए के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण तंत्र के तहत भी संभाला जाता है।
- **Q5.** रुद्रम-II डीआरडीओ और आईएएफ द्वारा परीक्षित एक स्वदेशी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है।
- **Q6.** एनपीसीआई इंटरनेशनल और एक्लेडा बैंक ने KHQR के माध्यम से कंबोडिया में यूपीआई भुगतान शुरू किया। पहले चरण में, कंबोडिया में भारतीय यात्री KHQR कोड स्कैन करके यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं।



- **Q7.** ऑब्जर्वेटरी क्रिटिकल मिनेरल आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी करती है और इसमें TEXMIN, IIT (ISM) धनबाद और केंब्रिज विश्वविद्यालय शामिल हैं। ईवी, बैटरी, सोलर, सेमीकंडक्टर, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्रिटिकल मिनेरल्स महत्वपूर्ण हैं।
- **Q8.** जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है, बलिया, उत्तर प्रदेश में है। यह भारत का 100वां रामसर स्थल बना। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत आते हैं, सीबीडी (CBD) के तहत नहीं।
- **Q9.** पीएम सूर्य घर घरेलू रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देता है। इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। यह वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है।
- **Q10.** दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन कृषि अपशिष्ट और अवशेषों का उपयोग कर सकते हैं। वे प्रत्यक्ष खाद्य-बनाम-ईंधन संघर्ष को कम करते हैं और सर्कुलर इकोनॉमी का समर्थन करते हैं। वे आयातित कच्चे तेल से नहीं बनते हैं।

2 MAINS QUESTIONS

Q1. "भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) अब घरेलू शासन से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ओर बढ़ रहा है।" यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भाषिणी के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

Expected Points:

- भारत के DPI मॉडल में UPI, आधार, डिजिलॉकर, ONDC, भाषिणी आदि शामिल हैं।
- KHQR के माध्यम से कंबोडिया में UPI का विस्तार दर्शाता है कि भारत की भुगतान प्रणालियाँ अंतर्राष्ट्रीय उपकरण बन रही हैं।
- क्रॉस-बॉर्डर UPI नकदी, फॉरेक्स कार्ड और महंगे मध्यस्थों पर निर्भरता कम करके यात्रियों, छोटे व्यापारियों, छात्रों और व्यवसायों की मदद करता है।
- यह ग्लोबल साउथ और आसियान (ASEAN) में भारत की फिनटेक उपस्थिति को भी मजबूत करता है।
- भाषिणी शासन और निवेश पहुंच में भाषा की बाधा को कम करके DPI के घरेलू समावेशन पक्ष को दिखाती है।

- भाषिणी-DPIIT समझौता ज्ञापन उद्यमियों और निवेशकों को भारतीय भाषाओं में निवेश संबंधी सेवाओं तक पहुँचने में मदद कर सकता है।
- साथ मिलकर, UPI और भाषिणी दिखाते हैं कि DPI केवल तकनीक नहीं है; यह एक शासन मॉडल है।
- चुनौती: डेटा सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी (अंतर-संचालनीयता), विश्वास, साइबर जोखिम और डिजिटल बहिष्कार को संबोधित किया जाना चाहिए।
- निष्कर्ष: यदि भारत का DPI समावेशी, सुरक्षित, कम लागत वाला और जन-केंद्रित बना रहता है, तो यह एक सॉफ्ट-पावर (नरम-शक्ति) उपकरण बन सकता है।

Q2. भारत के ऊर्जा संक्रमण (energy transition) के लिए न केवल नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार की बल्कि ईंधन के विविधीकरण और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा की भी आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Expected Points:

- भारत का ऊर्जा संक्रमण केवल सौर और पवन क्षमता विस्तार पर निर्भर नहीं रह सकता।
- पीएम सूर्य घर के तहत रूफटॉप सोलर परिवारों को बिजली पैदा करने, बिजली के बिल कम करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने में मदद करता है।
- दिसंबर 2026 तक 75 लाख रूफटॉप सोलर परिवारों का लक्ष्य विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन को दर्शाता है।
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन और E85 रोलआउट एक और रास्ता दिखाते हैं: इथेनॉल सन्मिश्रण के माध्यम से पेट्रोल निर्भरता को कम करना।
- इथेनॉल सन्मिश्रण कच्चे तेल के आयात को कम कर सकता है, विदेशी मुद्रा बचा सकता है, उत्सर्जन को कम कर सकता है और किसानों के लिए आय के अवसर पैदा कर सकता है।
- हालांकि, इथेनॉल नीति को खाद्य सुरक्षा और पानी के उपयोग के साथ ऊर्जा लक्ष्यों को संतुलित करना चाहिए, खासकर यदि गन्ना आधारित फीडस्टॉक का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
- दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे खाद्य फसलों के बजाय कृषि अपशिष्ट और कृषि-प्रसंस्करण अवशेषों का उपयोग करते हैं।
- यह वेस्ट-टू-वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी, पराली प्रबंधन और जीवाश्म ईंधन प्रतिस्थापन का समर्थन करता है।

- बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, पवन ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) आवश्यक हैं।
- भारत-यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी दर्शाती है कि भारत आपूर्ति जोखिमों की निगरानी करने और लचीली खनिज आपूर्ति श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहा है।
- महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि खनिज कुछ ही देशों में केंद्रित हैं तो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां नई निर्भरताएं पैदा कर सकती हैं।
- भारत को घरेलू अन्वेषण, रीसाइक्लिंग, विश्वसनीय साझेदारी, रणनीतिक भंडार और प्रौद्योगिकी सहयोग की आवश्यकता है।
- निष्कर्ष: एक गंभीर ऊर्जा संक्रमण के लिए एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है — नवीकरणीय उत्पादन, वैकल्पिक ईंधन, भंडारण, खनिज सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यवहार में बदलाव।



PIB

साप्ताहिक संक्षेप

अवसंरचना। सुशासन।
क्षमता निर्माण।



भारत की विकास यात्रा
के प्रमुख संकेत



विनिमय

स्मार्ट सीमा प्रबंधन
भूमि द्वारों का डिजिटल
रूपांतरण



वार्या (Varya)

भारत का AI वीडियो मॉडल
स्वदेशी AI नवाचार की
एक नई छलांग



डिजिलॉकर

35 करोड़ उपयोगकर्ता
भारत के डिजिटल विश्वास
इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार



जोजिला सुरंग

ऐतिहासिक उपलब्धि
साल भर कनेक्टिविटी
लेह-लद्दाख के लिए



Table of Contents

1. VINIMAY — LAND PORT MANAGEMENT SYSTEM	4
2. WEST ASIA INTER-MINISTERIAL BRIEFING — SUPPLY CHAIN RESILIENCE	6
3. AYUSHMAN BHARAT PM-JAY — WEST BENGAL JOINS AS 36TH STATE/UT.....	7
4. PMSMA — A DECADE OF MATERNAL CARE	9
5. DEFENCE INVESTITURE CEREMONY 2026 — GALLANTRY AWARDS	11
6. INDIAN NAVY EOD OPERATION — MT OLYMPIC LIFE.....	12
7. VARYA — INDIA'S INDIGENOUS AI VIDEO MODEL	14
8. BRICS AGRICULTURE MINISTERS' MEETING — INDORE	16
9. INDIA-NEPAL CROSS-BORDER REMITTANCE MECHANISM	17
10. NITI AAYOG — 11TH GOVERNING COUNCIL MEETING	19
11. JAL JEEVAN MISSION 2.0 — REFORM-LINKED MOUS	20
12. TEXTILE PLI SCHEME — ROUND III	22
13. ECLGS 5.0 — EMERGENCY CREDIT LINE GUARANTEE SCHEME MILESTONE.....	24
14. DIGILOCKER — MASSIVE EXPANSION	25
15. ZOJILA TUNNEL — HISTORIC BREAKTHROUGH.....	27
PRACTICE QUESTIONS — अभ्यास प्रश्न	29





| Click to Connect Now.



1. VINIMAY — LAND PORT MANAGEMENT SYSTEM

Ministry: Ministry of Home Affairs (गृह मंत्रालय)

सरल हिंदी व्याख्या:

कल्पना करें कि आप एक ट्रक चालक हैं और भारत से नेपाल माल लेकर जा रहे हैं। अभी सीमा पर आपको 5 अलग-अलग काउंटर पर जाना पड़ता है – Customs (सीमा शुल्क), Immigration (आव्रजन), Security (सुरक्षा), Tax (कर), और Inspection (निरीक्षण) – हर एक के पास अपने अलग कागज़, मुहरें और लाइनें होती हैं। घंटों, कभी-कभी पूरा दिन लग जाता है। अब कल्पना करें यह सब एक Digital Screen पर एक साथ हो जाए, ट्रक की नंबर प्लेट Camera से खुद-ब-खुद पढ़ ली जाए, और 90% कागज़ी काम खत्म हो जाए। यही VINIMAY करता है। भारत ने 9 जून को यह Land Port Management System (LPMS) लॉन्च किया, ताकि सभी भूमि सीमा चौकियों को आधुनिक बनाया जा सके। भारत की 7 देशों के साथ 15,000+ किमी की भूमि सीमा है – Bangladesh, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Pakistan, Afghanistan – और अभी 15 Land Ports सारे व्यापार और लोगों की आवाजाही को संभालते हैं। VINIMAY Customs, Immigration और Border Security को एक Digital Platform पर लाता है, ताकि माल तेज़ी से जाए, तस्करी पकड़ना आसान हो, और सीमाएं 'Smart' बनें।



| Click to Connect Now.

**Key Terms Table:**

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
VINIMAY	Land Port Management System (LPMS) – भूमि सीमा संचालन के लिए Real-time Digital Platform
LPAI	Land Ports Authority of India – MHA के अंतर्गत Land Ports का प्रबंधन करने वाली नोडल एजेंसी
Smart Border	MHA की चार-आयामी रणनीति: सुरक्षा, व्यापार सुविधा, Migration Management, कनेक्टिविटी
ANPR	Automatic Number Plate Recognition – Land Ports पर Automated Gate संचालन की सुविधा
Single Electronic Window	कई एजेंसियों की मंजूरी की जगह एकीकृत Digital Clearance; Processing समय घटाती है
ICP	Integrated Check Post – आधुनिक Land Port, जहाँ सभी एजेंसियाँ एक ही छत के नीचे होती हैं

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- भारत 7 देशों के साथ 15,106 किमी भूमि सीमा साझा करता है: Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan, Afghanistan
- वर्तमान में 15 Land Ports चालू हैं; अगले 2-3 वर्षों में 11 और – कुल 26 Land Ports होंगे
- VINIMAY ~90% कागज़ी काम खत्म करता है; ANPR-आधारित Gates से वाहन Processing समय काफी कम होगा
- Smart Border Concept के चार स्तंभ: Border Security, Trade Facilitation, Migration Management, People-to-People Connectivity
- Land Ports Authority of India (LPAI) की स्थापना Land Ports Authority of India Act, 2010 के तहत हुई



| Click to Connect Now.



- प्रमुख ICPs: Attari (Pakistan), Petrapole (Bangladesh), Agartala (Bangladesh), Raxaul (Nepal), Moreh (Myanmar)
- VINIMAY Forensic Data Trails सक्षम करता है – तस्करी, अवैध Immigration और Contraband रोकने के लिए महत्वपूर्ण
- ICIMOD और Neighbourhood First Policy को पूरक – SAARC देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा

2. WEST ASIA INTER-MINISTERIAL BRIEFING — SUPPLY CHAIN RESILIENCE

Ministry: Ministry of Petroleum & Natural Gas / Ministry of Defence

सरल हिंदी व्याख्या:

सोचिए आपकी गाड़ी का Petrol कहाँ से आता है। भारत का लगभग 80% Crude Oil – Petrol, Diesel, Cooking Gas का कच्चा माल – Middle East (West Asia) से आता है: Saudi Arabia, UAE, Iraq, Kuwait। अब मान लीजिए वह इलाका जल रहा है। Yemen में जंग है, Iran और Israel में टकराव है, और सशस्त्र गुट Red Sea और Gulf में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। वे Oil Tankers सुरक्षित नहीं चल सकते। कीमतें बढ़ती हैं, India का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है, Petrol महंगा होता है।

यह काल्पनिक नहीं है – यह अभी हो रहा है। इसलिए India के Defence Ministry ने Petroleum, External Affairs, Finance और Home Ministries को साथ बैठकर पूछा: 'हमारे पास कितने दिनों का Oil Stock है? क्या हम Russia या Norway से तेल ला सकते हैं? अगर Supply Routes टूट जाएं तो दवाओं का क्या होगा?' यह एक Inter-Ministerial Group Review है – India अपनी Supply Chain Security को Military Security की तरह ही गंभीरता से ले रहा है।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
IGoM	Inter-Governmental Group on Memorandum – संकट प्रतिक्रिया के लिए बहु-मंत्रालय समन्वय तंत्र



| Click to Connect Now.



SPR	Strategic Petroleum Reserve – भारत का आपातकालीन Crude Oil भंडार; वर्तमान में 5.33 MT = 67 दिन
Strait of Hormuz	महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जिससे ~30% वैश्विक तेल व्यापार गुजरता है; एकल-बिंदु संवेदनशीलता
IFC-IOR	Information Fusion Centre - Indian Ocean Region; Gurugram में भारत का Maritime Domain Awareness केंद्र
Houthi Attacks	Yemen के Houthi विद्रोही जो 2023 के अंत से Red Sea में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं
Supply Diversification	किसी एक Supplier पर निर्भरता कम करना; भारत Saudi, UAE, Iraq, Russia, Norway से आयात करता है
API	Active Pharmaceutical Ingredients – 70% China से; West Asia Transit Disruption का जोखिम

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- भारत का SPR 5 स्थानों पर: Vizag, Mangalore, Padur, Udupi, Indulkhand – वर्तमान क्षमता 67 दिन, लक्ष्य 90-100 दिन
- हर \$1/barrel मूल्य वृद्धि = भारत पर ~₹4,000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय बोझ
- Suez Canal ~12% वैश्विक व्यापार वहन करती है; 2023 से Houthi हमलों ने Red Sea Shipping को काफी बाधित किया है
- IGoM में Defence, Petroleum, External Affairs, Finance और Home Ministries शामिल – दुर्लभ बहु-मंत्रालय समन्वय
- SPR विस्तार योजना: ₹3,000 करोड़ निवेश; 90-दिवसीय लक्ष्य तक पहुँचने में 2-3 वर्ष

3. AYUSHMAN BHARAT PM-JAY — WEST BENGAL JOINS AS 36TH STATE/UT

Ministry: Ministry of Health and Family Welfare (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)



| Click to Connect Now.



सरल हिंदी व्याख्या:

कल्पना करें आप एक गरीब परिवार हैं और घर के किसी सदस्य को अचानक बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई – दिल का ऑपरेशन या Cancer का इलाज। Private Hospital में ₹3-5 लाख लग सकते हैं। यह रकम आपके पास नहीं है।

Ayushman Bharat PM-JAY इसी समस्या का सरकारी जवाब है: इसमें गरीब परिवारों को ₹5 लाख प्रति वर्ष का Health Insurance Card मिलता है, जिसे वे सरकारी और Empanelled Private Hospitals में मुफ्त इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2018 में शुरू हुई इस योजना में अब लगभग 50 करोड़ लोग – भारत की नीचे से 40% आबादी – शामिल हैं।

पेंच यह था कि West Bengal – भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, 10 करोड़ से अधिक लोग – ने 2018 से PM-JAY में शामिल होने से मना किया था। उनकी अपनी Swasthya Sathi योजना थी। लेकिन 8 जून 2026 को West Bengal आखिरकार शामिल हो गया – 36वें State/UT के रूप में। अब West Bengal के परिवार Chennai या Delhi के अस्पताल में भी Ayushman Card इस्तेमाल कर सकते हैं।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
PM-JAY	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना
Ayushman Bharat	दो घटकों वाला Umbrella Programme: PM-JAY (बीमा) + HWCs (Health and Wellness Centres)
₹5 Lakh Cover	Secondary और Tertiary Hospitalisation के लिए प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज
PMJAY-SECC	Socio-Economic Caste Census 2011 Data के आधार पर लाभार्थी चिन्हित – ~50 करोड़ लोग
Swasthya Sathi	West Bengal की अपनी स्वास्थ्य योजना; राज्य 2018 से PM-JAY की जगह यह चलाता था



**Empanelled Hospital**

PM-JAY के तहत Cashless Treatment के लिए पंजीकृत सरकारी या Private Hospital

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- PM-JAY 2018 में Ayushman Bharat के तहत लॉन्च; लक्ष्य – भारत की नीचे से 40% आबादी (~50 करोड़ लाभार्थी)
- West Bengal 36वाँ State/UT है – अब भी कुछ States/UTs इसके बाहर हैं
- Portability PM-JAY की प्रमुख विशेषता: लाभार्थी पूरे भारत में किसी भी Empanelled Hospital में इलाज करा सकते हैं
- PM-JAY का कार्यान्वयन National Health Authority (NHA) – MoHFW के अंतर्गत स्वायत्त संस्था
- Ayushman Bharat के दो घटक: (1) PM-JAY (बीमा), (2) Ayushman Arogya Mandirs/HWCs (Primary Care)
- AB-PMJAY ने अब तक 7+ करोड़ Hospitalizations सक्षम किए; 2018 से ₹1 लाख करोड़+ के Claims Authorized

4. PMSMA — A DECADE OF MATERNAL CARE

Ministry: Ministry of Health and Family Welfare (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

सरल हिंदी व्याख्या:

भारत में हजारों महिलाएं हर साल Pregnancy (गर्भावस्था) या Childbirth (प्रसव) के दौरान मर जाती थीं – इसलिए नहीं कि इलाज नहीं था, बल्कि इसलिए कि Pregnancy के दौरान कोई जाँच नहीं हुई। Blood Pressure या Haemoglobin किसी ने नहीं देखा।

PMSMA (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan) 2016 में एक सुंदर-सरल विचार के साथ आया: हर महीने की 9 तारीख को, भारत के हर Government Health Centre में Pregnant महिलाओं को मुफ्त जाँच मिलेगी – Blood Tests, Weight Check, Blood Pressure, Ultrasound – कोई बहाना नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई Appointment नहीं। Doctors और Gynaecologists उस एक दिन Volunteer होकर आते हैं। 10 वर्षों में 6



| Click to Connect Now.



करोड़ से अधिक Pregnant महिलाओं की जाँच हो चुकी है। परिणाम? भारत की Maternal Mortality Rate 2004 में 254 से घटकर 2023 में 97 हो गई।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
PMSMA	Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan – हर महीने 9 तारीख को सरकारी सुविधाओं में मुफ्त ANC
ANC	Antenatal Care – Pregnancy के दौरान चिकित्सा देखभाल; जाँच, Tests, पोषण सहायता शामिल
MMR	Maternal Mortality Rate – प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर मृत्यु; भारत में 254 (2004) से 97 (2023) हुई
High-Risk Pregnancy	जटिलताओं वाली Pregnancies (Anaemia, Hypertension, Gestational Diabetes) – PMSMA से पहचान
SBA	Skilled Birth Attendant – प्रसव के समय प्रशिक्षित पेशेवर; PMSMA SBA को Referral बढ़ाती है
SUMAN	Surakshit Matritva Aashwasan – रोकी जा सकने वाली Maternal/Newborn Deaths के प्रति शून्य सहनशीलता

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- PMSMA 9 जून 2016 को शुरू; हर महीने की 9 तारीख को ANC – Pregnant महिलाओं के लिए एक निश्चित, पूर्वानुमानित तारीख
- भारत की MMR 254 (2004-06) से 97 (2018-20) – वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ गिरावट में से एक; SDG Target: 2030 तक 70
- PMSMA ने 10 वर्षों में 6 करोड़+ Antenatal Check-ups संपन्न कराए; Specialist Doctors स्वेच्छा से भाग लेते हैं



| Click to Connect Now.



- PMSMA, Janani Suraksha Yojana (JSY) और Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK) की पूरक है
- भारत ने 93%+ Institutional Delivery Rate (NFHS-5, 2021) हासिल की – 2005-06 में 39% से बड़ी उपलब्धि

5. DEFENCE INVESTITURE CEREMONY 2026 — GALLANTRY AWARDS

Ministry: President's Secretariat / Ministry of Defence

सरल हिंदी व्याख्या:

हर देश के पास असाधारण बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों और नागरिकों को सम्मानित करने की व्यवस्था होती है। भारत में दो अलग Medal Systems हैं – एक युद्ध (Wartime) में बहादुरी के लिए, और एक शांतिकाल (Peacetime) में – Counter-terrorism, Anti-Naxal Operations या Rescue Missions जैसे अभियानों के लिए।

सर्वोच्च Wartime Medal है Param Vir Chakra – भारत का Victoria Cross या Medal of Honor के समकक्ष। इसके नीचे Maha Vir Chakra और Vir Chakra हैं। सर्वोच्च Peacetime Bravery Medal है Ashoka Chakra, फिर Kirti Chakra और Shaurya Chakra।

8 जून को India के President ने यह Medals एक औपचारिक Defence Investiture Ceremony में प्रदान किए – PM Modi भी उपस्थित थे। इस बार 7 Kirti Chakras (2 Posthumous – मतलब जो सैनिक शहीद हो चुके थे), 15 Vir Chakras और 29 Shaurya Chakras दिए गए।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
Param Vir Chakra	भारत का सर्वोच्च Wartime Gallantry Award; दुश्मन के सामने असाधारण वीरता के लिए
Maha Vir Chakra	दूसरा सर्वोच्च Wartime Gallantry Award; युद्ध में प्रमुख वीरता के कार्यों के लिए



| Click to Connect Now.



Vir Chakra	तीसरा सर्वोच्च Wartime Gallantry Award; युद्ध में बहादुरी के कार्यों के लिए
Ashoka Chakra	सर्वोच्च Peacetime Gallantry Award; Non-Combat बहादुरी/बलिदान के लिए (PVC के समतुल्य)
Kirti Chakra	दूसरा सर्वोच्च Peacetime Gallantry Award; प्रमुख वीरता के लिए
Shaurya Chakra	तीसरा सर्वोच्च Peacetime Gallantry Award; दुश्मन के सामने न होते हुए भी वीरता के लिए
Posthumous Award	मृत व्यक्ति को दिया गया पुरस्कार; परिवार के सदस्य द्वारा स्वीकार किया जाता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- भारत में Gallantry Awards की दो Series: Wartime (PVC, MVC, VC) और Peacetime (AC, KC, SC) – इन्हें कभी न मिलाएं
- Hierarchy – Wartime: Param Vir Chakra > Maha Vir Chakra > Vir Chakra; Peacetime: Ashoka Chakra > Kirti Chakra > Shaurya Chakra
- Param Vir Chakra (PVC): भारत के इतिहास में केवल 21 प्राप्तकर्ता; 14 Posthumous
- Defence Investiture Ceremony वर्ष में दो बार (Phase I और Phase II) आयोजित होती है; President Armed Forces के Supreme Commander हैं
- Kirti Chakra और Shaurya Chakra सैन्य कर्मियों के साथ-साथ नागरिकों और Police को भी दिए जा सकते हैं

6. INDIAN NAVY EOD OPERATION — MT OLYMPIC LIFE

Ministry: Ministry of Defence (रक्षा मंत्रालय)

सरल हिंदी व्याख्या:



| Click to Connect Now.



कल्पना करें चार Football Fields जितना बड़ा एक Oil Tanker – Dubai से Kochi की ओर Crude Oil लेकर जा रहा है। Oman के पास अचानक जहाज़ के किनारे पर धमाका होता है। Crew जाँच करती है और एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है: एक Missile जहाज़ की दीवार को भेदकर, कई Steel Compartments से गुज़रकर, एक Fuel Tank के अंदर जा बैठी है – लेकिन फटी नहीं है। यह एक जीवित Missile Warhead है, लाखों लीटर तेल से भरे Tank के अंदर।

यही 26 मई 2026 को MT Olympic Life के साथ हुआ। जहाज़ Kochi पहुँचा और Indian Navy को सूचित किया। Southern Naval Command ने तुरंत एक Bomb Disposal (EOD – Explosive Ordnance Disposal) Team भेजी। 7 दिनों में, सटीक Diagnostic Tools इस्तेमाल करते हुए, Team ने Warhead के Detonator को Disable किया और उसे Fuel Tank के अंदर से निकाल लिया। इस Operation ने Indian Ocean में India की बढ़ती 'Net Security Provider' भूमिका को दर्शाया।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
EOD	Explosive Ordnance Disposal – अविस्फोटित हथियारों को सुरक्षित रूप से पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए प्रशिक्षित विशेष सैन्य Unit
IFC-IOR	Information Fusion Centre - Indian Ocean Region; India का Maritime Domain Awareness Hub; Navy Response को Trigger किया
VLCC	Very Large Crude Carrier – 20 लाख+ Barrels ले जाने में सक्षम विशाल Oil Tanker; MT Olympic Life इसी Category में
Southern Naval Command	Kochi स्थित Command; Indian Ocean Operations के लिए प्राथमिक Navy Command
Gulf of Oman	वह समुद्री क्षेत्र जहाँ Hull Explosion हुआ; Energy Trade के लिए रणनीतिक Maritime Route
Warhead Forensics	Recovered Munition का वैज्ञानिक विश्लेषण – उत्पत्ति, प्रकार और Launch Platform जानने के लिए



**UNCLOS**

UN Convention on the Law of the Sea – Maritime Operations
और Jurisdiction के लिए कानूनी ढांचा

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- MT Olympic Life एक Marshall Islands-Flagged VLCC; Muscat से ~60 Nautical Miles पूर्व में 26 मई 2026 को Explosion हुई
- IFC-IOR (Gurugram) ने समन्वित Response Trigger किया – यह India का Real-time Maritime Domain Awareness केंद्र है
- Operation 7+ दिन चला; EOD Team ने निष्कासन से पहले Detonation Mechanism को Isolate किया
- Recovered Warhead Forensic जाँच के लिए भेजा गया – संभवतः Houthi Missile
- India की बढ़ती भूमिका: Indian Ocean Region में 'Net Security Provider' – एक घोषित विदेश नीति उद्देश्य

7. VARYA — INDIA'S INDIGENOUS AI VIDEO MODEL

Ministry: Ministry of Electronics & IT (MeitY) / IndiaAI Mission

सरल हिंदी व्याख्या:

आपने शायद Sora या Veo जैसे AI Tools देखे होंगे जो एक Text Description से Video बना देते हैं – 'सूर्यास्त के समय गेहूँ के खेत में नाचता किसान' लिखो और Video तैयार। लेकिन ये Tools बेहद महंगे हैं – एक सेकंड की Video बनाने में ₹8-10 (\$0.10) लग सकता है।

अब भारत ने खुद का Version बनाया है जिसका नाम है Varya – 12 जून को Avataar नामक Startup ने इसे लॉन्च किया। Varya वही Quality की Video सिर्फ ₹0.48 प्रति सेकंड में बनाती है – 20 गुना सस्ता। कैसे?

'Distillation' नामक Technique से – जैसे एक बड़ी Textbook की Concentrated Summary बनाना। Original AI Model 50 Steps में Video बनाती थी; Varya ने वही काम सिर्फ 4 Steps में करना सीखा।



| Click to Connect Now.



सबसे महत्वपूर्ण बात: Varya भारतीय संस्कृति को समझती है – Diwali उत्सव, Regional खान-पान, स्थानीय परिधान और Indian Faces सही-सही बना सकती है। यह IndiaAI Mission – India की ₹10,000 करोड़ की अपनी AI Technology बनाने की मुहिम – के तहत सरकारी Compute Power से बनाई गई।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
IndiaAI Mission	₹10,371 करोड़ की सरकारी पहल; India का AI Ecosystem बनाने के लिए – Compute, Data, Startups, Skilling
Foundation Model	विशाल Data पर Train किया गया बड़ा AI Model; कई Applications का आधार (जैसे GPT, Gemini)
Distillation	AI Technique: एक बड़े Model की क्षमताओं को एक छोटे, तेज़, सस्ते Version में संकुचित करना
Varya	India का पहला Indigenous Distilled Video AI Model; 14-Billion Parameter; IndiaAI Mission के तहत Avataar द्वारा
GPU Compute	Graphics Processing Units – AI Model Training के लिए आवश्यक Hardware; IndiaAI Mission Subsidised Access देता है
MeitY	Ministry of Electronics and Information Technology – IndiaAI Mission की Nodal Ministry
Frugal Innovation	बहुत कम लागत पर उच्च-गुणवत्ता Output – India की AI विकास दर्शन

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- IndiaAI Mission (2024 में Approved): ₹10,371 करोड़; सात Pillars – AI Compute, Datasets, Application Development, Skilling, Safety, Startups, International Partnerships
- Varya एक 14-Billion Parameter Model है; Distillation से Video Generation 50 Steps से घटाकर 4 Steps



| Click to Connect Now.



- Cost: ₹0.48/second बनाम Global Rivals का \$0.10+/second – India की जनसंख्या पैमाने पर Video AI सुलभ
- Avataar IndiaAI Mission द्वारा चुने गए 12 Startups में से एक था; Subsidised GPU Compute के बदले Open-Source Release अनिवार्य
- India की AI रणनीति: US/China के साथ Frontier Models पर प्रतिस्पर्धा की जगह Application Layers, Affordability और Cultural Relevance पर ध्यान

8. BRICS AGRICULTURE MINISTERS' MEETING — INDORE

Ministry: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)

सरल हिंदी व्याख्या:

BRICS पाँच प्रमुख विकासशील देशों का समूह है – Brazil, Russia, India, China, South Africa। मिलकर वे दुनिया का लगभग 40% खाना उगाते हैं। India वर्तमान में BRICS का Chairperson है (2024-25), इसलिए Meeting Host करने और Agenda तय करने का अधिकार है।

इस सप्ताह Indore में सभी पाँच देशों के Agriculture Ministers मिले – India का पहली बार ऐसी Meeting Host करना। चर्चा के दो महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला: Russia-Ukraine युद्ध ने Global Wheat और Sunflower Oil की Supply बाधित कर दी है – खाद्य कीमतें बढ़ी हैं। दूसरा: India Millets – Jowar, Bajra, Ragi जैसे प्राचीन अनाज – को Global Food और Climate Challenges का जवाब बताना चाहता है। भारत ने BRICS Seed Bank का भी प्रस्ताव रखा।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
BRICS	Brazil, Russia, India, China, South Africa – प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह; India 2024-25 में Chair
Food Security	खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता – BRICS की सामूहिक चिंता



| Click to Connect Now.



Millet Promotion	India का फोकस: BRICS द्वारा Millets (IYM 2023 की विरासत) को Climate-Resilient, पौष्टिक फसलों के रूप में अपनाना
Post-Harvest Loss	फसल कटाई और उपभोग के बीच नष्ट हुआ खाना; India का अनुमानित नुकसान ~15-20%
Agri-Tech Cooperation	BRICS सदस्यों के बीच Drone Technology, Precision Farming, AI in Agriculture की Sharing
BRICS Agricultural Research Network	India का प्रस्ताव: फसल किस्मों, कीट प्रबंधन, Climate Adaptation के लिए Joint R&D

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- BRICS Agriculture Ministers 2010 से सालाना मिलते हैं; Indore में 16वीं Meeting India की Chairship में
- India की दिशा: Millets को Food Security Crop के रूप में – IYM 2023 की विरासत को BRICS Multilateral Advocacy से आगे बढ़ाना
- BRICS देश मिलकर ~40% Global Agricultural Output और ~30% Global Arable Land के लिए जिम्मेदार
- India ने BRICS Seed Bank Cooperation प्रस्तावित किया – Crop Diversity और Food Security Insurance के लिए महत्वपूर्ण

9. INDIA-NEPAL CROSS-BORDER REMITTANCE MECHANISM

Ministry: Ministry of Finance / Reserve Bank of India

सरल हिंदी व्याख्या:

कल्पना करें Nepal के एक गाँव का युवक Delhi में Construction Site पर काम करता है। हर महीने वह ₹5,000 Kathmandu में अपने परिवार को भेजना चाहता है। अब तक उसके पास दो बुरे विकल्प थे: Western Union पर



| Click to Connect Now.



5-7% Fee दो (₹300-350 तुरंत गया), 2-3 दिन इंतज़ार करो। या किसी Nepal जाते दोस्त को Cash दो – Hawala, जो Informal, कभी-कभी Illegal है।

अब India और Nepal ने एक Direct Digital Remittance System लॉन्च किया है जो India के UPI (Google Pay, PhonePe का वही System) को Nepal के Payment System से जोड़ता है। Nepal का मज़दूर अब सेकंडों में, फोन से, बहुत कम लागत पर पैसे घर भेज सकता है। Nepal की अर्थव्यवस्था के लिए Remittance उसके GDP का ~22-25% है – India सबसे बड़ा Source है।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
Remittance	एक देश के श्रमिक द्वारा अपने गृह देश भेजा गया धन; Nepal की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण (~25% GDP)
UPI	Unified Payments Interface – India का Real-time Payment System; पहले से कई देशों से जुड़ा
Cross-Border Payments	दो देशों के बीच Financial Transactions; दोनों देशों के Central Banks द्वारा विनियमित
Hawala	Informal Money Transfer System – औपचारिक Banking Channels के बाहर; Money Laundering का जोखिम
NPCI International	National Payments Corporation of India की Global Arm – विदेशों में UPI Adoption की सुविधा
Remittance Cost	G20 Target: 2030 तक Cross-Border Remittance Cost 3% से कम (वर्तमान में ~5-7%)

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- Nepal की Remittance Dependency: Remittances ~22-25% GDP – विश्व में सर्वाधिक में से एक; India सबसे बड़ा Source





- India-Nepal Open Border (Treaty of Peace and Friendship 1950) – भौतिक Connectivity के पीछे Financial Connectivity रह गई थी
- UPI International Expansion: UAE, Singapore, Bhutan, France, Sri Lanka, Mauritius से पहले से जुड़ा – Nepal महत्वपूर्ण जोड़
- Hawala में कमी: Formal Channels से Money Laundering का जोखिम कम, Tax Compliance बेहतर
- Neighbourhood First Policy से जुड़ाव: Nepal के साथ Financial Integration, Infrastructure (Raxaul-Kathmandu Rail), Energy Trade और People-to-People Ties को पूरक

10. NITI AAYOG — 11TH GOVERNING COUNCIL MEETING

Ministry: NITI Aayog / Prime Minister's Office

सरल हिंदी व्याख्या:

65 वर्षों तक India में Planning Commission था – Delhi में एक संस्था जो तय करती थी कि हर State क्या करे, कितना पैसा पाए, क्या Targets हासिल करे। States की बात बहुत कम सुनी जाती थी। 2015 में PM Modi ने इसे बंद कर NITI Aayog बनाया – एक Think-Tank, Policy Advice Body, जहाँ Centre और States मिलकर India का भविष्य तय करें।

Governing Council NITI Aayog की सबसे बड़ी Meeting है – PM इसकी अध्यक्षता करते हैं और सभी Chief Ministers आते हैं। इस सप्ताह की 11वीं Governing Council Meeting दो ऐतिहासिक बातों के लिए उल्लेखनीय रही: (1) पहली बार सभी 28 Chief Ministers आए – पिछले वर्षों में Opposition-Ruled States जैसे West Bengal या Delhi ने Boycott किया था। (2) Theme था 'Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047' – जैसे India 2047 तक Developed Nation बनने की दौड़ में है, क्या हम किसी को पीछे छोड़ रहे हैं?

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
------	----------------------------



| Click to Connect Now.



NITI Aayog	National Institution for Transforming India; 1 जनवरी 2015 को Planning Commission की जगह लिया
Governing Council	NITI Aayog की Apex Body; PM (Chair), सभी CMs, UTs के LGs और Union Ministers शामिल
Cooperative Federalism	Centre और States का समान Partners के रूप में मिलकर काम करना; NITI Aayog का मूलभूत सिद्धांत
Viksit Bharat@2047	2047 तक Developed Nation बनने का India का Vision – स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष
Planning Commission	NITI Aayog द्वारा Replace; यह Top-Down Planning Body थी, NITI की Advisory/Think-Tank भूमिका के विपरीत
Demographic Dividend	India की युवा आबादी (70 करोड़ 25 वर्ष से कम) Economic Asset के रूप में – Skilling आवश्यक

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- NITI Aayog 1 जनवरी 2015 को Cabinet Resolution से बना; Planning Commission 1950 में बना था – 65 वर्ष बाद Replace हुआ
- मुख्य अंतर: Planning Commission Resources Allocate करता था (Top-Down); NITI Aayog Think-Tank/Advisory Body है – Resource Allocation Finance Ministry के पास
- 11वीं Meeting ऐतिहासिक: पहली बार सभी 28 State Chief Ministers उपस्थित – Cooperative Federalism का व्यावहारिक प्रदर्शन
- India की HDI Rank: 193 में 134 (2023-24); Viksit Bharat Target के लिए Health, Education और Income Indicators में बड़ा सुधार आवश्यक
- NITI Aayog में 15-Year Vision, 7-Year Strategy और 3-Year Action Agenda – पुरानी 5-Year Plans से अलग

11. JAL JEEVAN MISSION 2.0 — REFORM-LINKED MoUs



| Click to Connect Now.



Ministry: Ministry of Jal Shakti (जल शक्ति मंत्रालय)

सरल हिंदी व्याख्या:

2019 में India ने Jal Jeevan Mission (JJM) शुरू किया: लक्ष्य था 2024 तक हर ग्रामीण घर को Tap Water Connection देना। सरकार ने लाखों करोड़ खर्च कर Pipes बिछाई, Taps लगाए। 2024 तक 75%+ ग्रामीण घरों में Tap Connection की घोषणा हुई। लेकिन समस्या यह थी: कई Taps में पानी आ ही नहीं रहा था। Pipes बिछी थीं पर पानी नहीं। Taps दीवार पर लगे थे पर खोलने पर कुछ नहीं।

यही Gap – 'Connection' (Tap लगा है) और 'Functional Connection' (पानी आ रहा है) के बीच – JJM 2.0 की केंद्रीय समस्या बन गया। JJM 2.0 अब गिनता है कि पानी सच में परिवारों तक पहुँच रहा है या नहीं – कम से कम 55 Litres प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और नई बात यह है: States को पूरी Central Funding तभी मिलेगी जब वे MoU पर हस्ताक्षर करें – Water User Fee, Village-Level Water Committees, और Maintenance Plans। इस सप्ताह Sikkim, Manipur और Bihar ने ये MoUs Sign किए।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
JJM 1.0	Jal Jeevan Mission Original (2019): Target – 2024 तक हर ग्रामीण घर में Tap Water Connection
JJM 2.0	Jal Jeevan Mission Phase 2: Sustainability, Water Quality, Functionality और Community Ownership पर ध्यान
Har Ghar Jal	JJM का Tagline – हर घर को Functional Tap Water Connection (FHTC) मिले
FHTC	Functional Household Tap Connection – केवल Installed नहीं, बल्कि वास्तव में 55 lpcd पानी देता हो
Reform-Linked MoU	State Central Funds पाने के लिए Water Sector में Governance Reforms की प्रतिबद्धता वाला Agreement



| Click to Connect Now.

**O&M Framework**

Operations & Maintenance – Installation के बाद Water Infrastructure को चालू रखने की दीर्घकालिक योजना

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- JJM 1.0 (2019): India 17% Rural Tap Coverage से 75%+ तक पहुँचा – विश्व के सबसे तेज़ Water Delivery Programmes में से एक
- 55 lpcd Standard: WHO न्यूनतम 50 Litres Per Capita Per Day की सिफारिश करता है; JJM का Target 55 lpcd
- Reform-Linked MoU एक महत्वपूर्ण Governance Innovation: States को Water Tariff Rationalization और Community Participation की प्रतिबद्धता दिखानी होगी
- Water, State List का विषय (Entry 17); Centre Centrally Sponsored Scheme Structure से Funds देता है; Reform-Linked Conditionality Fiscal Federalism Tool है

12. TEXTILE PLI SCHEME — ROUND III

Ministry: Ministry of Textiles (वस्त्र मंत्रालय)

सरल हिंदी व्याख्या:

भारत हजारों वर्षों से सूती कपड़ा बना रहा है – हम इसमें माहिर हैं। लेकिन दुनिया अब ज्यादातर Synthetic Fabrics की ओर बढ़ गई है – Polyester Shirts, Nylon Sportswear, Stretch Jeans। Bangladesh और Vietnam इस Segment में राज करते हैं। India लगभग बाहर है।

क्यों? क्योंकि Indian Textile Factories ने Synthetic Fabrics बनाने की Machinery में कभी निवेश नहीं किया। इसे बदलने के लिए सरकार ने Textile PLI Scheme शुरू की – जो Companies Man-Made Fibre (MMF) कपड़े और Technical Textiles (अस्पताल, निर्माण, Defence में उपयोगी विशेष कपड़े) का उत्पादन बढ़ाएं, सरकार उन्हें 15% Bonus देती है। इस सप्ताह Round III में 96 Companies को ₹12,822 करोड़ के नए निवेश के साथ Approve किया गया।



| Click to Connect Now.

**Key Terms Table:**

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
PLI Scheme	Production-Linked Incentive – सरकार Manufacturing बढ़ाने के लिए Incremental Production Value का % देती है
MMF	Man-Made Fibre – Synthetic Fibres (Polyester, Nylon, Viscose); India Cotton में Strong पर MMF में कमज़ोर
Technical Textiles	Industrial/Medical/Defence उपयोग के Functional Textiles – Geotextiles, Medical Textiles, Protective Wear
RISA	Northeast India का पारंपरिक Woven Textile; PLI में Tribal Textiles और Handicrafts शामिल
Textile PLI Target	₹19,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश; 5 वर्षों में 7.5 लाख अतिरिक्त रोज़गार पैदा करना
PM MITRA	PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks – 7 States में Plug-and-Play Textile Parks

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- India का Textile Sector Agriculture के बाद दूसरा सबसे बड़ा Employer – ~4.5 करोड़ लोगों को सीधे रोज़गार
- India का Textile Export: ~\$35 Billion सालाना; China ~\$300 Billion; India की Global Textile Export में हिस्सेदारी ~5%
- Technical Textiles: उच्च-वृद्धि Segment; India का Technical Textile Market ~\$22 Billion; सरकारी Target 2030 तक \$40 Billion
- Geopolitical Opportunity: US-China Trade Tensions + Bangladesh की राजनीतिक अस्थिरता → Orders India की ओर; PLI क्षमता बढ़ाने की तैयारी करता है





13. ECLGS 5.0 — EMERGENCY CREDIT LINE GUARANTEE SCHEME MILESTONE

Ministry: Ministry of Finance / NCGTC

सरल हिंदी व्याख्या:

जब COVID-19 ने 2020 में दस्तक दी, लाखों छोटे व्यवसाय – आपके मोहल्ले का Restaurant, दर्जी की दुकान, छोटा Hotel, Local Tour Operator – रातोंरात अपनी सारी आमदनी खो बैठे। Banks उन्हें Loan देने से मना करते थे क्योंकि उनके पास Collateral (गिरवी रखने की संपत्ति) नहीं थी।

सरकार का जवाब था ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme)। यह इस तरह काम करता है: सरकार Banks से कहती है – 'हम Loan की Guarantee देते हैं। अगर छोटा व्यवसाय नहीं चुका सका, तो हम चुकाएंगे।' इस Guarantee से Banks तुरंत उधार देने को तैयार हो जाते हैं। ECLGS 5.0 में इस सप्ताह एक Milestone पार हुआ: 1 लाख व्यवसायों को Loans मिले, कुल ₹48,000 करोड़। इसकी खूबसूरती: सरकार यह पैसा सीधे नहीं खर्च करती – केवल Default होने पर देती है। ज्यादातर व्यवसाय Default नहीं करते।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
ECLGS	Emergency Credit Line Guarantee Scheme – MSMEs को Additional Credit पर 100% Government-Backed Guarantee
NCGTC	National Credit Guarantee Trustee Company – Credit Guarantee Schemes प्रबंधित करने वाली सरकारी संस्था
Credit Guarantee	सरकार Lender को Default पर Repayment का वचन देती है – MSMEs को Loan मिलना आसान
Collateral-Free Loan	संपत्ति/Assets Security के बिना दिया गया Loan – Limited Assets वाले MSMEs के लिए महत्वपूर्ण
NPA	Non-Performing Asset – वह Loan जहाँ Borrower ने Repayment रोक दी; ECLGS Borrowers को Support कर NPAs कम करता है



| Click to Connect Now.

**CGSMFI 2.0**

Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions – इस
सप्ताह ECLGS के साथ ही Extended/Upgraded

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- ECLGS मई 2020 में COVID-19 के दौरान शुरू; सभी Versions में कुल Outstanding ₹3.5 लाख करोड़ से अधिक
- ECLGS 5.0 विशेष रूप से COVID के बाद Stressed Sectors को Target करता है – Hospitality, Aviation, Health
- MSME Sector: 6.3 करोड़ MSMEs; GDP में 30%, Export में 45% योगदान, 11 करोड़ लोगों को रोज़गार
- Credit Guarantees Fiscal Tool हैं: सरकार Default होने तक पैसा नहीं खर्च करती; कम Fiscal Cost पर Private Credit बढ़ती है

14. DIGILOCKER — MASSIVE EXPANSION

Ministry: Ministry of Electronics & IT (MeitY)

सरल हिंदी व्याख्या:

सोचिए आप रोज़ाना कितने Physical Documents ले जाते हैं या ज़रूरत पड़ती है – Aadhaar Card, PAN Card, Driving Licence, Vehicle RC, School Marksheet, College Degree Certificate, Insurance Papers। ये खो जाते हैं, खराब होते हैं, या ज़रूरत के वक्त हाथ नहीं आते।

DigiLocker इसे हल करता है: यह आपके फोन पर Government-Issued Digital Locker है जहाँ सभी Official Documents Aadhaar से जुड़कर सुरक्षित रहते हैं। CBSE जैसे ही Class 12 Result देता है, Marksheet DigiLocker में आ जाती है। Bank, Airport या University माँगे तो DigiLocker से Digital Share करो – Legally Valid, Tamper-Proof। 2015 में कुछ Documents से शुरू हुआ DigiLocker अब 35 करोड़ Users, 800 करोड़ Documents और 2,500 Organisations के साथ विशाल बन गया है। UPSC के लिए: DigiLocker India का प्रमुख Digital Public Infrastructure (DPI) उदाहरण है।



| Click to Connect Now.

**Key Terms Table:**

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
DigiLocker	Government-Issued Digital Document Wallet; Digital India Programme का हिस्सा; Physical Documents ले जाने की ज़रूरत खत्म
Issuer	DigiLocker में Documents Issue करने वाला सरकारी निकाय या संस्था (जैसे CBSE, NHA, MoRTH, Banks)
Requester	DigiLocker Documents Accept करने वाला Organization (जैसे Airports, Banks, Universities)
eSign	DigiLocker में Integrated Electronic Signature Service; IT Act 2000 के तहत Legally Valid
National Digital Identity	Aadhaar के साथ DigiLocker India के Digital Identity Framework की रीढ़ बनाता है
Data Empowerment	Data Protection Act Framework: नागरिक अपना Data खुद नियंत्रित करता है; DigiLocker 'Consent-Based' Sharing Model है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- DigiLocker 2015 में Digital India के तहत Launch; Aadhaar Authentication; IT Act की Section 7B DigiLocker Documents को Original के समकक्ष Legal Validity देती है
- 35+ करोड़ Users = India की ~25% आबादी; 800+ करोड़ Documents संग्रहीत – DPI की बड़ी सफलता
- DigiLocker, India के DPI Stack का अभिन्न अंग है – Aadhaar (Identity), UPI (Payments), ABDM (Health Data) के साथ
- Document Fraud कम करता है: Government Issuers सीधे Documents Issue करते हैं – Physical Copies जैसा कोई Tampering संभव नहीं





- DPDP Act 2023 से संबंधित: DigiLocker का Consent-Based Data Sharing Model नए Data Protection Principles से मेल खाता है

15. ZOJILA TUNNEL — HISTORIC BREAKTHROUGH

Ministry: Ministry of Road Transport & Highways (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)

सरल हिंदी व्याख्या:

Ladakh – China और Pakistan की सीमा से लगा ऊँचाई वाला क्षेत्र – हर साल लगभग 6 महीने शेष India से कट जाता है। Himalayas में Zojila Pass के रास्ते वाली एकमात्र सड़क अक्टूबर से अप्रैल तक 20-30 फीट बर्फ में दब जाती है। इन महीनों में Ladakh को ज़रूरी हर चीज़ – खाना, दवाइयाँ, ईंधन, सैन्य सामग्री – या तो सर्दियों से पहले Stockpile करनी होती है, या Airlift करनी पड़ती है।

2020 के Galwan Valley Clash के बाद यह सिर्फ असुविधा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या बन गई। समाधान है Zojila Pass के नीचे पहाड़ों में 14.15 किमी की Tunnel – पूरी होने पर यह India और Asia की सबसे लंबी Road Tunnel होगी। इस सप्ताह दोनों तरफ से खोदी जा रही Tunnel के दोनों सिरे आपस में मिल गए – इसे 'Breakthrough' कहते हैं – Tunnel निर्माण का सबसे नाटकीय Milestone। खुदाई का कठिन काम पूरा हुआ। जब यह Tunnel खुलेगी, Ladakh को अपने इतिहास में पहली बार All-Weather Connectivity मिलेगी।

Key Terms Table:

Term	Hindi Meaning / हिंदी अर्थ
Zojila Pass	NH-1 पर 11,575 फीट की ऊँचाई पर Mountain Pass; Kashmir Valley को Ladakh से जोड़ता है; सर्दियों में 6 महीने बंद
Zojila Tunnel	14.15 किमी All-Weather Road Tunnel; India की सबसे लंबी; NH-1 (Srinagar-Kargil-Leh Highway) पर
Breakthrough	Tunnel निर्माण में वह बिंदु जब दोनों Ends दोनों तरफ से खुदाई कर मिलते हैं – एक बड़ा Milestone





NHIDCL	National Highways and Infrastructure Development Corporation – Zojila Tunnel की Implementing Agency
Z-Morh Tunnel	Srinagar-Sonamarg को जोड़ती है; पहले से पूर्ण; Zojila, साल भर Ladakh पहुँच के लिए अगला Segment है
Strategic Connectivity	Ladakh तक सैन्य और नागरिक पहुँच (China और Pakistan की सीमा); Galwan 2020 के बाद महत्वपूर्ण

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- Zojila Tunnel: 14.15 किमी लंबाई; अनुमानित लागत ₹8,213 करोड़; NHIDCL MoRTH के अंतर्गत लागू कर रहा है
- Strategic Significance: Galwan Valley Clash (जून 2020) के बाद, Ladakh तक All-Weather Connectivity राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता बन गई
- Tunnel, Srinagar से Kargil की यात्रा का समय Zojila Pass Section में 3.5 घंटे से घटाकर ~15 मिनट कर देगी
- Zojila Tunnel, Connectivity Cluster का हिस्सा: Z-Morh Tunnel (Sonamarg) + Zojila Tunnel + Shinkun La Tunnel (Manali-Leh) – मिलकर All-Weather Leh पहुँच बनाएंगे
- आर्थिक लाभ: Ladakh Tourism, Apple/Apricot Exports, Kargil Connectivity – अभी सब Seasonal हैं; Tunnel Year-Round बना देगी





PRACTICE QUESTIONS — अभ्यास प्रश्न

10 PRELIMS QUESTIONS (Answers at end)

Q1.

VINIMAY के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह Ministry of Commerce & Industry के तहत Seaports पर व्यापार सुविधा के लिए लॉन्च किया गया।
2. यह ANPR-आधारित Gate Operations का उपयोग करता है।
3. यह Land Ports पर ~90% कागज़ी काम समाप्त करता है।
4. भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ 15,000 किमी से अधिक भूमि सीमा साझा करता है।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) – Statement 1 गलत है; VINIMAY MHA के तहत है और Land Ports के लिए है।

Q2.

Gallantry Awards के जोड़े मिलाएं:

1. Kirti Chakra – Wartime
2. Vir Chakra – Wartime
3. Ashoka Chakra – Peacetime
4. Shaurya Chakra – Peacetime

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) – Kirti Chakra Peacetime Award है, Wartime नहीं।

Q3.

PM-JAY के बारे में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह Secondary और Tertiary Hospitalisation के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख प्रति वर्ष प्रदान करता है।
2. West Bengal PM-JAY में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था।



| Click to Connect Now.



3. PM-JAY के तहत लाभार्थी केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं।

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 3
- (c) 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a) – Statement 2 गलत (कुछ UTs अभी भी बाहर); Statement 3 गलत (Empanelled Private Hospitals भी शामिल)।

Q4.

IFC-IOR (Information Fusion Centre - Indian Ocean Region) क्या है?

- (a) Andaman Islands में Joint India-US Surveillance Facility
- (b) India का Maritime Domain Awareness Centre जो Partner Navies को Real-time Information Share करता है
- (c) Indian Ocean में Anti-Piracy Operations के लिए IMO-Mandated Body
- (d) Ministry of Ports के तहत Civilian Coast Guard Facility

उत्तर: (b)

Q5.

IndiaAI Mission के बारे में कथनों पर विचार करें:

1. इसे India के AI Ecosystem बनाने के लिए ₹10,371 करोड़ के Budget से Approve किया गया।
2. चुने गए Startups को Subsidised GPU Compute मिलता है बदले में उन्हें Model Public Release करना होता है।
3. Varya, पहला Indigenous Video AI Model, सरकारी Research Institution ने बनाया।

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a) – Statement 3 गलत; Varya Private Startup Avataar ने बनाया।

Q6.

NITI Aayog Governing Council, Planning Commission से किस प्रकार अलग है?

1. Planning Commission States को Financial Resources Allocate करता था; NITI Aayog नहीं करता।





2. Governing Council में सभी States के Chief Ministers हैं; Planning Commission में ऐसी अनिवार्य State Representation नहीं थी।

3. NITI Aayog Advisory Think-Tank है; Planning Commission के पास Executive Authority थी।

(a) 1 और 3 (b) केवल 2 (c) 1, 2 और 3 (d) 2 और 3

उत्तर: (c) – तीनों कथन सही हैं।

Q7.

PMSMA के संदर्भ में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह योजना हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त Antenatal Check-ups देती है।

2. भारत की MMR का SDG Target 2030 तक 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म से कम है।

3. PMSMA ग्रामीण India में Institutional Deliveries को प्रोत्साहित करने की प्राथमिक योजना है।

(a) केवल 1

(b) 1 और 2

(c) 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) – Statement 3 गलत; Institutional Deliveries के लिए JSY है, PMSMA नहीं।

Q8.

Zojila Tunnel के बारे में कथनों पर विचार करें:

1. यह NH-1, Srinagar-Kargil-Leh Highway पर बन रहा है।

2. 14.15 किमी में यह India और Asia की सबसे लंबी Bi-Directional Road Tunnel होगी।

3. Implementing Agency NHAI है।

4. Zojila Pass वर्तमान में Heavy Snowfall के कारण प्रतिवर्ष ~6 महीने बंद रहता है।

कितने कथन सही हैं?

(a) केवल दो

(b) केवल तीन

(c) सभी चार

(d) केवल एक

उत्तर: (b) – Statement 3 गलत; Implementing Agency NHIDCL है, NHAI नहीं।

Q9.



| Click to Connect Now.



India के Strategic Petroleum Reserve (SPR) के संदर्भ में कौन सा/से सही है/हैं?

1. वर्तमान SPR Capacity ~67 दिनों की Crude Oil Supply देती है।
2. SPR 5 स्थानों पर: Vizag, Mangalore, Padur, Udupi और Indulkhand।
3. Strait of Hormuz, जिससे ~30% Global Oil Transit होता है, India की सबसे बड़ी Energy Supply Vulnerability है।

- (a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) – तीनों सही हैं।

Q10.

Varya को विकसित करने में इस्तेमाल 'Distillation' Technique का सही वर्णन कौन सा है?

- (a) केवल Indian-Language Datasets से AI Model Train करना
(b) एक बड़े Model की क्षमताओं को Output Quality बनाए रखते हुए Smaller, Faster, Cheaper Version में संकुचित करना
(c) Foreign Entities द्वारा Reverse Engineering रोकने के लिए AI Model Weights को Encrypt करना
(d) Multiple AI Models को Single Unified Architecture में जोड़ना

उत्तर: (b)

2 MAINS QUESTIONS — मुख्य परीक्षा प्रश्न

Mains Q1 (150 शब्द):

'India की Digital Public Infrastructure – DigiLocker, UPI और IndiaAI Mission द्वारा उदाहरणित – Welfare Delivery से Capability Building की ओर एक बदलाव दर्शाती है।' हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें।

Mains Q2 (250 शब्द):



| Click to Connect Now.



'VINIMAY और Zojila Tunnel से लेकर ECLGS और Jal Jeevan Mission 2.0 तक, इस सप्ताह की Policy घोषणाएं एक सुसंगत विषय दर्शाती हैं: Physical और Institutional पहुँच को आर्थिक और सुरक्षा परिणामों में बदलना।' विश्लेषण करें।

PIB Weekly Brief | 6-12 June 2026 | Hindi Translation | itok IAS



| Click to Connect Now.

13-19
जून 2026

PIB

साप्ताहिक संक्षेप

भारत का वैश्विक उदय

व्यापार • प्रौद्योगिकी • रणनीतिक शक्ति



मुख्य बिंदु



भारत-यूके CETA

\$100 किलियन
व्यापार लक्ष्य

2030 तक द्विपक्षीय व्यापार
दोगुना करने का लक्ष्य



LRLACM मिसाइल

1,000+ किमी
स्ट्राइक क्षमता

भारत की नई लॉन्ग रेंज
कूज़ मिसाइल का
सफल परीक्षण



G7 एवीयान शिखर सम्मेलन

भारत का
कूटनीतिक अभियान

वैश्विक मुद्दों, व्यापार और
जलवायु कार्रवाई पर
मजबूत भागीदारी



ग्रीन हाइड्रोजन

वैश्विक प्रमाणन
ढांचा

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए
भारत का प्रमाणन सिस्टम
लॉन्च



Table of Contents

INDIA-UK CETA — COMPREHENSIVE ECONOMIC & TRADE AGREEMENT	6
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	6
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	6
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	7
WOMEN CADETS FROM NDA — FIRST BATCH COMMISSIONED	8
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	8
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	8
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	9
DRDO LRLACM — LONG RANGE LAND ATTACK CRUISE MISSILE TEST	10
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	10
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	10
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	11
INDIA-JAPAN JOINT CREDITING MECHANISM — ARTICLE 6.2 PARIS AGREEMENT	12
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	12
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	12
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	13
INDIA DEFENCE PRODUCTION — RECORD ₹1.78 LAKH CRORE IN FY26.....	14
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	14
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	14
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	15
PM MODI AT G7 EVIAN — INDIA'S DIPLOMATIC BLITZ.....	16
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	16
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	16
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	17
INDIA-FRANCE INNOVATION ROADMAP 2030 — BHARAT INNOVATES	18
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	18
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	18
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	19





CENSUS 2027 — FIELD OPERATIONS UNDERWAY ACROSS INDIA	20
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	20
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	20
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	21
KISHAU MULTIPURPOSE DAM — 8-YEAR DEADLOCK RESOLVED	22
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	22
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	22
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	23
INDIAN NAVY — THREE INDIGENOUS PLATFORMS COMMISSIONED IN KOLKATA	24
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	24
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	24
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	25
KAVACH — AUTOMATIC TRAIN PROTECTION SYSTEM EXPANSION	26
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	26
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	26
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	27
PMVBRY — PRADHAN MANTRI VIKSIT BHARAT ROZGAR YOJANA	28
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	28
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	28
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	29
SICKLE CELL DISEASE — INTERNATIONAL SICKLE CELL DAY	30
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	30
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	30
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	31
STUBBLE BURNING — HIGH-LEVEL MEETING FOR PERMANENT SOLUTION	32
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	32
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	32
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	33
NHAI MULTI-LANE FREE FLOW TOLLING — FASTAG 2.0	34





सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	34
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	34
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	35
DRONE-BASED MAIL DELIVERY — DEPARTMENT OF POSTS, HIMACHAL PRADESH	36
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	36
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	36
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	37
INDIA BIOECONOMY — \$10 BILLION TO \$190 BILLION IN 12 YEARS	38
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	38
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	38
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	39
GREEN HYDROGEN CERTIFICATION PORTAL — MNRE	40
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	40
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	40
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	41
NATIONAL CYBER CRIME HELPLINE 1930 — AMIT SHAH REVIEWS.....	42
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	42
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	42
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	43
BRICS INDORE DECLARATION — AGRICULTURE COOPERATION FRAMEWORK	44
सरल व्याख्या (EASY EXPLANATION)	44
मुख्य शब्द (KEY TERMS).....	44
UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु	45
PRACTICE QUESTIONS.....	46
10 PRELIMS QUESTIONS — UPSC PRELIMS 2026 STYLE.....	46
2 MAINS QUESTIONS	51
MAINS QUESTION 1 — 150 WORDS	51
MAINS QUESTION 2 — 250 WORDS	51
PRELIMS ANSWERS & EXPLANATIONS	52
MAINS MODEL ANSWERS	54
MAINS Q1 — MODEL ANSWER (150 WORDS)	54







INDIA-UK CETA — COMPREHENSIVE ECONOMIC & TRADE AGREEMENT

Ministry: Ministry of Commerce & Industry

PIB Date: 17th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

भारत और ब्रिटेन ने लगभग तीन साल की बातचीत के बाद आखिरकार एक बड़ा एलान किया: India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) — यानी व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता — 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। CETA को दो देशों के बीच अब तक की सबसे विस्तृत व्यापार नियम-पुस्तिका समझिए। यह केवल सीमा पर वस्तुओं पर लगने वाले करों (Tariffs — आयात शुल्क) को कम करने तक सीमित नहीं है — यह 26 क्षेत्रों को कवर करता है: वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, Intellectual Property (बौद्धिक संपदा), श्रम मानक, पर्यावरण, और भी बहुत कुछ।

सरल शब्दों में समझिए: एक भारतीय कपड़ा कंपनी जो ब्रिटेन को कपड़े निर्यात करती है, उसे फिलहाल हर वस्तु पर 9–12% Tariff (आयात शुल्क) देना पड़ता है। CETA के तहत भारत के 99% निर्यात ब्रिटेन में Duty-free (शुल्क-मुक्त) हो जाएंगे। ब्रिटिश उत्पाद — स्कॉच व्हिस्की, कारें, सौंदर्य प्रसाधन — भी भारत में सस्ते होंगे क्योंकि आयात शुल्क कटेगा।

भारतीय IT पेशेवरों को भी फायदा: एक अलग Social Security Agreement (DCC) का मतलब है कि ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय पेशेवर को अब दोनों देशों में एक साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा — हर साल हजारों पाउंड की बचत। लक्ष्य: द्विपक्षीय व्यापार को \$56 बिलियन से \$100 बिलियन तक 2030 तक ले जाना। यह एशिया के बाहर भारत का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
CETA	Comprehensive Economic and Trade Agreement — भारत का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता; 26 क्षेत्रों को कवर करता है (वस्तु, सेवाएं, निवेश आदि)
Tariff Elimination (शुल्क उन्मूलन)	भारत के 99% निर्यात ब्रिटेन में Duty-free (शुल्क-मुक्त); व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर



| Click to Connect Now.



Double Contribution Convention (DCC)	Social Security Agreement — भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में 5 साल तक दोहरा सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा
Rules of Origin (उद्गम नियम)	यह तय करने का मापदंड कि कोई उत्पाद 'Made in India' के लिए योग्य है या नहीं; तीसरे देशों से Transit (पारगमन) रोकता है
India-UK Roadmap 2030	2021 में हस्ताक्षरित ढांचा; \$100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य; CETA इसकी मुख्य उपलब्धि
Negotiations Timeline (वार्ता समयरेखा)	14 दौर की वार्ता; 6 मई 2025 को पूर्ण; 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षर; 15 जुलाई 2026 से लागू

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- CETA पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश सचिव Jonathan Reynolds ने PM मोदी और ब्रिटिश PM Keir Starmer की उपस्थिति में 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षर किए
- एशिया के बाहर भारत का सबसे व्यापक व्यापार समझौता — 26 क्षेत्र: वस्तु, सेवाएं, निवेश, IP (बौद्धिक संपदा), श्रम और पर्यावरण मानक
- भारत के 99% माल निर्यात ब्रिटेन में Duty-free; प्रमुख लाभार्थी: कपड़ा, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, फार्मा, समुद्री भोजन
- ब्रिटेन को लाभ: Scotch whisky पर शुल्क 150% से 75% (तत्काल), 10 वर्षों में 40% तक; ब्रिटिश कार, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण भी लाभान्वित
- Social Security Agreement (DCC): Indian professionals के लिए दोहरे अंशदान से छूट की अवधि 3 साल से 5 साल तक बढ़ाई गई
- 137 सेवा क्षेत्र भारत के लिए खोले गए — IT, परामर्श, वित्त, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण
- द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में \$56 बिलियन; 2030 तक \$100 बिलियन का लक्ष्य = ~10% की सालाना वृद्धि आवश्यक
- संदर्भ: इसी सप्ताह India-EU FTA वार्ता भी समाप्त हुई; India-Canada CEPA प्रगति पर





WOMEN CADETS FROM NDA — FIRST BATCH COMMISSIONED

Ministry: Ministry of Defence

PIB Date: 13th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

13 जून 2026 भारतीय सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। 75 वर्षों में पहली बार, National Defence Academy (NDA) — पुणे स्थित भारत का प्रमुख संयुक्त सेवा प्रशिक्षण संस्थान — में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी के रूप में औपचारिक रूप से Commissioned (कमीशन — अधिकारी पद पर नियुक्त) किया गया।

2021 तक NDA केवल पुरुष कैडेट्स को प्रवेश देती थी। सितंबर 2021 में भारत के Supreme Court ने Kush Kalra बनाम Union of India मामले में फैसला दिया कि महिलाओं को NDA से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। पहला महिला कैडेट बैच 2022 में NDA में शामिल हुआ। उन्होंने पुरुष समकक्षों के समान तीन साल का कठिन प्रशिक्षण लिया — परेड, बाधा कोर्स, हथियार प्रशिक्षण, तैराकी, घुड़सवारी, अकादमिक।

महत्व: NDA कोई साधारण सैन्य अकादमी नहीं है — यह भारत के भविष्य के सैन्य नेतृत्व को आकार देती है। इस संस्था में महिलाओं का प्रवेश एक मौलिक सांस्कृतिक बदलाव है, केवल एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर नहीं।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
NDA	National Defence Academy — पुणे, खड़कवासला; भारत की प्रमुख संयुक्त सेवा कैडेट प्रशिक्षण अकादमी; थल सेना, नौसेना, वायु सेना को अधिकारी देती है
Commissioning (कमीशनिंग)	औपचारिक समारोह जिसमें कैडेट अधिकारी बनता है; NDA स्नातक Second Lieutenant/Sub-Lieutenant के रूप में Commissioned होते हैं
Supreme Court Ruling 2021	Kush Kalra बनाम Union of India — अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं को NDA में शामिल करने का आदेश
Permanent Commission (स्थायी कमीशन)	पूर्ण सैन्य करियर मार्ग; NDA मार्ग स्थायी कमीशन की ओर ले जाता है



| Click to Connect Now.



Articles 14 & 15	समानता का अधिकार और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध — SC फैसले का संवैधानिक आधार
Agniveer Scheme	अल्पकालिक सैन्य भर्ती योजना (4 वर्ष); NDA Permanent Commission मार्ग से अलग

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- NDA की स्थापना 1954 में खड़कवासला, पुणे में; 2021 के SC आदेश तक 67 वर्षों तक केवल पुरुष कैडेट
- पहली महिला कैडेट्स जुलाई 2022 में NDA में शामिल हुईं — इस सप्ताह की Commissioning उस तीन-वर्षीय चक्र की परिणति
- 2022 से पहले भी महिलाएं सेना में थीं — Women Military Police (1992 से), Short Service Commission (1993 से), और Permanent Commission (SC आदेश 2020)
- NDA एक Joint Academy है — थल सेना, नौसेना, वायु सेना एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं; JNU से BSc/BA डिग्री भी
- भारत उन अंतिम प्रमुख लोकतंत्रों में था जिसने अपनी प्रमुख सैन्य अकादमी महिलाओं के लिए खोली — USA ने West Point 1976 में, UK ने Sandhurst 1984 में खोला
- Commissioning समारोह की समीक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की; राष्ट्रपति (सर्वोच्च सेनापति) औपचारिक रूप से अधिकारियों को Commission करते हैं





DRDO LRLACM — LONG RANGE LAND ATTACK CRUISE MISSILE TEST

Ministry: Ministry of Defence / DRDO

PIB Date: 15th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

15 जून 2026 को भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो उसकी रणनीतिक क्षमताओं को नया आयाम देती है। DRDO की Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM) — जिसका परीक्षण ओडिशा तट के Dr APJ Abdul Kalam Island से किया गया — एक Subsonic (ध्वनि की गति से धीमी) Cruise Missile है जो 1,000 किमी से अधिक दूरी तय कर एक जमीनी लक्ष्य को सटीकता से निशाना बना सकती है।

यह क्यों मायने रखता है: अब तक भारत की जमीनी हमला मिसाइल क्षमता मुख्यतः BrahMos (Supersonic — पर कम रेंज) और Nirbhay (जिसके कई परीक्षण विफल रहे) तक सीमित थी। LRLACM एक नई पीढ़ी की मिसाइल है जो: (क) रडार की पकड़ से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, (ख) वायु रक्षा (Air Defence) को चकमा देने के लिए Terrain-following Navigation (जमीन की ऊंचाई-नीचाई को फॉलो करते हुए उड़ान) का उपयोग करती है, (ग) Mobile Truck-mounted Launcher (ट्रक पर चलने वाले लांचर) से दागी जा सकती है, और (घ) स्वदेशी 'Manik' Turbofan Engine (पूरी तरह भारत में बना इंजन) का उपयोग करती है।

मिसाइल NavIC (भारत का अपना GPS) और Ring Laser Gyroscope Navigation का उपयोग करती है — विदेशी GPS पर कोई निर्भरता नहीं। भू-राजनीतिक अर्थ: भारत अब भारतीय धरती से दुश्मन के इलाके में गहराई तक स्थित सैन्य अड्डों, कमान केंद्रों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है — बिना विमान या पायलट को खतरे में डाले।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
LRLACM	Long Range Land Attack Cruise Missile — Subsonic; रेंज 1,000–1,500 किमी; DRDO के ADE, बेंगलुरु द्वारा स्वदेशी विकास
Cruise Missile (क्रूज मिसाइल)	स्व-चालित, हवा में उड़ने वाली मिसाइल जो विमान की तरह कम ऊंचाई पर उड़ती है; Ballistic Missile (जो ऊपर जाकर नीचे आती है) से अलग



| Click to Connect Now.



Manik Engine	भारत का पहला स्वदेशी Turbofan Engine जो एक Cruise Missile में इस्तेमाल हुआ; विदेशी Propulsion (प्रणोदन) पर निर्भरता खत्म
NavIC	Navigation with Indian Constellation — भारत का अपना उपग्रह नेविगेशन सिस्टम; LRLACM में उपयोग
Dr APJ Abdul Kalam Island	ओडिशा तट पर परीक्षण प्रक्षेपण स्थल (पहले Wheeler Island); भारत की प्राथमिक मिसाइल परीक्षण रेंज
ADE Bengaluru	Aeronautical Development Establishment — DRDO की वह प्रयोगशाला जिसने LRLACM डिज़ाइन किया

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- LRLACM, Nirbhay कार्यक्रम का उत्तराधिकारी है (Nirbhay के कई परीक्षण विफल रहे थे)
- रेंज: 1,000–1,500 किमी; Conventional (परंपरागत) और Nuclear (परमाणु) दोनों Warheads ले जाने में सक्षम — भारत के Nuclear Triad (परमाणु त्रिकोण) का हिस्सा
- Subsonic (~0.7 Mach) बनाम BrahMos Supersonic (~2.8 Mach) — धीमी लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण पकड़ना मुश्किल
- Navigation: Ring Laser Gyroscope (RLG) + GPS + NavIC — Redundant (बहुस्तरीय) Navigation, GPS Jam होने पर भी काम करती है
- Mobile Launcher: ट्रकों पर तैनात हो सकती है, जंगलों में छिपाई जा सकती है — Fixed Launch Sites की तुलना में दुश्मन के लिए निशाना बनाना बेहद मुश्किल
- भारत के पास अब China के DH-10 और Pakistan के Babur जैसी दीर्घ-दूरी की जमीनी हमला क्षमता — क्षेत्रीय Deterrence (प्रतिरोध) संतुलन बदलता है





INDIA-JAPAN JOINT CREDITING MECHANISM — ARTICLE 6.2 PARIS AGREEMENT

Ministry: Ministry of Environment, Forest and Climate Change

PIB Date: 16th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से निपटने के लिए देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emissions) को कम करना होगा। लेकिन कुछ देश सस्ते सौर पैनल बनाने में अच्छे हैं, और अन्य के पास उन पैनलों के लिए जमीन और जरूरत है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वे मिलकर काम करें? यही Paris Agreement (पेरिस समझौता) का Article 6.2 (अनुच्छेद 6.2) अनुमति देता है — दो देश किसी जलवायु परियोजना पर सहयोग कर सकते हैं, और जो Emission Reductions (उत्सर्जन में कमी) होती है उसे 'Credit' (प्रमाण-पत्र) के रूप में मान्यता मिलती है।

भारत और जापान ने इस प्रणाली को Joint Crediting Mechanism (JCM) के रूप में औपचारिक रूप दिया है। व्यावहारिक उदाहरण: एक जापानी कंपनी एक भारतीय कारखाने में ऊर्जा-कुशल मशीनें लगाती है। कारखाना सालाना 10,000 टन कम CO2 उत्सर्जित करता है। इन 10,000 टन की कमी को Third-party (तृतीय पक्ष) द्वारा सत्यापित किया जाता है और Carbon Credits (कार्बन क्रेडिट) में बदला जाता है। ये Credits भारत और जापान के बीच साझा की जाती हैं — दोनों अपने Paris Agreement प्रतिबद्धताओं (NDC — Nationally Determined Contribution) पर प्रगति दिखा सकते हैं।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Article 6.2 Paris Agreement	द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिट (ITMOs) के हस्तांतरण के माध्यम से देशों को जलवायु लक्ष्यों में सहयोग की अनुमति देता है
JCM	Joint Crediting Mechanism — जापान की 32 भागीदार देशों के साथ द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिट प्रणाली; भारत 2025 में शामिल
ITMO	Internationally Transferred Mitigation Outcome — Article 6.2 के तहत Carbon Credit की इकाई; 1 टन CO2 समकक्ष कमी दर्शाता है



| Click to Connect Now.



NDC	Nationally Determined Contribution — Paris Agreement के तहत प्रत्येक देश का स्व-घोषित जलवायु लक्ष्य; हर 5 साल में संशोधित
Carbon Credit (कार्बन क्रेडिट)	1 टन CO2 कमी का प्रमाण-पत्र; इसे खरीदा-बेचा या Offset (भरपाई) के लिए उपयोग किया जा सकता है
Double Counting Prevention	भारत और जापान दोनों को Corresponding Adjustments करने होंगे — एक Credit को दो बार नहीं गिना जा सकता

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Paris Agreement 2015 के Article 6 में तीन तंत्र: 6.2 (द्विपक्षीय), 6.4 (UN-supervised बहुपक्षीय बाजार), 6.8 (गैर-बाजार दृष्टिकोण) — JCM Article 6.2 के अंतर्गत
- भारत के NDC लक्ष्य: 2030 तक 2005 की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी; 50% विद्युत क्षमता Non-fossil से; 2070 तक Net Zero
- JCM के तहत प्रमुख क्षेत्र: नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता, Green Hydrogen, Electric Mobility, Smart Grids
- यह पुराने CDM (Kyoto Protocol के तहत Clean Development Mechanism) से अलग है — JCM द्विपक्षीय, तेज और Credits साझा होती हैं
- भारत को जापानी निजी क्षेत्र का निवेश और Technology मिलती है; जापान को घरेलू कमी से सस्ता Emission Reduction मिलता है





INDIA DEFENCE PRODUCTION — RECORD ₹1.78 LAKH CRORE IN FY26

Ministry: Ministry of Defence

PIB Date: 17th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

अपने अधिकांश स्वतंत्र इतिहास में भारत अपने हथियार विदेशों से खरीदता था — सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, इजरायल से। यह दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक था। 2014 के बाद दर्शन बदला। Atmanirbhar Bharat (आत्मनिर्भर भारत) की नीति, दो Defence Industrial Corridors (रक्षा औद्योगिक गलियारे — UP और तमिलनाडु), और निजी क्षेत्र को खोला गया।

परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं: भारत का रक्षा उत्पादन FY2025–26 में रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंचा। यह FY2013–14 (₹43,746 करोड़) का लगभग चार गुना और FY2020–21 (₹84,643 करोड़) का दोगुना से अधिक है। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24% तक बढ़ी — Tata, L&T, Bharat Forge जैसी कंपनियां अब हथियार बना रही हैं। रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ रहा — भारत 85+ देशों को उपकरण निर्यात कर रहा है, जबकि एक दशक पहले यह लगभग शून्य था।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
DPSUs	Defence Public Sector Undertakings — HAL, BEL, BDL, MDL, GRSE आदि; कुल उत्पादन का ~76% योगदान
Defence Exports (रक्षा निर्यात)	विदेशी देशों को बेचे गए हथियार/उपकरण; FY26 में ₹38,424 करोड़ बनाम FY13-14 में ₹686 करोड़ — 56 गुना वृद्धि
DAP 2020	Defence Acquisition Procedure 2020 — अनिवार्य न्यूनतम Indigenous Content (स्वदेशी सामग्री)%; खरीद में 'Make in India' को प्राथमिकता
Defence Industrial Corridors	दो गलियारे: UP (लखनऊ-आगरा) और तमिलनाडु (चेन्नई-कोयंबटूर); रक्षा उत्पादन के लिए समर्पित क्षेत्र
IDEX	Innovations for Defence Excellence — Startup कार्यक्रम; 350+ रक्षा Startups को समर्थन



| Click to Connect Now.

**Positive Indigenisation List**

500+ वस्तुओं की सूची जिन्हें Import नहीं किया जा सकता — भारत में ही बनाना अनिवार्य

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- मुख्य आंकड़े: FY2013-14: ₹43,746 करोड़ → FY2020-21: ₹84,643 करोड़ → FY2024-25: ₹1.54 लाख करोड़ → FY2025-26: ₹1.78 लाख करोड़ (15.6% YoY वृद्धि)
- निर्यात: ₹38,424 करोड़; प्रमुख उत्पाद: BrahMos मिसाइल सिस्टम, Tejas Components, Radars, Ammunition — 85+ देशों को
- Defence Budget FY2026-27: ₹7.85 लाख करोड़; ₹2.19 लाख करोड़ Capital Acquisitions (आधुनिकीकरण) — अब तक का सबसे बड़ा
- FDI in Defence: 100% Automatic Route तक बढ़ाया (पहले 26%); Global OEMs को भारत में उत्पादन के लिए आकर्षित किया
- चुनौती: उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आयातक — लड़ाकू जेट इंजन, Submarines जैसे जटिल Platform अभी भी आयात
- लक्ष्य: 2029 तक शीर्ष 10 वैश्विक रक्षा निर्यातक (वर्तमान में ~25वां); ₹50,000 करोड़ निर्यात का लक्ष्य





PM MODI AT G7 EVIAN — INDIA'S DIPLOMATIC BLITZ

Ministry: Prime Minister's Office / Ministry of External Affairs

PIB Date: 16th–17th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है: USA, UK, France, Germany, Japan, Italy और Canada। भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन G7 राष्ट्र नियमित रूप से महत्वपूर्ण विकासशील देशों के नेताओं को 'Outreach Guest' (आउटरीच अतिथि) के रूप में आमंत्रित करते हैं।

इस साल का G7 शिखर सम्मेलन 16-17 जून को Evian-les-Bains, France में था। PM मोदी ने AI Governance, आर्थिक विकास और 'New Partnerships' — तीन सत्रों में भाग लिया। लेकिन असली कार्यवाही द्विपक्षीय बैठकों में हुई: दो दिनों में मोदी ने मिले — US President Trump (India-US व्यापार समझौते पर प्रगति), UK PM Starmer (CETA का जश्न), French President Macron (Innovation Roadmap 2030), Canadian PM Carney (CEPA वार्ता), German Chancellor, UAE President और EU Council/Commission Presidents से।

यह है बड़े पैमाने पर कूटनीति — एक फ्रांस यात्रा में US, UK, EU, Canada और UAE के साथ संबंध एक साथ आगे बढ़ाना। PM मोदी ने Slovakia भी दौरा किया — किसी भारतीय PM की पहली Slovakia यात्रा — और Slovakia का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
G7	Group of Seven: USA, UK, France, Germany, Japan, Italy, Canada; भारत सदस्य नहीं लेकिन Outreach Guest के रूप में आमंत्रित
Outreach Session	G7 का गैर-सदस्य देशों को विशिष्ट सत्रों में आमंत्रित करने का अभ्यास; भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है
India-EU FTA	भारत और European Union के बीच व्यापक Free Trade Agreement; EU President ने 2026 के अंत तक हस्ताक्षर की घोषणा की



| Click to Connect Now.



VivaTech 2026	Paris में Europe का सबसे बड़ा Technology और Startup आयोजन; PM मोदी ने संबोधित किया
Multi-alignment (बहु-संरेखण)	भारत की विदेश नीति: किसी एक खेमे में शामिल हुए बिना सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना
Slovakia Visit	किसी भारतीय PM की पहली Slovakia यात्रा; PM को 'Order of the White Double Cross, 1st Class' — Slovakia का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- G7 Evian 2026 France द्वारा आयोजित; भारत ने AI, आर्थिक विकास और New Partnerships पर Outreach Sessions में भाग लिया
- Modi-Trump द्विपक्षीय: 'संतुलित, परस्पर लाभकारी' India-US BTA (Bilateral Trade Agreement) पर अधिकारियों को काम करने का निर्देश
- India-EU FTA घोषणा: EU Commission President Ursula von der Leyen ने कहा FTA '2026 के अंत तक हस्ताक्षरित होगा' — भारत के व्यापार विविधीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
- India-Canada: PM Carney के साथ बैठक; CEPA वार्ता में प्रगति; 2026 में समाप्त करने का साझा लक्ष्य — Nijjar प्रकरण के बाद संबंध सामान्य हो रहे हैं
- Slovakia: पहली भारतीय PM यात्रा; EU और NATO सदस्य — पूर्वी यूरोप में Supply Chain विविधीकरण के लिए संबंध गहरे





INDIA-FRANCE INNOVATION ROADMAP 2030 — BHARAT INNOVATES

Ministry: Ministry of Education / NITI Aayog

PIB Date: 14th–17th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

फ्रांस और भारत 1998 से Strategic Partners (रणनीतिक भागीदार) हैं। वर्षों में यह संबंध परमाणु ऊर्जा (Jaitapur परमाणु संयंत्र), रक्षा (Rafale लड़ाकू जेट), और अंतरिक्ष (ISRO-CNES सहयोग) में गहरा हुआ। इस सप्ताह एक नया आयाम जुड़ा: Deep-tech (गहरी तकनीक) और Innovation।

PM मोदी और French President Macron ने Nice, France में 'Bharat Innovates 2026' का उद्घाटन किया — यह दो दिवसीय आयोजन था जहां भारत के Technology Startups और अनुसंधान संस्थानों को यूरोपीय निवेशकों और भागीदारों के सामने प्रदर्शित किया गया। साथ ही, भारत और फ्रांस ने Innovation Roadmap 2030 पर हस्ताक्षर किए — AI, Quantum Computing (क्वांटम कंप्यूटिंग), Semiconductors (अर्धचालक), Green Hydrogen, अंतरिक्ष और Biotechnology में सहयोग की औपचारिक प्रतिबद्धता।

एक विशेष रूप से रोचक घटक: ATL Bridge — भारत की Atal Tinkering Labs (NITI Aayog के AIM कार्यक्रम के तहत स्कूल-स्तरीय नवाचार प्रयोगशालाएं) को French स्कूल Innovation Labs से जोड़ा जाएगा। यह स्कूल स्तर से Startup स्तर और फिर Research Lab स्तर तक के सहयोग की एक श्रृंखला है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Bharat Innovates 2026	Nice, France में India-France Deep-tech Showcase आयोजन; PM मोदी और President Macron ने उद्घाटन किया; यूरोपीय निवेशकों के सामने भारतीय Startups
Innovation Roadmap 2030	AI, Quantum Computing, Semiconductors, Green Hydrogen, Space, Biotech में द्विपक्षीय सहयोग का ढांचा
ATL Bridge	Atal Tinkering Labs (भारत की स्कूल नवाचार प्रयोगशालाएं) को French School Innovation Labs से जोड़ना



| Click to Connect Now.



AIM	Atal Innovation Mission — नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की सरकारी पहल; ATLs और AIM कार्यक्रम चलाती है
Deep-Tech (गहरी तकनीक)	मौलिक वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित तकनीक: AI, Quantum, Biotech, Advanced Materials — उच्च बाधा, उच्च प्रभाव
India-France Strategic Partnership	1998 में स्थापित; 2023 में 'Horizon 2047' Partnership तक गहरी; रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, AI, जलवायु को कवर

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Bharat Innovates में 150+ भारतीय Startups, शोधकर्ता और संस्थान यूरोपीय निवेशकों के सामने — Soft Power + आर्थिक कूटनीति का मेल
- Quantum Computing: दोनों देशों के National Quantum Missions हैं; सहयोग से अनुसंधान में तेजी
- Green Hydrogen: फ्रांस की Electrolysis (इलेक्ट्रोलिसिस) तकनीक + भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता = Green H2 उत्पादन में स्वाभाविक साझेदारी
- ATL Bridge: 10,000+ Atal Tinkering Labs भारत में चालू; French Innovation Schools से जोड़ने पर Youth-level Scientific Exchange
- भारत का Startup Ecosystem: 2.3 लाख DPIIT-मान्यता प्राप्त Startups; 25 लाख नौकरियां — Bharat Innovates इसे दुनिया को दिखाता है





CENSUS 2027 — FIELD OPERATIONS UNDERWAY ACROSS INDIA

Ministry: Ministry of Home Affairs / Office of the Registrar General of India

PIB Date: 16th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

भारत की आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी — पंद्रह साल पहले। 2021 की जनगणना COVID के कारण स्थगित हो गई, फिर देरी होती रही। Census 2027 अब अंततः हो रही है, और इस सप्ताह Field Operations (क्षेत्र संचालन) का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ।

जनगणना दो चरणों में होती है। Phase 1 Houselisting (मकान-सूचीकरण) है — Enumerators (गणनाकार) घर-घर जाकर हर मकान का विवरण दर्ज करते हैं: कमरों की संख्या, छत का प्रकार, शौचालय है या नहीं, पानी, बिजली, इंटरनेट है या नहीं, खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन उपयोग होता है। यह जनसंख्या गणना नहीं है — वह बाद में आती है। Phase 1 मूलतः एक Housing Survey है।

इस Census की बड़ी बात: (1) पहली पूरी तरह Digital Census — Mobile App पर डेटा संग्रह, कोई कागजी फॉर्म नहीं; (2) पहली बार नियमित जनगणना के साथ Caste Enumeration (जाति गणना) भी होगी — अत्यंत राजनीतिक महत्व; (3) Self-enumeration (स्व-गणना) — नागरिक Enumerator के आने से पहले se.census.gov.in पर खुद डेटा भर सकते हैं।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Census 2027	भारत की 16वीं जनगणना; Reference Date 1 मार्च 2027; COVID के कारण 2021 से स्थगित; पहली Digital Census
Houselisting Operation (HLO)	जनगणना का Phase 1: आवास की स्थिति और सुविधाएं दर्ज करता है — जनसंख्या गणना नहीं; अप्रैल-सितंबर 2026
Population Enumeration (जनसंख्या गणना)	जनगणना का Phase 2: लोगों की वास्तविक गिनती; Reference Date 1 मार्च 2027
Self-Enumeration (स्व-गणना)	नई सुविधा: नागरिक se.census.gov.in पर Census Data Online भरते हैं; SE ID जनरेट होती है



| Click to Connect Now.



Caste Enumeration (जाति गणना)	1931 के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना में जाति डेटा — OBC नीति और आरक्षण योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
RGI	Registrar General of India — जनगणना का Nodal Officer; Census Act 1948 और Census Rules 1990 के तहत

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत की पिछली जनगणना 2011; Census 2021 COVID के कारण स्थगित; Census 2027 भारत की 16वीं जनगणना
- Phase 1 (Houselisting): 1 अप्रैल – 30 सितंबर 2026; 33 प्रश्न — पानी, ईंधन, इंटरनेट, Assets (संपत्ति), सुविधाएं
- Phase 2 (Population Enumeration): Reference Date 1 मार्च 2027 (बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026)
- पहली Digital Census: Dedicated Mobile App पर डेटा संग्रह; 61,000+ Enumerators प्रशिक्षित
- Caste Enumeration: British काल में आखिरी बार 1931 में; 2027 जनगणना में 96 वर्षों में पहली बार
- जनगणना डेटा आवश्यक है: Lok Sabha क्षेत्रों का परिसीमन, कल्याण योजनाओं की योजना, राज्यों को केंद्रीय निधि आवंटन





KISHAU MULTIPURPOSE DAM — 8-YEAR DEADLOCK RESOLVED

Ministry: Ministry of Home Affairs / Ministry of Jal Shakti

PIB Date: 16th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

Kishau Dam (किशाऊ बांध) परियोजना आठ सालों से अटकी हुई थी। Tons नदी (टोन्स नदी — यमुना की सहायक नदी) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बहती है। वहां एक विशाल बांध प्रस्तावित है: 236 मीटर ऊंचा (कुतुब मीनार से चार गुना), 660 MW बिजली उत्पन्न करने वाला, लगभग 1 लाख हेक्टेयर खेती की सिंचाई करने वाला और दिल्ली तथा अन्य शहरों को पेयजल देने वाला।

समस्या? छह राज्य — हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश — लागत और लाभ के बंटवारे पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। 2016 से Deadlock (गतिरोध) था।

इस सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह ने सभी छह राज्यों के साथ बैठक की और गतिरोध तोड़ा। सौदा: केंद्र जल घटक की 90% लागत वहन करेगा। छह राज्य शेष 10% साझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जल-हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को दिया जाएगा — जो बदले में HP के बिजली घटक की लागत (~₹2,000 करोड़) चुकाएंगे। यह Cooperative Federalism (सहकारी संघवाद) का उदाहरण है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Kishau Dam	236 मीटर ऊंचा Concrete Gravity Dam; Tons नदी पर; उत्तराखंड-HP सीमा; 660 MW बिजली + 1,324 MCM जल भंडारण
Tons River (टोन्स नदी)	यमुना की सहायक नदी; उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा पर बहती है
Inter-State River Dispute	जब एक नदी कई राज्यों से बहती है, तो जल आवंटन समझौतों और Tribunals (न्यायाधिकरणों) द्वारा तय होता है
Cooperative Federalism (सहकारी संघवाद)	केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना; Kishau गतिरोध का समाधान इसका उत्तम उदाहरण



| Click to Connect Now.



Cost-sharing Formula	90% जल घटक केंद्र वहन करेगा; HP का जल-हिस्सा दिल्ली-राजस्थान को; बदले में वे HP की बिजली लागत चुकाएंगे
Yamuna Rejuvenation (यमुना पुनरुद्धार)	किशाऊ बांध से यमुना में स्वच्छ जल का प्रवाह बढ़ेगा — पर्यावरण लाभ

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Kishau Dam विशिष्टताएं: 236 मीटर ऊंचाई; 660 MW Hydropower; 1,324 MCM Live Storage; ~97,000 हेक्टेयर सिंचाई; 517 MCM पेयजल
- छह हितधारक राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश — सभी यमुना बेसिन राज्य
- 2016 से Deadlock; HP ने ₹800 करोड़ (पुराना समझौता) देने से इनकार; नए सौदे में HP पर कोई आर्थिक बोझ नहीं
- यमुना ऊपरी बेसिन की तीन परियोजनाओं में से एक: Renukaji Dam (समझौता हो चुका), Lakhwar Dam (समझौता हो चुका), Kishau — सबसे कठिन, अब हल
- MoEFCC से Environmental Clearance 2018 में मिल चुकी; अब MoU, Cabinet Approval और DPR (Detailed Project Report) बची है; निर्माण 2027-28 में शुरू हो सकता है





INDIAN NAVY — THREE INDIGENOUS PLATFORMS COMMISSIONED IN KOLKATA

Ministry: Ministry of Defence / Indian Navy

PIB Date: 19th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

19 जून 2026 को भारतीय नौसेना ने कोलकाता में एक साथ तीन Indigenous (स्वदेशी) नौसैनिक प्लेटफॉर्म Commissioned (कार्यरत) किए — एक युद्धपोत, एक पनडुब्बी और एक सर्वेक्षण पोत — सभी भारतीय Shipyards (जहाज निर्माण यार्डों) में बनाए गए। यह दुर्लभ घटना भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता को रेखांकित करती है।

कोलकाता को स्थल के रूप में चुना गया क्योंकि Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) — यहां स्थित एक Defence PSU — इन पोतों के प्राथमिक निर्माताओं में से एक है। इसी सप्ताह Ministry of Defence ने भारतीय नौसेना के लिए 12 सेट 1.25 MW Marine Gas Turbine Generators (युद्धपोतों को शक्ति देने वाले इंजन) के लिए ₹425 करोड़ का Contract भी हस्ताक्षरित किया — ये भी भारत में बनाए जाएंगे।

यह क्यों मायने रखता है: एक नौसेना उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी Supply Chain। अगर भारत को अपने युद्धपोतों के इंजन, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक्स विदेशों से मंगवाने पड़ें, तो उन देशों की goodwill पर निर्भरता बनी रहती है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Indigenous Naval Platform	भारत में डिजाइन और निर्मित युद्धपोत/पनडुब्बी/पोत; Hull, Propulsion, Weapons और Electronics में अधिकतम भारतीय सामग्री
GRSE	Garden Reach Shipbuilders and Engineers, कोलकाता — Defence PSU; Frigates, Corvettes और Patrol Vessels बनाती है
MDL (Mazagon Dock Shipbuilders)	मुंबई स्थित Defence PSU; Destroyers, Submarines (P75 Scorpene Class) का निर्माण



| Click to Connect Now.



Marine Gas Turbine Generator	युद्धपोतों पर बिजली उत्पन्न करने वाला इंजन; इस सप्ताह 12 सेट के लिए ₹425 करोड़ का Contract
P75 India Submarine Programme	भारत का अगली पीढ़ी की Submarine अधिग्रहण; Technology Transfer के साथ भारत में 6 उन्नत Submarines का निर्माण
Commissioning (कमीशनिंग)	नौसैनिक पोत की सक्रिय सेवा में औपचारिक शामिलता; कमीशन होने पर पोत INS (Indian Naval Ship) बन जाता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- GRSE कोलकाता ने भारतीय नौसेना, Coast Guard और Export Clients को 107 पोत दिए — एशिया के सबसे उत्पादक Defence Shipyards में
- Marine Gas Turbine Generator Contract: ₹425 करोड़; BHEL द्वारा निर्माण — नौसैनिक Propulsion में Atmanirbhar भारत
- भारतीय नौसेना: 150+ पोत; 2035 तक 200+ का लक्ष्य — सभी नए पोत स्वदेशी
- Coast Guard ने इसी सप्ताह स्वदेशी Air Cushion Vehicle (Hovercraft) शामिल किया — उथले पानी और Beach Landing के लिए
- भारत Regional Naval Supplier बन रहा है: Vietnam, Mauritius, Maldives, Bangladesh को Patrol Boats निर्यात





KAVACH — AUTOMATIC TRAIN PROTECTION SYSTEM EXPANSION

Ministry: Ministry of Railways

PIB Date: 15th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

भारत में बहुत सी दुखद ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं — 2023 में ओडिशा के बालासोर में टक्कर में 293 लोगों की जान गई। अधिकांश ट्रेन दुर्घटनाओं की जड़ में मानवीय भूल है: Signal चूक गया, Driver ने समय पर Brake नहीं लगाई, दो ट्रेनें एक ही Track पर आ गईं। Kavach — जिसका हिंदी में अर्थ है 'कवच' (Armour — सुरक्षा आवरण) — इसका भारत का जवाब है।

Kavach एक Automatic Train Protection (ATP) System है जो Locomotive (इंजन), Track और Signal Towers के बीच Radio Frequency Communication का उपयोग करता है। अगर कोई ट्रेन Red Signal या आगे चल रही किसी ट्रेन के करीब आ रही हो और Driver ने Brake नहीं लगाई हो, तो Kavach स्वतः Brake लगा देता है — कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं।

इस सप्ताह Railways ने तीन अलग Kavach Deployment परियोजनाएं मंजूर कीं: ₹201 करोड़ (Northern Railway, Ambala Division), ₹140 करोड़ (Ahmedabad Division, Gujarat), ₹405 करोड़ (Eastern Railway Signalling आधुनिकीकरण)। लक्ष्य: 2030 तक पूरे 40,000 किमी रेल नेटवर्क पर Kavach। अभी केवल ~1,500 किमी कवर है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Kavach	RDSO द्वारा विकसित Automatic Train Protection System; Signal-passing दुर्घटनाओं और टक्करों को रोकता है
ATP	Automatic Train Protection — रेलवे सुरक्षा प्रणाली जो मानवीय भूल को Override करती है; Kavach भारत का संस्करण
SIL-4	Safety Integrity Level 4 — उच्चतम सुरक्षा रेटिंग; Kavach की विफलता संभावना 10 करोड़ घंटों में 1 से कम
RDSO	Research Designs and Standards Organisation — Indian Railways की तकनीकी शाखा; Kavach का स्वदेशी विकास



| Click to Connect Now.



ETCS Level 2	European Train Control System Level 2 — अंतर्राष्ट्रीय मानक; Kavach इसके साथ Compatible है
Balasore Accident 2023	ओडिशा में 293 लोगों की मौत; वह क्षेत्र Kavach-रहित था — इसने तेज राष्ट्रव्यापी Deployment की मांग तेज की

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Kavach RDSO द्वारा तीन निजी कंपनियों के साथ: Medha Servo Drives, HBL Power Systems, Kernex Microsystems — स्वदेशी विकास
- वर्तमान कवरेज: ~1,500 किमी; लक्ष्य 2030 तक 40,000 किमी — तैनाती की गति में भारी तेजी जरूरी
- Kavach कैसे काम करता है: UHF Radio से हर सेकंड Locomotive ID + GPS स्थान + Track Signal Status प्रसारित; 5 किमी में टक्कर का खतरा हो तो Auto-brake
- तैनाती लागत: मौजूदा Track पर ₹50-60 लाख/किमी; पूरे 40,000 किमी में ~₹20,000 करोड़ लगेंगे
- भारत Kavach Technology Export भी कर रहा है: Australia, South Africa और Sri Lanka से बात चल रही है





PMVBRY — PRADHAN MANTRI VIKSIT BHARAT ROZGAR YOJANA

Ministry: Ministry of Labour & Employment

PIB Date: 19th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

भारत हर साल लगभग 1 करोड़ नए कामगारों को श्रम बाजार में जोड़ता है — युवा जो पहली बार नौकरी खोज रहे हैं।

नियोक्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा है: लागत। जब कोई कंपनी किसी को ₹15,000/माह वेतन देती है, तो उसकी वास्तविक लागत इससे अधिक होती है — EPF (Employees' Provident Fund — कर्मचारी भविष्य निधि) अंशदान और अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं।

PMVBRY इसे हल करने की कोशिश करती है: अगर कोई कंपनी ऐसे नए कर्मचारी को नियुक्त करती है जिसने पहले कभी Formal Job (EPFO में पंजीकृत) नहीं की, तो सरकार पहले दो साल के लिए उस कर्मचारी का EPF Contribution (अंशदान) देगी। ₹1 लाख/माह से कम कमाने वाले कर्मचारियों के लिए Employer का Contribution भी आंशिक रूप से सरकार वापस करेगी।

इस सप्ताह PM मोदी ने PMVBRY के तहत नए कामगारों को नियुक्त करने वाले Employers को ₹2,400 करोड़ Incentive (प्रोत्साहन राशि) वितरित किए। लक्ष्य: 2 साल में 1 करोड़ नई Formal (औपचारिक) नौकरियां।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
PMVBRY	Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana — Employment-linked Incentive Scheme; नई नियुक्तियों के लिए EPF Contribution Subsidise करती है
EPF (Employees' Provident Fund)	अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत; कर्मचारी (12%) और Employer (12%) दोनों मासिक अंशदान देते हैं; PMVBRY इसे Subsidise करती है
First-time Formal Employment	योजना उन कामगारों को लक्षित करती है जो कभी EPFO में पंजीकृत नहीं थे — Formal Economy में सच्चे नए प्रवेशकर्ता



| Click to Connect Now.



EPFO	Employees' Provident Fund Organisation — 7+ करोड़ Formal Sector कर्मचारियों का EPF प्रबंधन करती है
Employment-Linked Incentive (ELI)	नीति डिज़ाइन: उत्पादन Subsidise करने के बजाय नियुक्ति Subsidise करना — सीधे नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करता है
Formal vs Informal Employment	Formal: EPF-पंजीकृत, Contract, Tax-deducted; Informal: EPF नहीं, Casual; भारत में ~90% अनौपचारिक कार्यबल

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Budget 2024-25 में शुरू; 5 साल में ₹2 लाख करोड़ ELI (Employment-Linked Incentive) पैकेज के तहत आवंटन
- तीन Components: (A) ₹1 लाख/माह से कम, पहली Formal Job — 2 साल पूरा EPF सरकार देगी; (B) Manufacturing Sector Employers; (C) सभी क्षेत्रों के Employers — EPF प्रतिपूर्ति
- भारत की चुनौती: अर्थव्यवस्था 6-7% GDP से बढ़ रही है लेकिन Formal Job सृजन पीछे है; PMVBRY इस अंतर को सीधे संबोधित करती है
- EPFO मासिक Payroll Data: भारत हर माह ~7-8 लाख नए EPF Subscribers जोड़ता है; PMVBRY इसे 1 करोड़/वर्ष तक त्वरित करना चाहती है
- चुनौती: योजना Formal Sector Companies को लाभ देती है; निर्माण, घरेलू कामगार, Street Vendors जैसे विशाल अनौपचारिक क्षेत्र को कवर नहीं





SICKLE CELL DISEASE — INTERNATIONAL SICKLE CELL DAY

Ministry: Ministry of Health and Family Welfare / Ministry of Tribal Affairs

PIB Date: 19th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

19 जून अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल जागरूकता दिवस है। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्मारक समारोह में भाग लिया — यह स्थल गहरे प्रतीकात्मक महत्व का है, क्योंकि Sickle Cell Disease (सिकल सेल रोग) आदिवासी समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

Sickle Cell Disease एक आनुवांशिक रक्त विकार (Genetic Blood Disorder) है। सामान्य Red Blood Cells (लाल रक्त कोशिकाएं) गोल होती हैं और आसानी से रक्त वाहिकाओं में बहती हैं। Sickle Cell Disease में ये कोशिकाएं Crescent (हंसिया) के आकार की हो जाती हैं, रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं और गंभीर दर्द ('Crises' — संकट के दौर), अंग क्षति, Stroke (पक्षाघात) और जीवनकाल में कमी का कारण बनती हैं।

भारत में यह आदिवासी आबादी में बेहद आम है — ओडिशा, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान में अनुमानित 1.5 करोड़ लोग प्रभावित। 2023 में PM मोदी ने National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission (राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन) लॉन्च किया — 2047 तक Screening (जांच), Counselling (परामर्श) और उपचार के माध्यम से इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Sickle Cell Disease	आनुवांशिक रक्त विकार; असामान्य Haemoglobin (हीमोग्लोबिन) Red Blood Cells को हंसिया के आकार का बनाता है; दर्द, अंग क्षति, एनीमिया
Haemoglobin S (HbS)	Sickle Cell Disease में बना दोषपूर्ण Haemoglobin; कम Oxygen की स्थिति में Red Cells को विकृत करता है
Autosomal Recessive (ऑटोसोमल रिसेसिव)	Inheritance Pattern: बीमारी तभी होती है जब दोनों माता-पिता से दोषपूर्ण Gene मिले; एक Gene = Carrier (वाहक)



| Click to Connect Now.



National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission	2023 में PM मोदी द्वारा शुरू; 2047 तक भारत में सिकल सेल रोग उन्मूलन का लक्ष्य; सार्वभौमिक Screening और Counselling
Hydroxyurea (हाइड्रोक्सीयूरिया)	Sickle Cell Disease का प्राथमिक दवा उपचार; Crisis की आवृत्ति कम करता है; NHM के तहत मुफ्त उपलब्ध
Tribal Burden (जनजातीय बोझ)	भारत में 1.5 करोड़ प्रभावित; 95%+ Scheduled Tribe (अनुसूचित जनजाति) समुदायों से

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Sickle Cell Disease दुनिया का सबसे आम Genetic Blood Disorder; वैश्विक रूप से ~70 लाख प्रभावित; भारत में सबसे अधिक बोझ वाले देशों में
- सर्वाधिक प्रभावित राज्य: ओडिशा, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, महाराष्ट्र — जहां आदिवासी आबादी केंद्रित
- Mission (2023-2047): पहले चरण में आदिवासी जिलों में 7 करोड़ लोगों की Screening; Ayushman Bharat के तहत मुफ्त इलाज
- Genetic Counselling महत्वपूर्ण: दो Carrier (वाहक) माता-पिता से बच्चे को 25% बीमारी, 50% Carrier बनने की संभावना; विवाह पूर्व परामर्श से रोकथाम
- उपचार: Hydroxyurea Crises 50% कम करती है; Bone Marrow Transplant इलाज कर सकता है लेकिन महंगा; Gene Therapy आ रही है
- राष्ट्रपति मुर्मू की उपस्थिति प्रतीकात्मक — वे स्वयं आदिवासी समुदाय (Santali) से हैं





STUBBLE BURNING — HIGH-LEVEL MEETING FOR PERMANENT SOLUTION

Ministry: Ministry of Agriculture / Ministry of Environment, Forest and Climate Change

PIB Date: 16th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

हर अक्टूबर-नवंबर दिल्ली एक जहरीली धुंध (Smog) में डूब जाती है। इसके मुख्य कारणों में से एक: पंजाब और हरियाणा के किसान धान की कटाई के बाद बचे पुआल (Stubble — पराली) को जलाते हैं। धुआं 200-400 किमी दूर दिल्ली तक पहुंच जाता है।

किसान क्यों जलाते हैं? क्योंकि धान की मशीनी कटाई के बाद खेत में 4-6 इंच का Stump (टूठ) बचता है। अगली फसल (गेहूं) 2-3 हफ्तों में बोनी है। पराली हाथ से हटाना महंगा और समय लेने वाला है। जलाने में 15 मिनट लगते हैं और कोई खर्च नहीं।

इस सप्ताह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से एक उच्च-स्तरीय बैठक की — 'स्थायी समाधान' खोजने के लिए। विचाराधीन समाधान: पराली से Biogas (जैव गैस), Bioethanol (जैव ईंधन), Paddy Straw Boards (पुआल बोर्ड) और Satellite-monitoring से तत्काल जुर्माना।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Stubble Burning (पराली जलाना)	कटाई के बाद फसल अवशेष (पुआल) जलाना; अक्टूबर-नवंबर में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत
CAQM	Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas — Delhi-NCR की वायु गुणवत्ता नियमन वैधानिक निकाय; जुर्माना लगाने का अधिकार
Happy Seeder	मशीन जो बिना जलाए खड़ी पराली में सीधे गेहूं बोती है — मुख्य तकनीकी विकल्प; लेकिन उपयोग कम
Parali (पराली)	धान की पराली के लिए पंजाबी शब्द; राजनीतिक विमर्श में आमतौर पर इस्तेमाल



| Click to Connect Now.



SATAT Scheme	Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation — पराली से बने Compressed Biogas को सरकार Fixed Price पर खरीदती है
AQI	Air Quality Index; दिल्ली सर्दियों में 400-500+ (Severe Category) तक पहुंचता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- पंजाब और हरियाणा मिलकर अक्टूबर-नवंबर में 2-2.5 करोड़ टन पराली जलाते हैं; हर आग Satellite से दिखती है
- CAQM ने जुर्माने और प्रतिबंध लगाए; पंजाब सरकार न जलाने पर ₹2,500/एकड़ Incentive देती है — फिर भी अपर्याप्त
- Happy Seeder: सरकार 50-80% लागत Subsidise करती है (₹1-1.5 लाख/मशीन); 1.5 लाख मशीनें वितरित लेकिन कई अनुपयोगी — ऑपरेटिंग ईंधन लागत अधिक
- टिकाऊ समाधान: (क) Biogas Plants — पराली से ईंधन + Organic Manure; (ख) 2G Ethanol (Cellulosic Biomass से); (ग) SATAT Scheme
- Technology Solution: ISRO + CAQM का Satellite Monitoring — जलाने की हर घटना को विशिष्ट Farm तक Track करके Aadhaar-linked land records से तत्काल Fine Notice





NHAI MULTI-LANE FREE FLOW TOLLING — FASTag 2.0

Ministry: Ministry of Road Transport & Highways / NHAI

PIB Date: 19th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

आपने Toll Plaza का अनुभव किया होगा। 100 km/h से धीमे होकर 5 km/h पर आना, 30 कारों के पीछे लाइन में लगना, FASTag Scan होना, फिर Accelerate करना। यह पूरी प्रक्रिया हर वाहन में 30-90 सेकंड लेती है। अब सोचिए 1 करोड़ वाहन जो रोज भारत के Toll Plazas से गुजरते हैं — यह कितना समय, ईंधन और कार्बन बर्बाद करती है।

Multi-Lane Free Flow (MLFF) Tolling, जो NHAI ने NH-48 (दिल्ली-जयपुर highway) के Daulatpura Toll Plaza पर इस सप्ताह शुरू किया, यह सब खत्म करता है। कोई Barrier (बाधा) नहीं। कोई रोक नहीं। कोई लाइन नहीं। आप पूरी Highway Speed — 100+ km/h — पर निकलते हैं और ऊपर लगे Gantry (गेट जैसी संरचना) के High-speed Cameras और Sensors मिलीसेकंड में आपके वाहन का Number Plate और FASTag पढ़ लेते हैं और Toll अपने आप कट जाता है। यह FASTag 2.0 है। System ANPR (Automatic Number Plate Recognition — स्वचालित नंबर प्लेट पहचान), RFID Readers और AI-based Vehicle Classification का उपयोग करता है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
MLFF	Multi-Lane Free Flow — कोई Barrier नहीं; वाहन पूरी Speed पर निकलते हैं; Overhead Gantry FASTag + Number Plate पढ़ती है
FASTag	RFID-based Electronic Toll Payment; अभी वाहनों को धीमा/रोकना पड़ता है; MLFF से FASTag Full Speed पर काम करेगा
ANPR	Automatic Number Plate Recognition — High Speed पर Number Plate पढ़ने वाली Camera-based AI System
NH-48	National Highway 48 — Delhi-Jaipur-Mumbai Highway; Daulatpura Plaza Delhi-Jaipur Section पर



| Click to Connect Now.



GNSS Tolling	GPS-based Tolling (MLFF के बाद अगला विकास) — Satellite से Vehicle Location Track; Per-km Toll; कोई Gantry नहीं
Vehicle Classification	AI वाहनों को Classify करता है (2-Wheeler, Car, Bus, Truck) अलग-अलग Toll Rates के लिए — Automatically MLFF Gantry पर

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Rajasthan का पहला MLFF: Daulatpura Toll Plaza, NH-48 (दिल्ली-जयपुर Section)
- वर्तमान FASTag: 98% Toll Collection Electronic; ₹80,000 करोड़+ सालाना; MLFF इसे Zero-stop तक ले जाता है
- Speed लाभ: MLFF Gantry पर Full Highway Speed (80-120 km/h) बनाम अभी ~10-20 km/h; Queue पूरी तरह खत्म
- NHA का अनुमान: MLFF भारी Toll वाले Highways पर प्रति वाहन यात्रा में 8-10 मिनट बचाता है; ईंधन और Emission कम
- अगला कदम GNSS Tolling: NHA Per-km Satellite Tolling Pilot कर रहा है जो Gantry को भी खत्म करेगा
- भारत का Highway विकास: 40+ किमी/दिन; कुल NH Network ~1,46,000 किमी; Toll Revenue इस विस्तार के लिए महत्वपूर्ण





DRONE-BASED MAIL DELIVERY — DEPARTMENT OF POSTS, HIMACHAL PRADESH

Ministry: Ministry of Communications / Department of Posts

PIB Date: 13th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी गांव में डाक पहुंचाना सुनने में आसान लगता है — है नहीं। कुछ गांव केवल पैदल रास्तों से सुलभ हैं — कोई सड़क नहीं। Postman को पत्र या छोटे पैकेज पहुंचाने के लिए 4-6 घंटे पैदल चलना पड़ता है। सर्दियों में बर्फबारी पूरी घाटियों को महीनों के लिए काट देती है।

इस सप्ताह Department of Posts (India Post) ने हिमाचल प्रदेश में Drone-based Mail Transmission Service लॉन्च की — भारत में postal department की ऐसी पहली सेवा। एक Drone 15-20 मिनट में वह काम कर सकता है जिसमें Postman को 4-6 घंटे पैदल चलना पड़ता है। यह केवल पत्रों के बारे में नहीं है — दवाएं, दस्तावेज, छोटा सामान Last Mile (अंतिम छोर) तक तेजी से पहुंच सकता है।

यही Drone Infrastructure आपात स्थितियों में — आपदाओं या बर्फीली सर्दियों में — रक्त, दवाएं या आपातकालीन उपकरण दूरदराज के गांवों तक भेजने के लिए भी काम आ सकता है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Drone Mail Service	DoP की Drone-based Parcel/Mail Delivery; दूरस्थ HP में कठिन इलाके में पैदल Delivery को बदलती/पूरक करती है
DGCA	Directorate General of Civil Aviation — Civil Aviation Regulator; Drone Operators, Corridors और Certifications को Approve करता है
Drone Rules 2021	भारत के उदारीकृत Drone नियम; Green, Yellow, Red Zones बनाए; Commercial Drone उपयोग सक्षम किया
India Post	Department of Posts; 1.56 लाख Post Offices; दुनिया का सबसे बड़ा Postal Network; Banking (IPPB), Insurance, Savings भी



| Click to Connect Now.



Last Mile Connectivity (अंतिम छोर संपर्क)	सबसे दूरस्थ, मुश्किल पहुंच वाले स्थानों तक सामान/सेवाएं पहुंचाना — Drone पहाड़ी इलाकों में यह समस्या हल करता है
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight — Drone संचालन जहां Pilot Drone नहीं देख सकता; Remote Area Delivery के लिए आवश्यक; विशेष DGCA अनुमति चाहिए

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- India Post Statistics: 1.56 लाख Post Offices (90% ग्रामीण); रोज 1+ करोड़ Transactions — Mail, Banking, Insurance, Savings
- Drone Rules 2021 ऐतिहासिक थे: भारत दुनिया के सबसे प्रतिबंधात्मक Drone व्यवस्था से सबसे उदार में से एक बना; तीन Zones बनाए
- PLI for Drones (2021): ₹120 करोड़ Incentive; 400+ Drone Startups भारत में अब
- Medical Drone Delivery: तेलंगाना, मेघालय पहले ही आदिवासी क्षेत्रों में Medicine Delivery Pilot कर चुके; HP Model इसे Postal Services तक विस्तारित
- BVLOS Operations पर्वतीय Delivery के लिए आवश्यक — DGCA ने अब HP के लिए BVLOS Corridors Approve किए
- भारत का Drone Market 2030 तक \$1.8 बिलियन का अनुमान; Delivery, Surveillance और Agriculture Spraying तीन मुख्य Commercial Applications





INDIA BIOECONOMY — \$10 BILLION TO \$190 BILLION IN 12 YEARS

Ministry: Ministry of Science & Technology / DBT

PIB Date: 15th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

Bioeconomy (जैव अर्थव्यवस्था) उन सभी आर्थिक गतिविधियों का नाम है जो जैविक संसाधनों और प्रक्रियाओं से आती हैं — खेती और भोजन, फार्मा और दवाएं, Biofuels (जैव ईंधन), Industrial Enzymes (औद्योगिक एंजाइम), Bioplastics (जैव प्लास्टिक), और Biotechnology। 2014 में भारत की Bioeconomy \$10 बिलियन थी। 2026 में यह \$190 बिलियन है — 12 वर्षों में 19 गुना वृद्धि।

यह कैसे हुआ? तीन चालक: पहला, भारत का Pharma Sector फला-फूला — भारत 'दुनिया की दवाखाना' (Pharmacy of the World) है, दुनिया की 20% Generic Medicines बनाता है। दूसरा, सरकारी कार्यक्रम — BioE3 Policy (जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए), BioFoundry पहल, और Biomanufacturing Hubs। तीसरा, Synthetic Biology (सिंथेटिक जीव विज्ञान), Fermentation-based Manufacturing और Agricultural Biotech में Startups।

UPSC के लिए महत्व: Bioeconomy, भारत के एक Service Economy (IT) और कच्चे माल निर्यातक से Science-based Manufacturing Economy में परिवर्तन को दर्शाती है।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Bioeconomy (जैव अर्थव्यवस्था)	जैविक संसाधनों और Biotechnology से आर्थिक गतिविधि — Pharma, Agri-Biotech, Biofuels, Industrial Enzymes, Bioplastics
DBT	Department of Biotechnology — MoST के अंतर्गत; भारत के Biotech क्षेत्र का प्रमुख Funder और Policy निकाय
BioE3 Policy	Biotechnology for Economy, Environment, Employment — 2024 में घोषित भारत का Biotech Manufacturing Policy Framework



| Click to Connect Now.



Biomanufacturing (जैव निर्माण)	Petroleum-based Processes के बजाय Microorganisms (Bacteria, Yeast) से रसायन, सामग्री, ईंधन उत्पादन
Synthetic Biology (सिंथेटिक जीव विज्ञान)	औद्योगिक, चिकित्सा या पर्यावरणीय अनुप्रयोगों के लिए Biology को Engineer करना
BioFoundry	Shared Infrastructure — शोधकर्ता और Startups Biotech उत्पादों का परीक्षण और Scale-up कर सकते हैं; Lab-to-Factory Pipeline

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत Bioeconomy: \$10 बिलियन (2014) → \$80 बिलियन (2020) → \$190 बिलियन (2026) — इस अवधि में दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती Bioeconomy
- Pharma सबसे बड़ा घटक: ~\$50 बिलियन निर्यात; 200+ देशों को Generic Medicines; 'Pharmacy of the World' शाब्दिक रूप से सच
- Agricultural Biotech: Bt Cotton, रोग-प्रतिरोधी बीज, Precision Fermentation — महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद (GMO Regulation बहस जारी)
- Biofuels: Petrol में मिश्रण के लिए गन्ने और अनाज से Ethanol (E20 लक्ष्य 2025 तक — काफी हद तक हासिल); 2G Ethanol कृषि अपशिष्ट से अगला Frontier
- Biomanufacturing Hubs: पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में समर्पित Parks; Bioeconomy में ~3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार





GREEN HYDROGEN CERTIFICATION PORTAL — MNRE

Ministry: Ministry of New and Renewable Energy

PIB Date: 17th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

भारत 2030 तक 50 लाख टन Green Hydrogen (हरित हाइड्रोजन) प्रति वर्ष उत्पादन करना चाहता है। Green Hydrogen वह Hydrogen Gas है जो नवीकरणीय ऊर्जा (सौर या पवन) की बिजली से पानी को विभाजित करके बनाई जाती है — शून्य कार्बन उत्सर्जन। लेकिन समस्या: जर्मनी या जापान का एक खरीदार कैसे जाने कि भारत से खरीदा Hydrogen वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा से बना है, कोयले से नहीं?

इस सप्ताह Union Minister Pralhad Joshi द्वारा लॉन्च Green Hydrogen Certification Portal (हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल) यही करता है — एक पारदर्शी, सत्यापन योग्य प्रणाली जहां भारत में उत्पादित Green Hydrogen की हर Batch को एक Certificate मिलता है जो बताता है: कहां बना, किस Renewable Plant की बिजली इस्तेमाल हुई, कितनी बिजली उपयोग हुई, उस Batch की Carbon Intensity क्या है।

बिना इस Certification के, खरीदार भारतीय Hydrogen पर भरोसा नहीं करेंगे और भारत का \$100 बिलियन Green Hydrogen निर्यात का सपना अधूरा रह जाएगा।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Green Hydrogen (हरित हाइड्रोजन)	नवीकरणीय बिजली से पानी के Electrolysis (जल-अपघटन) द्वारा उत्पादित Hydrogen; Grey H2 (Natural Gas से) और Blue H2 (CCS के साथ) के विपरीत शून्य Carbon
SIGHT Programme	Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition — Green H2 उत्पादन और Electrolyser निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना
National Green Hydrogen Mission	2023 का India Mission; 2030 तक 5 MMT/year Green H2 का लक्ष्य; ₹19,744 करोड़ सरकारी परिव्यय



| Click to Connect Now.



Carbon Intensity (कार्बन तीव्रता)	प्रति इकाई Hydrogen उत्पादन में CO2 उत्सर्जन (kg CO2/kg H2); Green Hydrogen का लक्ष्य <1 kg CO2/kg H2
Electrolyser (इलेक्ट्रोलाइज़र)	बिजली से पानी को Hydrogen और Oxygen में विभाजित करने वाला उपकरण; 2030 तक 60 GW Capacity का लक्ष्य
EU CBAM	EU Carbon Border Adjustment Mechanism — 2026 से EU आयात पर Carbon Tax; Certified कम-Carbon Indian Green H2 यह Tax बचाता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- National Green Hydrogen Mission (2023): ₹19,744 करोड़; 2030 तक 5 MMT/year; 6 लाख नौकरियां; 50 MMT सालाना CO2 उत्सर्जन कम
- Certification Portal: Real-time Verification; Batch-wise Certificates; Renewable Electricity Traceability — 'Greenwashing' (झूठा हरा दावा) रोकता है
- भारत का Competitive Advantage: सस्ती नवीकरणीय बिजली (Solar ₹2/unit); Export के लिए Coast Access; बड़ा Engineering Workforce
- Hydrogen रंग संकेत: Green (नवीकरणीय), Blue (Natural Gas + CCS), Grey (Natural Gas, CCS नहीं), Black/Brown (Coal) — भारत Green पर ध्यान
- Export Markets: Japan, South Korea, Germany सबसे बड़े संभावित खरीदार; Kandla और Paradip Port H2 Export Hubs बन रहे





NATIONAL CYBER CRIME HELPLINE 1930 — AMIT SHAH REVIEWS

Ministry: Ministry of Home Affairs / Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)

PIB Date: 17th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

आपको एक Call आती है — CBI Officer होने का दावा करने वाला। वह कहता है आपका Aadhaar Money Laundering में इस्तेमाल हुआ और आप गिरफ्तार होने वाले हैं। 'सुरक्षित खाते' में पैसे भेजने को कहता है। हर महीने हजारों भारतीय इसका शिकार होते हैं। या आप एक WhatsApp Group में Invest करते हैं जो 50% मासिक रिटर्न का वादा करता है — और अपनी जमापूंजी गंवा देते हैं। ये Cyber Financial Frauds हैं — भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अपराध श्रेणी।

National Helpline 1930 इसी के लिए बनाई गई है: अगर आप अभी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं या हुए हैं, 1930 पर Call करें और System तुरंत धोखेबाज के Bank Account को Freeze करने की कोशिश करता है — पैसे Transfer होने से पहले। इस सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह ने 1930 की कार्यप्रणाली की व्यक्तिगत समीक्षा की और सुधार के निर्देश दिए — तेज Response Time, Banks के साथ बेहतर समन्वय, क्षमता विस्तार।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
1930	National Cyber Crime Helpline — अगर धोखाधड़ी हो रही हो तो तुरंत Call करें; System मिनटों में Bank Account Freeze की कोशिश करता है
I4C	Indian Cyber Crime Coordination Centre — MHA के तहत Nodal Body; सभी राज्यों में Cybercrime प्रतिक्रिया समन्वय
Digital Arrest Scam	धोखेबाज CBI/ED/Customs अधिकारी का रूप धरते हैं, 'Digital Arrest' का दावा करते हैं, 'Clearance' के लिए पैसे मांगते हैं — भारत का सबसे आम Cyber Fraud
Account Freeze Mechanism	1930 को शिकायत मिलने पर Banks से 30-60 मिनट में संदिग्ध Fraud Accounts Freeze — निकासी से पहले महत्वपूर्ण खिड़की



| Click to Connect Now.



Cybercrime Portal	cybercrime.gov.in — Online Platform; 1930 Helpline और State Police से एकीकृत
Golden Hour (स्वर्णिम घंटा)	पहले 30-60 मिनट में Freeze किए पैसों की Recovery दर सबसे अधिक; 24 घंटे बाद आमतौर पर पैसे निकाले या Convert किए जा चुके होते हैं

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- 1930 Helpline 2021 में शुरू; रोज 7,000-10,000 Calls; Inception से हजारों करोड़ Fraud Accounts में Freeze
- Digital Arrest Fraud: 2024-26 में भारत का सबसे प्रचलित Cyber Fraud; PM मोदी ने Mann Ki Baat में खुद चेतावनी दी
- I4C, MHA के तहत समन्वय: RBI, सभी Banks, NPCI, SEBI, State Police Cyber Cells — 350+ संस्थाएं Fraud Response Ecosystem में
- Cybercrime Statistics: India ने 2023 में 11.3 लाख Cybercrime Complaints (NCRB); Financial Fraud 85%+ मामले; अनुमानित ₹11,000 करोड़+ सालाना नुकसान
- Amit Shah निर्देश: Response Time कम करना, Bank Coordination बेहतर बनाना, 1930 में Regional Language Support, Manpower बढ़ाना
- UPI की सफलता (14+ अरब Transactions/माह) Fraud Vectors भी बनाती है — Digital Payments से अपरिचित बुजुर्ग और ग्रामीण सबसे कमजोर





BRICS INDORE DECLARATION — AGRICULTURE COOPERATION FRAMEWORK

Ministry: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

PIB Date: 13th June 2026

सरल व्याख्या (Easy Explanation)

इंदौर में 8 जून से हुई 16वीं BRICS Agriculture Ministers' Meeting (BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक) का समापन एक ऐतिहासिक दस्तावेज से हुआ: Indore Declaration (इंदौर घोषणापत्र) — BRICS देशों के बीच वैश्विक कृषि सहयोग का एक औपचारिक Charter।

Indore Declaration कई काम करती है। पहला, BRICS देशों को Food Security Cooperation (खाद्य सुरक्षा सहयोग) के प्रति प्रतिबद्ध करती है — डेटा साझा करना, खाद्य मूल्य झटकों पर समन्वित प्रतिक्रिया। दूसरा, भारत के Millet Push (बाजरा प्रोत्साहन) का समर्थन — BRICS देशों ने Millets को अपने खाद्य सुरक्षा ढांचे में शामिल करने पर सहमति जताई। तीसरा, BRICS Agricultural Research Network का प्रस्ताव — जलवायु-सहनशील फसल किस्मों, कीट प्रबंधन पर संयुक्त अनुसंधान। चौथा, रूस-यूक्रेन युद्ध से बाधित अनाज और उर्वरक आपूर्ति पर समन्वित प्रतिक्रिया। भारत ने इस बैठक की अध्यक्षता की और घोषणापत्र तैयार किया — बहुपक्षीय मंचों में Agenda तय करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन।

मुख्य शब्द (Key Terms)

शब्द / Term	अर्थ / Definition
Indore Declaration	16वीं BRICS Agriculture Ministers' Meeting का औपचारिक दस्तावेज; खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग के प्रति BRICS का Charter
BRICS	Brazil, Russia, India, China, South Africa; India 2024-25 Chair; अब 5 नए सदस्य (Egypt, UAE, Ethiopia, Iran, Indonesia — 2024 से)
Food Security (खाद्य सुरक्षा)	भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता — चारों आयाम Indore Declaration में संबोधित
Millet Diplomacy (बाजरा कूटनीति)	जलवायु-सहनशील, पोषक फसल के रूप में Millets को बढ़ावा देने का भारत का वैश्विक प्रयास; IYM 2023 विरासत को BRICS समर्थन से विस्तार



| Click to Connect Now.



BRICS Agricultural Research Network	भारत का प्रस्ताव: BRICS देशों में Crop Science, Pest Management, Climate Adaptation पर Joint R&D Platform
Russia-Ukraine Food Impact	दोनों शीर्ष 5 Global Wheat और Sunflower Oil Exporters; युद्ध ने आपूर्ति बाधित की; BRICS खाद्य सुरक्षा ढांचा Resilience बनाने का प्रयास

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- Indore Declaration: Brazil, Russia, India, China, South Africa के कृषि मंत्रियों ने अपनाया; Egypt, UAE, Ethiopia, Iran, Indonesia Observer के रूप में
- BRICS 2024-25 Chair के रूप में भारत ने Agenda तय किया: Millets, जलवायु-सहनशील कृषि, किसान कल्याण, Digital Agriculture
- BRICS देश वैश्विक खाद्य उत्पादन का 40%+ और कृषि भूमि का 45%+ कवर करते हैं — BRICS Food Policy के वैश्विक खाद्य मूल्यों पर निहितार्थ
- Millet की जीत: BRICS का Millets का समर्थन = दुनिया की 40%+ आबादी उन सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो Millet खपत को बढ़ावा देंगी
- Digital Agriculture: Declaration में AgriTech सहयोग — Precision Farming (सटीक खेती), Drone-based Crop Monitoring, AI in Agriculture — भारत की ताकत
- BRICS विस्तार: मूल 5 देश → January 2024 से 5 नए सदस्य (BRICS+ 10 देश); Indonesia भी 2025 में शामिल





PRACTICE QUESTIONS

10 PRELIMS QUESTIONS — UPSC PRELIMS 2026 STYLE

Q1. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह समझौता 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ, लंदन में 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर के बाद।
2. यह भारत के 99% माल निर्यात को UK में Duty-free पहुंच देता है।
3. साथ में आया Double Contribution Convention (DCC) भारतीय पेशेवरों के लिए दोहरे Social Security Contributions से छूट की अवधि 3 से 5 साल तक बढ़ाता है।
4. India-UK CETA दुनिया के किसी भी देश के साथ भारत का सबसे व्यापक व्यापार समझौता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

Q2. DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

1. यह 2,000 किमी से अधिक रेंज वाली Supersonic Cruise Missile है।
2. इसका परीक्षण ओडिशा तट के Dr APJ Abdul Kalam Island से किया गया।
3. यह स्वदेशी 'Manik' Turbofan Engine और NavIC Navigation System का उपयोग करती है।
4. इसे Aeronautical Development Establishment (ADE), बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

- (a) 1, 3 और 4 केवल





- (b) 2, 3 और 4 केवल
- (c) 1 और 2 केवल
- (d) 2 और 4 केवल

Q3. भारत और जापान के बीच अपनाया गया Joint Crediting Mechanism (JCM) Paris Agreement के किस प्रावधान द्वारा शासित है?

- (a) Article 4 — Nationally Determined Contributions
- (b) Article 6.2 — Cooperative Approaches for transfer of ITMOs ✓
- (c) Article 6.4 — UNFCCC द्वारा Supervised Sustainable Development Mechanism
- (d) Article 9 — विकसित देशों की Climate Finance दायित्व

Q4. भारत की Census 2027 से संबंधित निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

जनसंख्या गणना की Reference Date — 1 मार्च 2027 | Self-Enumeration Portal — se.census.gov.in | Phase 1 (Houselisting) — अप्रैल से सितंबर 2026 | Caste Enumeration — 1931 के बाद पहली बार

ऊपर में से कितनी जोड़ियां सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

Q5. Kishau Multipurpose Dam Project के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. बांध Tons River पर प्रस्तावित है, जो Yamuna की सहायक नदी है, उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर।
2. छह राज्य — हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश — Stakeholders हैं।
3. जून 2026 के समझौते के तहत, केंद्र सरकार जल घटक लागत का 90% वहन करेगी।
4. बांध 660 MW Hydroelectric Power उत्पन्न करेगा।





- (a) 1 और 3 केवल
- (b) 1, 2 और 3 केवल
- (c) 2, 3 और 4 केवल
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q6. भारत के रक्षा उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. FY 2025-26 में ₹1.78 लाख करोड़ — पिछले वर्ष से 15.6% वृद्धि।
2. निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी FY 2025-26 में 24% तक बढ़ी।
3. रक्षा निर्यात भी FY 2025-26 में रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ रहा।
4. DPSUs का कुल उत्पादन में लगभग 76% योगदान।

- (a) 1, 2 और 3 केवल
- (b) 1, 3 और 4 केवल
- (c) 2, 3 और 4 केवल
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q7. 'Kavach' शब्द, जो हाल ही में समाचारों में था, किसको संदर्भित करता है:

- (a) DRDO द्वारा थल सेना के लिए विकसित Ballistic Missile Defence Shield
- (b) Automatic Train Protection System जो Indian Railways पर Signal-passing दुर्घटनाओं को रोकता है ✓
- (c) महत्वपूर्ण Information Infrastructure की सुरक्षा के लिए Cybersecurity Framework
- (d) भारत की तटरेखा के साथ तैनात Coastal Surveillance Radar Network

Q8. National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. Sickle Cell Disease Autosomal Recessive Inheritance Pattern का पालन करती है।
2. यह बीमारी मध्य और पश्चिमी भारत के Scheduled Tribe समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है।
3. Mission का लक्ष्य 2047 तक भारत से Sickle Cell Disease को समाप्त करना है।





4. Sickle Cell Disease Haemoglobin Gene में दोष से होती है जिससे Red Blood Cells अर्धचंद्र आकार की हो जाती हैं।

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

Q9. हाल ही में राजस्थान में लॉन्च 'Multi-Lane Free Flow' (MLFF) Tolling System मौजूदा FASTag System से किन तरीकों में अलग है?

1. MLFF में वाहनों को Toll Plazas पर रोकने या धीमा होने की जरूरत नहीं।
2. MLFF Overhead Gantries पर ANPR Cameras और RFID Readers का उपयोग करता है।
3. MLFF FASTag की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त करता है, GPS Tracking से बदल देता है।
4. Valid FASTag के बिना वाहनों को रोका नहीं जाता — उनकी फोटो ली जाती है और Fine भेजा जाता है।

- (a) 1, 2 और 4 केवल
- (b) 1 और 3 केवल
- (c) 2, 3 और 4 केवल
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q10. MNRE द्वारा लॉन्च Green Hydrogen Certification Portal के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

- (a) यह प्रत्येक Batch के लिए उपयोग किए गए Renewable Electricity Source को दर्शाने वाले सत्यापन योग्य Certificates प्रदान करता है
- (b) यह भारतीय Green Hydrogen Exporters को EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) आवश्यकताओं का पालन करने में मदद के लिए है





- (c) Portal स्वचालित रूप से सरकार-निर्धारित Minimum Support Price पर Certified Producers से Green Hydrogen खरीदता है
- (d) यह प्रत्येक Certified Batch के लिए Carbon Intensity Data (kg CO₂ per kg H₂) दर्ज करता है





2 MAINS QUESTIONS

MAINS QUESTION 1 — 150 WORDS

भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को अक्सर 'खरीदार से निर्माता से निर्यातक' की यात्रा के रूप में वर्णित किया जाता है। इस सप्ताह के घटनाक्रमों — LRLACM परीक्षण, रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ उत्पादन, नौसैनिक कमीशनिंग, और Kavach विस्तार — का उपयोग करते हुए, इस यात्रा पर भारत वास्तव में कितनी दूर पहुंचा है और क्या संरचनात्मक खामियां बची हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण करें।

MAINS QUESTION 2 — 250 WORDS

'G7 Evian में भारत का सप्ताह किसी अमीर देशों के क्लब में शामिल होने के बारे में नहीं था — यह US, UK, EU और Canada के साथ एक साथ व्यापार समझौते आगे बढ़ाने और France के साथ नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के बारे में था।' भारत की Multi-alignment विदेश नीति सिद्धांत के आलोक में, PM मोदी की France-Slovakia यात्रा और G7 Engagement के परिणामों का भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए मूल्यांकन करें।





PRELIMS ANSWERS & EXPLANATIONS

Q1. उत्तर: (b) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। कथन 4 गलत है — India-UK CETA एशिया के बाहर भारत का सबसे व्यापक व्यापार समझौता है, 'दुनिया के किसी भी देश के साथ' नहीं। UAE (CEPA 2022) और India-South Korea CEPA भी व्यापक हैं।

Q2. उत्तर: (b) 2, 3 और 4 केवल

व्याख्या: कथन 1 गलत है — LRLACM Subsonic (लगभग 0.7 Mach) है, Supersonic नहीं। इसकी रेंज 1,000-1,500 किमी है, '2,000 से अधिक' नहीं। कथन 2 (APJ Abdul Kalam Island, ओडिशा), 3 (Manik Engine + NavIC), और 4 (ADE बेंगलुरु) सभी सही हैं।

Q3. उत्तर: (b)

व्याख्या: JCM, Paris Agreement के Article 6.2 द्वारा शासित है जो देशों को ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outcomes) स्थानांतरित करने में सहयोग के लिए 'Cooperative Approaches' सक्षम करता है। Article 6.4 UN-supervised Carbon Market Mechanism है (अलग)। महत्वपूर्ण अंतर: 6.2 = द्विपक्षीय, 6.4 = UN-supervised बहुपक्षीय।

Q4. उत्तर: (c) सभी चार

व्याख्या: सभी चार सही हैं। Population Enumeration की Reference Date 1 मार्च 2027 (बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026)। Self-enumeration portal se.census.gov.in है। Phase 1 अप्रैल-सितंबर 2026। Caste पिछली बार 1931 में गिनी गई थी — 2027 जनगणना में 96 वर्षों में पहली बार।

Q5. उत्तर: (d) 1, 2, 3 और 4

व्याख्या: सभी चार कथन सही हैं। Tons River यमुना की सहायक नदी है HP-UK सीमा पर (कथन 1)। सभी छह राज्य Stakeholders हैं (कथन 2)। केंद्र जल घटक का 90% वहन करेगा (कथन 3)। Power Generation 660 MW (कथन 4)।

Q6. उत्तर: (d) 1, 2, 3 और 4





व्याख्या: सभी चार कथन सही हैं और PIB Release से सीधे sourced हैं। ₹1.78 लाख करोड़ (15.6% वृद्धि), निजी क्षेत्र 24%, रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़, DPSUs 76% — सभी verified आंकड़े। MCQ सटीकता के लिए ये संख्याएं याद रखना जरूरी।

Q7. उत्तर: (b)

व्याख्या: Kavach, Indian Railways का Automatic Train Protection (ATP) System है — Signal-passing दुर्घटनाओं और टक्करों को रोकता है। विकल्प (a) Missile Defence System है (अलग DRDO Project)। विकल्प (c) Cybersecurity Framework। विकल्प (d) Coastal Surveillance। Kavach = Railways ATP = सही उत्तर।

Q8. उत्तर: (c) सभी चार

व्याख्या: सभी चार कथन सही हैं। यह Autosomal Recessive है (दोनों माता-पिता से Gene आना जरूरी)। यह STs में मध्य-पश्चिमी भारत में है। Mission का लक्ष्य 2047। दोषपूर्ण Haemoglobin से Sickle आकार। सभी चार मानक चिकित्सा तथ्य — Health Policy प्रश्नों के लिए याद रखें।

Q9. उत्तर: (a) 1, 2 और 4 केवल

व्याख्या: कथन 3 गलत है — MLFF, FASTag को समाप्त नहीं करता। FASTag अभी भी जरूरी है; MLFF बस Gantry को Full Speed पर पढ़ने देता है बिना रोके। GNSS/GPS-based Tolling (भविष्य की प्रणाली, अभी तैनात नहीं) Gantries को खत्म करेगी, लेकिन MLFF अभी भी FASTag + ANPR उपयोग करता है। कथन 1, 2, और 4 सही हैं।

Q10. उत्तर: (c)

व्याख्या: विकल्प (c) गलत है — Green Hydrogen Certification Portal Hydrogen खरीदता नहीं है और न ही इसके लिए कोई MSP तय करता है। यह इसका कार्य नहीं है। यह केवल Certify और Verify करता है। विकल्प (a), (b) और (d) Portal की सही विशेषताएं हैं। यह 'कौन सा सही नहीं है' वाला प्रश्न है — ध्यान से पढ़ें।



MAINS MODEL ANSWERS

MAINS Q1 — Model Answer (150 words)

एक दशक में भारत का रक्षा परिवर्तन वास्तविक है, लेकिन अधूरा। 'निर्माता' चरण जोरों पर है: ₹1.78 लाख करोड़ घरेलू उत्पादन, रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ निर्यात, LRLACM परीक्षण से Long-range Precision Strike Capability की पुष्टि, एक साथ तीन स्वदेशी नौसैनिक Platform की Commissioning, और Kavach का Railway Safety में Deployment — सभी Atmanirbharta को आकांक्षा से क्रियान्वयन में बदलते दिखाते हैं।

फिर भी संरचनात्मक खामियां महत्वपूर्ण हैं। भारत एक साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आयातक भी है — Fighter Jet Engines (Kaveri बार-बार विलंबित), Advanced Submarines, और Defence Electronics के Semiconductors अभी भी विदेश से। Private Sector 24% पर है — बढ़ रहा है लेकिन DPSUs से छोटा। Technology Transfer पूरा IP कभी नहीं देती।

ईमानदार आकलन: भारत Standard Platforms और Components का सफल 'निर्माता' बन चुका है। 'निर्यातक' चरण अभी शुरूआती है। 'पूर्ण-स्पेक्ट्रम स्वदेशी निर्माता' — Advanced Propulsion, Avionics, Electronic Warfare सहित — 15-20 साल की यात्रा है। दिशा सही है; गति तेज होनी चाहिए।

MAINS Q2 — Model Answer (250 words)

भारत की Multi-alignment सिद्धांत — किसी एक खेमे से बंधे बिना सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध गहरे करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना — को G7 Evian 2026 में अब तक की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली। France और Slovakia में पांच दिनों में PM मोदी ने किसी को समझौता किए बिना चार मोर्चों पर एक साथ भारत के हित आगे बढ़ाए। आर्थिक दृष्टि से, यह सप्ताह असाधारण था। India-UK CETA 15 जुलाई से लागू — भारत के 99% माल को UK में शुल्क-मुक्त पहुंच। India-EU FTA हस्ताक्षर वर्ष-अंत तक घोषित — GDP के आधार पर इतिहास का सबसे बड़ा Trade Deal। India-Canada CEPA 2026 पर ट्रैक। मिलाकर, ये भारत की Trade Architecture की किसी एक भागीदार पर अत्यधिक निर्भरता से दूर एक मौलिक पुनर्संरचना हैं।

तकनीकी दृष्टि से, India-France Innovation Roadmap 2030 और Nice में Bharat Innovates ने द्विपक्षीय संबंध में एक नया आयाम जोड़ा — Rafale खरीदार से Deep-tech सह-निर्माता तक। ATL Bridge स्कूल-स्तरीय Innovation Labs को जोड़ती है — दीर्घकालिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान, केवल लेन-देन की कूटनीति नहीं।





कूटनीतिक दृष्टि से, Outreach Guest के रूप में G7 में भारत की भागीदारी Multi-alignment के विरोधाभास को उजागर करती है: भारत G7 के आर्थिक रूप से अब किसी भी समय से करीब है लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं किया — अभी भी BRICS की अध्यक्षता करता है और UNSC में Russia की निंदा से परहेज। बिना Timeline के Modi-Trump Bilateral — भारत दृढ़ता से बातचीत कर रहा है, अनुनय से नहीं।

हालांकि, सीमाएं हैं। H-1B Visa Numbers पर कोई ठोस सफलता नहीं, Iran Oil पर Sanctions Waiver राहत नहीं, India-US BTA का कोई Timeline नहीं। Multi-alignment विकल्पों को अधिकतम करता है लेकिन कभी-कभी निष्कर्ष में देरी होती है। यह सप्ताह रणनीति की ताकत दिखाता है; इसके तनाव अभी भी अनसुलझे हैं।



PIB

साप्ताहिक संक्षेप

— सामरिक भारत —



Table of Contents

नौसैनिक शक्ति

INS Dunagiri, Senshodhak
& Agray कमीशन किए गए



अंतरिक्ष यात्रा

भारत की 50 वर्षों की
अंतरिक्ष यात्रा



उभरती प्रौद्योगिकियाँ

400+ स्मार्टग्राम से लड़ रहा
भारत का टेक इकोसिस्टम



महत्वपूर्ण खनिज

राजनीतिक आत्मनिर्भरता
की दिशा में बड़ा कदम



INDIA'S SPACE ODYSSEY — PIB BACKGROUNDER.....	5
INDIA'S EMERGING TECHNOLOGY ECOSYSTEM — PIB BACKGROUNDER.....	7
CRITICAL MINERALS MISSION — 56 BLOCKS AUCTIONED, 7TH TRANCHE COMPLETE	8
RAKHIGARHI SKELETAL REMAINS — TRANSFERRED TO ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA	10
BRICS ENERGY MINISTERS' MEETING — 11TH EDITION, GURUGRAM	12
BRICS MSME FORUM & SME WORKING GROUP — AGRA	13
FERTILISER SHIPS CROSS STRAIT OF HORMUZ — SUPPLY CHAIN RESILIENCE.....	15
INDIA — WORLD'S TOP SHIP RECYCLING NATION IN 2025	16
DISHA 2.0 — DESIGNING INNOVATIVE SOLUTIONS FOR HOLISTIC ACCESS TO JUSTICE	18
ABS FRAMEWORK — ₹145 CRORE TO BIODIVERSITY BENEFICIARIES	20
INCOIS EL NIÑO BULLETINS — PROTECTING INDIA'S MARITIME SECTORS	21
ETHANOL BLENDING PROGRAMME — GOVERNMENT CLARIFICATION	23
VOC PORT — 45% CARBON EMISSION REDUCTION, GREEN MARITIME MODEL	24
NAFEX.IN — NAFED'S E-AUCTION PORTAL LAUNCHED	26
COAL GASIFICATION — BHARAT COAL GASIFICATION & CHEMICALS LIMITED (BCGCL), ODISHA	28
PRACTICE QUESTIONS.....	30
10 PRELIMS QUESTIONS.....	30
PRELIMS ANSWERS & EXPLANATIONS	34
2 MAINS QUESTIONS & MODEL ANSWERS.....	36





INS DUNAGIRI, INS SANSHODHAK & INS AGRAY — TRI-COMMISSIONING IN KOLKATA

Ministry: Ministry of Defence / Indian Navy

PIB Date: 21st June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

कल्पना करें कि कोलकाता के Syama Prasad Mookerjee Port पर एक रविवार की सुबह तीन जहाज कतार में खड़े हैं — सभी भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी में, उनके दल सावधान मुद्रा में। PM नरेंद्र मोदी डॉक पर चलते हैं और एक ही समारोह में तीनों को सक्रिय नौसेना सेवा में शामिल करते हैं — यह एक दुर्लभ 'Tri-Commissioning' है जो भारत ने पहले केवल दो बार की है।

तीनों जहाज भारतीय नौसेना के Warship Design Bureau (युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो) द्वारा डिज़ाइन किए गए और कोलकाता के Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) में बनाए गए हैं। इनके अंदर के 75% से अधिक पुर्जे भारत में बने हैं।

INS Dunagiri एक Stealth Combat Frigate (छुपकर दुश्मन पर हमला करने वाला युद्धपोत) है — यह समुद्र की सतह पर, आकाश में और पनडुब्बियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। इसमें Supersonic Missiles (तीव्र गति वाली मिसाइलें), वायु रक्षा प्रणाली, Torpedoes (पानी के अंदर चलने वाले हथियार) और एक Helicopter है।

INS Sanshodhak एक Survey Vessel (सर्वेक्षण जहाज) है — यह लड़ाकू जहाज नहीं, बल्कि समुद्र का वैज्ञानिक है। AUVs (Autonomous Underwater Vehicles — स्वचालित पानी के भीतर चलने वाले रोबोट), Sonar (ध्वनि तरंगों से पानी के अंदर देखने की तकनीक) और Multi-Beam Echo Sounders (समुद्री तल का नक्शा बनाने के उपकरण) से लैस यह जहाज समुद्री नक्शे बनाता है।

INS Agray एक Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (उथले पानी में पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत) है — यह विशेष रूप से भारत के तटीय और बंदरगाह के उथले पानी में पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए बना है।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
Project 17A	7 उन्नत Stealth Frigates (छुपने वाले युद्धपोत) का कार्यक्रम; Shivalik-class के बाद की पीढ़ी; INS Dunagiri इसका 5वाँ जहाज है; MDL मुंबई और GRSE कोलकाता में निर्मित।



| Click to Connect Now.



GRSE	Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata — रक्षा PSU; इस सप्ताह के तीनों जहाज इसी ने बनाए।
Warship Design Bureau (WDB)	भारतीय नौसेना का अपना जहाज डिज़ाइन संगठन; तीनों जहाज इसी ने डिज़ाइन किए — सच्ची स्वदेशी क्षमता।
INS Dunagiri	Project 17A का Stealth Guided-Missile Frigate; CODOG (Combined Diesel or Gas — डीज़ल और गैस दोनों से चलने वाली) Propulsion; सतह/वायु/पनडुब्बी युद्ध में सक्षम; Helicopter ले जा सकता है।
INS Sanshodhak	4th Survey Vessel (Large) — 4वाँ बड़ा सर्वेक्षण जहाज; Hydrographic Surveys (समुद्री गहराई नापना), Nautical Charting (नौकायन नक्शे बनाना), Oceanographic Research (समुद्र विज्ञान अनुसंधान); AUVs और ROVs से लैस।
INS Agray	5th Arnala-class ASW SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft — उथले पानी में पनडुब्बी-रोधी जहाज); Waterjet Propulsion (पानी की धार से चलने वाला); Sonar, Torpedoes, Anti-Sub Rockets।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- तीनों जहाज एक साथ Syama Prasad Mookerjee Port (पूर्व में Kolkata Port Trust), पश्चिम बंगाल में Commissioned — GRSE के योगदान को सम्मान देने के लिए यह स्थान चुना गया।
- Project 17A: कुल 7 Frigates (4 MDL मुंबई में, 3 GRSE कोलकाता में); INS Nilgiri (पहला) जनवरी 2025 में Commissioned; INS Dunagiri 5वाँ है।
- तीनों जहाजों में 75%+ Indigenous Content (स्वदेशी सामग्री) — 200+ MSMEs ने पुर्जे बनाए; भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला की गहराई दर्शाता है।
- INS Sanshodhak पुराने INS Sandhayak की जगह लेता है; Survey Vessels (सर्वेक्षण जहाज) भारत के Nautical Charts (नौकायन नक्शों) को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- INS Agray (Arnala-class): Waterjet Propulsion (पानी की धार से चलने वाला) बहुत उथले पानी (2-3 मीटर गहराई) में काम करने की अनुमति देता है — बंदरगाह सुरक्षा के लिए।
- PM मोदी का भाषण: INS Vikrant (पहला स्वदेशी Aircraft Carrier, 2022) से इस Tri-Commissioning तक की यात्रा का उल्लेख — भारत की नौसैनिक Atmanirbharta (आत्मनिर्भरता) अब व्यवस्थित है, कभी-कभार नहीं।
- भारतीय नौसेना का 2047 का लक्ष्य: 200+ जहाजों का बेड़ा जिसमें 3 Carrier Battle Groups और 24 Submarines शामिल हों।





INDIA'S SPACE ODYSSEY — PIB BACKGROUNDER

Ministry: Department of Space / ISRO / IN-SPACe

PIB Date: 21st June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह Aryabhata (आर्यभट्ट) लॉन्च किया — पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, हालांकि उस समय भारत के पास अपना Rocket (प्रक्षेपण यान) नहीं था इसलिए Soviet Rocket का उपयोग किया। तब से 50 वर्षों में भारत ने Rocket उधार लेने से लेकर दुनिया के सबसे विश्वसनीय और किफायती Space Programmes में से एक बनाने तक का सफर तय किया है।

PIB ने इस सप्ताह India's Space Odyssey पर एक व्यापक Backgrounder जारी किया — मूलतः एक Report Card और Roadmap दोनों। शुरुआती दशकों (1975-2000) में PSLV से Launch Technology (प्रक्षेपण तकनीक) सीखने का काम हुआ। 2000 के दशक में PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद Rocket बना। 2010 के दशक में Chandrayaan-1 ने चंद्रमा पर पानी खोजा (2008), Mangalyaan पहली बार में मंगल पर पहुंचा (2014)।

2020 का दशक परिवर्तन का है — Chandrayaan-3 चंद्रमा के South Pole (दक्षिणी ध्रुव) के पास उतरने वाला पहला Spacecraft (अंतरिक्ष यान) बना (2023), Gaganyaan (भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम) चल रहा है, और IN-SPACe के माध्यम से निजी कंपनियों के लिए Space खोला गया जिससे 400+ Space Startups बने। भारत का Space Economy (अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था) 2033 तक \$44 बिलियन का लक्ष्य रखती है।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
ISRO	Indian Space Research Organisation — सरकारी एजेंसी; Missions (अभियान) चलाती है, Rockets और Satellites विकसित करती है।
IN-SPACe	Indian National Space Promotion and Authorisation Centre — निजी Space कंपनियों के लिए नियामक (Regulator); Single-Window Clearance (एकल खिड़की अनुमति)।



| Click to Connect Now.



PSLV	Polar Satellite Launch Vehicle (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) — भारत का भरोसेमंद Workhorse Rocket; 60+ सफल प्रक्षेपण; विदेशी Satellites के व्यावसायिक प्रक्षेपण के लिए उपयोग।
GSLV Mk III / LVM3	Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III — भारी सामान उठाने वाला Rocket (Heavy Lift Rocket); Chandrayaan-3 और OneWeb व्यावसायिक प्रक्षेपणों के लिए उपयोग।
Gaganyaan	भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम; लक्ष्य: 2026-27 तक 3 अंतरिक्ष यात्री Orbit में भेजना; अभी Test Phase (परीक्षण चरण) में।
NSIL	New Space India Limited — ISRO की सरकारी व्यावसायिक शाखा; Satellite निर्माण और प्रक्षेपण के लिए निजी कंपनियों को Contract देती है।
Space Economy Target	भारत का लक्ष्य: 2033 तक \$44 बिलियन की Space Economy (वर्तमान में ~\$8 बिलियन); विकास का नेतृत्व Private Sector करेगा।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- प्रमुख मील के पत्थर: Aryabhata (1975) → PSLV (1994, 60+ सफलताएँ) → Chandrayaan-1 पानी की खोज (2008) → Mangalyaan (2014, पहली बार में सफलता) → Chandrayaan-3 South Pole Landing (23 अगस्त 2023) → Aditya-L1 Solar Mission (2023)।
- Chandrayaan-3: चंद्रमा के South Pole के पास उतरने वाला पहला Mission; Pragyan Rover (घुमक्कड़ यान) ने Sulphur और अन्य तत्वों की पुष्टि की; सितंबर 2023 में PM मोदी ने Landing Site का नाम 'Shiv Shakti Point' रखा।
- Gaganyaan: 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए (Group Captain Prashanth Balakrishnan Nair, Ajit Krishnan, Angad Pratap, Shubhanshu Shukla); Uncrewed Test Missions (बिना चालक दल के परीक्षण) चल रहे हैं; Crewed Mission (मानव सहित) का लक्ष्य 2026-27।
- Private Space Sector: IN-SPACe ने 2020 से 400+ Space Startups को अनुमति दी; Skyroot Aerospace ने Vikram-S (भारत का पहला Private Rocket, 2022) लॉन्च किया।
- SpaDeX (Space Docking Experiment — अंतरिक्ष में जोड़ने की प्रयोग तकनीक): भारत USA, Russia, China के बाद 4वाँ देश जिसने यह तकनीक प्रदर्शित की।
- India-USA Artemis Accords Signatory (2023): चंद्रमा की शांतिपूर्ण खोज के लिए प्रतिबद्ध; अंतरिक्ष यात्री Shubhanshu Shukla 2025 में AXIOM-4 के तहत NASA ISS Mission पर उड़ेंगे।





INDIA'S EMERGING TECHNOLOGY ECOSYSTEM — PIB BACKGROUNDER

Ministry: Ministry of Electronics & IT / MoST / DPIIT

PIB Date: 22nd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

एक दशक पहले जब भारत की Technology Sector की बात होती थी, तो IT Services (सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ) का नाम आता था — भारतीय Engineers अमेरिकी कंपनियों के लिए Software लिखते थे, Call Centres में काम करते थे। वह तस्वीर अब पुरानी पड़ गई है।

PIB ने इस सप्ताह India's Emerging Technology Ecosystem पर एक व्यापक Backgrounder जारी किया। संख्याएँ चौंकाने वाली हैं: 2.3 लाख DPIIT-Recognised (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) Startups (USA और China के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा Startup Ecosystem), 25 लाख नौकरियाँ, 119 Unicorns (1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले Startups), Bioeconomy (जैव अर्थव्यवस्था) जो 12 वर्षों में \$10 बिलियन से \$190 बिलियन तक पहुंची।

साथ ही IndiaAI Mission (₹10,371 करोड़ से स्वदेशी AI बनाना), India Semiconductor Mission (₹76,000 करोड़ से Chip Manufacturing — चिप निर्माण), और Space Tech Startups लगभग शून्य से 400+ तक। तीन चीजें बदलीं: Government Policy (PLI Schemes — उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, नियामक उदारीकरण), Capital (Venture Capital — जोखिम पूंजी) और Talent (IITs से विश्वस्तरीय Engineers, 50 लाख STEM Graduates प्रति वर्ष)।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
DPIIT	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) — Startups को मान्यता देता है; 2026 तक 2.3 लाख Startups मान्यता प्राप्त।
Unicorn	1 अरब डॉलर या अधिक मूल्य का Startup; भारत में 119 Unicorns — USA और China के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा।





Deep Tech	मौलिक वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित Technology — AI, Quantum Computing (क्वांटम कंप्यूटिंग), Biotech (जैव प्रौद्योगिकी), Space, Semiconductors (अर्धचालक); भारत का उभरता Focus।
PLI Scheme	Production-Linked Incentive (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) — 14 क्षेत्रों में लागू; ₹1.97 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता।
Quantum Mission	National Quantum Mission (NQM): ₹6,003 करोड़; 2031 तक Quantum Computers (क्वांटम कंप्यूटर), Communication (संचार), Sensing (संवेदन), Metrology (माप विज्ञान) के लक्ष्य।
Semiconductor Mission	ISM: ₹76,000 करोड़; Micron Technology (₹22,516 करोड़ Fab — कारखाना — Gujarat में), Tata Electronics Fab in Assam — भारत के Chip Manufacturing (चिप निर्माण) की शुरुआत।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- भारत का Startup Ecosystem: 2.3 लाख DPIIT-Recognised Startups; 25 लाख नौकरियाँ; 119 Unicorns; ₹10+ लाख करोड़ कुल मूल्य — दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा।
- National Quantum Mission (2023-2031): ₹6,003 करोड़; चार विषयगत Hubs (Q-Computing, Q-Communication, Q-Sensing, Q-Materials); 2026-27 तक 50-Qubit Quantum Computer बनाने का लक्ष्य।
- IndiaAI Mission: ₹10,371 करोड़; शोधकर्ताओं और Startups के लिए 10,000 GPU Compute Cluster (कंप्यूटिंग संसाधन); Varya (Video AI — वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पहला परिणाम है।
- India का R&D Gap (अनुसंधान अंतर): भारत GDP का केवल 0.65% R&D पर खर्च करता है बनाम USA, China, South Korea का 2%+ — यह अंतर पाटना जरूरी है।
- Emerging Tech Districts (उभरते प्रौद्योगिकी केंद्र): Bengaluru (AI/Biotech), Hyderabad (Pharma/Biotech), Pune (EV/Defence), Chennai (Semiconductors/Autos), Delhi-NCR (Fintech)।

CRITICAL MINERALS MISSION — 56 BLOCKS AUCTIONED, 7TH TRANCHE COMPLETE

Ministry: Ministry of Mines

PIB Date: 23rd June 2026



| Click to Connect Now.



Easy Explanation (सरल व्याख्या)

Electric Vehicles (विद्युत वाहन) को Lithium (लिथियम) चाहिए। Solar Panels (सौर पैनल) को Silicon (सिलिकॉन) और Silver (चाँदी) चाहिए। Wind Turbines (पवन चक्कियों) को Rare Earth Elements (दुर्लभ भू-तत्व) चाहिए। Semiconductors (अर्धचालक) को Gallium (गैलियम) और Germanium (जर्मेनियम) चाहिए। इन्हें Critical Minerals (महत्वपूर्ण खनिज) कहते हैं। समस्या यह है कि इनकी आपूर्ति कुछ ही देशों में केंद्रित है। China (चीन) अधिकांश Critical Minerals के Processing (प्रसंस्करण) पर 60-80% नियंत्रण रखता है। अगर China निर्यात रोक दे (वह Gallium और Germanium के साथ ऐसा कर चुका है), तो निर्भर देश मुश्किल में पड़ जाते हैं।

भारत ने इसे समझकर National Critical Mineral Mission (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज अभियान) शुरू किया। इस सप्ताह Ministry of Mines ने Critical Mineral Block Auctions (खनिज ब्लॉक नीलामी) का 7वाँ Tranche (चरण) पूरा किया — कुल 88 में से 56 ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए (63% सफलता दर)।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
Critical Minerals	Clean Energy (स्वच्छ ऊर्जा), EVs, Defence (रक्षा), Semiconductors के लिए आवश्यक खनिज; आपूर्ति जोखिम के कारण महत्वपूर्ण; भारत भारी आयात पर निर्भर।
National Critical Mineral Mission (NCMM)	भारत का रणनीतिक Framework (ढाँचा) — Exploration (खोज), Mining (खनन) और विदेशों में अधिग्रहण द्वारा Critical Minerals की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना।
Exploration Licence (EL)	नई License श्रेणी — Commercial Mining (वाणिज्यिक खनन) से पहले खोज करने की अनुमति; वास्तविक भंडार का आकलन करने में मदद।
7th Tranche	Critical Mineral Block Auctions का नवीनतम दौर; 10 ब्लॉक नीलाम; अब तक 88 में से 56 ब्लॉक (63% सफलता दर)।
MMDR Act 1957	Mines and Minerals (Development and Regulation) Act — खनिज नीलामी का कानूनी ढाँचा; Critical Minerals को शामिल करने के लिए कई बार संशोधित।



**KABIL**

Khanij Bidesh India Limited — NALCO, HCL और MECL का Joint Venture (संयुक्त उद्यम); विदेशों में Critical Mineral संपत्तियाँ हासिल करता है; Australia और Argentina से MoU।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- भारत की Critical Mineral आयात निर्भरता: Lithium (100% आयात), Cobalt (100% आयात), Nickel (अधिकांश आयात), REEs (अधिकांश China से आयात) — रणनीतिक कमजोरी।
- 7वें Tranche का विवरण: 10 ब्लॉक नीलाम; खनिजों में Graphite, REEs, Vanadium, Titanium, Glauconite, Rock Phosphate शामिल; पहली बार Gujarat, Uttarakhand और Telangana में नीलामी।
- NCMM के 4 स्तंभ: (1) घरेलू Exploration और Mining, (2) KABIL के माध्यम से विदेशी अधिग्रहण, (3) Critical Minerals का Recycling और Recovery (पुनःप्राप्ति), (4) Technology Development।
- India के पास दुनिया के 5वें सबसे बड़े REE Reserves (दुर्लभ भू-तत्व भंडार) — अनुमानित 6.9 मिलियन टन — लेकिन Processing Capacity (प्रसंस्करण क्षमता) न्यूनतम।
- Global Context (वैश्विक परिदृश्य): US Inflation Reduction Act, EU Critical Raw Materials Act — सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ Critical Minerals Supply Chains सुरक्षित करने की दौड़ में हैं।

RAKHIGARHI SKELETAL REMAINS — TRANSFERRED TO ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Ministry: Ministry of Culture / ASI / AnSI

PIB Date: 22nd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

हरियाणा के Hisar जिले में स्थित Rakhigarhi (राखीगढ़ी) सिर्फ एक Archaeological Site (पुरातात्विक स्थल) नहीं है — यह संभवतः मानवता की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक, Indus-Saraswati (सिंधु-सरस्वती) या Harappan Civilisation (हड़प्पा सभ्यता) का सबसे बड़ा शहर है, जो 4,500 साल पहले फला-फूला। 550 Hectares (हेक्टेयर) में फैला यह Pakistan के Mohenjo-daro (मोहेंजो-दारो) या Harappa से भी बड़ा है।



| Click to Connect Now.



इस सप्ताह, 2025-26 सत्र में Mound No. 7 (एक Cemetery Area — कब्रिस्तान क्षेत्र) से खुदाई में मिले तीन पूर्ण मानव Skeletons (कंकाल) और अतिरिक्त Skeletal Fragments (हड्डियों के टुकड़े) को Archaeological Survey of India (ASI) से Anthropological Survey of India (AnSI) को एक नए MoU (समझौता ज्ञापन) के तहत हस्तांतरित किया गया।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन हड्डियों में रहस्य हैं। आधुनिक विज्ञान हजारों साल पुरानी हड्डियों और दांतों से Ancient DNA (प्राचीन डीएनए) निकाल सकता है और पुनर्निर्माण कर सकता है: ये लोग आनुवंशिक रूप से कौन थे, उनके पूर्वज कहाँ से आए थे, क्या वे प्रवासी थे, और वे आधुनिक दक्षिण एशियाई जनसंख्या से कैसे संबंधित थे। यह सीधे Aryan Migration Theory (आर्य प्रवास सिद्धांत) से जुड़ा है।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
Rakhigarhi	सबसे बड़ा ज्ञात Harappan Site (हड़प्पा स्थल); 550 Hectares; Hisar District, Haryana; Early से Mature Harappan Period (प्रारंभिक से परिपक्व हड़प्पा काल) तक निरंतर आवास।
ASI	Archaeological Survey of India (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) — उत्खनन (Excavations) करता है; Ministry of Culture के अंतर्गत; Skeletal Remains हस्तांतरित किए।
AnSI	Anthropological Survey of India (भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण) — मानव जनसंख्या का अध्ययन; Remains का विश्लेषण करता है; Repository (संग्रह केंद्र) Kolkata में।
Ancient DNA (aDNA)	प्राचीन मानव अवशेषों से निकाला गया DNA; Ancestry (वंशावली), Migration Patterns (प्रवास पैटर्न), प्राचीन जनसंख्या के Genetic Diseases का पुनर्निर्माण संभव।
Palaeogenomics	प्राचीन Genomes का अध्ययन; Archaeology और Genetics को जोड़ता है; जनसंख्या की उत्पत्ति और प्रवास पर विवादों को सुलझा सकता है।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- Rakhigarhi: 550 Hectares; Hisar, Haryana; विश्व स्तर पर सबसे बड़ा Harappan Site — Mohenjo-daro (300 ha) और Harappa (150 ha) से बड़ा।



| Click to Connect Now.



- ASI (Archaeological Survey of India) और AnSI (Anthropological Survey of India) दोनों Ministry of Culture के अंतर्गत — अलग-अलग कार्य: ASI खुदाई करता है, AnSI मानव अवशेषों का अध्ययन करता है।
- AnSI का Repository Kolkata में है — NOT New Delhi — MCQ के लिए महत्वपूर्ण तथ्य।
- अनुसंधान विधियाँ: Ancient DNA Extraction (प्राचीन DNA निष्कर्षण), Osteological Analysis (हड्डी माप), Isotope Analysis (आहार और प्रवास का अध्ययन), Radiocarbon Dating (कार्बन आधारित आयु निर्धारण), CT Scanning।
- Academic Controversy (शैक्षणिक विवाद): 2019 की Rakhigarhi DNA Study (David Reich et al.) ने सुझाया कि Harappan लोगों में Central Asian Steppe (मध्य एशियाई स्टेप) से कोई वंशानुगत संबंध नहीं था — Aryan Migration Theory के विपरीत।

BRICS ENERGY MINISTERS' MEETING — 11TH EDITION, GURUGRAM

Ministry: Ministry of Power / Ministry of Petroleum & Natural Gas

PIB Date: 25th–26th June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

ऊर्जा हर चीज की नींव है — आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन, परिवहन और राष्ट्रीय सुरक्षा। 11वीं BRICS Energy Ministers' Meeting (BRICS ऊर्जा मंत्रियों की बैठक) Gurugram में 25-26 जून को भारत की BRICS Chairship (अध्यक्षता) में हुई। BRICS देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% ऊर्जा का उपभोग करते हैं।

इस बैठक का समय बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया Energy Transition (ऊर्जा परिवर्तन) में है — Coal और Oil से Renewables (नवीकरणीय ऊर्जा) की ओर। Russia-Ukraine युद्ध ने 2022-23 में Global Energy Crisis (वैश्विक ऊर्जा संकट) पैदा किया। West Asia (पश्चिम एशिया) में तनाव तेल आपूर्ति को खतरे में डालते हैं।

BRICS सदस्यों के अलग-अलग हित हैं: Russia Fossil Fuels (जीवाश्म ईंधन) बेचना चाहता है; India और China विकास के लिए सस्ती ऊर्जा चाहते हैं। भारत की Agenda (एजेंडा) तीन बिंदुओं पर था: Energy Access (सभी को बिजली), Energy Security (विविध आपूर्ति), और Energy Transition (Renewables, Green Hydrogen)।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
-------------	----------------------



| Click to Connect Now.



BRICS Energy Ministers' Meeting	BRICS देशों के ऊर्जा मंत्रियों की वार्षिक Ministerial-Level Meeting (मंत्री स्तरीय बैठक); 11वाँ संस्करण India की 2024-25 Chairship में।
Energy Trilemma	तीन प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लक्ष्य: Security (विश्वसनीय आपूर्ति), Equity (सस्ती पहुँच), Sustainability (कम Carbon) — BRICS चर्चाएँ इन तीनों पर।
Just Energy Transition	जीवाश्म ईंधन उद्योगों में काम करने वालों को पीछे छोड़े बिना स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना; Coal-Dependent (कोयला-निर्भर) अर्थव्यवस्थाओं के लिए BRICS की चिंता।
BRICS+ Energy Cooperation	5 नए BRICS सदस्यों (UAE, Saudi Arabia, Iran, Egypt, Ethiopia) के साथ — विस्तारित गुट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के और अधिक हिस्से को नियंत्रित करता है।
Energy Security	विश्वसनीय, सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना; भारत का दृष्टिकोण: स्रोतों में विविधता (Saudi, Russia, UAE), SPR (Strategic Petroleum Reserve — रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार) बनाना, Renewables में निवेश।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- BRICS देश: 40%+ वैश्विक ऊर्जा खपत; Russia (दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक), Saudi Arabia (नया सदस्य, सबसे बड़ा तेल निर्यातक), UAE (नया सदस्य) — BRICS+ अब एक प्रमुख Energy Bloc (ऊर्जा गुट) है।
- भारत का ऊर्जा Agenda: 2030 तक 500 GW नवीकरणीय क्षमता, 2070 तक Net Zero (शुद्ध शून्य Carbon), E20 Ethanol Blending प्राप्त, 2030 तक 5 MMT Green Hydrogen।
- Russia-India ऊर्जा आयाम: 2022 से India रूसी तेल छूट पर खरीद रहा है (Russia की भारतीय आयात में हिस्सेदारी 2% से ~35% हो गई)।
- Coal Transition Sensitivity (कोयला परिवर्तन की संवेदनशीलता): India तेज़ी से Coal Phase-Out (कोयला बंद करना) का खर्च नहीं उठा सकता — Base Load के लिए अभी भी 200 GW कोयला आवश्यक।

BRICS MSME FORUM & SME WORKING GROUP — AGRA

Ministry: Ministry of MSME

PIB Date: 21st June 2026



| Click to Connect Now.



Easy Explanation (सरल व्याख्या)

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) हर विकासशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत में ये 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, GDP का 30% और Exports (निर्यात) का 45% योगदान करते हैं। लेकिन छोटे व्यवसायों को हमेशा दो चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है: Finance (वित्त) और Markets (बाजार)।

इस सप्ताह Agra में 1st BRICS MSME Forum और 3rd BRICS SME Working Group Meeting हुई। India ने BRICS Chair के रूप में तीन प्रस्ताव रखे: (1) BRICS MSME Digital Marketplace — सभी BRICS देशों के छोटे व्यवसाय एक Platform पर आएँ और एक-दूसरे के देशों में Buyers (खरीदार) खोजें। (2) BRICS Credit Guarantee Framework — BRICS देश मिलकर MSME Loans की गारंटी दें। (3) Technology Sharing — भारत के सफल Digital Infrastructure (Udyam Portal, GeM, TReDS) को अन्य BRICS देशों के लिए Model के रूप में प्रस्तुत किया।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
MSME	Micro ($\leq$ ₹1 करोड़ Turnover — कारोबार), Small (₹1-10 करोड़), Medium (₹10-50 करोड़) उद्यम; भारत में 6.3 करोड़ MSMEs जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं।
GeM	Government e-Marketplace (सरकारी ई-बाज़ार) — MSMEs से सरकारी खरीद का Online Platform; ₹4 लाख करोड़+ संचयी आदेश।
TReDS	Trade Receivables Discounting System (व्यापार प्राप्त्य छूट प्रणाली) — MSMEs को लंबित Invoice (बिल) को तुरंत Cash में बदलने की सुविधा; MSME को 60-90 दिन इंतजार नहीं करना पड़ता।
Udyam Portal	MSME Registration (पंजीकरण) का सरकारी Portal; 4.5 करोड़+ पंजीकरण; Schemes (योजनाओं), Credit (ऋण), Market Linkages (बाजार संपर्क) तक पहुँच।
Credit Guarantee Framework	प्रस्तावित Multilateral (बहुपक्षीय) गारंटी तंत्र; MSMEs को ऋण देने में Banks का जोखिम कम करता है — India के CGTMSE और ECLGS पर आधारित।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)



| Click to Connect Now.



- भारत के MSME आँकड़े: 6.3 करोड़ MSMEs; 11 करोड़ नौकरियाँ; GDP का 30%; Exports का 45%; सभी उद्यमों का 99% — Inclusive Growth (समावेशी विकास) के लिए महत्वपूर्ण।
- 1st BRICS MSME Forum: India ने पहली बार Host किया; MSMEs को Multilateral Platform (बहुपक्षीय मंच) देने की India की प्राथमिकता को दर्शाता है।
- GeM: 2016 से ₹4+ लाख करोड़ के संचयी आदेश; 60 लाख+ Sellers (विक्रेता); 10,000+ Product Categories।
- Agra को प्रतीकात्मक रूप से चुना गया — यह India के MSME Heartland (केंद्र) में है (UP अकेले में 90+ लाख MSMEs)।

FERTILISER SHIPS CROSS STRAIT OF HORMUZ — SUPPLY CHAIN RESILIENCE

Ministry: Ministry of Chemicals & Fertilizers

PIB Date: 22nd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

भारत China के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा Fertiliser (उर्वरक) उपभोक्ता है। 14 करोड़ किसानों को हर Kharif (खरीफ) और Rabi (रबी) सीजन में Urea (यूरिया), DAP (Diammonium Phosphate — डाईअमोनियम फॉस्फेट) और MOP (Muriate of Potash — म्यूरेट ऑफ पोटाश) चाहिए। बिना Fertiliser के फसल उत्पादन गिर जाता है और खाद्य कीमतें बढ़ जाती हैं।

समस्या: भारत महत्वपूर्ण मात्रा में Fertiliser आयात करता है और कई Gulf (खाड़ी) क्षेत्र से आते हैं। West Asia (पश्चिम एशिया) में बढ़ते तनाव और Houthis विद्रोहियों के Red Sea और Arabian Sea में जहाजों पर हमलों से India की Fertiliser Supply Chains (आपूर्ति श्रृंखलाएँ) खतरे में थीं। इस सप्ताह PIB ने पुष्टि की कि चार Fertiliser Ships (उर्वरक जहाज) Strait of Hormuz (होर्मुज जलडमरूमध्य) को पार करके Indian Ports (भारतीय बंदरगाहों) की ओर आ रहे हैं।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
Strait of Hormuz	Iran और Oman के बीच संकीर्ण जलमार्ग; दुनिया के 30% तेल AND महत्वपूर्ण Fertiliser व्यापार यहाँ से गुजरता है; Strategic Chokepoint (रणनीतिक संकरा बिंदु)।



| Click to Connect Now.



Kharif Season	गर्मी की फसल का मौसम (जून-नवंबर); बुवाई जून-जुलाई में; प्रमुख Kharif फसलें: धान, कपास, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली।
Urea	सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला Nitrogen Fertiliser (नाइट्रोजन उर्वरक); भारत ~20% आयात करता है।
DAP	Diammonium Phosphate — प्रमुख Phosphatic Fertiliser (फॉस्फेटिक उर्वरक); भारत ~80% Morocco, Jordan, China, Saudi Arabia से आयात करता है।
MOP	Muriate of Potash — Potassic Fertiliser (पोटैशिक उर्वरक); भारत 100% Canada, Russia, Belarus, Jordan से आयात करता है — शून्य घरेलू उत्पादन।
Nutrient-Based Subsidy (NBS)	P और K Fertilisers पर Nutrient Content (पोषक तत्व सामग्री) के आधार पर Subsidy (सब्सिडी); Urea पर अलग Flat Subsidy।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- भारत की Fertiliser आयात निर्भरता: Urea ~20%, DAP ~80%, MOP ~100% — आखिरी दो पूरी तरह या भारी रूप से Import-Dependent हैं, जो Supply Vulnerability (आपूर्ति भेद्यता) पैदा करते हैं।
- Strait of Hormuz की प्रासंगिकता: केवल तेल नहीं — Gulf से Fertiliser Ships भी Hormuz से गुजरती हैं; व्यवधान ऊर्जा AND कृषि दोनों को प्रभावित करता है।
- Kharif Fertiliser आवश्यकता: भारत को Kharif Season के लिए ~33 मिलियन टन Fertiliser चाहिए; जून-जुलाई में कोई भी कमी पूरे सीजन की फसल को नुकसान पहुँचाती है।
- Nano Fertilisers: Nano Urea (IFFCO), Nano DAP — 50% कम सामग्री से समान Nutrient Delivery (पोषक तत्व वितरण); स्केल होने पर आयात निर्भरता काफी कम होगी।

INDIA — WORLD'S TOP SHIP RECYCLING NATION IN 2025

Ministry: Ministry of Ports, Shipping and Waterways

PIB Date: 22nd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)



| Click to Connect Now.



हर जहाज — चाहे Container Vessel (कंटेनर जहाज), Oil Tanker (तेल टैंकर) या Cruise Liner (कूज जहाज) — की कार्यकारी आयु लगभग 25-30 वर्ष होती है। जब वह बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे 'Recycle' करना होता है — Steel (स्टील) और Components (पुर्जो) में तोड़ा जाता है जिन्हें दोबारा उपयोग किया जा सके।

Gujarat के Gulf of Khambhat (खंभात की खाड़ी) पर भारत का Alang Ship Recycling Yard (अलंग जहाज पुनःचक्रण यार्ड) दशकों से यही काम कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा Ship Breaking Yard (जहाज तोड़ने का यार्ड) है — 10 km तट पर पुराने जहाजों को उच्च ज्वार में किनारे पर लाकर तोड़ा जाता है।

इस सप्ताह UN की व्यापार संस्था UNCTAD ने पुष्टि की कि भारत 2025 में दुनिया का नंबर एक Ship Recycling Nation (जहाज पुनःचक्रण राष्ट्र) बन गया — 35.4% वैश्विक Market Share के साथ (2024 में 30.1% था)। यह Maritime India Vision 2030 के लक्ष्य को पाँच वर्ष पहले पूरा करना है।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
Alang Ship Recycling Yard	दुनिया का सबसे बड़ा Ship Breaking Facility (जहाज तोड़ने की सुविधा); Gujarat के Gulf of Khambhat पर 50+ km; 50,000-70,000 श्रमिक।
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development (व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) — वार्षिक Ship Recycling Data जारी करता है; 2025 के लिए भारत की #1 Ranking की पुष्टि।
Maritime India Vision (MIV) 2030	भारत के Maritime Sector (समुद्री क्षेत्र) के विकास का Blueprint; Ship Recycling में वैश्विक नेतृत्व एक लक्ष्य था; 5 वर्ष पहले प्राप्त।
Hong Kong Convention (HKC)	Safe और Environmentally Sound Ship Recycling (पर्यावरण-अनुकूल जहाज पुनःचक्रण) के लिए International Treaty (अंतर्राष्ट्रीय संधि); India ने Recycling of Ships Act 2019 के माध्यम से Ratify किया।
EU Ship Recycling Regulation (EUSRR)	EU के लिए जरूरी है कि EU Flag वाले जहाजों को Approved Yards (अनुमोदित यार्डों) में Recycle किया जाए; अगर Alang EU List में आ गया — भारी व्यावसायिक अवसर।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)





- भारत का 2025 Market Share: 35.4% (2024 में 30.1% से); Volume: 2.99 मिलियन Gross Tonnes (2024 में 1.86 मिलियन GT से 60% वृद्धि) — UNCTAD डेटा।
- MIV 2030 का लक्ष्य 5 वर्ष पहले प्राप्त: भारत 2030 तक Ship Recycling में वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखता था; 2025 में ही प्राप्त हुआ — भारत का अपनी Timeline से आगे रहने का दुर्लभ उदाहरण।
- Alang-Sosiya Yard, Gujarat: Gulf of Khambhat पर; Natural Tidal Variation (प्राकृतिक ज्वार भिन्नता — 10m Tidal Range) जहाजों को Beaching (किनारे लगाने) के लिए आदर्श; 150+ Active Recycling Plots।
- Recycling of Ships Act 2019: Hong Kong Convention Standards के अनुरूप घरेलू कानून; अनिवार्य Ship Recycling Plan और Inventory of Hazardous Materials (खतरनाक सामग्री की सूची) आवश्यक।

DISHA 2.0 — DESIGNING INNOVATIVE SOLUTIONS FOR HOLISTIC ACCESS TO JUSTICE

Ministry: Ministry of Law and Justice

PIB Date: 22nd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

भारत में न्याय का एक विरोधाभास है। संविधान हर नागरिक को समान न्याय की गारंटी देता है। लेकिन व्यवहार में, किसी दूरदराज के गाँव का गरीब किसान Lawyer (वकील) का खर्च नहीं उठा सकता, अपने अधिकार नहीं जानता, और अगर Court (न्यायालय) जाए भी तो 10-15 साल इंतजार करना पड़ सकता है। भारत में 5 करोड़ Pending Cases (लंबित मामले) हैं।

DISHA 2.0 — Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice (न्याय तक समग्र पहुँच के लिए नवीन समाधान) — सरकार का पुनर्निर्मित कार्यक्रम है। यह पूरे Access-to-Justice Ecosystem (न्याय तक पहुँच के तंत्र) को कवर करता है: Legal Literacy (लोगों को उनके अधिकार बताना), Lok Adalats (वैकल्पिक विवाद समाधान मंच), Tele-Law (गाँव के Common Service Centres से Video Call पर Lawyers), Nyaya Bandhu (Pro Bono — निःशुल्क — Lawyer Programme), और जेलों में Legal Aid Clinics।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
-------------	----------------------



| Click to Connect Now.



DISHA 2.0	Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice — MoLJ (Ministry of Law and Justice) का पुनर्निर्मित कानूनी पहुँच कार्यक्रम; Legal Literacy (कानूनी जागरूकता), Aid (सहायता), Lok Adalats, Tele-Law को कवर करता है।
Lok Adalat	Alternative Dispute Resolution (वैकल्पिक विवाद समाधान) Forum (मंच); मामलों को Court के बाहर सुलझाता है; Lok Adalat के फैसले के खिलाफ Appeal (अपील) नहीं; Legal Services Authorities Act 1987।
Tele-Law	गाँवों में Common Service Centres (CSCs) पर Video Call के माध्यम से Lawyers से परामर्श; 2017 से 30 लाख+ परामर्श।
Nyaya Bandhu	Pro Bono Lawyer Programme — प्रशिक्षित Lawyers गरीब Litigants (वादियों) को मुफ्त सेवाएँ देने के लिए Volunteer (स्वयंसेवी) होते हैं।
NALSA	National Legal Services Authority — Legal Aid (कानूनी सहायता) के लिए Apex Body (सर्वोच्च संस्था); Legal Services Authorities Act 1987 के तहत गठित; Chief Justice of India की अध्यक्षता।
Undertrial Prisoners	विचाराधीन कैदी — Trial (मुकदमे) का इंतजार कर रहे; India के 5.5 लाख कैदियों में से 75%+ Undertrials हैं — अक्सर अपनी सज़ा से अधिक जेल में रहते हैं।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- India का न्याय पहुँच का अंतर: 5 करोड़ Pending Cases; जिला स्तर पर औसत Case 10-15 साल लेता है; गरीबों के लिए कानूनी प्रणाली दुर्गम।
- Undertrial Crisis: India की 5.54 लाख जेल आबादी में 75%+ Undertrials हैं (दोषी नहीं); Section 436A CrPC (Criminal Procedure Code) अधिकतम सज़ा का आधा समय बाद Bail की अनुमति देता है — जागरूकता कम।
- NALSA: Constitutional Mandate (संवैधानिक जनादेश) Article 39A के तहत — Free Legal Aid (मुफ्त कानूनी सहायता) एक Fundamental Right (मौलिक अधिकार) है।
- Lok Adalat Impact: शुरुआत से अब तक 20 करोड़+ मामले Lok Adalats के माध्यम से सुलझाए गए; Court पर बोझ कम; Binding Settlement (बाध्यकारी समझौता), कोई Appeal नहीं — तेज़ और अंतिम।
- SDG 16 Connection: Sustainable Development Goal 16 — 'शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ'; India का DISHA 2.0 इसका घरेलू Implementation Vehicle (क्रियान्वयन माध्यम) है।





ABS FRAMEWORK — ₹145 CRORE TO BIODIVERSITY BENEFICIARIES

Ministry: Ministry of Environment, Forest and Climate Change / National Biodiversity Authority

PIB Date: 20th June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

कल्पना करें कि Odisha की एक जनजातीय समुदाय पीढ़ियों से जानती है कि एक विशेष जंगली पौधे की छाल बुखार ठीक करती है। वे सदियों से इसका उपयोग करते रहे। एक दिन एक Pharmaceutical Company (दवा कंपनी) यही गुण खोजती है, Active Compound (सक्रिय यौगिक) Synthesise (संश्लेषित) करती है, Drug (दवा) का Patent (एकाधिकार) लेती है और करोड़ों कमाती है। समुदाय को कुछ नहीं मिलता। इसे Biopiracy (जैव-चोरी) कहते हैं।

India के Biological Diversity Act 2002 (जैव विविधता अधिनियम 2002) के तहत Access and Benefit Sharing (ABS — पहुँच और लाभ साझाकरण) Framework इसे रोकने के लिए है। इस सप्ताह PIB ने खुलासा किया: 2008 से NBA ने ₹266 करोड़ ABS के माध्यम से जुटाए, ₹145 करोड़ 23 राज्यों में 10,500+ Biodiversity Management Committees (जैव विविधता प्रबंधन समितियों) को वितरित किए।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
ABS	Access and Benefit Sharing (पहुँच और लाभ साझाकरण) — Framework जो सुनिश्चित करता है कि जब उनके Biological Resources (जैविक संसाधन) या Traditional Knowledge (पारंपरिक ज्ञान) का व्यावसायिक उपयोग हो तो समुदायों को उचित हिस्सा मिले।
Biological Diversity Act 2002	CBD (Convention on Biological Diversity — जैव विविधता पर सम्मेलन) को लागू करने का भारत का कानून; NBA, SBBs और BMCs की स्थापना; ABS अनिवार्य; 2023 में AYUSH पहुँच के लिए संशोधित।
NBA	National Biodiversity Authority (राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण) — Chennai में Statutory Body (वैधानिक निकाय); Biological Resources तक पहुँच को मंजूरी देता है; ABS Funds एकत्र और वितरित करता है।





BMC	Biodiversity Management Committee (जैव विविधता प्रबंधन समिति) — ग्राम/वार्ड स्तर पर; People's Biodiversity Register (लोगों का जैव विविधता रजिस्टर) रखता है; ABS Funds प्राप्त करता है; 2.76 लाख BMCs सक्रिय।
Nagoya Protocol 2010	CBD का Supplementary Agreement (पूरक समझौता) — COP-10, Nagoya, Japan; ABS के लिए International Framework; India ने इसे Ratify किया — NBA घरेलू स्तर पर लागू करता है।
Kunming-Montreal GBF	Global Biodiversity Framework (वैश्विक जैव विविधता ढाँचा) (COP-15, 2022); Target 13: 'उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण'; India का ABS Framework इस Target को सीधे लागू करता है।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- ABS Framework के आँकड़े: 2008 से ₹266 करोड़ जुटाए; ₹145 करोड़ वितरित (FY2025-26 में अकेले ₹78 करोड़ — अब तक का सर्वाधिक Single-Year Disbursement)।
- क्षेत्रवार ABS Collections: Red Sanders 45% (₹120 करोड़); Seeds Sector (बीज क्षेत्र) 32% (₹85 करोड़); Pharma/AYUSH 14% (₹37 करोड़)।
- Red Sanders (*Pterocarpus santalinus* — लाल चंदन): Andhra Pradesh के लिए Endemic (स्थानीय); अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी व्यापार; Japan, China में Furniture और Medicine के लिए माँग।
- NBA का तीन-स्तरीय ढाँचा: NBA (राष्ट्रीय) → State Biodiversity Boards (राज्य) → Biodiversity Management Committees (ग्राम) — NBA Collections का 85-90% राज्य और स्थानीय स्तर पर जाता है।

INCOIS EL NIÑO BULLETINS — PROTECTING INDIA'S MARITIME SECTORS

Ministry: Ministry of Earth Sciences / INCOIS

PIB Date: 23rd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)



| Click to Connect Now.



El Niño (अल नीनो) एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें Central और Eastern Pacific Ocean (मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर) की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। यह भारत से दूर लगता है, लेकिन El Niño के प्रभाव सीधे भारत तक पहुँचते हैं: यह Indian Monsoon (भारतीय मानसून) को कमजोर करता है, जिससे कई भागों में सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है।

Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत INCOIS (Indian National Centre for Ocean Information Services — भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र) ने इस सप्ताह विशेष El Niño Bulletins (बुलेटिन) लॉन्च किए — विशेष रूप से भारत के Maritime Sectors (समुद्री क्षेत्रों) के लिए। ये Generic Weather Alerts (सामान्य मौसम चेतावनियाँ) नहीं हैं — ये Sector-Specific Forecasts (क्षेत्र-विशिष्ट पूर्वानुमान) हैं।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
El Niño	Central/Eastern Pacific Ocean के सतह तापमान का आवधिक गर्म होना; हर 2-7 वर्षों में होता है; Indian Monsoon (भारतीय मानसून) को कमजोर करता है, Marine Ecosystems (समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र) को बाधित करता है।
INCOIS	Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad — MoES के तहत; Ocean State Forecasts (समुद्र अवस्था पूर्वानुमान), Tsunami Warnings (सुनामी चेतावनियाँ), Fish Potential Zones (मछली की संभावित क्षेत्र) प्रदान करता है।
La Niña	El Niño का विपरीत: Pacific का ठंडा होना; Indian Monsoon को मजबूत करता है; ENSO Cycle में El Niño के साथ बारी-बारी आता है।
ENSO	El Niño-Southern Oscillation (अल नीनो-दक्षिणी दोलन) — Pacific Ocean के तापमान को Atmospheric Pressure (वायुमंडलीय दाब) परिवर्तनों से जोड़ने वाला जलवायु पैटर्न; वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है।
Potential Fishing Zone (PFZ)	INCOIS की Advisory (सलाह) — Ocean Temperature और Chlorophyll Satellite Data के आधार पर मछलियों की अधिक उपस्थिति वाले क्षेत्रों की पहचान; 4 लाख+ मछुआरों द्वारा रोजाना उपयोग।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)



| Click to Connect Now.



- INCOIS की स्थापना 1999 में Hyderabad में; Ministry of Earth Sciences के तहत; मत्स्य पालन, शिपिंग, जलवायु और आपदा प्रबंधन के लिए Ocean Information और Advisory Services।
- El Niño 2023-24 रिकॉर्ड पर सबसे मजबूत में से एक था; भारत के 2023 Monsoon को कमजोर किया; कई राज्यों में कम Groundwater Recharge (भूजल पुनर्भरण) और फसल तनाव।
- PFZ Advisories (संभावित मत्स्य क्षेत्र सलाह): मछुआरों को SMS, App और Regional Languages (क्षेत्रीय भाषाओं) में Radio के माध्यम से भेजी जाती हैं; Fuel Cost में 20-30% की कमी।
- Tsunami Early Warning: INCOIS 2007 से India का Tsunami Early Warning Centre (सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र) संचालित करता है; Submarine Earthquake (पानी के नीचे भूकंप) के 10 मिनट के भीतर Alert।

ETHANOL BLENDING PROGRAMME — GOVERNMENT CLARIFICATION

Ministry: Ministry of Petroleum & Natural Gas

PIB Date: 23rd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

आपके नजदीकी Petrol Station (पेट्रोल स्टेशन) पर मिलने वाले Petrol (पेट्रोल) में Ethanol (इथेनॉल — गन्ने या अनाज से बना Alcohol / शराब) का एक प्रतिशत मिला होता है। यह Imported Crude Oil (आयातित कच्चे तेल) पर निर्भरता कम करने और Carbon Emissions (कार्बन उत्सर्जन) घटाने के लिए किया जाता है।

India का Ethanol Blending Programme (EBP — इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम) दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है: India ने Petrol में 15% Ethanol Blending (E15) हासिल कर लिया है और राष्ट्रीय स्तर पर 20% Blending (E20) का लक्ष्य है। इस सप्ताह Ministry of Petroleum & Natural Gas ने Social Media पर भ्रामक दावों के बाद Clarification Statement (स्पष्टीकरण वक्तव्य) जारी किया।

EBP की उपलब्धियाँ: 9 Ethanol Supply Years (2013-14 से 2022-23) में 654 करोड़ लीटर Ethanol Blended (मिश्रित) किया, ₹87,320 करोड़ Foreign Exchange (विदेशी मुद्रा) बचाई और 318 लाख Metric Tonnes Carbon Emissions कम कीं। कार्यक्रम ने गन्ना किसानों को Ethanol Price (इथेनॉल मूल्य) के रूप में ₹1,13,000 करोड़ का भुगतान किया।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
-------------	----------------------



| Click to Connect Now.



EBP	Ethanol Blending Programme (इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम) — Ethanol (गन्ने, मक्के, क्षतिग्रस्त अनाज से बना) को Petrol के साथ मिलाना; तेल आयात और Carbon Emissions कम करता है।
E20	80% Petrol के साथ 20% Ethanol का मिश्रण; India का राष्ट्रीय लक्ष्य; वाहनों को बेहतर प्रदर्शन के लिए मामूली Modifications (संशोधन) चाहिए; 2025-26 में Rollout।
1G Ethanol	First Generation Ethanol (पहली पीढ़ी का इथेनॉल) — गन्ने के रस, Molasses (शीरे) या खाद्य अनाज से; वर्तमान में EBP का प्रमुख स्रोत।
2G Ethanol	Second Generation Ethanol (दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल) — Agricultural Waste (कृषि अपशिष्ट) जैसे Rice Straw (धान की पराली), Wheat Straw (गेहूँ की पराली), Bagasse (गन्ने का चोया) से; खाद्य बनाम ईंधन का कोई संघर्ष नहीं।
BIS	Bureau of Indian Standards (भारतीय मानक ब्यूरो) — Ethanol Blended Petrol के लिए Quality Standards (गुणवत्ता मानक) प्रमाणित करता है; Engine Compatibility (इंजन अनुकूलता) सुनिश्चित करता है।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- EBP उपलब्धियाँ: 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर E15 प्राप्त; 2025-26 में E20 Rollout; 9 वर्षों में 654 करोड़ लीटर Ethanol Blended; ₹87,320 करोड़ Forex बचाई; किसानों को ₹1.13 लाख करोड़ का भुगतान।
- गन्ना किसान लाभ: EBP को 'गन्ना किसान का MSP' कहा जाता है — सरकार Fixed Price (₹63.19/लीटर गन्ने के रस से बने Ethanol के लिए 2024-25 में) पर Ethanol खरीदती है।
- 2G Ethanol Plants: IOC ने Panipat (2022) में India का पहला Commercial 2G Ethanol Plant बनाया — Rice Straw से Ethanol उत्पादन; Stubble Burning (पराली जलाने) की समस्या से सीधे जुड़ा।
- International Comparison: Brazil (E27 Blending, 50+ वर्षों का अनुभव), USA (राष्ट्रीय स्तर पर E10) — India का E20 वैश्विक Leaders की ओर बढ़ रहा है।

VOC PORT — 45% CARBON EMISSION REDUCTION, GREEN MARITIME MODEL



| Click to Connect Now.



Ministry: Ministry of Ports, Shipping and Waterways

PIB Date: 23rd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

V.O. Chidambaranar Port (VOC Port — वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह), जिसे पहले Tuticorin Port कहा जाता था, Tamil Nadu में है और भारत के 12 Major Ports (प्रमुख बंदरगाहों) में से एक है। Ports (बंदरगाह) महत्वपूर्ण Carbon Emitters (कार्बन उत्सर्जक) हैं — Port में रुके जहाज Heavy Fuel Oil (भारी ईंधन तेल) जलाते हैं, Refrigerated Containers (प्रशीतित कंटेनर) Diesel Generators पर चलते हैं।

VOC Port ने हाल के वर्षों में अपना Carbon Emissions 45% कम किया है जिससे यह Asia का एक Model Green Port (आदर्श हरित बंदरगाह) बन गया। कैसे? उपायों का संयोजन: Port Equipment को Diesel से Electric में बदलना (Electric Cranes, Electric Port Vehicles), Campus पर Rooftop Solar (छत पर सौर पैनल) लगाना, Shore Power (बंदरगाह की Grid Electricity से जहाजों को Power देना — ताकि Berthing के दौरान Engine बंद रहें), LED Lighting और Real-Time Emission Tracking।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
VOC Port	V.O. Chidambaranar Port, Tuticorin, Tamil Nadu; India के 12 Major Ports में से एक; 45% Carbon Emission Reduction — Model Green Port (आदर्श हरित बंदरगाह)।
Shore Power	बंदरगाह की Grid (विद्युत जाल) से Berthed (खड़े) जहाज का Electrical Connection; जहाज अपने Engines बंद करके Grid Power उपयोग करता है — Port में Diesel जलाना समाप्त।
IMO Green Voyage 2050	International Maritime Organization (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की 2008 की तुलना में 2050 तक Global Shipping के Carbon Emissions को 50% कम करने की रणनीति।
CBAM (Shipping)	EU का Carbon Border Adjustment Mechanism — Maritime Sector (समुद्री क्षेत्र) तक विस्तारित; निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले जहाजों को EU Ports पर Carbon Tax देना होगा।



| Click to Connect Now.

**Major Port Authorities Act 2021**

Major Port Trusts Act 1963 को प्रतिस्थापित किया; Ports को Corporate Governance (कॉर्पोरेट प्रशासन), अधिक Financial Autonomy (वित्तीय स्वायत्तता), Tariff (शुल्क) निर्धारित करने की शक्ति।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- India के 12 Major Ports: Deendayal (Kandla), Mumbai, JNPA, Mormugao, New Mangalore, Cochin, Chennai, Kamraj, VOC, Visakhapatnam, Paradip, Kolkata/Haldia — मिलकर India के 65% Maritime Trade को संभालते हैं।
- 45% Emission Reduction: Electric Cargo Handling Equipment, 100% LED Lighting, Rooftop Solar, Shore Power for Berthed Vessels और Electric Port Vehicles के माध्यम से प्राप्त।
- IMO के Shipping के लिए Carbon Targets: 2030 तक 40% Carbon Intensity Reduction (2008 के सापेक्ष); 2050 तक 70%; 2050 तक 'Zero Emissions' — Indian Ports को इसके साथ Align करना होगा।
- CBAM Shipping Extension: EU को निर्यात करने वाले Indian Exporters प्रभावित होंगे अगर उनका माल High-Carbon Vessels पर Ship हो; Indian Port Green Certification एक Competitive Trade Advantage बन जाता है।
- Sagarmala Programme (सागरमाला कार्यक्रम): India की Port-Led Development (बंदरगाह आधारित विकास) पहल; Green Ports Sagarmala का नवीनतम आयाम हैं।

NAFEX.IN — NAFED'S E-AUCTION PORTAL LAUNCHED

Ministry: Ministry of Cooperation / NAFED

PIB Date: 23rd June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

Maharashtra का एक किसान प्याज उगाता है। जब फसल आती है, बाजार में प्याज की अधिकता से कीमत ₹1-2 प्रति किलो तक गिर जाती है — फसल काटने का खर्च भी नहीं निकलता। किसान निराश होकर प्याज सड़क पर फेंकता है। यह दशकों से दोहराई जाने वाली सच्ची तस्वीर है। उसी समय, दिल्ली में एक Restaurant Owner ₹60 प्रति किलो प्याज दे रहा है। किसान को ₹2 और उपभोक्ता ₹60 देता है — बीच का कोई लगभग सारा मुनाफा खींच ले जाता है।

NAFED (National Agricultural Cooperative Export and Development Federation — राष्ट्रीय कृषि सहकारी निर्यात और विकास संघ) सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो इसे रोकने का काम करती है। NAFEX.in NAFED का नया E-Auction Portal (ई-नीलामी पोर्टल) है जिसे इस सप्ताह गृह मंत्री Amit Shah ने Launch किया। यह एक Transparent (पारदर्शी), Real-Time Digital



| Click to Connect Now.



Marketplace (बाज़ार) है जहाँ Buyers (Traders, Processors, Exporters — व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक) NAFED के संग्रहीत Stocks (भंडार) के लिए Competitive Auctions (प्रतिस्पर्धी नीलामी) में बोली लगा सकते हैं।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
NAFED	National Agricultural Cooperative Export and Development Federation — Agricultural Marketing (कृषि विपणन) के लिए Apex Cooperative (शीर्ष सहकारी संस्था); खेत उत्पाद खरीदती, संग्रहीत करती और बेचती है।
NAFEX.in	NAFED का E-Auction Portal (ई-नीलामी पोर्टल); NAFED के संग्रहीत Agricultural Commodity Stocks (कृषि वस्तु भंडार) पर Transparent, Competitive Bidding (पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली) के लिए Digital Platform।
Price Discovery	बाजार की वह प्रक्रिया जिसमें Supply और Demand (माँग और आपूर्ति) से Fair Price (उचित मूल्य) निर्धारित होता है; E-Auctions बोलियों को पारदर्शी बनाकर Price Discovery सुधारते हैं।
Price Stabilisation Fund (PSF)	सरकारी Fund (निधि) जिसका उपयोग NAFED MSP से नीचे आने पर वस्तुएँ खरीदने और कीमतें बढ़ने पर जारी करने के लिए करता है।
MSP	Minimum Support Price (न्यूनतम समर्थन मूल्य) — सरकार द्वारा घोषित Agricultural Commodities (कृषि वस्तुओं) की Floor Price (आधार मूल्य); NAFED MSP पर खरीदता है।
e-NAM vs NAFEX	e-NAM: Physical Mandis (भौतिक मंडियों) को ताजे उत्पाद के व्यापार के लिए Digital रूप से जोड़ता है। NAFEX.in: विशेष रूप से NAFED के अपने Procurement Stocks (खरीद भंडार) के लिए — अलग उद्देश्य, पूरक प्रणालियाँ।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- NAFED की स्थापना 1958 में हुई; Apex Agricultural Cooperative; PSS (Price Stabilisation Scheme — मूल्य स्थिरीकरण योजना) और PSF के तहत तिलहन, दलहन, अनाज, मसाले, प्याज, कपास की खरीद।
- Cooperative Sector Reforms (सहकारी क्षेत्र सुधार): गृह मंत्री Amit Shah Ministry of Cooperation (2021 में बनाया गया) के भी प्रमुख हैं; NAFEX.in Launch व्यापक Cooperative Sector Digitisation (डिजिटलीकरण) अभियान का हिस्सा।



| Click to Connect Now.



- Price Volatility Problem (मूल्य अस्थिरता समस्या): भारत सालाना ₹1.5 लाख करोड़ Post-Harvest Losses (कटाई के बाद नुकसान) में खोता है; Price Volatility से ₹40,000+ करोड़ किसानों की आय का नुकसान।

COAL GASIFICATION — BHARAT COAL GASIFICATION & CHEMICALS LIMITED (BCGCL), ODISHA

Ministry: Ministry of Coal

PIB Date: 20th June 2026

Easy Explanation (सरल व्याख्या)

भारत के पास 361 अरब टन Coal (कोयला) भंडार है — दुनिया में सबसे बड़े में से एक। दशकों से लगभग सभी का उपयोग Electricity (बिजली) उत्पादन के लिए जलाने में हुआ है। लेकिन कोयला सीधे जलाना सबसे गंदा तरीका है: अधिक CO₂, Particulate Pollution (कण प्रदूषण), Ash Disposal (राख निपटान) की समस्याएँ।

Coal Gasification (कोयला गैसीकरण) एक स्वच्छ विकल्प है जो कोयला जलाता नहीं — बल्कि High Pressure और Temperature पर Steam (भाप) और Oxygen से कोयले को Syngas (Synthetic Gas — सिंथेटिक गैस, H₂+CO+CO₂ का मिश्रण) में बदलता है। इस Syngas का उपयोग Chemicals (रसायन), Fertilisers (उर्वरक), Fuels (ईंधन) और Hydrogen (हाइड्रोजन) बनाने में हो सकता है।

राष्ट्रपति Droupadi Murmu और PM Modi ने इस सप्ताह Lakhanpur, Odisha में Bharat Coal Gasification & Chemicals Limited (BCGCL) की Foundationstone (नींव का पत्थर) रखी। BCGCL भारत के कोयले से Ammonium Nitrate (अमोनियम नाइट्रेट — खनन, निर्माण और खुदाई में उपयोग होने वाला Industrial Explosive) बनाएगा। अभी भारत अधिकांश Ammonium Nitrate आयात करता है। सरकार का लक्ष्य है: 2030 तक प्रति वर्ष 100 मिलियन टन कोयले का Gasification।

Key Terms (प्रमुख शब्द)

Term / शब्द	Definition / परिभाषा
Coal Gasification	Coal को Steam (भाप) और Oxygen से Syngas (H ₂ +CO+CO ₂) में बदलना; जलाने से स्वच्छ; Syngas का उपयोग Chemicals, Fertilisers, Hydrogen के लिए।



| Click to Connect Now.



BCGCL	Bharat Coal Gasification & Chemicals Limited — नई Entity (संस्था); Foundationstone Lakhanpur, Odisha में रखी गई; भारतीय कोयले से Ammonium Nitrate बनाएगी।
Syngas	कोयले के Gasification से बना Synthetic Gas (H_2+CO का मिश्रण); Ammonia (अमोनिया), Methanol (मेथेनॉल), Hydrogen सहित कई Chemical Products के लिए Feedstock (कच्चा माल)।
Ammonium Nitrate	Industrial Explosive (औद्योगिक विस्फोटक); Mining, Construction (निर्माण), Quarrying (पत्थर खनन) के लिए महत्वपूर्ण; अभी भारत भारी मात्रा में आयात करता है — BCGCL इसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य।
Underground Coal Gasification (UCG)	जमीन के अंदर ही Coal Seams (कोयला परत) का In-Situ Gasification (स्थानीय गैसीकरण) बिना Mining किए; India इसे Deep/Difficult Coal Seams के लिए Explore कर रहा है।
100 MT Gasification Target	सरकार का लक्ष्य: 2030 तक प्रति वर्ष 100 मिलियन टन कोयला Gasify करना — कोयला उत्पादक राज्यों में कई बड़े Projects के माध्यम से।

Important Points for UPSC (UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु)

- भारत के Coal Reserves: 361 अरब टन (विश्व में 5वें सबसे बड़े); Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, MP प्रमुख कोयला राज्य — Lakhanpur (Odisha) रणनीतिक रूप से स्थित।
- Coal Gasification बनाम Coal Burning: Burning = सीधे CO_2 + Particulates; Gasification = CO_2 Capture के विकल्प (CCUS — Carbon Capture, Utilisation and Storage — कार्बन पकड़ना और संग्रहीत करना) के साथ Syngas; स्वच्छ Chemistry लेकिन Zero-Carbon नहीं।
- BCGCL Product: Ammonium Nitrate — खनन Explosives, Quarrying, Construction Blasting में उपयोग; भारत ~8-10 लाख टन/वर्ष आयात करता है।
- Methanol Economy Connection: Coal Gasification → Methanol → Methanol Blended with Petrol (M15, M20); India का Methanol Economy Programme (मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम) Coal-Derived Methanol का Transport Fuel के रूप में उपयोग।
- CIL (Coal India Limited) की भूमिका: दुनिया की सबसे बड़ी Coal Mining Company; Dankuni (WB) और Talcher (Odisha) में Coal Gasification Projects — BCGCL इस Ecosystem में नया जुड़ाव।





PRACTICE QUESTIONS

10 PRELIMS QUESTIONS

Q1. 21 जून 2026 को कोलकाता में Commissioned जहाजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. INS Dunagiri एक Project 17A Stealth Frigate है — यह अपनी श्रेणी का पाँचवाँ जहाज है।
2. INS Sanshodhak एक Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft है जो Torpedoes और Sonar से लैस है।
3. INS Agray Arnala-class का पाँचवाँ जहाज है जो उथले पानी में Anti-Submarine Operations के लिए बनाया गया है।
4. तीनों जहाज Warship Design Bureau द्वारा डिज़ाइन और Garden Reach Shipbuilders and Engineers, कोलकाता में निर्मित हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

Q2. India के Critical Minerals Mission के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. 7वें Tranche में 88 में से कुल 56 Blocks सफलतापूर्वक नीलाम किए गए।
2. Exploration Licence (EL) Blocks पहली बार Arunachal Pradesh, Uttar Pradesh और Odisha में नीलाम किए गए।





3. नीलाम खनिजों में Graphite, Rare Earth Elements, Vanadium, Titanium और Rock Phosphate शामिल हैं।
4. India का Critical Mineral Mission पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q3. Rakhigarhi पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

1. यह लगभग 550 Hectares में फैला Indus-Saraswati Civilisation का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है।
2. इस स्थल से कंकाल अवशेष Anthropological Survey of India के New Delhi स्थित Repository में स्थानांतरित किए गए हैं।
3. मानव कंकाल अवशेष Harappan लोगों की वंशावली और प्रवास पैटर्न के बारे में आनुवंशिक साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।

नीचे दिए गए Code का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1

Q4. India 2025 में दुनिया का शीर्ष Ship Recycling Nation बना। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?



| Click to Connect Now.



1. UNCTAD Data के अनुसार 2024 में 30.1% से बढ़कर 2025 में India की वैश्विक हिस्सेदारी 35.4% हो गई।
2. Gujarat का Alang Ship Recycling Yard India की प्राथमिक Ship Recycling सुविधा है।
3. इस उपलब्धि ने Maritime India Vision 2030 के Ship Recycling लक्ष्य को पाँच वर्ष पहले पूरा किया।
4. India ने 2019 में Hong Kong Convention के अनुरूप Recycling of Ships Act पारित किया।

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q5. India में Access and Benefit Sharing (ABS) Framework किस कानून के तहत लागू किया जाता है?

- (a) Environment (Protection) Act, 1986
- (b) Wildlife (Protection) Act, 1972
- (c) Biological Diversity Act, 2002
- (d) Forest Rights Act, 2006

Q6. DISHA 2.0 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. DISHA का अर्थ है Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice।
2. इस योजना में Common Service Centres के माध्यम से Tele-Law Consultations, Lok Adalats और जेल Legal Aid Clinics शामिल हैं।
3. भारतीय संविधान में Article 39A के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता की गारंटी दी गई है।
4. NALSA (National Legal Services Authority) की अध्यक्षता Chief Justice of India करते हैं।

उपरोक्त में से कौन से सही हैं?





- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) 1, 2, 3 और 4
- (d) केवल 1 और 3

Q7. INCOIS, जिसने इस सप्ताह विशेष El Niño Bulletins लॉन्च किए, मुख्य रूप से किस मंत्रालय से संबंधित है?

- (a) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
- (b) Ministry of Earth Sciences
- (c) Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- (d) Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Q8. India के Space Programme से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

Mission/Programme	विवरण
1. Gaganyaan	India का Crewed Spaceflight Programme
2. SpaDeX	Space Docking Experiment; Docking Technology का परीक्षण
3. PSLV	Chandrayaan-3 के लिए उपयोग किया गया Heavy-Lift Rocket
4. IN-SPACe	India के Private Space Sector का Regulator

कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक





Q9. India के Ethanol Blending Programme के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. India का Petrol में 20% Ethanol Blending (E20) का राष्ट्रीय लक्ष्य है।
2. 2G Ethanol, Rice Straw और Bagasse जैसे Agricultural Residues से बनता है जिससे खाद्य बनाम ईंधन का कोई संघर्ष नहीं होता।
3. इस Programme से नौ Ethanol Supply Years में ₹87,000 करोड़ से अधिक Foreign Exchange की बचत हुई है।

सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q10. Bharat Coal Gasification & Chemicals Limited (BCGCL) की Foundation Stone Odisha के Lakhanpur में रखी गई। BCGCL द्वारा निर्मित किया जाने वाला प्राथमिक उत्पाद कौन सा है?

- (a) Transport Fuel Blend के रूप में उपयोग के लिए Synthetic Methanol
- (b) खनन और निर्माण में Industrial Explosive के रूप में उपयोग के लिए Ammonium Nitrate
- (c) Green Energy Applications के लिए Blue Hydrogen
- (d) Thermal Power Generation में प्रत्यक्ष उपयोग के लिए Synga

PRELIMS ANSWERS & EXPLANATIONS

Q1. Answer: (b) Only three



| Click to Connect Now.



Statement 2 WRONG — INS Sanshodhak Survey Vessel (सर्वेक्षण जहाज) है, Anti-Submarine Warfare craft नहीं। यह Hydrographic Surveys और Oceanographic Research के लिए है। INS Agray ASW-SWC है। Statements 1, 3, 4 सही हैं।

Q2. Answer: (a) 1, 2 and 3 only

Statement 4 WRONG — Critical Minerals Mission Ministry of Mines के अंतर्गत है, Ministry of Environment के नहीं। MoEFCC Mining Projects के लिए Environment Clearances देता है लेकिन Nodal Ministry (केंद्रीय मंत्रालय) नहीं है।

Q3. Answer: (a) 1 and 3 only

Statement 2 WRONG — Skeletal Remains AnSI के KOLKATA Repository में स्थानांतरित किए गए, New Delhi में नहीं। यह एक Frequently Tested Factual Trap (बार-बार परीक्षित तथ्यात्मक जाल) है।

Q4. Answer: (d) 1, 2, 3 and 4

सभी चार Statements सही हैं। 35.4% Market Share (UNCTAD Data), Alang Gujarat (Primary Yard), MIV 2030 Target 5 वर्ष पहले प्राप्त, Recycling of Ships Act 2019 (Hong Kong Convention) — सभी PIB से पुष्टि।

Q5. Answer: (c) Biological Diversity Act, 2002

ABS Framework India में Biological Diversity Act, 2002 के तहत लागू है। यह Act NBA, State Biodiversity Boards और BMCs की स्थापना करता है और CBD और Nagoya Protocol के तहत India की जिम्मेदारियाँ पूरी करता है।

Q6. Answer: (c) 1, 2, 3 and 4

सभी चार Statements सही हैं। DISHA = Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice; Tele-Law, Lok Adalats, Prison Legal Aid सभी Components; Article 39A Free Legal Aid का जनादेश देता है; NALSA की अध्यक्षता Chief Justice of India करते हैं।

Q7. Answer: (b) Ministry of Earth Sciences

INCOIS (Indian National Centre for Ocean Information Services) Ministry of Earth Sciences (MoES) के तहत है, Hyderabad में मुख्यालय। Agriculture, Environment या Fisheries Ministries के तहत नहीं।

Q8. Answer: (b) Only three





Statement 3 WRONG — PSLV भारत का Workhorse Rocket है लेकिन Chandrayaan-3 LVM3 (Launch Vehicle Mark 3, पहले GSLV Mk III) से Launch हुआ, PSLV से नहीं। Statements 1 (Gaganyaan), 2 (SpaDeX) और 4 (IN-SPACe) सही हैं।

Q9. Answer: (d) 1, 2 and 3

तीनों Statements सही हैं। E20 India का National Petrol Blending Target है; 2G Ethanol Rice Straw जैसे Agricultural Residues से बनता है; ₹87,320 करोड़ Forex 9 Ethanol Supply Years में बचाई।

Q10. Answer: (b) Ammonium Nitrate

BCGCL का Primary Product Ammonium Nitrate है — Mining, Quarrying और Construction में उपयोग होने वाला Industrial Explosive। PIB Release विशेष रूप से इसे 'Coal-to-Ammonium Nitrate Project' कहता है।

2 MAINS QUESTIONS & MODEL ANSWERS

MAINS QUESTION 1 — 150 WORDS:

MAINS QUESTION 1 — 150 शब्द:

India का दुनिया का शीर्ष Ship Recycling Nation बनना, INS Dunagiri, Sanshodhak और Agray का Tri-Commissioning, और NAFEX.in का Launch — ये सभी एक ही सप्ताह में हुए। इन प्रतीत होने वाली असंबंधित घटनाओं को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र क्या है और ये सामूहिक रूप से India की समुद्री और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या संकेत देते हैं?

MAINS QUESTION 2 — 250 शब्द:

'India के Space Odyssey और Emerging Technology Ecosystem पर PIB Backgrounders एक ऐसे देश को उजागर करते हैं जो एक साथ अपनी उपलब्धियों पर गर्वित है और अभी तय की जानी वाली दूरी के प्रति ईमानदार भी



है।' India की Technology यात्रा — उसकी वास्तविक उपलब्धियों और संरचनात्मक बाधाओं — का आलोचनात्मक परीक्षण करें और अगले दशक के लिए नीति मार्ग सुझाएँ।

Model Answer 1 (आदर्श उत्तर)

इन तीनों घटनाओं का सामान्य सूत्र है **Maritime Power** — India का अपने Oceanic Neighbourhood को आर्थिक, सैन्य और संस्थागत रूप से Dominate करने का व्यवस्थित, बहु-आयामी प्रयास।

INS Dunagiri, Sanshodhak और Agray का Tri-Commissioning नौसैनिक **Atmanirbharta** की परिपक्वता दर्शाता है। भारत अब युद्धपोत विदेश से नहीं खरीदता — वह Warship Design Bureau से Design करवाता है, GRSE में बनवाता है और एक साथ तीन Commission करता है। Indo-Pacific में समुद्री प्रभुत्व के लिए यह क्षमता अनिवार्य है।

दुनिया का शीर्ष **Ship Recycling Nation** बनना आर्थिक समुद्री प्रभुत्व है। Alang जैसे Yards केवल जहाज नहीं तोड़ते — वे Steel और धातु पुनर्प्राप्त कर Secondary Industry को पोषित करते हैं और 50,000+ रोजगार देते हैं।

NAFEX.in समुद्री अर्थव्यवस्था का कृषि आयाम है — दलहन, तिलहन, प्याज जैसी वस्तुएँ बंदरगाहों से वैश्विक बाजारों तक जाती हैं। E-Auction से पारदर्शी Price Discovery India की Export Competitiveness बढ़ाती है।

तीनों मिलकर संकेत देते हैं कि भारत अब केवल Coastline वाला देश नहीं — वह **Maritime Strategy** वाला देश बन रहा है जिसमें रक्षा, व्यापार, पुनःचक्रण और किसान की आय एक ही राष्ट्रीय दृष्टि से जुड़े हैं।

Model Answer (आदर्श उत्तर)

India की Technology यात्रा वास्तव में उल्लेखनीय है और वास्तव में अधूरी भी — ईमानदार नीति-निर्माण के लिए दोनों सत्यों को एक साथ स्वीकारना होगा।

वास्तविक उपलब्धियाँ:

PSLV के 60+ सफल Launches विश्वस्तरीय Reliability के प्रमाण हैं। Chandrayaan-3 का चंद्रमा के South Pole के पास Landing एक वास्तविक Planetary First था जिसे कोई देश पहले नहीं कर पाया था। दो दशकों में 2.3 लाख Startups और 119 Unicorns का Ecosystem दिखाता है कि उद्यमशीलता की जड़ें गहरी हैं। Bioeconomy का \$10 बिलियन से \$190 बिलियन तक 19 गुना विस्तार प्रमाणित करता है कि Life Sciences में Science-to-Commerce Translation सफलतापूर्वक काम कर रही है। IndiaAI Mission का Varya जैसा Output दर्शाता है कि Frugal Innovation (किफायती नवाचार) एक वैध और प्रभावी रणनीति है, न केवल बजटीय मजबूरी।

संरचनात्मक बाधाएँ:

India GDP का मात्र 0.65% R&D पर खर्च करता है — China का एक तिहाई और South Korea का एक चौथाई। बिना पर्याप्त R&D निवेश के India दूसरों की Frontier Science का अनुप्रयोगकर्ता बना रहेगा, निर्माता नहीं।

Semiconductor Mission शून्य Manufacturing Capability से शुरू हो रही है जबकि Taiwan और South Korea को 40 वर्ष की बढ़त है। India में Chip Design की ताकत (Qualcomm, AMD, Intel के बड़े R&D Centres)

Manufacturing में नहीं बदल पाई — 'Design to Fab' का सेतु अभी नहीं बना। AI Infrastructure बन रहा है लेकिन छोटे Startups और Academic Researchers के लिए पहुँच अभी भी सीमित है।

अगले दशक के लिए नीति मार्ग:

तीन प्राथमिकताएँ आवश्यक हैं। **प्रथम**, R&D व्यय को GDP के 1.5% तक दोगुना किया जाए — सार्वजनिक वित्तपोषण (DST, DBT, DRDO) और Corporate R&D के लिए Tax Incentives के मेल से। **द्वितीय**, Technology Commons बनाए जाएँ — GPU Clusters, Biotech Labs, Quantum Computers को Startups, Academia और MSMEs के लिए Subsidised Rates पर उपलब्ध कराया जाए। **तृतीय**, Education को Innovation से जोड़ा जाए — Patent Filing Support, Technology Transfer Offices और Industry-Academia Joint Research Mandates के माध्यम से IIT-Startup-IP Pipeline को मजबूत किया जाए।

Space Odyssey का आख्यान — Soviet Rocket उधार लेने से चंद्रमा के South Pole पर Landing तक — भारत की Technology Policy का सार है: धैर्यपूर्ण निवेश, किफायती नवाचार और दशकों तक अनुशासित क्रियान्वयन। Emerging Technology Ecosystem को यही धैर्य, अभी और बड़े पैमाने पर, चाहिए।





PIB

साप्ताहिक संक्षेप

भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम

UPSC अभ्यर्थियों के लिए चुनींदा PIB जानकारीयाँ



NETRA AEW&C
भारत की आँखें
आकाश में



न्यूक्लियर
हाइड्रोजन
स्वच्छ ऊर्जा.
तैयार भविष्य.



भारत-जापान
शिखर वार्ता
AI, नवाचार और
रणनीतिक सहयोग



आरोग्य सेतु 2.0
स्वास्थ्य पहुँच
का नया वुग



UPI
दुनिया की ओर
अब ग्रीस में



Table of Contents

IAF NETRA — FINAL OPERATIONAL CLEARANCE FOR INDIGENOUS AEW&C SYSTEM	4
EASY EXPLANATION.....	4
KEY TERMS:.....	5
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	5
DAE — WORLD'S FIRST NUCLEAR HYDROGEN FACILITY USING COPPER-CHLORINE CYCLE.....	7
EASY EXPLANATION.....	7
KEY TERMS:.....	7
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	8
PM MODI STATE VISIT TO SEYCHELLES — 19 BILATERAL OUTCOMES.....	9
EASY EXPLANATION.....	9
KEY TERMS:.....	9
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	9
INDIA-JAPAN 16TH ANNUAL SUMMIT — 16-POINT STRATEGIC ROADMAP	11
EASY EXPLANATION.....	11
KEY TERMS:.....	11
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	11
NCORD 10TH APEX MEETING — VISION DOCUMENT ON DRUG CONTROL 2026-2029.....	13
EASY EXPLANATION.....	13
KEY TERMS:.....	13
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	13
AAROGYA SETU 2.0 & DIGITAL HEALTH LAUNCHES — 16TH CCHFW.....	15
EASY EXPLANATION.....	15
KEY TERMS:.....	15
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	15
VB-G RAM G ACT — INDIA'S REVISED RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE IN FORCE	17
EASY EXPLANATION.....	17
KEY TERMS:.....	17
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	17
DIGITAL INDIA — 11 YEARS: PIB BACKGROUNDER	19
EASY EXPLANATION.....	19
KEY TERMS:.....	19



IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	19
TIGER REINTRODUCTION — NATIONAL WORKSHOP, ALWAR, RAJASTHAN	21
EASY EXPLANATION	21
KEY TERMS:	21
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	21
INDIA-EU SHIP RECYCLING — THREE ALANG YARDS READY FOR EU RECOGNITION	23
EASY EXPLANATION	23
KEY TERMS:	23
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	23
NINE YEARS OF GST — PIB BACKGROUNDER	25
EASY EXPLANATION	25
KEY TERMS:	25
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	25
FCRA 2.0 PORTAL + E-OCI CARD — HOME MINISTRY LAUNCHES	27
EASY EXPLANATION	27
KEY TERMS:	27
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	27
UPI GOES LIVE IN GREECE — INDIA'S PAYMENT TECH GOES EUROPEAN	29
EASY EXPLANATION	29
KEY TERMS:	29
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	29
NPPA + PHARMA JAN SAMADHAN — INTEGRATED DRUG PRICE GRIEVANCE SYSTEM	31
EASY EXPLANATION	31
KEY TERMS:	31
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	31
AIR SUVIDHA 2.0 — EBOLA HEALTH SCREENING AT POINTS OF ENTRY	33
EASY EXPLANATION	33
KEY TERMS:	33
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	33
INS TRIKAND RESPONDS TO PIRACY — MV GOLDEN ARSENAL, GULF OF ADEN	35
EASY EXPLANATION	35
KEY TERMS:	35
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	35
RAJASTHAN-HARYANA YAMUNA WATER PROJECT AGREEMENT	37





EASY EXPLANATION.....	37
KEY TERMS:.....	37
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	37
INDIA-JAPAN AI JOINT STATEMENT — FIRST BILATERAL AI PARTNERSHIP	39
EASY EXPLANATION.....	39
KEY TERMS:.....	39
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	39
BHASHINI — MULTILINGUAL AI SHOWCASED AT NCEG 2026	41
EASY EXPLANATION.....	41
KEY TERMS:.....	41
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	41
BHARAT TAXI — COOPERATIVE-BASED TAXI SERVICE LAUNCHED IN GUJARAT.....	43
EASY EXPLANATION.....	43
KEY TERMS:.....	43
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	43
HIGH-SPEED RAIL — PIB BACKGROUNDER ON INDIA'S BULLET TRAIN JOURNEY	45
EASY EXPLANATION.....	45
KEY TERMS:.....	45
IMPORTANT POINTS FOR UPSC:	45
PRACTICE QUESTIONS.....	47
10 PRELIMS QUESTIONS — UPSC PRELIMS STYLE	47
2 MAINS QUESTIONS.....	50
PRELIMS ANSWERS & EXPLANATIONS	51

IAF NETRA — FINAL OPERATIONAL CLEARANCE FOR INDIGENOUS AEW&C SYSTEM

Ministry: Ministry of Defence / DRDO / Indian Air Force

PIB Date: 25th June 2026

Easy Explanation

मान लीजिए आपको किसी देश के हवाई क्षेत्र (airspace) की रक्षा करनी है। जमीन पर लगे रडार सिर्फ क्षितिज (horizon) तक ही देख पाते हैं — पहाड़, पृथ्वी की गोलाई और ऊँचाई की सीमाएँ अंधे क्षेत्र (blind spots) बना देती हैं। नीची उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान इन रडारों की पकड़ से आसानी से बच सकता है। यहीं पर AEW&C (Airborne Early Warning and Control — हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली) प्रणाली काम आती है। यह असल में एक 'उड़ता हुआ रडार स्टेशन' है — एक विमान जिस पर शक्तिशाली रडार लगा होता है, जो ऊँचाई



| Click to Connect Now.



पर उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ देख सकता है: दुश्मन के लड़ाकू विमान, कूज़ मिसाइलें, ड्रोन, यहाँ तक कि समुद्र की सतह पर मौजूद जहाज़ भी। यह तुरंत यह पूरी तस्वीर सभी भारतीय लड़ाकू विमानों और ज़मीनी कमान केंद्रों को भेज देता है, यानी आसमान में एक युद्धक्षेत्र समन्वयक (battlefield coordinator) की तरह काम करता है। भारत ने पहले इज़राइल से ऐसी ही एक प्रणाली आयात की थी — रूसी IL-76 विमान पर लगा फाल्कन AWACS। लेकिन विदेशी प्रणाली पर निर्भर रहने में जोखिम है: संकट के समय तकनीक देने से इनकार, आपूर्ति शृंखला (supply chain) पर निर्भरता, और ज़्यादा रखरखाव लागत। इसलिए DRDO ने भारत की अपनी प्रणाली विकसित की — जिसका नाम नेत्र (Netra) रखा गया, संस्कृत में जिसका अर्थ 'आँख' है। 25 जून को नेत्र को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस (FOC — अंतिम परिचालन स्वीकृति) मिली, यानी इसने हर परीक्षण, हर परख और हर सत्यापन पूरा कर लिया है और अब इसे पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार घोषित किया गया है। नेत्र पहले ही असली अभियानों में अपनी क्षमता साबित कर चुका है — इसका इस्तेमाल 2019 के बालाकोट हमलों और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था।

Key Terms:

Term	Definition
AEW&C	Airborne Early Warning and Control — एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन, जो ज़मीनी रडार प्रणालियों से कहीं आगे तक रडार की पहुँच बढ़ा देता है और युद्ध प्रबंधन (battle management) में मदद करता है।
AWACS	Airborne Warning and Control System — AEW&C जैसी ही प्रणाली; फाल्कन (Phalcon) भारत का इज़राइली EL/W-2090 रडार वाला आयातित AWACS है, जो IL-76 विमान पर लगा है।
Netra	भारत की स्वदेशी AEW&C प्रणाली; संस्कृत में 'आँख'; DRDO की CABS और LRDE प्रयोगशालाओं ने इसे विकसित किया; इसे Embraer ERJ-145 विमान पर लगाया गया है।
FOC	Final Operational Clearance — अंतिम परिचालन स्वीकृति; यह प्रमाणपत्र दिखाता है कि प्रणाली ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब बिना किसी रोक-टोक के युद्ध में इस्तेमाल हो सकती है।
IOC	Initial Operational Clearance — प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति; नेत्र को यह 2017 में मिली थी; 2026 में FOC मिलना इसकी पूर्ण परिपक्वता दर्शाता है।
AESA Radar	Active Electronically Scanned Array — एक उन्नत रडार जिसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता; यह तेज़, ज़्यादा सटीक और जाम करना मुश्किल होता है; नेत्र में इसी का इस्तेमाल किया गया है।
CABS	Centre for Airborne Systems, Bengaluru — DRDO की वह प्रयोगशाला जिसने नेत्र के विकास का नेतृत्व किया; इसने पूरे सिस्टम का डिज़ाइन और उड़ान-परीक्षण संभाला।
Phalcon AWACS	इज़राइल का EL/W-2090 रडार, जो रूसी IL-76 विमान पर लगा है; भारत का आयातित AWACS; नेत्र इसका छोटा, स्वदेशी पूरक है।

Important Points for UPSC:

- नेत्र = DRDO (CABS + LRDE, बेंगलुरु) का AESA रडार, जो Embraer ERJ-145 विमान पर लगा है — MCQ के लिए यह सूत्र याद रखें।
- LRDE (Electronics & Radar Development Establishment), बेंगलुरु ने AESA रडार डिज़ाइन किया — यह CABS से अलग है, जिसने पूरे सिस्टम का एकीकरण (integration) किया।





- नेत्र लगभग 240 डिग्री तक हवाई कोणीय (azimuthal) रडार कवरेज देता है; यह 375 किमी तक की दूरी पर लक्ष्यों का पता लगा सकता है — लड़ाकू विमान, कूज़ मिसाइलें, UAV और सतही जहाज़।
- IOC (2017) से FOC (2026) तक: शुरुआती शामिल होने से पूर्ण युद्धक प्रमाणीकरण तक की 9 साल की यात्रा — तेजस LCA जैसा ही पैटर्न।
- भारत के पास फिलहाल 3 नेत्र विमान हैं; बेहतर गैलियम नाइट्राइड TRM वाले नेत्र Mk1A और Airbus A321 प्लेटफॉर्म पर नेत्र Mk2 (6 विमानों को मंजूरी) की योजना है।
- नेत्र, फाल्कन AWACS का पूरक है: फाल्कन = बड़ा, ज़्यादा देर उड़ने वाला, 360 डिग्री कवरेज (IL-76 पर आयातित); नेत्र = मध्यम आकार, तेज़ी से तैनात होने वाला, स्वदेशी (ERJ-145 पर)।
- युद्ध में परखा गया: नेत्र का इस्तेमाल बालाकोट हमलों (2019) और ऑपरेशन सिंदूर (2025) में हो चुका है — यह सिर्फ प्रदर्शन के लिए बना सिस्टम नहीं है।
- भारत अब उन गिने-चुने देशों (अमेरिका, रूस, चीन, इज़राइल, EU) की सूची में शामिल हो गया है जो स्वदेशी रूप से AEW&C प्रणाली विकसित करने में सक्षम हैं।





DAE — WORLD'S FIRST NUCLEAR HYDROGEN FACILITY USING COPPER-CHLORINE CYCLE

Ministry: Department of Atomic Energy / IGCAR / BARC

PIB Date: 26th June 2026

Easy Explanation

जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) की जगह लेने के लिए दुनिया को बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की ज़रूरत है — स्टील बनाने, खाद उत्पादन, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए। लेकिन आज 'ग्रीन' हाइड्रोजन बनाने के लिए सौर या पवन ऊर्जा से भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है, और इसकी लागत प्रति किलो 400-500 रुपये तक आती है। वैज्ञानिक लंबे समय से एक और तरीका जानते हैं: थर्मोकेमिकल साइकिल (thermochemical cycle) — रासायनिक प्रतिक्रियाएँ, जो सिर्फ गर्मी से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं, बिजली की बहुत कम ज़रूरत होती है। कॉपर-क्लोरीन (Cu-Cl) साइकिल तांबे और क्लोरीन के यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का इस्तेमाल करता है, जो बार-बार दोहराकर पानी से लगातार हाइड्रोजन निकालती रहती है। इसे केवल लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए — अन्य थर्मोकेमिकल प्रक्रियाओं से कहीं कम — और बिजली भी बहुत कम लगती है। यह गर्मी कहाँ से आती है? परमाणु रिएक्टर से। कलपक्कम स्थित भारत का फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) अपने संचालन के दौरान भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। अब इस परमाणु गर्मी को Cu-Cl हाइड्रोजन उत्पादन चक्र चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 26 जून को परमाणु ऊर्जा विभाग ने दुनिया की पहली ऐसी सुविधा का उद्घाटन किया, जो परमाणु प्रोसेस हीट (process heat) को Cu-Cl थर्मोकेमिकल साइकिल के साथ जोड़कर हाइड्रोजन बनाती है। मुंबई स्थित BARC द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र (technology demonstration plant) है — जो यह साबित करता है कि यह अवधारणा (concept) काम करती है, और इलेक्ट्रोलिसिस (electrolysis) की तुलना में संभावित रूप से बहुत कम लागत पर कार्बन-मुक्त हाइड्रोजन का रास्ता खोलती है।

Key Terms:

Term	Definition
Cu-Cl Thermochemical Cycle	तांबे और क्लोरीन की रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला, जो गर्मी (लगभग 500 डिग्री सेल्सियस) का इस्तेमाल कर पानी को H ₂ और O ₂ में तोड़ देती है; इसे BARC ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है।
FBTR	Fast Breeder Test Reactor — भारत का एकमात्र चालू सोडियम-कूल्ड फास्ट रिएक्टर; यह IGCAR, कलपक्कम में स्थित है और परमाणु प्रोसेस हीट प्रदान करता है।
IGCAR	Indira Gandhi Centre for Atomic Research, कलपक्कम, तमिलनाडु — भारत की प्रमुख फास्ट रिएक्टर अनुसंधान संस्था; इसकी स्थापना 1971 में हुई थी।
BARC	Bhabha Atomic Research Centre, मुंबई — इसने Cu-Cl प्रक्रिया को स्वदेशी रूप से विकसित किया; यह भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है।
Nuclear Hydrogen	परमाणु गर्मी (थर्मोकेमिकल) या परमाणु बिजली (इलेक्ट्रोलिसिस) का इस्तेमाल कर बनाई गई हाइड्रोजन; यदि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल हो तो यह कार्बन-मुक्त होती है।
PFBR	Prototype Fast Breeder Reactor — 500 मेगावाट का रिएक्टर; कलपक्कम में निर्माणाधीन; भारत के तीन-चरण परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण।
India's 3-Stage Nuclear Programme	पहला चरण: PHWR (प्राकृतिक यूरेनियम); दूसरा चरण: FBR (प्लूटोनियम); तीसरा चरण: थोरियम रिएक्टर — FBTR पहले चरण को दूसरे चरण से जोड़ता है।

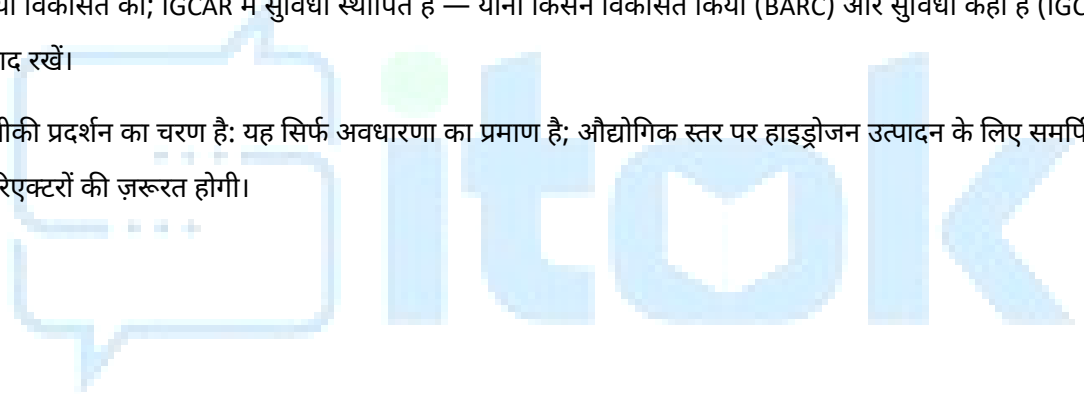


| Click to Connect Now.



Important Points for UPSC:

- दुनिया में पहली बार: इससे पहले किसी भी देश ने फास्ट रिएक्टर की परमाणु प्रोसेस हीट को Cu-Cl थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन उत्पादन चक्र से नहीं जोड़ा था — भारत इसमें अग्रणी है।
- Cu-Cl साइकिल का तापमान: अधिकतम लगभग 500 डिग्री सेल्सियस (जबकि सल्फर-आयोडीन साइकिल को 850+ डिग्री सेल्सियस चाहिए) — इससे यह ज़्यादा तरह के परमाणु रिएक्टरों के साथ काम करने लायक बनता है।
- इलेक्ट्रोलिसिस से तुलना: Cu-Cl साइकिल के इलेक्ट्रोलिसिस चरण में केवल 0.5-1.0 वोल्ट लगते हैं (पारंपरिक जल-इलेक्ट्रोलिसिस के 1.23+ वोल्ट के मुकाबले) — यानी काफी कम बिजली।
- कलपक्कम का FBTR: भारत का एकमात्र चालू सोडियम-कूल्ड फास्ट रिएक्टर; 40 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है; प्लूटोनियम-यूरेनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का इस्तेमाल करता है; इसकी प्रोसेस हीट अब हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल हो रही है।
- PFBR (Prototype Fast Breeder Reactor, 500 MW): कलपक्कम में निर्माणाधीन; चालू होने पर बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कहीं ज़्यादा प्रोसेस हीट उपलब्ध कराएगा।
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़ाव: यह तकनीक 'न्यूक्लियर हाइड्रोजन' का रास्ता देती है — कार्बन-मुक्त, और नवीकरणीय ऊर्जा से बनी ग्रीन हाइड्रोजन से संभावित रूप से सस्ती।
- BARC ने प्रक्रिया विकसित की; IGCAR में सुविधा स्थापित है — यानी किसने विकसित किया (BARC) और सुविधा कहाँ है (IGCAR), इन दोनों में फर्क याद रखें।
- अभी यह तकनीकी प्रदर्शन का चरण है: यह सिर्फ अवधारणा का प्रमाण है; औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समर्पित परमाणु गर्मी और बड़े रिएक्टरों की ज़रूरत होगी।





PM MODI STATE VISIT TO SEYCHELLES — 19 BILATERAL OUTCOMES

Ministry: Prime Minister's Office / Ministry of External Affairs

PIB Date: 27th–29th June 2026

Easy Explanation

सेशेल्स हिंद महासागर में एक छोटा-सा द्वीपीय देश है — 115 द्वीप, 1.3 लाख लोग, और पर्यटन व मछली-पालन पर आधारित अर्थव्यवस्था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा (state visit) के लिए यह एक असामान्य गंतव्य लग सकता है। लेकिन भू-राजनीति (geopolitics) में आकार से महत्व तय नहीं होता। सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर के बीचोंबीच स्थित है, ठीक उन शिपिंग मार्गों पर जहाँ से दुनिया के 40% कंटेनर व्यापार का आवागमन होता है। चीन हिंद महासागर में भारी निवेश करता रहा है — अपनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्स' (String of Pearls — मोतियों की माला रणनीति) मौजूदगी बनाने की कोशिश में। भारत अपनी हिंद महासागर पहुँच के ज़रिये इसका मुकाबला करता रहा है। पीएम मोदी की 27-29 जून की सेशेल्स यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और इसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा, डिजिटल भुगतान (UPI सेशेल्स में लॉन्च हुआ), स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और शिक्षा से जुड़े 19 द्विपक्षीय समझौते हुए। भारत ने 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज (Special Economic Package) घोषित किया। पीएम मोदी को 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न' (Guardian of the Blue Horizon) से सम्मानित किया गया — यह सेशेल्स का सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान है, जिसे यात्रा से बस कुछ दिन पहले ही स्थापित किया गया था — यह सम्मान उनके पर्यावरणीय नेतृत्व, ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy — समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था) की वकालत, और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के समर्थन को मान्यता देता है। मोदी ने सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ — स्वर्ण जयंती वर्ष — के समारोह में भी शामिल हुए।

Key Terms:

Term	Definition
SIDS	Small Island Developing States — संयुक्त राष्ट्र की श्रेणी; सेशेल्स एक SIDS है; इन देशों को जलवायु संबंधी संवेदनशीलता, छोटी अर्थव्यवस्था और समुद्र-निर्भर आजीविका जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
Blue Economy	समुद्र और सागर से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ — मछली-पालन, नौवहन, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन; सेशेल्स की पूरी अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी पर आधारित है।
Guardian of Blue Horizon	सेशेल्स का सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान; इसे पाने वाले पहले व्यक्ति पीएम मोदी बने; यह पर्यावरणीय नेतृत्व और SIDS की वकालत को मान्यता देता है।
String of Pearls	चीन की हिंद महासागर में बंदरगाह और सुविधाएँ बनाने की रणनीति; इसका संतुलन बनाना भारत का लक्ष्य है।
IORA	Indian Ocean Rim Association — 23 सदस्य देशों वाला संगठन; भारत और सेशेल्स दोनों इसके सदस्य हैं; यह ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है।
\$175 Million SEP	पीएम मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज; सेशेल्स के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए अनुदान और ऋण-सुविधाएँ (lines of credit)।
SAGAR	Security and Growth for All in the Region — पीएम मोदी की हिंद महासागर नीति; इसमें भारत एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (शुद्ध सुरक्षा प्रदाता) की भूमिका निभाता है।

Important Points for UPSC:



| Click to Connect Now.



- किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सेशेल्स की पहली यात्रा — देश की रणनीतिक हिंद महासागर स्थिति को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है।
- 19 द्विपक्षीय समझौते: रक्षा (समुद्री गश्ती जहाज़ की डिलीवरी), डिजिटल (UPI सेशेल्स में लॉन्च), स्वास्थ्य, अंतरिक्ष (ISRO का उपग्रह डेटा साझा करना), शिक्षा, कृषि, संस्कृति।
- 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज: बुनियादी ढांचे, जलवायु सहनशीलता (climate resilience) और आर्थिक विविधीकरण के लिए अनुदान और ऋण-सुविधाओं का मिश्रण।
- 'गार्जियन ऑफ ब्लू होराइज़न': सेशेल्स का सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान; इसे पहली बार पाने वाले व्यक्ति; इसे 24 जून 2026 को स्थापित किया गया — समारोह से सिर्फ 4 दिन पहले।
- मोदी ने सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया — विदेशी नेताओं को यह विशेषाधिकार कम ही मिलता है; उन्होंने अपने भाषण में SAGAR सिद्धांत पर ज़ोर दिया।
- स्वर्ण जयंती: सेशेल्स की स्वतंत्रता 29 जून 1976 को मिली थी; पीएम मोदी 50वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए।
- सेशेल्स में UPI: भारत के डिजिटल भुगतान की पहुँच एक और हिंद महासागरीय द्वीपीय देश तक फैली — मालदीव, श्रीलंका और मॉरीशस में पहले से UPI चल रहा है।
- चीन का मुकाबला: चीन ने सेशेल्स को गश्ती जहाज़ और बुनियादी ढांचा दिया है; भारत 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को द्वीपीय देशों तक विस्तार देकर गहरे जुड़ाव से इसका मुकाबला कर रहा है।





INDIA-JAPAN 16TH ANNUAL SUMMIT — 16-POINT STRATEGIC ROADMAP

Ministry: Prime Minister's Office / Ministry of External Affairs

PIB Date: 2nd July 2026

Easy Explanation

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 1-3 जुलाई 2026 को भारत का दौरा किया — यह सम्मेलन हर साल दोनों देशों की राजधानियों में बारी-बारी से आयोजित होता है। 2026 का शिखर सम्मेलन खासतौर पर समृद्ध रहा, जिसमें असाधारण रूप से कई क्षेत्रों में 16 समझौते हुए। इसकी मुख्य थीम तीन थीं: आर्थिक सुरक्षा (सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मा और AI की आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा), कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI (भारत की AI प्रतिभा और जापान का AI निवेश), और ऊर्जा सहनशीलता (energy resilience — दोनों देश पश्चिम एशिया में तेल आपूर्ति बाधित होने के प्रति संवेदनशील हैं)। तीन औपचारिक दस्तावेज़ अपनाए गए: भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा संयुक्त घोषणापत्र; AI सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य; और ऊर्जा सहनशीलता पर संयुक्त वक्तव्य। इसके अलावा, जापान डेयरी सहकारी समितियों के ज़रिये भारत भर में 1,000 बायोगैस संयंत्र (CBG पहल) स्थापित करने में मदद करेगा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश करेगा, और दवा सामग्री (pharmaceutical APIs) पर सहयोग करेगा। दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर 2027 को 'भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष' घोषित किया। पीएम ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत को अपनी शुरुआती द्विपक्षीय यात्राओं में से एक बनाया — जो भारत-जापान संबंध के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।

Key Terms:

Term	Definition
Special Strategic and Global Partnership	2014 से चली आ रही भारत-जापान की सबसे ऊँची द्विपक्षीय साझेदारी की श्रेणी; वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों राजधानियों में बारी-बारी से होता है।
Economic Security Declaration	सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, AI, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मा में मज़बूत आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाने की साझा प्रतिबद्धता।
Joint AI Statement	पहली बार हुआ द्विपक्षीय AI सहयोग वक्तव्य; सुरक्षित, मानव-केंद्रित AI अनुसंधान की रूपरेखा; IndiaAI मिशन और जापान के METI के बीच समझौता।
Energy Resilience Statement	रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार प्रबंधन, समुद्री ऊर्जा परिवहन, और स्वच्छ हाइड्रोजन-अमोनिया सहयोग का समन्वय करता है।
CBG Initiative	India-Japan Cooperative Biogas for Growth — जापान डेयरी सहकारी नेटवर्क के ज़रिये भारत में 1,000 बायोगैस और जैविक खाद संयंत्रों के लिए धन देता है।
LUPEX	Lunar Polar Exploration Mission — भारत-जापान की साझा चंद्र मिशन; 'साझा क्षितिज वर्ष 2027' की गतिविधियों में इसका ज़िक्र है।
PM Sanae Takaichi	जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री; 1-3 जुलाई 2026 को भारत आई; जापान की LDP पार्टी की नेता; शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ।

Important Points for UPSC:

- 16 समझौते: आर्थिक सुरक्षा पर भारत-जापान संयुक्त घोषणापत्र; AI पर संयुक्त वक्तव्य; ऊर्जा सहनशीलता पर संयुक्त वक्तव्य; साथ ही बैटरी, फार्मा, बायोगैस, गतिशीलता, बायोटेक, इंटरनेट गवर्नेंस और वित्तीय सेवाओं में 13 और समझौते (MoC/MoU)।



| Click to Connect Now.



- AI सहयोग: IndiaAI मिशन और जापान के METI के बीच कंप्यूटिंग संसाधन साझा करने का समझौता; IIT बॉम्बे + BharatGen + जापान का NII वैज्ञानिक तर्क वाले (scientific reasoning) LLM विकसित करेंगे; SarvamAI + Preferred Networks फाउंडेशन मॉडल पर काम करेंगे।
- 2030 तक जापान में 500 भारतीय AI पेशेवर: AI प्रतिभाओं की आवाजाही को आसान बनाने की द्विपक्षीय प्रतिबद्धता — भारत के इंजीनियर, जापान की उद्योग-मांग।
- बैटरी समझौता: जापान (पैनासोनिक आदि) वैश्विक बैटरी क्षेत्र में अग्रणी है; भारत को EV के लिए बैटरी चाहिए; यह सहयोग चीन पर निर्भरता घटाकर भरोसेमंद आपूर्ति शृंखला बनाता है।
- LUPEX: भारत-जापान की साझा चंद्र मिशन; ISRO-JAXA साझेदारी; चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के पानी की खोज करेगी।
- भारत-जापान संबंध: वार्षिक शिखर सम्मेलन 2000 से चल रहा है; दोनों क्वाड (Quad) के सदस्य हैं; दोनों को चीन की आपूर्ति शृंखला एकाग्रता और आर्थिक दबाव को लेकर चिंता है।
- CBG पहल: डेयरी सहकारी समितियों के ज़रिये 1,000 बायोगैस संयंत्र, जापान की तकनीकी मदद को सीधे भारत के ग्रामीण ऊर्जा और कृषि क्षेत्र से जोड़ते हैं।
- 2027 = भारत-जापान राजनयिक संबंधों के 75 साल; सांस्कृतिक उत्सव, युवा आदान-प्रदान, शैक्षणिक व खेल आयोजनों सहित पूरे साल समारोह होंगे।





NCORD 10TH APEX MEETING — VISION DOCUMENT ON DRUG CONTROL 2026-2029

Ministry: Ministry of Home Affairs / Narcotics Control Bureau

PIB Date: 26th June 2026

Easy Explanation

भारत में नशीले पदार्थों की गंभीर समस्या है। पंजाब का चिट्ठा (सिंथेटिक हेरोइन) संकट एक पूरी पीढ़ी को तबाह कर चुका है। पूर्वोत्तर में म्यांमार के गोल्डन ट्राएंगल से जुड़ी अफीम की खेती हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाह कोकीन व हेरोइन तस्करी गिरोहों के प्रवेश-द्वार बने हुए हैं। और डार्कनेट बाज़ार अब यह संभव बना रहे हैं कि किसी भी शहर में आपके दरवाज़े तक नशीले पदार्थ मंगवाए जा सकें। नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) भारत की शीर्ष अंतर-एजेंसी नशा-रोधी समन्वय संस्था है — यह NCB, राज्य पुलिस, सीमा शुल्क (customs), राजस्व खुफिया, तटरक्षक और 44 केंद्रीय मंत्रालयों को एक मंच पर लाती है। 26 जून को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10वीं शीर्ष-स्तरीय NCORD बैठक हुई, जिसमें 'विज़न डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026-2029' जारी किया गया — नशीले पदार्थों से लड़ने के लिए भारत की तीन साल की योजना। इस रणनीति के चार स्तंभ हैं: प्रवर्तन और अभियान (खुफिया-आधारित लक्षित कार्रवाई), अग्रगामी रसायन और सिंथेटिक ड्रग्स (नशीले पदार्थ बनने से पहले ही रासायनिक तत्वों पर नियंत्रण), मांग व नुकसान में कमी (युवाओं को नशे से दूर रखना, पुनर्वास केंद्रों का विस्तार), और क्षमता निर्माण व समन्वय (एजेंसियों का प्रशिक्षण, NDPS अदालतों की स्थापना)। शाह ने ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोज़ल फोर्टनाइट (Online Drugs Disposal Fortnight) भी शुरू किया — जिसमें देशभर में जब्त किए गए 2,09,500 किलो, यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए जा रहे हैं। इस रणनीति को यह कहकर संक्षेप में बताया गया: 'पहचानो, बाधित करो, नष्ट करो' (Detect, Disrupt, Destroy)।

Key Terms:

Term	Definition
NCORD	Narco-Coordination Centre — भारत की शीर्ष नशा-रोधी समन्वय संस्था; इसमें NCB, राज्य पुलिस, सीमा शुल्क, तटरक्षक और 44 केंद्रीय मंत्रालय शामिल होते हैं।
NCB	Narcotics Control Bureau — भारत की राष्ट्रीय नशा-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी; यह NDPS अधिनियम लागू करती है; UNODC और इंटरपोल के साथ समन्वय करती है।
NDPS Act 1985	Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act — भारत का मुख्य नशा-रोधी कानून; अपराध व दंड तय करता है; बड़ी मात्रा के मामलों में न्यूनतम सज़ा अनिवार्य है।
Vision Document 2026-2029	तीन साल की योजना; चार स्तंभ: प्रवर्तन, अग्रगामी रसायन नियंत्रण, मांग में कमी, क्षमता निर्माण; रणनीति: पहचानो, बाधित करो, नष्ट करो।
Precursor Chemicals	वैध रसायन जिन्हें नशीले पदार्थ बनाने में मोड़ा जा सकता है (जैसे हेरोइन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड, मेथ के लिए स्यूडोएफेड्रिन); इन पर नियंत्रण अहम है।
Synthetic Drugs	रासायनिक रूप से बनाए गए नशीले पदार्थ (मेथ, फेंटानिल, MDMA); ये पौधों से बनने वाले नशीले पदार्थों की जगह लेते जा रहे हैं; डार्कनेट इनके वितरण को आसान बनाता है।
ANTF	Anti-Narcotics Task Force — राज्य-स्तरीय विशेष इकाइयाँ; शाह ने राज्यों को ANTF को पूर्णकालिक समर्पित इकाइयों में बदलने का निर्देश दिया।

Important Points for UPSC:

- NCORD ढांचा: अब तक 15,876 ज़िला-स्तरीय बैठकें, 266 राज्य-स्तरीय बैठकें, 7 कार्यकारी समिति बैठकें, और 10 शीर्ष-स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं — यह एक विशाल समन्वय ढांचा दर्शाता है।



| Click to Connect Now.



- 2014-2026 प्रवर्तन: 1.84 लाख करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त; 89,896 करोड़ रुपये के नष्ट; 8,75,000 मामले दर्ज; 10,97,000 गिरफ्तारियाँ — जबकि 2004-2014 में सिर्फ 8,000 करोड़ रुपये नष्ट हुए थे, 1,73,000 मामले दर्ज हुए थे।
- ड्रग डिस्पोज़ल फोर्टनाइट: 6,000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,09,500 किलो नशीले पदार्थ नष्ट किए जाने हैं — दुनिया के सबसे बड़े एकल नशा-विनाश अभियानों में से एक।
- चार स्तंभ: (1) प्रवर्तन, खुफिया और अभियान; (2) अग्रगामी रसायन व सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण; (3) मांग व नुकसान में कमी; (4) क्षमता निर्माण, समन्वय व निगरानी।
- डार्कनेट खतरा: विज़न डॉक्यूमेंट खासतौर पर डार्कनेट के ज़रिये होने वाली तस्करी को संबोधित करता है — ऑनलाइन ऑर्डर होकर कूरियर से डिलीवर होने वाले नशीले पदार्थ; इसके लिए AI-आधारित निगरानी ज़रूरी है।
- विशेष NDPS अदालतें: शाह ने राज्यों को NDPS अधिनियम के मामलों के लिए समर्पित अदालतें स्थापित करने को कहा — इससे देरी घटेगी और सज़ा की दर बढ़ेगी।
- वित्तीय जांच अनिवार्यता: बड़ी मात्रा वाले मामलों में वित्तीय जांच (संपत्ति और धन के प्रवाह का पता लगाना) अब मानक प्रक्रिया बनेगी — इससे गिरोहों को आर्थिक रूप से तोड़ा जाता है।
- नशा मुक्त भारत अभियान: प्रवर्तन के साथ-साथ चलने वाला राष्ट्रीय नशा-रोकथाम कार्यक्रम; यह युवाओं, स्कूलों और कॉलेजों पर केंद्रित है; यह मांग में कमी वाले स्तंभ का हिस्सा है।





AAROGYA SETU 2.0 & DIGITAL HEALTH LAUNCHES — 16TH CCHFW

Ministry: Ministry of Health and Family Welfare

PIB Date: 29th June 2026

Easy Explanation

29 जून 2026 भारत के डिजिटल स्वास्थ्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक था। दिल्ली में हुए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की केंद्रीय परिषद (CCHFW) के 16वें सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक साथ आठ बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य पहलें शुरू कीं। इसका केंद्र-बिंदु था आरोग्य सेतु 2.0 — कोविड-काल की संपर्क-अनुरेखण (contact tracing) ऐप का नया रूप — जो अब हर नागरिक के लिए भारत की 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप' बन गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट बुकिंग, लैब रिपोर्ट, दवा-इतिहास, टीकाकरण रिकॉर्ड और स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ — सब एक ही मंच पर, नागरिक के आधार और ABHA ID से जुड़े हुए हैं। साथ ही, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI) भी लॉन्च किया गया — जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 'UPI जैसा क्षण' कहा जा रहा है — यह एक इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability — आपसी तालमेल) प्रोटोकॉल है, जो किसी भी अस्पताल प्रणाली, डायग्नोस्टिक लैब, फार्मसी या हेल्थ ऐप को आपस में सहजता से बात करने देता है। दिल्ली में लिखा गया नुस्खा मुंबई में भरा जा सकता है; एक लैब में हुई खून की जांच कहीं भी किसी डॉक्टर द्वारा देखी जा सकती है। सुमन रोडमैप 2030 ने मातृ व नवजात स्वास्थ्य के नए लक्ष्य तय किए। SSBSK ने बाल स्वास्थ्य सेवा को नया रूप दिया। NAS 2026 ने आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को मानकीकृत किया। और आयुष्मान सारथी — एक व्हाट्सएप चैटबॉट — हर नागरिक के फोन पर 12 भाषाओं में PM-JAY योजना की जानकारी उपलब्ध कराता है।

Key Terms:

Term	Definition
Aarogya Setu 2.0	भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप; इसमें ABHA, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, नुस्खे, टीके, लैब रिपोर्ट और योजनाओं के लाभ एकीकृत हैं।
ABHA	Ayushman Bharat Health Account — हर भारतीय के लिए 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य ID; यह जीवनभर सभी संस्थाओं में स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ती है।
Unified Health Interface (UHI)	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल — भुगतान के लिए UPI जैसा, पर स्वास्थ्य डेटा के लिए; कोई भी हेल्थ ऐप या अस्पताल मरीज़ का डेटा साझा कर सकता है।
ABDM	Ayushman Bharat Digital Mission — मुख्य ढांचा; ABHA, PHR, UHI सब इसी के अंतर्गत आते हैं; यह भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे का आधार है।
CCHFW	Central Council of Health and Family Welfare — केंद्र व राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों वाली शीर्ष सलाहकार संस्था; यह कुछ वर्षों में एक बार मिलती है।
SUMAN Roadmap 2030	'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन' के लक्ष्य — यानी रोकी जा सकने वाली मातृ व नवजात मौतों को शून्य करना; इसे 2030 के लक्ष्यों के साथ अद्यतन किया गया है।
SSBSK	Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram — पोषण, टीकाकरण और प्रारंभिक बाल विकास को कवर करने वाला व्यापक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
Ayushman Sarathi	PM-JAY का व्हाट्सएप चैटबॉट; यह नागरिकों को पात्रता, अस्पतालों की सूची और दावे की स्थिति के बारे में 12 क्षेत्रीय भाषाओं में मार्गदर्शन देता है।

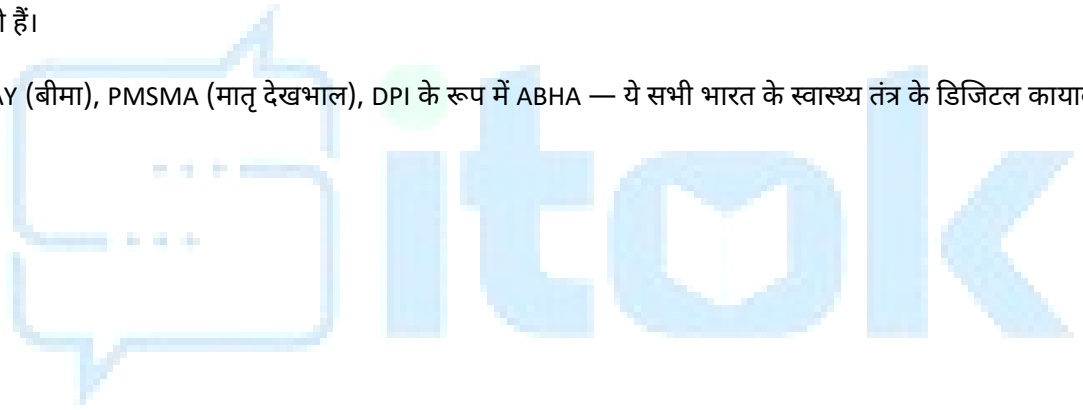
Important Points for UPSC:



| Click to Connect Now.



- 16वाँ CCHFW: अनुच्छेद 263 जैसे प्रावधान के तहत गठित; केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को एक साथ लाती है; राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की दिशा तय करती है।
- आरोग्य सेतु का विकास: 2020 की कोविड-19 संपर्क-अनुरेखण ऐप से एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप तक; शुरुआत में 24+ करोड़ डाउनलोड हुए; 2.0 अब पूरी तरह ABHA से जुड़ता है।
- UHI का महत्व: फिलहाल स्वास्थ्य डेटा अलग-थलग (siloes) है — अपोलो अस्पताल के रिकॉर्ड AIIMS में नहीं देखे जा सकते; UHI एक खुले प्रोटोकॉल (जैसा UPI ने भुगतान में किया) के ज़रिये इन दीवारों को तोड़ता है।
- ABHA ID: हर भारतीय की एक विशिष्ट 14 अंकों की स्वास्थ्य ID होगी; अब तक 67+ करोड़ ABHA बन चुके हैं; यह जीवनभर सभी प्रदाताओं में स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ती है।
- NAS 2026 (राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा): प्रतिक्रिया समय (शहरों में 8 मिनट, गाँवों में 20 मिनट), उपकरण और प्रशिक्षण के मानकीकृत प्रोटोकॉल — भारत की आपातकालीन देखभाल की बड़ी कमी को दूर करने की कोशिश।
- eSushrut@clinic: C-DAC ने छोटे क्लिनिकों के लिए ABDM-सक्षम HMIS (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) बनाई है — यह छोटे कस्बों व गाँवों के क्लिनिकों के रिकॉर्ड-रखरखाव को डिजिटल बनाती है।
- ड्रग रजिस्ट्री: भारत के स्वास्थ्य तंत्र में दवाओं की जानकारी (नाम, खुराक, परस्पर-प्रभाव) को मानकीकृत करती है — इससे नुस्खे की गलतियाँ रुकती हैं।
- जुड़ाव: PM-JAY (बीमा), PMSMA (मातृ देखभाल), DPI के रूप में ABHA — ये सभी भारत के स्वास्थ्य तंत्र के डिजिटल कार्यालय का हिस्सा हैं।





VB-G RAM G ACT — INDIA'S REVISED RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE IN FORCE

Ministry: Ministry of Rural Development

PIB Date: 1st July 2026

Easy Explanation

मनरेगा (MGNREGA) — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम — भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। 2005 से यह किसी भी ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम की मांग करें, साल में 100 दिन का रोज़गार गारंटी देता आया है। यह ग्रामीण गरीबों के लिए एक जीवनरेखा रहा है: सड़कें, तालाब, चेक-डैम और सार्वजनिक संपत्तियाँ बनाते हुए ऐसी मज़दूरी देना जो कमज़ोर कृषि मौसम में परिवारों को आय देती है। लेकिन 20 सालों में मनरेगा में कई दिक्कतें रहीं: मज़दूरी दरें महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ीं, भुगतान में कभी-कभी महीनों की देरी हुई, 100 दिन की सीमित सीमा रही, और कई बार बनी संपत्तियों की गुणवत्ता खराब रही। विकसित भारत — ग्रामीण रोज़गार महा गारंटी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 आज — यानी 1 जुलाई 2026 से — लागू हो गया, जो मनरेगा की जगह एक काफी बेहतर ढांचा लेकर आया है। मुख्य बदलाव: मज़दूरी अब स्वतः ही कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) से जुड़ी हुई है। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों के लिए अब यह योजना साल में 150 दिन कवर करती है। एक नया AI-सक्षम ग्रामीण आंतरिक ऑडिट पोर्टल संपत्ति की गुणवत्ता और मज़दूरी भुगतान की समय-सीमा पर वास्तविक समय में नज़र रखता है। और अब यह कार्यक्रम स्पष्ट रूप से मज़दूरी रोज़गार को कौशल विकास से जोड़ता है — मनरेगा में किया गया काम अब व्यावसायिक प्रशिक्षण योग्यताओं में गिना जा सकता है।

Key Terms:

Term	Definition
MGNREGA	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 — पूर्ववर्ती योजना; हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का गारंटीशुदा अकुशल रोज़गार।
VB-G RAM G Act	विकसित भारत — ग्रामीण रोज़गार महा गारंटी अधिनियम, 2025 — उत्तराधिकारी कानून; 1 जुलाई 2026 से लागू; उन्नत ग्रामीण रोज़गार ढांचा।
CPI-AL	Consumer Price Index for Agricultural Labour — कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक; मज़दूरी को इससे जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि वह ग्रामीण महंगाई के साथ स्वतः बढ़े।
Job Card	मनरेगा और VB-G RAM G के तहत परिवार की विशिष्ट पहचान; इसमें परिवार की पात्रता दर्ज होती है; मांगे गए काम और दी गई मज़दूरी का रिकॉर्ड रखता है।
Demand-Driven	मुख्य सिद्धांत: मांग के 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य है; न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता देना होगा — यह एक कानूनी अधिकार है।
Rural Internal Audit Portal	संपत्ति की गुणवत्ता और मज़दूरी भुगतान की AI-सक्षम वास्तविक-समय निगरानी; VB-G RAM G अधिनियम लागू होने के साथ शुरू किया गया।
150-Day Extension	दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों के लिए बढ़ा हुआ प्रावधान; पहले सभी के लिए सीमा 100 दिन थी; यह सामाजिक समानता का पहलू है।

Important Points for UPSC:

- मनरेगा 2005 एक ऐतिहासिक सामाजिक कानून था: भाग IX-A के तहत काम का अधिकार; मांग-आधारित; किसी भी वयस्क ग्रामीण परिवार-सदस्य द्वारा काम की मांग की जा सकती है।



| Click to Connect Now.



- VB-G RAM G अधिनियम 2025 के मुख्य बदलाव: (1) CPI-AL मज़दूरी सूचीकरण — स्वतः; (2) दिव्यांग परिवारों के लिए 150 दिन; (3) AI ऑडिट पोर्टल; (4) कौशल विकास से जुड़ाव; (5) PM आवास योजना की संपत्तियों से समागम।
- CPI-AL सूचीकरण: मनरेगा में मज़दूरी दरें सरकारी अधिसूचना से सालाना बदली जाती थीं — अक्सर देरी से; नई स्वतः सूचीकरण व्यवस्था इस अंतर को खत्म करती है।
- मज़दूरी भुगतान की समय-सीमा: VB-G RAM G के तहत 15 दिन में मज़दूरी देना अनिवार्य है; AI पोर्टल देरी को स्वतः चिह्नित करता है — इससे बदनाम 'देरी से भुगतान' की समस्या घटती है।
- पीएम मोदी ने VB-G RAM G को आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया — NDA सहयोगी की भागीदारी का राजनीतिक महत्व।
- मनरेगा के आंकड़े (2024-25): 25 करोड़ पंजीकृत परिवार; शिखर मांग में 8-9 करोड़ सक्रिय; 80,000-90,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट; 2.5 अरब व्यक्ति-दिवस सृजित।
- राजनीतिक संदर्भ: मनरेगा कांग्रेस का कार्यक्रम था; मूल ढांचे को बनाए रखते हुए VB-G RAM G नाम देना, ब्रांडिंग बदलाव के साथ निरंतरता दिखाता है।





DIGITAL INDIA — 11 YEARS: PIB BACKGROUNDER

Ministry: Ministry of Electronics & IT (MeitY)

PIB Date: 1st July 2026

Easy Explanation

1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक सरल लेकिन साहसिक सोच के साथ डिजिटल इंडिया शुरू किया था: भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-अर्थव्यवस्था में बदलना। ग्यारह साल बाद, PIB ने अब तक बने ढांचे की विस्तृत जानकारी जारी की है। आँकड़े चौंकाने वाले हैं: UPI हर महीने 14+ अरब लेनदेन संभालता है और अब 10+ देशों में चालू है। भारतनेट ने 2.1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ दिया है। डिजिलॉकर के 35 करोड़ उपयोगकर्ता और 800 करोड़ दस्तावेज़ हैं। आधार 133 करोड़ भारतीयों को जारी हो चुका है। कॉमन सर्विस सेंटर 5.5 लाख गाँवों में डिजिटल सेवाएँ देते हैं। UMANG ऐप एक ही मंच पर 2,000+ सरकारी सेवाएँ देती है। डिजिटल इंडिया सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है — इसने बुनियादी तौर पर बदल दिया है कि सरकार कैसे काम करती है और नागरिक सेवाओं तक कैसे पहुँचते हैं। एक किसान अब अपने फोन पर PM-KISAN भुगतान की स्थिति देख सकता है। बिहार के किसी गाँव से मरीज़ AIIMS में अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। कोई छोटा व्यापारी अपना MSME पंजीकृत कर सकता है, कर्ज़ के लिए आवेदन कर सकता है, और सरकारी बाज़ार पर बेच सकता है — यह सब ऑनलाइन। यह विस्तृत जानकारी अगले चरण का भी संकेत देती है: AI-संचालित शासन, सेमीकंडक्टर विनिर्माण (भारत का चिप निर्माता बनना), और 6G (भारत का 6G मानक तय करने वाला देश बनने का इरादा)।

Key Terms:

Term	Definition
Digital India	पीएम मोदी का प्रमुख कार्यक्रम, जो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ; तीन स्तंभ: डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाएँ, डिजिटल साक्षरता।
DPI (Digital Public Infrastructure)	सरकार द्वारा बनाई गई खुली डिजिटल प्रणालियाँ: आधार, UPI, डिजिलॉकर, ABDM, ONDC — भारत का यह मॉडल अब वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है।
BharatNet	सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़ने की परियोजना; 2.1 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं; ग्रामीण डिजिटल पहुँच को सक्षम बनाती है।
UMANG	Unified Mobile Application for New-age Governance — एक ऐसी ऐप जो विभिन्न मंत्रालयों की 2,000+ सरकारी सेवाएँ एक जगह देती है।
Common Service Centres (CSCs)	गाँवों में डिजिटल सेवा वितरण केंद्र; 5.5 लाख CSC; डिजिटल साक्षरता, बैंकिंग, बीमा व सरकारी सेवाएँ देते हैं।
IndiaStack	भारत का DPI तंत्र: आधार (पहचान) + UPI (भुगतान) + डिजिलॉकर (दस्तावेज़) + ABDM (स्वास्थ्य) + ONDC (वाणिज्य)।
6G India	6G मानक तय करने में भाग लेने की भारत की महत्वाकांक्षा; TSDSI (भारत की दूरसंचार मानक संस्था) ITU में सक्रिय है।

Important Points for UPSC:

- डिजिटल इंडिया चरण 1 (2015-2019): बुनियादी ढांचा बनाना — आधार, भारतनेट, CSC, जन धन खाते, मोबाइल कनेक्टिविटी।
- डिजिटल इंडिया चरण 2 (2019-2024): सेवाएँ बनाना — UPI का दबदबा, आरोग्य सेतु, कोविन, PM-KISAN, डिजिलॉकर का विस्तार।



| Click to Connect Now.



- डिजिटल इंडिया चरण 3 (2024-2030): नई सीमा बनाना — AI, सेमीकंडक्टर, 6G, क्वांटम, डीप-टेक।
- UPI की यात्रा: जुलाई 2016 से 2026 तक — 0 से 14+ अरब मासिक लेनदेन; 10+ देश; 22 लाख करोड़ रुपये का मासिक मूल्य; भारत को वैश्विक फिनटेक अगुआ बनाया।
- भारतनेट: 6 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई; 2.1 लाख+ ग्राम पंचायतें जुड़ीं; ग्रामीण डिजिटल खाई घटाती है; ग्रामीण BPO, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाती है।
- भारत का DPI मॉडल: विश्व बैंक, IMF, G20 विकासशील देशों में इसे दोहराने के लिए भारत के DPI का अध्ययन कर रहे हैं; भारत ने G20 अध्यक्षता (2023) में DPI को वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में साझा किया।
- सेमीकंडक्टर: माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के फैब निर्माणाधीन हैं — डिजिटल इंडिया का हार्डवेयर पहलू; भारत 'उपभोक्ता से निर्माता' बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
- बाकी बची डिजिटल खाई: ग्रामीण भारत के 35% हिस्से में अब भी स्मार्टफोन नहीं हैं; बुजुर्गों और महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता अब भी सीमित है — चरण 3 को इन कमियों को दूर करना होगा।





TIGER REINTRODUCTION — NATIONAL WORKSHOP, ALWAR, RAJASTHAN

Ministry: Ministry of Environment, Forest and Climate Change / NTCA

PIB Date: 28th–29th June 2026

Easy Explanation

भारत की बाघ संरक्षण (tiger conservation) की कहानी उल्लेखनीय रही है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर की गणना में सिर्फ 1,411 बाघ पाए गए थे। 2022 तक यह संख्या बढ़कर 3,682 हो गई — यानी दुनिया के 70% से ज्यादा जंगली बाघ अब भारत में रहते हैं। लेकिन इस सफलता ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है: कई अभयारण्यों में बाघों की संख्या अब वहन-क्षमता (carrying capacity) के बराबर या उससे ज्यादा हो गई है, जिससे बाघ इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ने लगे हैं और इंसान-बाघ टकराव बढ़ रहा है। वहीं, कई ऐसे वन क्षेत्र, जहाँ पहले बाघ रहते थे — लेकिन शिकार और आवास-विनाश के कारण खत्म हो गए — अब वे बाघों को फिर से बसाने के लिए तैयार हैं। अलवर, राजस्थान में हुई 'बाघ पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला' (28-29 जून), जिसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया, बाघों को भीड़भाड़ वाले अभयारण्यों से नई जगहों पर ले जाने के विज्ञान, नीति और चुनौतियों पर केंद्रित थी। राजस्थान का सरिस्का बाघ अभयारण्य यहाँ मुख्य संदर्भ है: सरिस्का ने 2004-2005 में शिकार के कारण अपने सभी बाघ खो दिए थे, और 2008 में रणथंभौर से बाघों को सफलतापूर्वक फिर से बसाया गया — भारत का पहला बाघ पुनर्वास। अब सवाल यह है: बाघों को और कहाँ फिर से बसाया जाए? संभावित स्थलों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के वे जंगल शामिल हैं जहाँ शिकार-आधार और आवास पर्याप्त हैं, लेकिन बाघ अनुपस्थित हैं।

Key Terms:

Term	Definition
Tiger Reintroduction	स्रोत आबादी (source population) से बाघों को उन ऐतिहासिक रूप से बाघ-निवासित क्षेत्रों में ले जाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, जो अब बाघ-रहित हो चुके हैं।
NTCA	National Tiger Conservation Authority — MoEFCC के तहत एक वैधानिक संस्था; यह प्रोजेक्ट टाइगर लागू करती है; देशभर के 55 बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन करती है।
Project Tiger	1973 में शुरू भारत का बाघ संरक्षण कार्यक्रम; 18 राज्यों के 55 बाघ अभयारण्यों को कवर करता है; इसका वार्षिक बजट 1,000+ करोड़ रुपये है।
Source Population	अतिरिक्त बाघों वाला अभयारण्य, जो पुनर्वास के लिए बाघ दे सकता है; रणथंभौर एक प्रमुख स्रोत अभयारण्य है।
Carrying Capacity	शिकार की उपलब्धता और क्षेत्र को देखते हुए किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समा सकने वाले अधिकतम बाघों की संख्या; क्षमता पूरी होने पर बाघ फैलने लगते हैं और टकराव बढ़ता है।
Sariska Tiger Reserve	अलवर, राजस्थान; शिकार के कारण सभी बाघ खो दिए (2004-05); 2008 में भारत का पहला सफल बाघ पुनर्वास हुआ; अब यहाँ 30+ बाघ हैं।
Tiger Census 2022	भारत की 5वीं बाघ गणना; 3,682 जंगली बाघ गिने गए; भारत के पास दुनिया की 75%+ जंगली बाघ आबादी है।

Important Points for UPSC:

- भारत में बाघों की संख्या: 1,411 (2006) से 1,706 (2010), 2,226 (2014), 2,967 (2018), फिर 3,682 (2022) — लगातार बढ़ोतरी, जो संरक्षण की सफलता दर्शाती है।
- विश्व जंगली बाघ दिवस: 29 जुलाई; भारत की नवीनतम गणना (3,682) वैश्विक जंगली बाघ आबादी का 75%+ है।



| Click to Connect Now.



- सरिस्का उदाहरण: 2004-05 तक सभी बाघों का शिकार हो चुका था; 2008 से रणथंभौर से बाघों को फिर बसाया गया; अब 30+ बाघ हैं — अभयारण्य स्तर पर दुनिया का पहला सफल बाघ पुनर्वास।
- बाघ-मानव टकराव: जैसे-जैसे अभयारण्य भरते हैं, बाघ खेतों और गाँवों की ओर फैलते हैं; हर साल बाघों से 50-60 मानव मृत्यु होती हैं; पुनर्वास योजना में इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है।
- पुनर्वास की शर्तें: पर्याप्त शिकार-आधार (हिरण, जंगली सुअर), इंसान-रहित मूल क्षेत्र, समुदाय का समर्थन, और शिकार-रोधी बुनियादी ढांचा — पुनर्वास से पहले ये सब होना ज़रूरी है।
- IUCN पुनर्वास दिशानिर्देश: यह दिखाना ज़रूरी है कि विलुप्ति का मूल कारण दूर हो चुका है; दाता आबादी में आनुवंशिक विविधता हो; आवास बहाली पूरी हो।
- संभावित नए स्थल: मुकुंदरा हिल्स (राजस्थान), संजय-दुबरी बाघ अभयारण्य (मध्य प्रदेश), सतकोसिया (ओडिशा) — ऐतिहासिक रूप से बाघों की मौजूदगी और वर्तमान शिकार-आधार के कारण।





INDIA-EU SHIP RECYCLING — THREE ALANG YARDS READY FOR EU RECOGNITION

Ministry: Ministry of Ports, Shipping and Waterways

PIB Date: 1st July 2026

Easy Explanation

पिछले हफ्ते भारत 2025 में 35.4% वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी के साथ दुनिया का शीर्ष जहाज़ पुनर्चक्रण (ship recycling) राष्ट्र बना था। इस हफ्ते अगला अध्याय सामने आया है। भारत के जहाज़ पुनर्चक्रण उद्योग के लिए सबसे बड़ा अच्छा अवसर है EU-ध्वजांकित (EU-flagged) जहाज़ — यानी यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश का झंडा लगाए जहाज़। EU के पास अपना जहाज़ पुनर्चक्रण नियमन (EUSRR) है, जिसके तहत EU-ध्वजांकित जहाज़ों को सिर्फ EU-अनुमोदित सूची में शामिल यार्ड्स में ही पुनर्चक्रित किया जा सकता है। फिलहाल, ज़्यादातर अनुमोदित यार्ड्स यूरोप और तुर्की में हैं — भारत में एक भी नहीं, जबकि भारत के पास वैश्विक क्षमता का 35%+ हिस्सा है। गुजरात के अलंग स्थित तीन भारतीय यार्ड्स ने अनुपालन-सत्यापन (compliance verification) प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब औपचारिक EU मान्यता के लिए तैयार हैं: श्री राम ग्रुप, लीला शिप यार्ड, और IHX रीसाइक्लिंग। यदि EU (औपचारिक फैसला यूरोपीय आयोग के पास है) इन्हें मंजूरी देता है, तो ये यार्ड्स EU-ध्वजांकित जहाज़ ले सकेंगे, जिससे भारत की बाज़ार हिस्सेदारी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। EU सूची में शामिल होने के लिए हॉन्ग कॉन्ग कन्वेंशन (HKC) मानकों का पालन दिखाना ज़रूरी है — यानी एस्बेस्टस, भारी धातुओं और खतरनाक सामग्रियों को संभालने के पर्यावरणीय व सुरक्षा मानक।

Key Terms:

Term	Definition
EUSRR	EU Ship Recycling Regulation — EU का कानून, जिसके तहत EU-ध्वजांकित जहाज़ों को सिर्फ EU-अनुमोदित सुविधाओं में ही पुनर्चक्रित किया जा सकता है।
Hong Kong Convention (HKC)	जहाज़ों के सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि; भारत ने इसे शिप्स रीसाइक्लिंग एक्ट 2019 के ज़रिये अपनाया है।
EU Approved List	यूरोपीय आयोग की उन विश्व स्तर पर अनुमोदित यार्ड्स की सूची, जहाँ EU-ध्वजांकित जहाज़ पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं; भारतीय यार्ड्स फिलहाल आवेदन कर रहे हैं।
EU-Flagged Ships	दुनिया के व्यापारिक बेड़े का लगभग 25% हिस्सा EU सदस्य देशों का झंडा लगाता है; इस बेड़े तक पहुँच मिलने से भारत की बाज़ार हिस्सेदारी काफी बढ़ सकती है।
Alang-Sosiya	भारत का प्रमुख जहाज़ पुनर्चक्रण केंद्र; गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित; 150+ प्लॉट; 50,000+ श्रमिक; दुनिया की सबसे बड़ी 'बीचिंग-टाइप' सुविधा।
Recycling of Ships Act 2019	HKC को लागू करने वाला भारत का घरेलू कानून; खतरनाक सामग्रियों की अनिवार्य सूची (IHM) और जहाज़ पुनर्चक्रण योजना ज़रूरी है।

Important Points for UPSC:

- मौजूदा अंतर: EU-ध्वजांकित जहाज़ फिलहाल अलंग नहीं भेजे जा सकते क्योंकि भारतीय यार्ड्स EU अनुमोदित सूची में नहीं हैं — यह एक बड़ा बाज़ार-अंतर है।
- तीन तैयार यार्ड्स: श्री राम ग्रुप, लीला शिप यार्ड, IHX रीसाइक्लिंग — सभी गुजरात के अलंग में स्थित; इन्होंने अनुपालन-सत्यापन पूरा कर लिया है और यूरोपीय आयोग के पास आवेदन कर दिया है।





- EU अनुमोदन प्रक्रिया: यूरोपीय आयोग तकनीकी ऑडिट करता है; संतुष्ट होने पर यार्ड्स को अनुमोदित सूची में जोड़ता है — इसमें आमतौर पर 6-12 महीने लगते हैं।
- बाज़ार पर असर: EU-ध्वजांकित बेड़ा वैश्विक व्यापारिक टनभार का लगभग 25% है; मंजूरी मिलने पर भारत की हिस्सेदारी 35% से बढ़कर 50%+ हो सकती है।
- पर्यावरणीय सुधार: EU मान्यता के लिए ऊँचे पर्यावरणीय मानकों की ज़रूरत होती है — हरित पुनर्चक्रण, श्रमिकों के लिए PPE, कचरा प्रबंधन; इससे पूरे अलंग की गुणवत्ता बढ़ती है।
- शिप्स रीसाइक्लिंग एक्ट 2019 की आवश्यकता: हर जहाज़ को खतरनाक सामग्रियों की सूची (IHM) रखनी होगी — यह वह मुख्य दस्तावेज़ है जिसे EU ऑडिटर यार्ड-मंजूरी के लिए जाँचते हैं।
- भारत-EU टिकाऊ जहाज़ पुनर्चक्रण सहयोग: द्विपक्षीय जुड़ाव जारी है; EU भारत को टिकाऊ समुद्री क्षेत्र विकास के लिए एक अहम साझेदार मानता है।





NINE YEARS OF GST — PIB BACKGROUNDER

Ministry: Ministry of Finance / GST Council

PIB Date: 29th June 2026

Easy Explanation

1 जुलाई 2017 को भारत ने 17 केंद्रीय व राज्य करों के जटिल जाल की जगह एक एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया। इसे आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया। नौ साल बाद, PIB ने इस यात्रा का विस्तृत आकलन जारी किया है। इसका विज़न था 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार' — 'टैक्स पर टैक्स' (cascading) की समस्या खत्म करना, माल की आवाजाही धीमी करने वाली अंतर-राज्यीय चेक-पोस्टों को हटाना, और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाना। GST संग्रह दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है: वित्त वर्ष 2017-18 के 7.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 20.18 लाख करोड़ रुपये — अप्रैल 2024 में एक ही महीने में सबसे ज़्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपये का संग्रह हुआ। GST पंजीकृत व्यवसायों की संख्या 60 लाख से बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई है — यानी ज़्यादा व्यवसाय अब औपचारिक कर-दायरे में हैं। औसत कर दरें GST-पूर्व के लगभग 15% प्रभावी दर से घटकर GST में लगभग 11.6% रह गई हैं — यानी सामान सस्ता हुआ है। लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं: GST में चार मुख्य दरें (5%, 12%, 18%, 28%) और कई छूट हैं; पेट्रोलियम, शराब और रियल एस्टेट GST के दायरे से बाहर हैं; और राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर (compensation cess) की व्यवस्था विवादास्पद रही है।

Key Terms:

Term	Definition
GST	Goods and Services Tax — गंतव्य-आधारित (destination-based), बहु-चरणीय उपभोग कर; यह उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT, चुंगी (octroi) व प्रवेश कर जैसे करों की जगह लेता है।
GST Council	संवैधानिक संस्था (101वाँ संशोधन); केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं; यह GST दरें व नीतियाँ तय करती है; निर्णय 3/4 बहुमत से होते हैं।
IGST	Integrated GST — अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगता है; केंद्र इसे इकट्ठा करके गंतव्य राज्य के साथ साझा करता है।
CGST/SGST	केंद्रीय GST और राज्य GST — राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर लगते हैं; CGST केंद्र को, SGST राज्य को बराबर हिस्से में जाता है।
Input Tax Credit (ITC)	इनपुट पर चुकाए गए GST को आउटपुट पर देय GST से घटाया जा सकता है — इससे कर पर कर लगने की समस्या खत्म होती है; यह GST की मुख्य विशेषता है।
E-Way Bill	50,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य के माल की राज्य-सीमा पार आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट; डिजिटल माल-ट्रैकिंग; इसने भौतिक चेक-पोस्टों की जगह ली।
Compensation Cess	GST के बाद पहले 5 सालों तक राज्यों को 14% वार्षिक राजस्व वृद्धि की गारंटी दी गई थी; विलासिता व नुकसानदायक वस्तुओं पर उपकर से क्षतिपूर्ति हुई; अवधि खत्म हो चुकी है, पर मुद्दा बना हुआ है।

Important Points for UPSC:

- GST संग्रह का रुझान: वित्त वर्ष 17-18 में 7.19 लाख करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 22-23 में 18.1 लाख करोड़ रुपये, फिर वित्त वर्ष 25-26 में 20.18 लाख करोड़ रुपये — 9 सालों में 2.8 गुना वृद्धि।



| Click to Connect Now.



- रिकॉर्ड महीना: अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये GST संग्रह हुआ — अब तक का सबसे ज़्यादा एकल-मासिक संग्रह।
- करदाता आधार: 2017 में 60 लाख पंजीकृत व्यवसायों से 2026 में 1.46 करोड़ — अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में बड़ी वृद्धि।
- औसत दर में कमी: GST-पूर्व प्रभावी कर दर लगभग 15% थी, GST के बाद लगभग 11.6% — कई वस्तुओं पर उपभोक्ता कीमतें घटीं।
- 101वाँ संवैधानिक संशोधन: इसमें अनुच्छेद 246A (GST लगाने की समवर्ती शक्ति), 279A (GST परिषद), 269A (IGST) जोड़े गए।
- GST के दायरे से बाहर वस्तुएँ: पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, डीज़ल, ATF, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल), मानव उपभोग के लिए शराब, रियल एस्टेट (आंशिक रूप से) — इससे आपूर्ति शृंखला में कर-प्रभाव बना रहता है।
- ई-वे बिल का असर: हर महीने 9 करोड़+ ई-वे बिल बनते हैं; इससे अंतर-राज्यीय चेक-पोस्ट खत्म हुए (ट्रक की यात्रा का समय लगभग 30% घटा)।
- बाकी सुधार: पेट्रोलियम को GST में लाना (केंद्र-राज्य राजस्व बंटवारे का मुद्दा), दर-युक्तिकरण (4 स्लैब घटाना), रियल एस्टेट की सफाई — सुधार का एजेंडा जारी है।





FCRA 2.0 PORTAL + e-OCI CARD — HOME MINISTRY LAUNCHES

Ministry: Ministry of Home Affairs

PIB Date: 30th June 2026

Easy Explanation

30 जून को गृह मंत्रालय ने दो अलग लेकिन महत्वपूर्ण डिजिटल शुरुआतें कीं। पहला: FCRA 2.0 पोर्टल। विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (FCRA) यह नियंत्रित करता है कि भारतीय NGO, धार्मिक संस्थाएँ और राजनीतिक दल विदेशी स्रोतों से किस तरह पैसा प्राप्त कर सकते हैं। बिना निगरानी के भारत में आने वाला विदेशी पैसा राजनीति को प्रभावित करने, विरोध-प्रदर्शन को वित्तपोषित करने, या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। नया FCRA 2.0 पोर्टल पूरी प्रक्रिया — पंजीकरण, नवीनीकरण, पूर्व-अनुमति आवेदन, वार्षिक रिटर्न, अनुपालन निगरानी — को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाता है। यह अनुपालन को भी सख्त करता है: उपयोग की कड़ी निगरानी, संदिग्ध लेनदेन की AI-आधारित पहचान, और विदेशी अंशदान प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उसकी अनिवार्य रिपोर्टिंग। दूसरा: e-OCI कार्ड। भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले लोगों के लिए ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्ड भारत का 'आजीवन वीज़ा' है — यह उन्हें कुछ प्रतिबंधों (वोट नहीं दे सकते, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते) के साथ भारत में हमेशा के लिए रहने, काम करने और पढ़ने का अधिकार देता है। फिलहाल, OCI कार्डधारकों को OCI बुकलेट और अपना मौजूदा पासपोर्ट, दोनों साथ रखने होते हैं। e-OCI कार्ड डिजिटलॉकर में रखा जाने वाला पूरी तरह डिजिटल दस्तावेज़ होगा, जिससे भौतिक बुकलेट की ज़रूरत खत्म हो जाएगी — यह दुनियाभर के 1.5 करोड़+ OCI कार्डधारकों के लिए जीवन आसान बनाता है।

Key Terms:

Term	Definition
FCRA	Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 — भारत में NGO, धार्मिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करता है।
FCRA 2.0 Portal	FCRA पंजीकरण, नवीनीकरण, पूर्व-अनुमति, वार्षिक अनुपालन रिपोर्टिंग और उपयोग-निगरानी के लिए पूरी तरह डिजिटल मंच।
OCI	Overseas Citizen of India — यह नागरिकता नहीं है; भारतीय मूल के लोगों को दिया जाने वाला दीर्घकालिक बहुउद्देश्यीय वीज़ा दर्जा; भारत में जीवनभर बिना वीज़ा प्रवेश।
e-OCI Card	डिजिटलॉकर में रखा गया डिजिटल OCI कार्ड; भौतिक OCI बुकलेट की ज़रूरत खत्म करता है; डिजिटल सत्यापन के साथ समान रूप से मान्य।
Foreign Contribution	किसी विदेशी स्रोत द्वारा किसी भारतीय नागरिक या संगठन को दी गई कोई भी मुद्रा, वस्तु या प्रतिभूति (security) का दान, वितरण या हस्तांतरण।
FCRA 2020 Amendment	सख्त नियम: उप-अनुदान (sub-granting) पर रोक, अनिवार्य SBI खाता, खर्च की सख्त सीमा (प्रशासनिक खर्च 20% से कम), आधार-लिंगिंग अनिवार्य।

Important Points for UPSC:

- FCRA 2010 ने FCRA 1976 की जगह ली; 2020 में मुख्य संशोधन: अन्य NGO को उप-अनुदान देने पर रोक, अनिवार्य सरकारी SBI खाता (नई दिल्ली), प्रशासनिक खर्च की सीमा 20%।
- FCRA 2020 विवाद: कई विदेशी-वित्तपोषित NGO का पंजीकरण रद्द हुआ; एमनेस्टी इंडिया, ग्रीनपीस इंडिया FCRA रद्दीकरण के बाद भारत छोड़ गए — यह नागरिक समाज की स्वतंत्रता की बहस से जुड़ा है।



| Click to Connect Now.



- FCRA 2.0 की नई सुविधाएँ: AI-आधारित लेनदेन निगरानी; 48 घंटे में विदेशी अंशदान की अनिवार्य रिपोर्टिंग; सभी FCRA खातों के लिए PAN-लिंकिंग — सख्त जवाबदेही।
- OCI कार्ड: दुनियाभर में 1.5 करोड़+ OCI कार्डधारक; अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बड़ी प्रवासी आबादी; भारतीय प्रवासी जुड़ाव व प्रेषण (remittance) के लिए अहम समूह।
- OCI पर प्रतिबंध: वोट नहीं दे सकते, संवैधानिक पद नहीं संभाल सकते, सशस्त्र बलों या सिविल सेवाओं में काम नहीं कर सकते, या कृषि/बागान भूमि नहीं खरीद सकते — ये प्रतिबंध e-OCI में भी बने रहेंगे।
- e-OCI का फायदा: पासपोर्ट नवीनीकरण पर OCI का दोबारा जारी होना अनिवार्य नहीं रहेगा (यह पहले एक बड़ी परेशानी थी); डिजिलॉकर आधार से जुड़ी मौजूदा OCI जानकारी रखता है।
- दोहरी नागरिकता बनाम OCI: OCI दोहरी नागरिकता नहीं है — भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता (संविधान का अनुच्छेद 9); OCI एक विशेष दीर्घकालिक निवास दर्जा है।





UPI GOES LIVE IN GREECE — INDIA'S PAYMENT TECH GOES EUROPEAN

Ministry: Ministry of Commerce & Industry / NPCI International

PIB Date: 30th June 2026

Easy Explanation

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लंदन में भारत-यूके CETA के जश्न के बाद एक व्यापारिक शिष्टमंडल लेकर ग्रीस पहुँचे थे। 30 जून को ग्रीस के सबसे बड़े बैंकों में से एक यूरोबैंक (Eurobank) में, मंत्री गोयल ने खुद ग्रीस में UPI (Unified Payments Interface) की शुरुआत को अपनी आँखों से देखा। इसका मतलब है कि ग्रीस में मौजूद भारतीय पर्यटक, व्यापारी यात्री और प्रवासी अब किसी भी सहभागी ग्रीक व्यापारी के यहाँ सिर्फ अपनी UPI ऐप से QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। न नकद, न मुद्रा-विनिमय, न अंतरराष्ट्रीय कार्ड शुल्क। ग्रीस दो कारणों से खासतौर पर महत्वपूर्ण है: यह यूरोपीय संघ की भुगतान व्यवस्था में भारत का प्रवेश-द्वार है, और ग्रीस में भारतीय पर्यटकों का काफी आवागमन रहता है। रणनीतिक रूप से, यह भारत की डिजिटल भुगतान तकनीक का एक G7-निकटवर्ती अर्थव्यवस्था में विस्तार है। UPI अब 10+ देशों में स्वीकार्य है: UAE, सिंगापुर, मॉरीशस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, UK, मलेशिया, और अब ग्रीस। लक्ष्य यह है कि UPI दुनिया की पसंदीदा सीमा-पार भुगतान प्रणाली बने — भारत का एक 'डिजिटल निर्यात', जो एक साथ सद्भावना और व्यापार-सुविधा दोनों पैदा करता है।

Key Terms:

Term	Definition
UPI	Unified Payments Interface — भारत की वास्तविक-समय डिजिटल भुगतान प्रणाली; NPCI द्वारा विकसित; हर महीने 14+ अरब लेनदेन संभालती है।
NPCI International	NPCI की अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए बनाई गई सहायक इकाई; यह विदेशी बैंकों के साथ साझेदारी कर UPI को अपनाने में मदद करती है।
Eurobank	ग्रीस के चार सबसे बड़े बैंकों में से एक; UPI को एकीकृत करने वाला पहला ग्रीक बैंक; अपने व्यापारी नेटवर्क में UPI स्वीकृति सक्षम करता है।
QR Code Payment	सार्वभौमिक व्यापारी भुगतान तरीका; भारतीय पर्यटक व्यापारी का QR कोड UPI ऐप से स्कैन करते हैं; भुगतान तुरंत भारतीय खाते से कटता है।
G20 Cross-Border Payments	भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के तहत तेज़ व सस्ते सीमा-पार भुगतान एक मुख्य लक्ष्य था; UPI का अंतरराष्ट्रीयकरण इसी का क्रियान्वयन है।
RuPay International	भारत का घरेलू कार्ड नेटवर्क (वीज़ा या मास्टरकार्ड जैसा); UPI के साथ-साथ यह भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है — एक पूरक डिजिटल निर्यात।

Important Points for UPSC:

- UPI वाले देश (10+): UAE, सिंगापुर, मॉरीशस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, UK, मलेशिया, फिजी, और अब ग्रीस — पर्यटन व प्रवासी गलियारों में विस्तार।
- ग्रीस का महत्व: पहला EU देश जहाँ UPI व्यापारी स्तर पर चालू है; इससे व्यापक EU-UPI एकीकरण का रास्ता खुलता है।
- ग्रीस जाने वाले भारतीय पर्यटक: सालाना 2+ लाख भारतीय पर्यटक; UPI विदेशी-मुद्रा की परेशानी दूर करता है; यह खासतौर पर ग्रीक द्वीप पर्यटन के लिए प्रासंगिक है।





- डिजिटल निर्यात रणनीति: अन्य देशों में UPI अपनाए जाने से NPCI को प्रति-लेनदेन शुल्क मिलता है; भारत की भुगतान तकनीक एक राजस्व-अर्जक निर्यात बनती जा रही है।
- यूरोबैंक एकीकरण: ग्रीस के सभी यूरोबैंक-सम्बद्ध व्यापारियों में UPI QR कोड दिखेंगे; भारतीय बैंकों (SBI, HDFC, ICICI) ने अपने ग्राहकों के लिए अंतरराष्ट्रीय UPI सक्षम किया है।
- भारत-ग्रीस द्विपक्षीय संबंध: गोयल के शिष्टमंडल ने व्यापार, संगमरमर आयात (भारत एक बड़ा खरीदार है), ग्रीक फार्मास्युटिकल्स और पर्यटन सहयोग पर समझौते किए।
- प्रतिस्पर्धा: चीन का अलीपे (Alipay) 50+ देशों में मौजूद है; मास्टरकार्ड/वीज़ा का वैश्विक दबदबा है; UPI 10 देशों में है, पर अंतरराष्ट्रीय प्रेषण हिस्सेदारी के लिए इसे तेज़ी लानी होगी।





NPPA + PHARMA JAN SAMADHAN — INTEGRATED DRUG PRICE GRIEVANCE SYSTEM

Ministry: Ministry of Chemicals and Fertilizers / National Pharmaceutical Pricing Authority

PIB Date: 25th June 2026

Easy Explanation

भारत में दवाइयाँ खरीदना कई बार उलझन भरा और शोषणकारी हो सकता है। कोई दवा MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) पर बेची जा सकती है — या कोई केमिस्ट ज़्यादा कीमत वसूल सकता है, या किसी मरीज़ को पता ही न हो कि वही दवा जन औषधि केंद्र पर कहीं सस्ती मिल रही है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) भारत में दवाओं की कीमतें नियंत्रित करती है — यह ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के तहत आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करती है। जब किसी नागरिक से दवा के लिए ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं या वह किसी उल्लंघन की शिकायत करना चाहता है, तो अब उसके पास 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल है — एक समर्पित शिकायत-निवारण व्यवस्था। इस हफ्ते, NPPA ने फार्मा जन समाधान पोर्टल को 'फार्मा सही दाम' पोर्टल (जो दवाओं की सही MRP और उपलब्धता दिखाता है) के साथ जोड़ दिया। इस एकीकरण का मतलब है: एक नागरिक फार्मा सही दाम पर सही कीमत जाँच सकता है, और ज़्यादा पैसे लिए जाने पर उसी मंच से फार्मा जन समाधान पर शिकायत दर्ज कर सकता है। अलग से, इस हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने QR कोड-आधारित दवा ट्रेसेबिलिटी को टीकों, एंटीमाइक्रोबियल और कैंसर-रोधी दवाओं तक बढ़ा दिया — जिससे इन महत्वपूर्ण दवाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी और आपूर्ति शृंखला पर नज़र रखी जा सकेगी।

Key Terms:

Term	Definition
NPPA	National Pharmaceutical Pricing Authority — DoP के तहत वैधानिक संस्था; आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतें तय व निगरानी करती है; DPCO लागू करती है।
DPCO 2013	Drug Price Control Order 2013 — आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत; NLEM में शामिल आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने का अधिकार NPPA को देता है।
NLEM	National List of Essential Medicines — लगभग 384 दवाओं की सूची, जिनका उपलब्ध व किफ़ायती होना ज़रूरी है; इनकी कीमतें DPCO के तहत नियंत्रित हैं।
Pharma Sahi Daam	NPPA का पोर्टल, जो दवाओं की सही MRP दिखाता है; उपभोक्ता खरीदने से पहले जाँच सकते हैं; ऐप और वेबसाइट, दोनों रूप में उपलब्ध।
Pharma Jan Samadhan	दवा की कीमत, ज़्यादा वसूली या अनुपलब्धता की शिकायतों के लिए NPPA का पोर्टल; अब इसे फार्मा सही दाम के साथ जोड़ दिया गया है।
Jan Aushadhi Kendra	PM भारतीय जन औषधि परियोजना के केंद्र; ब्रांडेड कीमतों से 50-90% कम कीमत पर जेनेरिक दवाएँ बेचते हैं; देशभर में 12,000+ केंद्र हैं।

Important Points for UPSC:

- NPPA, DPCO 2013 के तहत दवाओं की कीमतें नियंत्रित करती है; NLEM में शामिल आवश्यक दवाओं (लगभग 384) की अधिकतम कीमत तय है; व्यापार मार्जिन भी नियंत्रित है।
- फार्मा सही दाम ऐप: 2017 में लॉन्च हुआ; नागरिक बारकोड स्कैन या दवा का नाम खोजकर असली MRP जान सकते हैं; 1 करोड़+ डाउनलोड।
- एकीकरण का महत्व: पहले कीमत जाँचना (सही दाम) और शिकायत दर्ज करना (जन समाधान) अलग-अलग व्यवस्थाएँ थीं; एकीकरण से एक सहज अनुभव मिलता है।



| Click to Connect Now.



- जन औषधि केंद्र: 12,000+ केंद्र; इनसे मरीज़ों को ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।
- QR कोड दवा ट्रेसबिलिटी: अब टीकों, एंटीमाइक्रोबियल और कैंसर-रोधी दवाओं तक बढ़ाई गई — यह प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है, आपूर्ति शृंखला पर नज़र रखती है, और नकली दवाओं को रोकती है।
- भारत का फार्मा बाज़ार: सालाना 2.1 लाख करोड़ रुपये का; भारत निर्यात के लिए 'दुनिया की फार्मसी' है, पर घरेलू किफ़ायत अब भी एक चुनौती है।
- ज़्यादा वसूली की समस्या: DPCO के बावजूद छोटी केमिस्ट दुकानों में ज़्यादा वसूली आम है; NPPA को सालाना 20,000+ शिकायतें मिलती हैं; एकीकृत पोर्टल से प्रतिक्रिया बेहतर होगी।





AIR SUVIDHA 2.0 — EBOLA HEALTH SCREENING AT POINTS OF ENTRY

Ministry: Ministry of Civil Aviation / Ministry of Health and Family Welfare

PIB Date: 25th June 2026

Easy Explanation

WHO ने अफ्रीका में इबोला (Ebola) के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया — इस पर भारत की प्रतिक्रिया रही सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य जांच को उन्नत करना। एयर सुविधा को मूल रूप से कोविड-19 के दौरान अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल स्व-घोषणा पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एयर सुविधा 2.0, खासतौर पर इबोला-युग की जांच के लिए बनाया गया एक उन्नत संस्करण है, जो सभी प्रवेश-बिंदुओं (Points of Entry — PoE) — अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भूमि सीमा चौकियों पर लागू है। उच्च-जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अब रवानगी से पहले स्वास्थ्य घोषणा पूरी करनी होगी, आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, और 76 हवाई अड्डों पर तैनात पोर्ट हेल्थ अधिकारियों (PHO) द्वारा निगरानी की जाएगी। यह प्रणाली वास्तविक समय में भारत के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) से जुड़ी है — यानी अगर किसी यात्री में लक्षण दिखते हैं, तो अलर्ट एक साथ IDSP, राज्य स्वास्थ्य विभागों और जिला अस्पतालों तक पहुँच जाता है। यह कोविड-पूर्व की कागज़ी घोषणाओं से कहीं ज़्यादा स्मार्ट प्रणाली है, और कोविड-19 के शुरुआती अस्त-व्यस्त दौर, जब डिजिटल तंत्र शुरू से बनाया जा रहा था, उससे कहीं बेहतर है।

Key Terms:

Term	Definition
Air Suvidha 2.0	अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए उन्नत डिजिटल स्वास्थ्य घोषणा व स्क्रीनिंग पोर्टल; नागरिक उड्डयन मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय की साझा पहल; सभी प्रवेश-बिंदुओं पर सक्रिय।
PoE	Point of Entry — अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंदरगाह या भूमि सीमा चौकी, जहाँ से विदेश से आने वाले यात्री भारत में प्रवेश करते हैं; सभी PoE पर PHO तैनात हैं।
PHO	Port Health Organization — अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच करती है; 76 हवाई अड्डों पर तैनात; थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य घोषणा की समीक्षा करती है।
IDSP	Integrated Disease Surveillance Programme — भारत की रोग निगरानी की रीढ़; 100+ बीमारियों को कवर करता है; 3,500+ सेंटिनल केंद्रों से वास्तविक-समय डेटा मिलता है।
PHEIC	Public Health Emergency of International Concern — WHO का सबसे ऊँचा अलर्ट स्तर; इससे सभी सदस्य देशों के लिए IHR 2005 पालन की बाध्यता जुड़ जाती है।
IHR 2005	International Health Regulations 2005 — WHO की बाध्यकारी संधि; सदस्य देशों को PoE पर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का पता लगाने, रिपोर्ट करने और प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत होती है।
DIAL	Delhi International Airport Limited — IGI हवाई अड्डे का संचालन करती है; एयर सुविधा 2.0 के क्रियान्वयन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साझेदारी; ट्रैफिक के लिहाज़ से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा।

Important Points for UPSC:



| Click to Connect Now.



- एयर सुविधा को मूल रूप से अप्रैल 2021 में कोविड-19 स्वास्थ्य घोषणाओं के लिए शुरू किया गया था; एयर सुविधा 2.0 इसका इबोला के अनुरूप ढाला गया, उन्नत संस्करण है।
- भारत के लिए इबोला का जोखिम: भारत की 60% आबादी 3-4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के ज़रिये इसके संपर्क में आ सकती है; इबोला का इनक्यूबेशन काल 2-21 दिन है — यात्री लक्षण दिखने से पहले भी संक्रामक हो सकता है।
- थर्मल स्क्रीनिंग उन्नत: अब 76 हवाई अड्डों पर थर्मल कैमरे हैं; IDSP से जुड़ाव का मतलब है कि कोई भी सकारात्मक स्क्रीनिंग तुरंत बहु-एजेंसी समन्वित प्रतिक्रिया शुरू कर देती है।
- यात्री स्वास्थ्य घोषणा: उच्च-जोखिम देश से रवानगी से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है; आगमन पर यह जानकारी PHO को दिखती है; इससे मैनुअल कागज़ी काम कम होता है।
- IHR 2005 की बाध्यता: भारत कानूनी रूप से IHR 2005 के तहत बाध्य है कि वह PHEIC-प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच करे और 24-48 घंटे में मामलों की जानकारी WHO को दे।
- एयर सुविधा 2.0, CoWIN/ABHA से भी जुड़ा है — टीकाकरण इतिहास के लिए; यह कुछ अफ्रीकी देशों से ज़रूरी पीत ज्वर (yellow fever) के टीकाकरण को डिजिटल रूप से सत्यापित कर सकता है।





INS TRIKAND RESPONDS TO PIRACY — MV GOLDEN ARSENAL, GULF OF ADEN

Ministry: Ministry of Defence / Indian Navy

PIB Date: 2nd July 2026

Easy Explanation

2 जुलाई को भारतीय नौसेना के गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) में एक संकट-कॉल मिली। बहामास-ध्वजांकित बल्क कैरियर MV गोल्डन आर्सेनल पर हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने चढ़ने की कोशिश करते हुए हमला किया था। उस क्षेत्र में समुद्री डकैती-रोधी गश्त पर तैनात INS त्रिकंद ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फ्रिगेट के दल ने नाव और हेलीकॉप्टर से मरीन कमांडो (MARCOS) की टीम भेजी। MARCOS ने जहाज़ के डेक को सुरक्षित किया, हथियारबंद डाकुओं को पकड़ा, और चालक दल को मुक्त कराया — सभी 18 चालक दल के सदस्य डाकुओं के काटने की कोशिश के दौरान एक सिटाडेल (citadel — इसी उद्देश्य के लिए बना एक विशेष मज़बूत कमरा) में खुद को बंद कर चुके थे। सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे। नौ डाकुओं को पकड़ लिया गया। अदन की खाड़ी दुनिया के सबसे ज़्यादा समुद्री-डकैती-प्रवण शिपिंग मार्गों में से एक है — यह लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, और वैश्विक व्यापार का 12-15% इसी रास्ते से गुज़रता है। भारत 2008 से यहाँ ऑपरेशन संकल्प और उसके बाद के अभियानों के तहत लगातार समुद्री-डकैती-रोधी गश्त करता आया है। यह अभियान यह याद दिलाता है कि जहाँ हूँ हमले सुर्खियों में छाए रहते हैं, वहीं परंपरागत सोमाली डकैती (गैर-राज्य आपराधिक गिरोहों द्वारा) भी इस क्षेत्र में जारी है।

Key Terms:

Term	Definition
INS Trikand	भारतीय नौसेना का गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट; तलवार-श्रेणी (Krivak-III); अदन की खाड़ी में समुद्री-डकैती-रोधी गश्त पर तैनात; नाम का अर्थ 'त्रिशूल' है।
Gulf of Aden	यमन और सोमालिया के बीच स्थित समुद्र; लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है; वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण चोकपॉइंट; ऐतिहासिक रूप से समुद्री-डकैती-प्रवण।
MARCOS	मरीन कमांडो — भारत की विशिष्ट नौसैनिक विशेष अभियान बल; समुद्री आतंक-रोधी अभियानों और समुद्री-डकैती-रोधी बोर्डिंग में विशेषज्ञ।
Citadel	व्यापारिक जहाज़ों पर एक मज़बूत कमरा, जहाँ हमले के दौरान चालक दल शरण लेता है; बचाव आने तक बाहरी पहुँच रोकने के लिए बनाया गया।
Operation Sankalp	2008 में शुरू भारतीय नौसेना का अदन की खाड़ी समुद्री-डकैती-रोधी अभियान; निरंतर तैनाती; 4,000+ जहाज़ों को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया, दर्जनों डकैती-ग्रस्त जहाज़ों को बचाया।
Maritime Anti-Piracy Act 2022	भारत का घरेलू कानून, जो नौसेना द्वारा पकड़े गए समुद्री डाकुओं पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाता है; भारत में अब समुद्री डकैती एक संज्ञेय अपराध है।
SAGAR	Security and Growth for All in the Region — पीएम मोदी की हिंद महासागर नीति; समुद्री-डकैती-रोधी गश्त इसी का सीधा क्रियान्वयन है।

Important Points for UPSC:

- INS त्रिकंद: तलवार-श्रेणी का गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट; रूस से Krivak-III डिज़ाइन; 2012 में कमीशन हुआ; 4,000+ टन विस्थापन; इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें, टॉरपीडो और हेलीकॉप्टर हैं।



| Click to Connect Now.



- ऑपरेशन संकल्प (2019 से आगे): भारत का अरब सागर में समुद्री-डकैती-रोधी अभियान; 2008 से भारत ने 150+ नौसैनिक जहाज़ तैनात किए हैं।
- डकैती के आंकड़े: अदन की खाड़ी में घटनाएँ 2011 में सबसे ज़्यादा (200+ घटनाएँ) रहीं; 2019 तक घटकर सालाना 10 से कम रह गई; यमन संघर्ष से उत्पन्न सुरक्षा-शून्यता के कारण 2024-26 में फिर बढ़ीं।
- MARCOS की क्षमता: भारत के विशिष्ट समुद्री कमांडो, बंधक-बचाव, समुद्री-डकैती-रोधी और समुद्र में आतंक-रोधी अभियानों में प्रशिक्षित; समुद्री अभियानों में अमेरिकी नेवी सील्स के समकक्ष माने जाते हैं।
- 9 डाकू पकड़े गए: UNCLOS प्रावधानों के तहत, खुले समुद्र में पकड़े गए डाकुओं पर उन्हें पकड़ने वाला कोई भी देश मुकदमा चला सकता है; भारत आमतौर पर उन्हें केन्या या सेशेल्स की अदालतों को सौंपता है।
- मैरिटाइम एंटी-पाइरेसी एक्ट 2022: डाकुओं पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाने वाला भारत का घरेलू कानून; 2022 से भारतीय कानून के तहत समुद्री डकैती एक संज्ञेय अपराध है।
- हूती बनाम सोमाली डकैती में फर्क: हूती हमले राज्य-प्रायोजित, राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं; सोमाली डकैती गैर-राज्य तत्वों का आपराधिक उद्यम है — दोनों की कानूनी व परिचालन प्रतिक्रिया अलग होती है।





RAJASTHAN-HARYANA YAMUNA WATER PROJECT AGREEMENT

Ministry: Ministry of Home Affairs / Ministry of Jal Shakti

PIB Date: 29th June 2026

Easy Explanation

जहाँ इस हफ्ते भारत का ज़्यादातर ध्यान सेशेल्स और डिजिटल स्वास्थ्य पर था, वहीं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक चुपचाप लेकिन महत्वपूर्ण समझौता हुआ: राजस्थान और हरियाणा ने यमुना जल परियोजना के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए समझौता किया। राजस्थान एक जल-अभावग्रस्त राज्य है — इसका भारत में सबसे बड़ा भूभाग है, लेकिन भारत के जल संसाधनों का 2% से भी कम हिस्सा इसके पास है। इसके पश्चिमी ज़िले इंदिरा गांधी नहर पर निर्भर हैं, लेकिन अरावली पर्वतमाला के पास पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में लगभग कोई भरोसेमंद बारहमासी जल-स्रोत नहीं है। यमुना जल परियोजना यमुना नदी से — खासतौर पर हरियाणा के यमुना नहर नेटवर्क से — पानी मोड़कर जयपुर, अलवर, दौसा और आसपास के इलाकों सहित पूर्वी राजस्थान के ज़िलों को आपूर्ति करेगी। यह समझौता आवंटित किए जाने वाले पानी की मात्रा, लागत-साझाकरण फॉर्मूला, बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचे (हेडवर्क्स, नहरें, पाइपलाइन), और समय-सीमा तय करता है। यह सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का एक बेहतरीन उदाहरण है — दो भाजपा-शासित राज्य, गृह मंत्री की मध्यस्थता से, मुकदमेबाज़ी की बजाय बातचीत के ज़रिये एक लंबे समय से लंबित अंतर-राज्यीय जल-बंटवारे के मुद्दे को सुलझा रहे हैं।

Key Terms:

Term	Definition
Yamuna Water Project	हरियाणा के नहर नेटवर्क के ज़रिये यमुना का पानी जल-अभावग्रस्त पूर्वी राजस्थान के ज़िलों तक पहुँचाने का अंतर-राज्यीय समझौता।
Inter-State River Water Disputes Act 1956	राज्यों के बीच नदी-जल विवादों को नियंत्रित करने वाला कानून; इसके तहत न्यायाधिकरण (tribunals) बनते हैं; यमुना समझौता आपसी सहमति से न्यायाधिकरण को टालता है।
Upper Yamuna River Board	6 बेसिन राज्यों — हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश — के बीच यमुना जल के बंटवारे का प्रबंधन करने वाली वैधानिक संस्था।
Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)	राजस्थान की राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की बड़ी परियोजना; यमुना समझौता पूर्वी ज़िलों के लिए ERCP का पूरक है।
Haryana Canal Network	हरियाणा को पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों के ज़रिये यमुना का पानी मिलता है; अतिरिक्त पानी राजस्थान के साथ साझा किया जाएगा।
Cooperative Federalism	केंद्र और राज्यों का बराबर भागीदारों की तरह मिलकर काम करना; गृह मंत्री ने इस अंतर-राज्यीय समझौते में मध्यस्थता की।

Important Points for UPSC:

- राजस्थान का जल-संकट: राजस्थान का 60% हिस्सा शुष्क या अर्ध-शुष्क है; प्रति व्यक्ति जल-उपलब्धता भारत में सबसे कम में से एक है; पूर्वी ज़िलों में अक्सर पीने के पानी की भी कमी रहती है।
- यमुना बेसिन के राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश — सभी यमुना जल साझा करते हैं; अपर यमुना रिवर बोर्ड बंटवारे का समन्वय करता है।
- ERCP: केन, बेतवा, बनास नदियों को जोड़कर 13 पूर्वी ज़िलों को पानी देने की राजस्थान की बड़ी परियोजना; यह यमुना समझौता इसका पूरक है।



| Click to Connect Now.



- गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका: किशाऊ बांध समझौते जैसा ही पैटर्न — केंद्रीय गृह मंत्री अंतर-राज्यीय समझौतों में मध्यस्थता कर रहे हैं; यह सहकारी संघवाद में गृह मंत्रालय की भूमिका दर्शाता है।
- दोनों भाजपा-शासित राज्य: राजस्थान (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा) और हरियाणा (मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी) के बीच राजनीतिक तालमेल ने समझौते को आसान बनाया।
- ऐतिहासिक चेतावनी: हरियाणा-राजस्थान जल-बंटवारा विवादास्पद रहा है; पंजाब-हरियाणा के बीच SYL (सतलुज-यमुना लिंक) नहर विवाद दिखाता है कि ऐसे विवाद दशकों तक अनसुलझे रह सकते हैं।
- JJM 2.0 से जुड़ाव: पूर्वी राजस्थान जिलों में यमुना का पानी पहुँचने से वर्तमान में जल-अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल जीवन मिशन 2.0 के लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी।





INDIA-JAPAN AI JOINT STATEMENT — FIRST BILATERAL AI PARTNERSHIP

Ministry: Ministry of Electronics & IT / IndiaAI Mission

PIB Date: 2nd July 2026

Easy Explanation

हमने इस हफ्ते के लेख 4 में भारत-जापान शिखर सम्मेलन को व्यापक रूप से कवर किया। AI संयुक्त वक्तव्य पर अलग से गहराई से नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है — यह पहली बार है जब भारत ने किसी भी देश के साथ सरकार-से-सरकार स्तर पर द्विपक्षीय AI सहयोग समझौता किया है। यह संयुक्त वक्तव्य AI तकनीक की पूरी शृंखला को कवर करता है: अनुसंधान (फाउंडेशन मॉडल का साझा विकास), बुनियादी ढांचा (साझा कंप्यूटिंग संसाधन), सुरक्षा (भरोसेमंद AI के लिए सामान्य मानक), प्रतिभा (2030 तक जापान में 500 भारतीय AI पेशेवर), और अनुप्रयोग (स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट सिटी के लिए AI)। IndiaAI मिशन और जापान के METI ने एक समझौता जापान (MoC) पर हस्ताक्षर किए — यह इसका संस्थागत आधार है। दो विशेष अकादमिक सहयोग: IIT बॉम्बे + BharatGen + जापान का NII मिलकर वैज्ञानिक तर्क-आधारित LLM विकसित करेंगे; और SarvamAI (भारतीय AI स्टार्टअप) + जापान का Preferred Networks फाउंडेशन मॉडल बनाएंगे। दोनों देश स्पष्ट रूप से 'मानव-केंद्रित, सुरक्षित और भरोसेमंद AI' चाहते हैं — वे खुद को अमेरिका-चीन AI दौड़ के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, जो क्षमता से ज़्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। भारत की AI ताकत (प्रतिभा, सॉफ्टवेयर, किफ़ायती नवाचार) और जापान की AI ताकत (रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, विनिर्माण अनुप्रयोग) मिलकर एक सच्ची पूरक साझेदारी बनाते हैं।

Key Terms:

Term	Definition
India-Japan AI Joint Statement	पहला सरकार-से-सरकार द्विपक्षीय AI सहयोग समझौता; इससे संबंध 'रणनीतिक AI अनुसंधान व विकास साझेदारी' तक ऊँचा उठता है।
IndiaAI Mission	भारत के AI तंत्र के लिए 10,371 करोड़ रुपये का सरकारी कार्यक्रम; जापान के METI के साथ समझौते का हस्ताक्षरकर्ता।
METI	Ministry of Economy, Trade and Industry, जापान — जापान का उद्योग व तकनीक मंत्रालय; जापान की AI रणनीति की देखरेख करता है।
BharatGen	भारत की स्वदेशी बहुभाषी बड़ी भाषा मॉडल (LLM) पहल; IIT बॉम्बे के नेतृत्व में; सरकार समर्थित।
SarvamAI	भारतीय-भाषा फाउंडेशन मॉडल बनाने वाला भारतीय AI स्टार्टअप; इस समझौते के तहत जापान के Preferred Networks के साथ साझेदारी।
Preferred Networks	जापान की अग्रणी AI कंपनी; डीप लर्निंग व रोबोटिक्स AI में विशेषज्ञ; फाउंडेशन मॉडल पर SarvamAI के साथ साझेदारी।
Human-Centric AI	AI विकास का वह दर्शन, जो शुद्ध क्षमता बढ़ाने की बजाय मानवीय मूल्यों, सुरक्षा और नियंत्रण को प्राथमिकता देता है; भारत-जापान दोनों का साझा दृष्टिकोण।

Important Points for UPSC:

- पहला द्विपक्षीय AI वक्तव्य: भारत का AI का ज़िक्र बहुपक्षीय समझौतों (G20, क्वाड) में तो रहा है, लेकिन यह पहला समर्पित द्विपक्षीय सरकारी AI सहयोग ढांचा है।



| Click to Connect Now.



- पूरी AI शृंखला को कवर करना: अनुसंधान (LLM विकास) से बुनियादी ढांचे (कंप्यूट साझाकरण) से सुरक्षा (भरोसेमंद AI मानक) से प्रतिभा (500 AI पेशेवर) से अनुप्रयोगों (स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट सिटी) तक।
- 2030 तक जापान में 500 भारतीय AI पेशेवर: जापान की गंभीर AI प्रतिभा की कमी (बुजुर्ग होती आबादी) का समाधान; भारत का बड़ा AI व ML कार्यबल इसका उपाय है।
- IIT बॉम्बे + BharatGen + NII LLM: वैज्ञानिक तर्क-आधारित LLM पर ध्यान — ऐसा AI जो शोध-पत्रों को समझ सके और वैज्ञानिक खोज में मदद कर सके।
- SarvamAI का महत्व: बहुभाषी AI (22 भारतीय भाषाएँ) और जापान की रोबोटिक्स AI का मेल — भारत की भाषाई विविधता और जापान की विनिर्माण स्वचालन ज़रूरतों का संगम।
- सुरक्षा पहलू: भारत और जापान दोनों 'AI सियोल शिखर सम्मेलन' (2024) के सिद्धांतों और G7 हिरोशिमा AI प्रक्रिया का समर्थन करते हैं — यह समझौता उन बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को द्विपक्षीय रूप से लागू करता है।
- भू-राजनीतिक संदर्भ: अमेरिका निर्यात-नियंत्रण के साथ AI में आगे है; चीन का AI तंत्र बंद है; भारत-जापान की 'भरोसेमंद AI' साझेदारी एक तीसरा रास्ता बनाती है — खुला, सुरक्षित, लोकतांत्रिक।
- JCM से जुड़ाव: भारत-जापान के बीच पहले से कार्बन क्रेडिट सहयोग (JCM, अनुच्छेद 6.2) है; AI वक्तव्य एक नए क्षेत्र में उसी संरचित द्विपक्षीय ढांचे के मॉडल का अनुसरण करता है।





BHASHINI — MULTILINGUAL AI SHOWCASED AT NCeG 2026

Ministry: Ministry of Electronics & IT (MeitY)

PIB Date: 2nd July 2026

Easy Explanation

भारत में 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ हैं। दशकों तक, डिजिटल इंडिया मूल रूप से 'अंग्रेज़ी इंडिया' ही रहा — सरकारी वेबसाइटें, फॉर्म, ऐप और सेवाएँ मुख्यतः अंग्रेज़ी में थीं, जिससे ज़्यादातर भारतीय, जो हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मराठी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा सहज हैं, बाहर रह जाते थे। भाषिणी (BHASHINI — Bharat ki Bhasha Interfaces for India) सरकार का वह मिशन है, जिसका लक्ष्य AI-संचालित अनुवाद, प्रतिलेखन (transcription) और वाणी-संश्लेषण (voice synthesis) के ज़रिये सभी डिजिटल सामग्री और सेवाओं को सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। MeitY के भाषिणी कार्यक्रम के तहत विकसित, यह खुले-स्रोत (open-source) ध्रुव AI ढांचे पर बना है और खासतौर पर भारतीय भाषा डेटा पर प्रशिक्षित AI मॉडल का इस्तेमाल करता है — क्षेत्रीय भाषाओं के लिए गूगल ट्रांसलेट जैसे वैश्विक मॉडल यहाँ पिछड़ जाते हैं। इस हफ्ते जयपुर में हुए नेशनल ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस (NCeG) 2026 में, भाषिणी ने अपने बहुभाषी AI नवाचारों — जिसमें राजस्थान भाषा मॉडल प्रशिक्षण हैकाथॉन का शुभारंभ भी शामिल है — का प्रदर्शन किया। जो मुख्य क्षमताएँ दिखाई गईं: भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक-समय वाणी-से-वाणी अनुवाद (कोई तमिल में बोले, दूसरा तुरंत हिंदी में सुने), क्षेत्रीय भाषाओं में अदालती कार्यवाही की AI-संचालित प्रतिलेखन, और सरकारी चैटबॉट जो नागरिक की पसंदीदा भाषा में जवाब देते हैं।

Key Terms:

Term	Definition
BHASHINI	Bharat ki Bhasha Interfaces for India — MeitY का राष्ट्रीय भाषा-अनुवाद मिशन; 22+ भारतीय भाषाओं में AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल सेवाएँ।
Dhruva AI	भाषिणी को शक्ति देने वाला खुले-स्रोत बहुभाषी AI ढांचा; भारतीय भाषा डेटासेट पर प्रशिक्षित; भाषिणी अनुप्रयोगों की नींव।
NCeG	National Conference on e-Governance — वार्षिक सम्मेलन; 2026 संस्करण जयपुर में हुआ; डिजिटल शासन नवाचारों को प्रदर्शित करता है।
ASR	Automatic Speech Recognition — बोले गए शब्दों को पाठ (text) में बदलता है; भाषिणी का ASR 22+ भारतीय भाषाओं के लिए काम करता है।
TTS	Text-to-Speech — पाठ को बोले गए ऑडियो में बदलता है; भाषिणी का TTS कम-साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री को सुनने योग्य बनाता है।
MT	Machine Translation — भाषाओं के बीच AI अनुवाद; भारतीय भाषाओं के लिए भाषिणी का MT सामान्य उपकरणों से काफी बेहतर सटीकता देता है।
Rajasthan Language Model Hackathon	राजस्थानी बोली के लिए AI मॉडल बनाने की डेवलपर प्रतियोगिता; इससे कम-संसाधन वाली भारतीय भाषाओं में भाषिणी की पहुँच और गहरी होती है।

Important Points for UPSC:

- भाषिणी का मिशन: इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाना; लक्ष्य: सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में प्रमुख सरकारी सेवाओं की 100% उपलब्धता।



| Click to Connect Now.



- भाषिणी क्यों ज़रूरी है: 55% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता क्षेत्रीय भाषा सामग्री पसंद करते हैं; सिर्फ-अंग्रेज़ी इंटरफ़ेस 70 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को डिजिटल शासन के लाभों से बाहर रखते हैं।
- ध्रुव ढांचा: खुला-स्रोत; कोई भी डेवलपर इस पर ऐप बना सकता है; 22 भाषाओं में ASR, MT, TTS के लिए 100+ मॉडल; भारतीय भाषाओं के लिए वाणिज्यिक समाधानों के बराबर या उनसे बेहतर।
- अदालती प्रतिलेखन: भाषिणी को क्षेत्रीय भाषाओं में अदालती कार्यवाही के वास्तविक-समय प्रतिलेखन के लिए पायलट किया गया — गैर-अंग्रेज़ी भाषी वादियों के लिए न्याय तक पहुँच के लिहाज़ से अहम।
- आरोग्य सेतु 2.0 में भाषिणी: क्षेत्रीय भाषाओं में स्वास्थ्य सेवाएँ; आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट 12 भाषाओं में भाषिणी-संचालित अनुवाद का इस्तेमाल करता है।
- सरकारी इस्तेमाल: अब 100+ सरकारी चैटबॉट भाषिणी-संचालित हैं; ई-कोर्ट, जन समर्थ पोर्टल, किसान सारथी — सभी क्षेत्रीय भाषा समर्थन के लिए भाषिणी का इस्तेमाल करते हैं।
- भारत-जापान से जुड़ाव: SarvamAI और BharatGen (दोनों भारत-जापान AI वक्तव्य से जुड़े) भाषिणी के भाषा-डेटासेट तंत्र पर आधारित हैं।
- निजी क्षेत्र में अपनाना: ज़ोमैटो, IRCTC, UIDAI ने क्षेत्रीय भाषा उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के लिए भाषिणी API को एकीकृत किया है।





BHARAT TAXI — COOPERATIVE-BASED TAXI SERVICE LAUNCHED IN GUJARAT

Ministry: Ministry of Cooperation / Ministry of Home Affairs

PIB Date: 27th June 2026

Easy Explanation

ओला और उबर ने भारत में शहरी आवागमन (urban mobility) को बदल दिया है। लेकिन ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स में एक ढांचागत समस्या है: प्लेटफॉर्म कमीशन बढ़ने (कभी-कभी हर किराए का 30-35%) के साथ ड्राइवरों की कमाई घटती जाती है, उनके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं, कोई लाभ नहीं, कीमत तय करने में कोई राय नहीं, और जिस प्लेटफॉर्म पर वे काम करते हैं उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह, जो सहकारिता मंत्रालय के भी प्रभारी हैं, ने 27 जून को गुजरात में भारत टैक्सी शुरू की — एक सहकारी-आधारित टैक्सी सेवा, जिसमें ड्राइवर खुद प्लेटफॉर्म के मालिक होते हैं। यह इस तरह काम करता है: ड्राइवर एक सहकारी समिति (cooperative society) बनाते हैं। यह सहकारी समिति ऐप और ब्रांड की मालिक होती है। जब कोई यात्री 100 रुपये चुकाता है, तो उसका 95% हिस्सा वापस ड्राइवरों की सहकारी समिति के पास जाता है — कोई बाहरी निवेशक या कॉर्पोरेशन बड़ा हिस्सा नहीं काटता। कीमत पारदर्शी है और सहकारी समिति के अपने लोकतांत्रिक प्रशासन से नियंत्रित होती है। यह मॉडल सीधे उस अमूल डेयरी सहकारी मॉडल से लिया गया है जिसने गुजरात को मशहूर किया — जहाँ दूध उत्पादक उस सहकारी समिति के मालिक हैं, जो उनके दूध को ब्रांड करके बेचती है, और इससे किसी निजी डेयरी कंपनी को बेचने की तुलना में कहीं ज़्यादा मूल्य उन्हें मिलता है। भारत टैक्सी की शुरुआत अहमदाबाद, सूरत और राजकोट से हो रही है। अगर यह सफल रहा, तो पूरे देश में इसे शुरू करने की योजना है, जो संभवतः ओला और उबर के कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म मॉडल का एक विकल्प बन सकता है।

Key Terms:

Term	Definition
Bharat Taxi	गुजरात में शुरू की गई सहकारी-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर सेवा; ड्राइवर-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म; सहकारी अर्थशास्त्र पर आधारित; लगभग 5% कमीशन ढांचा।
Cooperative Society	सदस्यों के स्वामित्व वाला संगठन; लोकतांत्रिक प्रशासन (एक सदस्य एक वोट); सदस्यों के बीच मुनाफे का बंटवारा; राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत।
Ministry of Cooperation	2021 में बना; अमित शाह इसके प्रभारी हैं; सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देता है; राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है।
AMUL Model	आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड — दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समिति; गुजरात-मूल; उत्पादकों के स्वामित्व वाली; इसी मॉडल को भारत टैक्सी तक बढ़ाया जा रहा है।
Platform Cooperative	बाहरी निवेशकों की बजाय अपने उपयोगकर्ताओं या श्रमिकों के स्वामित्व वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म; ओला और उबर के निवेशक-स्वामित्व वाले मॉडल के विपरीत।
Gig Economy	ऐसी कार्य-व्यवस्था जिसमें लोग औपचारिक रोज़गार के बिना अस्थायी, लचीले आधार पर काम करते हैं; ओला और उबर के ड्राइवर बिना किसी सुरक्षा के गिग वर्कर होते हैं।

Important Points for UPSC:

- सहकारिता मंत्रालय अगस्त 2021 में बना — पहली बार भारत के पास सहकारी समितियों के लिए समर्पित मंत्रालय है; अमित शाह का गृह और सहकारिता, दोनों मंत्रालयों का प्रभार राजनीतिक प्राथमिकता दर्शाता है।
- अमूल का उदाहरण: 36 लाख डेयरी किसान सदस्य; 72,000 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार; किसानों को उपभोक्ता मूल्य का 80% मिलता है, जबकि निजी डेयरी आपूर्ति श्रृंखलाओं में यह 20-30% होता है — भारत टैक्सी का लक्ष्य भी वैसा ही ढांचा है।



| Click to Connect Now.



- ड्राइवर अर्थशास्त्र: ओला और उबर आमतौर पर हर सवारी पर 20-35% कमीशन लेते हैं; भारत टैक्सी लगभग 5% प्रशासनिक शुल्क लेती है; ड्राइवर 95% रखते हैं — कमाई में भारी बढ़ोतरी।
- प्रशासन: ड्राइवर लोकतांत्रिक रूप से सहकारी बोर्ड चुनते हैं; बोर्ड कीमतें, नीतियाँ, सेवा मानक तय करता है — कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्मों के विपरीत श्रमिकों की असली आवाज़ है।
- गुजरात में शुरुआत: पहले अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में; कुल मिलाकर 1.2 करोड़+ की आबादी; सफल रहने पर राष्ट्रीय विस्तार का प्रमाण बनेगा।
- राष्ट्रीय सहकारी तंत्र: भारत में 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जो 13 करोड़ लोगों को रोज़गार देती हैं; चीनी, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास सहकारी समितियाँ स्थापित हैं; शहरी परिवहन सहकारी समितियाँ नई हैं।
- चुनौती: ओला और उबर के पास भारी नेटवर्क प्रभाव (लाखों मौजूदा ड्राइवर और सवारियों) है; भारत टैक्सी को शुरुआत में पर्याप्त ड्राइवर और सवारियाँ एक साथ जुटाने की चुनौती ('कोल्ड-स्टार्ट समस्या') का सामना करना होगा।
- राष्ट्रीय सहकारिता नीति: सहकारिता मंत्रालय के तहत तैयार हो रही है; भारत टैक्सी यह दिखाने वाला एक पायलट है कि एक सहकारी शहरी सेवा अर्थव्यवस्था कैसे दिख सकती है।





HIGH-SPEED RAIL — PIB BACKGROUNDER ON INDIA'S BULLET TRAIN JOURNEY

Ministry: Ministry of Railways / National High Speed Rail Corporation

PIB Date: 3rd July 2026

Easy Explanation

भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना — मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर — कई सालों से निर्माणाधीन है। PIB ने इस हफ्ते 'भारत का हाई-स्पीड रेल भविष्य: विस्तार के लिए एक मानकीकृत रास्ता बनाना' पर एक विस्तृत जानकारी जारी की। MAHSR परियोजना जापान की शिंकांसेन (E5 श्रृंखला) तकनीक का इस्तेमाल करती है, यह 320 किमी/घंटा की रफ़्तार से चलेगी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किमी की दूरी लगभग 3 घंटे में तय करेगी (जबकि मौजूदा ट्रेनों से 6+ घंटे लगते हैं), और इसमें 12 स्टेशन होंगे। भारत जापान की ODA (Official Development Assistance) के साथ मिलकर इसे वित्तपोषित कर रहा है — जापान ने 50 साल के लिए 0.1% ब्याज़ पर लगभग 88,000 करोड़ रुपये (लगभग 12 अरब डॉलर) का कम-ब्याज़ ऋण दिया है। निर्माण की स्थिति: गुजरात में वायाडक्ट (viaduct) निर्माण अच्छी प्रगति पर है (लगभग 80% पूरा); मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स का भूमिगत स्टेशन सबसे जटिल चुनौती है; महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में भूमि अधिग्रहण मुख्य बाधा थी और अब यह काफी हद तक सुलझ चुका है। PIB की इस जानकारी में भारत की छह और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की योजनाओं का भी ज़िक्र है: दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली-अहमदाबाद, मुंबई-नागपुर, मुंबई-हैदराबाद, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-अमृतसर — इन भावी कॉरिडोर के लिए लागत घटाने और स्वदेशी विनिर्माण को सक्षम बनाने के वास्ते तकनीक मानकीकरण चल रहा है।

Key Terms:

Term	Definition
MAHSR	मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल; 508 किमी; 12 स्टेशन; 320 किमी/घंटा की रफ़्तार; जापान की शिंकांसेन E5 तकनीक; परिचालन लक्ष्य 2028-29।
NHSRCL	National High Speed Rail Corporation Limited — MAHSR को क्रियान्वित करने वाली विशेष उद्देश्य कंपनी; केंद्र व राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम।
Shinkansen	जापान की बुलेट ट्रेन प्रणाली; दुनिया की पहली हाई-स्पीड रेल (1964 टोक्यो ओलंपिक); समय-पालन (औसत देरी 1 मिनट से कम) और 60 सालों में शून्य यात्री मृत्यु के लिए जानी जाती है।
ODA	Official Development Assistance — जापान की JICA का 50 साल के लिए 0.1% ब्याज़ पर 88,000 करोड़ रुपये का ऋण; दुनिया के सबसे रियायती ऋणों में से एक।
Viaduct	एलिवेटेड (उठा हुआ) ढांचा (पुल जैसा), जिस पर हाई-स्पीड रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं; MAHSR का 92% हिस्सा वायाडक्ट पर है; सिर्फ 7 किमी भूमिगत (मुंबई में) है।
Six Future HSR Corridors	दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली-अहमदाबाद, मुंबई-नागपुर, मुंबई-हैदराबाद, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-अमृतसर — शुरुआती योजना में; तकनीक मानकीकरण चल रहा है।
Technology Standardisation	लागत घटाने और स्वदेशी विनिर्माण को सक्षम बनाने के लिए भारत सभी कॉरिडोर में एकसमान HSR तकनीकी मानक विकसित कर रहा है।

Important Points for UPSC:

- MAHSR मार्ग: मुंबई BKC (भूमिगत) से ठाणे, विरार, सूरत, वडोदरा, आणंद होते हुए अहमदाबाद तक; 12 स्टेशन; 508 किमी; रफ़्तार 320 किमी/घंटा तक।



| Click to Connect Now.



- निर्माण की स्थिति: गुजरात खंड (352 किमी) का वायाडक्ट लगभग 80% पूरा; महाराष्ट्र खंड (156 किमी) शहरी जटिलताओं और पहले की भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण धीमा है।
- भूमि अधिग्रहण: 1,396 हेक्टेयर की ज़रूरत थी; अधिकांश अधिग्रहीत; पालघर (महाराष्ट्र) सबसे बड़ा लंबित क्षेत्र था — अब काफी हद तक सुलझा, कुछ मुकदमेबाज़ी बाकी है।
- जापान ODA की शर्तें: 88,000 करोड़ रुपये, 0.1% ब्याज़, 50 साल की चुकौती, 15 साल की मोहलत (grace period) — दुनिया के सबसे रियायती ऋणों में से एक; भारत में जापान की रणनीतिक दिलचस्पी को दर्शाता है।
- परिचालन लक्ष्य: गुजरात खंड का आंशिक शुभारंभ 2027 के लिए घोषित; पूरा कॉरिडोर 2028-29 तक परिचालन में — मूल 2023 के लक्ष्य के बाद ये समय-सीमाएँ कई बार बदली गई हैं।
- आर्थिक तर्क: MAHSR से मुंबई-अहमदाबाद यात्रा घटकर 3 घंटे रह जाएगी (6+ घंटे के मुकाबले); प्रतिदिन 35,000 यात्रियों की क्षमता; भारत के चौथे और पाँचवें सबसे बड़े शहरों को जोड़ता है।
- तकनीक हस्तांतरण: जापानी कंपनियों (हिताची, कावासाकी) को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी अनिवार्य है; MAHSR के बाद के HSR कॉरिडोर के लिए 70% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य है।
- भारत-जापान जुड़ाव: HSR की यह जानकारी भारत-जापान शिखर सम्मेलन के उसी हफ्ते जारी हुई; नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप (NGMP) में रेलवे व HSR सहयोग शामिल है।





PRACTICE QUESTIONS

10 PRELIMS QUESTIONS — UPSC PRELIMS STYLE

Q1. नेत्र (Netra) AEW&C प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स (CABS), बेंगलुरु ने विकसित किया।
2. यह प्रणाली इल्युमिन IL-76 विमान प्लेटफॉर्म पर लगी है।
3. इसका AESA रडार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (LRDE) ने डिज़ाइन किया।
4. प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति (IOC) 2017 में और अंतिम परिचालन स्वीकृति (FOC) 2026 में मिली।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

Q2. कॉपर-क्लोरीन (Cu-Cl) थर्मोकेमिकल साइकिल पर आधारित दुनिया की पहली हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ?

- (a) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई
- (b) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), कलपक्कम
- (c) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तारापुर
- (d) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

Q3. पीएम मोदी की सेशेल्स राजकीय यात्रा (27-29 जून 2026) के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सेशेल्स की पहली राजकीय यात्रा थी।
2. पीएम मोदी को 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न' — सेशेल्स का सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान — दिया गया।
3. भारत ने सेशेल्स के लिए 250 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
4. इस यात्रा में रक्षा, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 19 द्विपक्षीय समझौते हुए।

उपरोक्त में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q4. 10वीं NCORD शीर्ष बैठक में जारी 'विज़न डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026-2029' कितने प्रमुख स्तंभों पर आधारित है?

- (a) तीन
- (b) चार
- (c) पाँच
- (d) छह





Q5. 16वें CCHFW में हुए डिजिटल स्वास्थ्य शुभारंभों के संदर्भ में, कौन-सी जोड़ी गलत है?

- (a) यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस — स्वास्थ्य डेटा के सहज आदान-प्रदान के लिए इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल
- (b) ABHA — हर भारतीय के लिए 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य खाता ID
- (c) आयुष्मान सारथी — PM-JAY योजना के मार्गदर्शन के लिए 12 भाषाओं में व्हाट्सएप चैटबॉट
- (d) SSBSK — राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के परिचालन दिशानिर्देश

Q6. VB-G RAM G अधिनियम, 2025, 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन-सा मनरेगा से एक मुख्य बदलाव को सही ढंग से बताता है?

- 1. मज़दूरी दरें स्वतः कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) से जुड़ी हैं।
- 2. सभी ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीशुदा रोज़गार अवधि 100 से बढ़ाकर 200 दिन कर दी गई है।
- 3. दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार 100 की बजाय 150 दिनों के रोज़गार तक पहुँच सकते हैं।
- 4. एक AI-सक्षम ग्रामीण आंतरिक ऑडिट पोर्टल संपत्ति की गुणवत्ता और मज़दूरी भुगतान समय-सीमा की निगरानी करता है।

उपरोक्त में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q7. 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न' किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान से जुड़ा है?

- (a) मॉरीशस
- (b) मालदीव
- (c) सेशेल्स
- (d) कोमोरोस

Q8. भारत-जापान 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणामों के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

- 1. तीन मुख्य दस्तावेज़ अपनाए गए: आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणापत्र, AI पर संयुक्त वक्तव्य, और ऊर्जा सहनशीलता पर संयुक्त वक्तव्य।
- 2. जापान CBG पहल के तहत भारत में 1,000 बायोगैस व जैविक खाद संयंत्रों की स्थापना में सहयोग देगा।
- 3. दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर 2027 को 'भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष' घोषित किया।
- 4. भारत 2030 तक भारत में 500 जापानी AI पेशेवरों को भेजने पर सहमत हुआ।

उपरोक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

Q9. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2026 में प्रदर्शित भाषिणी (BHASHINI) को सबसे बेहतर किस रूप में वर्णित किया जा सकता है?

- (a) महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए भारत का राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा ढांचा





- (b) 22+ भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने वाला AI-संचालित बहुभाषी मंच
- (c) सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली
- (d) सरकारी डेटा भंडारण के लिए भारत का राष्ट्रीय क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा

Q10. गुजरात में शुरू हुई भारत टैक्सी मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है?

- (a) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मॉडल, जहाँ सरकार टैक्सी सेवा की मालिक व संचालक है
- (b) फ्रैंचाइज़ी मॉडल, जहाँ निजी संचालक सरकार के ब्रांड व तकनीक इस्तेमाल करने के लिए शुल्क देते हैं
- (c) सहकारी मॉडल, जहाँ ड्राइवर प्लेटफॉर्म के मालिक होते हैं, जो अमूल सहकारी ढांचे से प्रेरित है
- (d) PPP मॉडल, जहाँ एक निजी कंपनी सरकारी बुनियादी ढांचे पर सेवा संचालित करती है





2 MAINS QUESTIONS

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 — 150 शब्द:

'IAF नेत्र की FOC, DAE की कॉपर-क्लोरीन हाइड्रोजन सुविधा, और डिजिटल इंडिया की 11 साल की यात्रा — ये तीनों एक ही अंतर्निहित सिद्धांत दर्शाते हैं: भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता खरीदी नहीं जाती — यह धैर्यपूर्वक निर्मित होती है।' इस हफ्ते के घटनाक्रमों का इस्तेमाल करते हुए इस कथन की समालोचनात्मक (critically) समीक्षा करें और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की रणनीति में साझा सूत्रों की पहचान करें।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 — 250 शब्द:

पीएम मोदी की सेशेल्स यात्रा और एक ही हफ्ते में हुआ भारत-जापान शिखर सम्मेलन, भारत की विदेश नीति के दो अलग लेकिन परस्पर-पूरक आयाम दर्शाते हैं: 'हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदाता' और 'इंडो-पैसिफिक में तकनीकी साझेदार'। दोनों यात्राओं को एक एकीकृत रणनीतिक विदेश नीति वक्तव्य के रूप में विश्लेषित करें, और मूल्यांकन करें कि क्या भारत हिंद महासागर, इंडो-पैसिफिक और ग्लोबल साउथ में एक साथ खुद को एक अपरिहार्य (indispensable) साझेदार के रूप में स्थापित करने में सफल हो रहा है।



PRELIMS ANSWERS & EXPLANATIONS**Q1. उत्तर: (b) केवल तीन**

कथन 2 गलत है — नेत्र AEW&C, Embraer ERJ-145 पर लगा है, IL-76 पर नहीं। IL-76 पर आयातित फाल्कन AWACS लगा है। यह क्लासिक नेत्र बनाम फाल्कन वाला जाल (trap) है। कथन 1 (CABS, बेंगलुरु), 3 (LRDE ने AESA रडार डिज़ाइन किया), और 4 (IOC 2017, FOC 2026) सभी सही हैं। यानी तीन कथन सही हैं।

Q2. उत्तर: (b)

Cu-Cl हाइड्रोजन सुविधा IGCAR (इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र), कलपक्कम, तमिलनाडु में है — जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की प्रोसेस हीट का इस्तेमाल करती है। BARC (मुंबई) ने Cu-Cl प्रक्रिया विकसित की, लेकिन सुविधा IGCAR में है। किसने प्रक्रिया विकसित की (BARC) और सुविधा कहाँ है (IGCAR), इसी अंतर में यह जाल छिपा है।

Q3. उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 4

कथन 3 गलत है — भारत ने सेशेल्स के लिए 250 मिलियन नहीं, बल्कि 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया। कथन 1 (पहली भारतीय PM यात्रा), 2 (गार्जियन ऑफ ब्लू होराइज़न सम्मान), और 4 (19 द्विपक्षीय परिणाम) सही हैं। संख्याएँ UPSC में हमेशा परखी जाती हैं — 175 मिलियन डॉलर याद रखना ज़रूरी है।

Q4. उत्तर: (b) चार

‘विज़न डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026-2029’ के चार स्तंभ हैं: (1) प्रवर्तन, खुफिया व अभियान; (2) अग्रगामी रसायन व सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण; (3) मांग व नुकसान में कमी; (4) क्षमता निर्माण, समन्वय व निगरानी। रणनीति का सार: ‘पहचानो, बाधित करो, नष्ट करो’।

Q5. उत्तर: (d)

विकल्प (d) गलत जोड़ी है — SSBSK (समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) एक व्यापक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, न कि एम्बुलेंस सेवा। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा दिशानिर्देश को NAS 2026 कहा जाता है। विकल्प (a) UHI = इंटरऑपरेबिलिटी, (b) ABHA = 14 अंकों की स्वास्थ्य ID, (c) आयुष्मान सारथी = व्हाट्सएप चैटबॉट — सभी सही जोड़े गए हैं।

Q6. उत्तर: (a) केवल 1, 3 और 4

कथन 2 गलत है — VB-G RAM G अधिनियम सिर्फ दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों के लिए 150 दिन तक बढ़ाता है, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 200 दिन नहीं। सामान्य हकदारी 100 दिन ही रहती है (संकट में अतिरिक्त दिन संभव)। कथन 1 (स्वतः CPI-AL सूचीकरण), 3 (दिव्यांगों के लिए 150 दिन), और 4 (AI ऑडिट पोर्टल) सही हैं।

Q7. उत्तर: (c)

‘गार्जियन ऑफ ब्लू होराइज़न’ सेशेल्स का सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान है, जो पीएम मोदी को उनकी राजकीय यात्रा के दौरान 28 जून 2026 को दिया गया। इसे सेशेल्स कैबिनेट ने 24 जून 2026 को नया स्थापित किया था — समारोह से सिर्फ 4 दिन पहले। मॉरीशस, मालदीव या कोमोरोस नहीं।

Q8. उत्तर: (b) केवल तीन

कथन 4 गलत है — यह 2030 तक जापान भेजे जाने वाले 500 भारतीय AI पेशेवरों की बात है (भारत में जापानी पेशेवर नहीं)। भारत के पास AI प्रतिभा है; जापान के पास उद्योग-मांग और प्रतिभा की कमी है। कथन 1 (तीन दस्तावेज़), 2 (CBG पहल के तहत 1,000 बायोगैस संयंत्र), और 3 (2027 = 75 साल संबंध = साझा क्षितिज वर्ष) सभी सही हैं।

Q9. उत्तर: (b)



भाषिणी 22+ भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने वाला भारत का AI-संचालित बहुभाषी मंच है — यह MeitY के भाषिणी कार्यक्रम के तहत ध्रुव AI ढांचे पर विकसित हुआ है। यह साइबर-सुरक्षा नहीं है (वह CERT-In/NCIIPC का काम है), न ही ब्लॉकचेन, न ही क्लाउड बुनियादी ढांचा (वह MeghRaj/NIC है)।

Q10. उत्तर: (c)

भारत टैक्सी एक सहकारी मॉडल है, जहाँ टैक्सी ड्राइवर प्लेटफॉर्म के मालिक होते हैं — यह सीधे गुजरात के अमूल सहकारी ढांचे से प्रेरित है। यह कोई PSU (सरकारी स्वामित्व) नहीं है, न फ्रैंचाइज़ी है, न PPP। मुख्य अंतर यह है: ड्राइवर मालिक हैं, कर्मचारी या ठेकेदार नहीं। यही सहकारी अर्थशास्त्र वाला पहलू इसे UPSC के लिहाज़ से प्रासंगिक बनाता है।

